सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
स्थानीय सरकार पर 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष का
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

बिहार सरकार

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-3

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
स्थानीय सरकार पर 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष का
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

बिहार सरकार

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-3

विषय सूची

अध्याय	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ सं0
	प्राक्कथन		v
	विहंगावलोकन		vii
I	**पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकलापों, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित विषयों की रुपरेखा**		
	परिचय	1.1	1
	पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा	1.2	2
	पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली	1.3	2
	विभिन्न समितियों का गठन	1.4	5
	लेखापरीक्षा व्यवस्था	1.5	6
	लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया	1.6	7
	जवाबदेही तंत्र	1.7	9
	वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित मामले	1.8	11
II	**अनुपालन लेखापरीक्षा**		
	पंचायती राज विभाग		
	कपटपूर्ण भुगतान	2.1	17
III	**शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकलापों, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित विषयों की रुपरेखा**		
	परिचय	3.1	19
	शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा	3.2	20
	शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली	3.3	20
	विभिन्न समितियों का गठन	3.4	23
	लेखापरीक्षा व्यवस्था	3.5	24
	लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया	3.6	25
	जवाबदेही तंत्र	3.7	27
	वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित मामले	3.8	30
IV	**अनुपालन लेखापरीक्षा**		
	शहरी विकास एवं आवास विभाग		
	ब्याज और जुर्माने का परिहार्य व्यय	4.1	35
	कपटपूर्ण भुगतान	4.2	36

अध्याय	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ सं0
V	**निष्पादन लेखापरीक्षा**		
	नगर विकास एवं आवास विभाग		
	प्रस्तावना	5.1	40
	बिहार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति	5.2	46
	लेखांकन प्रक्रिया और वित्तीय प्रबंधन	5.3	56
	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना एवं रणनीति	5.4	62
	नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण और परिवहन	5.5	70
	नगरीय ठोस अपशिष्टों का प्रसंस्करण और निपटान	5.6	86
	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत क्रय	5.7	108
	इंटेलीजेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली	5.8	118
	विशेष अपशिष्ट और अन्य अपशिष्टों का प्रबंधन	5.9	124
	अनुश्रवण और मूल्यांकन	5.10	129

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ सं.
4.1	ब्याज और जुर्माने का परिहार्य व्यय	4.1	**137**
5.1	शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढाँचा	5.1.1	**142**
5.2 (**अ**)	नमूना जांचित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिवेदित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये सेवा स्तर मानक (मार्च 2017 / मार्च 2018)	5.2.1	**143**
5.2 (**ब**)	नमूना जांच किये गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिवेदित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये सेवा स्तर मानक (मार्च 2022)	5.2.1	**144**
5.2 (**स**)	लेखापरीक्षा द्वारा पाये गये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (मार्च 2022) के लिए सेवा स्तर मानक	5.2.1	**146**
5.2 (**द**)	सेवा स्तर मानक	5.2.1	**150**
5.3	बिहार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति	5.2.1	**151**
5.4	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपभोक्ता शुल्क का अधिरोपण एवं संग्रहण	5.3.2	**162**
5.5	अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) जमा करने में विलम्ब	5.3.5	**164**
5.6	अगस्त–दिसंबर 2022 तक अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत न करना	5.3.5	**165**
5.7	2017–22 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों में सूचना, शिक्षण एवं संचार गतिविधियों की स्थिति	5.4.4	**166**
5.8	2016–22 के दौरान परिवारों को प्रदान किए गए कुड़ेदान की स्थिति	5.5.2.2	**167**
5.9	वर्ष 2017–22 के दौरान विभिन्न सामुदायिक स्थानों पर स्थापित सामुदायिक कूड़ेदानों की स्थिति	5.5.2.7	**169**
5.10	बिना पंजीकरण, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन	5.5.6.2	**171**
5.11	जी.पी.एस. के माध्यम से अपशिष्ट के परिवहन में लगे वाहनों की निगरानी न होना	5.5.6.5	**172**
5.12	ईंधन लागत के भुगतान पर किया गया अधिक व्यय	5.5.6.6	**173**
5.13	विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण केंद्रों की आवश्यकता	5.6.1.1	**176**
5.14	कम्पोस्टर्स का सब–ऑप्टिमल उपयोग	5.6.1.2	**179**

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ सं.
5.15	गया नगर निगम में केंद्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र से संबंधित कार्य–वार विवरण	5.6.1.3	**181**
5.16	गया नगर निगम में ताजे मिश्रित अपशिष्ट के प्रसंस्करण के बिलों में दर्शाया गया वाहनों का अधिक फेरा	5.6.1.3 (iv)	**183**
5.17	शहरी स्थानीय निकायों में डंपिंग स्थलों की स्थिति	5.6.3.2	**184**
5.18	क्रय के बाद से अप्रयुक्त रखे गए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपकरण	5.7.5	**186**
5.19	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वीकृत बल और कार्यरत बल की स्थिति	5.10.3	**187**
	संक्षिप्तियों की शब्दावली		**189**

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में, पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों तथा संबंधित विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2021–22 के दौरान नमूना–लेखापरीक्षा के क्रम में पाये गये मामलों के साथ–साथ वैसे मामले भी उल्लेखित हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाए गए, परंतु पूर्व के प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। 2021–22 के अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामलों को, जहाँ आवश्यक हो, अद्यतन स्थिति देते हुए शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा अवलोकन सीमित नमूना जांच पर आधारित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरुप लेखापरीक्षा संपादित की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में पाँच अध्याय हैं। पहले और तीसरे अध्याय में क्रमशः पंचायती राज संस्थानों (पं.रा.सं.) एवं शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) के कार्यकलापों, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित मुद्दों का विवरण शामिल है। दूसरे और चौथे अध्याय में क्रमशः पं.रा.सं. एवं श.स्था.नि. के अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित टिप्पणियाँ शामिल हैं। पाँचवें अध्याय में ''बिहार के शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष शामिल हैं। इस विहंगावलोकन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत किया गया है।

अनुपालन लेखापरीक्षा–पंचायती राज संस्थाएं

ग्राम पंचायत, बुधुआ, वित्त आयोगों के अनुदानों से वित्तपोषित किए जाने वाले कार्यों की निगरानी करने में विफल रहा और ₹ 12.50 लाख का भुगतान अभिकर्त्ता को उन कार्यों के लिए किया जो कार्यान्वित नहीं किए गये थे।

(कंडिका 2.1)

अनुपालन लेखापरीक्षा–शहरी स्थानीय निकाय

कर्मचारी भविष्य निधि में वैधानिक अंशदान का ससमय प्रेषण सुनिश्चित करने में नगर परिषद्, सहरसा की विफलता के फलस्वरूप क्षति के लिए दंड शुल्क और ब्याज के रूप में ₹ 1.14 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 4.1)

सौर ऊर्जा संयंत्रों (रूफ टॉप) की आपूर्ति के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लेने वाली एक निजी फर्म को भुगतान करते समय जाँच करने में नगर परिषद्, शेखपुरा की विफलता के कारण ₹ 91.14 लाख का फर्जी भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त, तकनीकी बोली में एक पात्र फर्म की अनियमित अयोग्यता के कारण नगर परिषद् को ₹ 1.37 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 4.2)

"बिहार के शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा

'ठोस अपशिष्ट' में ठोस या अर्ध–ठोस घरेलू अपशिष्ट, सेनेटरी अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, केटरिंग एवं बाजार अपशिष्ट और अन्य गैर–आवासीय अपशिष्ट, सड़क की सफाई आदि शामिल हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस.डब्ल्यू.एम.) नियम, 2016, शहरी स्थानीय निकायों को यह शक्तियां प्रदान करती है कि वे अन्य बातों के साथ–साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करने; सभी घरों, वाणिज्यिक और अन्य गैर–आवासीय परिसरों से उत्पन्न और पृथक किए गए ठोस कचरे के घर–घर संग्रहण की व्यवस्था करने; अपशिष्ट उत्पादकों से उपभोक्ता शुल्क निर्धारित करने और संग्रह करने; पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों की छंटाई के लिए सामग्री रिकवरी सुविधाएं स्थापित करने; और ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं, जैसे कम्पोस्टिंग एवं स्वास्थ्यकर भूमि–भरण आदि के निर्माण, संचालन और रखरखाव की सुविधा प्रदान करने से संबंधित कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण कर सकती हैं (अप्रैल 2016)।

वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–2022 के लिए 'बिहार के श.स्था.नि. में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा (पी.ए.) यह आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी कि क्या नगरीय ठोस अपशिष्ट (एम.एस.डब्ल्यू.) का प्रबंधन प्रभावी और कुशल था और

आर्थिक और वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। लेखापरीक्षा पद्धति में नमूना के तौर पर लिए गए 28 श.स्था.नि. के अभिलेखों की जांच; शहरी विकास एवं आवास विभाग (यू.डी. एंड एच.डी.) और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बी.एस.पी.सी.बी.) से सूचना/डेटा का संग्रहण; लैंडफिल सहित विभिन्न स्थलों पर अपशिष्टों के प्रबंधन का संयुक्त भौतिक सत्यापन; और 1,408 घरों/दुकानदारों का सर्वेक्षण शामिल था।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आठ सेवा स्तर मानक संकेतक हैं। मार्च 2022 तक, इन सेवा स्तर मानकों के सभी आठ मापदंडों को किसी भी नमूना जांचित श.स्था.नि. (दरभंगा नगर निगम को छोड़कर) द्वारा हासिल नहीं किया गया था। मानकों की उपलब्धियों की यथार्थता, जैसा कि नमूना जांचित श.स्था.नि. द्वारा शहरी विकास एवं आवास विभाग और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रतिवेदित की गई थी, सत्यापन योग्य नहीं थी, क्योंकि श.स्था.नि. ने इन मानकों की उपलब्धि के समर्थन में दस्तावेज संधारित नहीं किए थे। हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा सुनिश्चित की गई वास्तविक स्थिति, प्रतिवेदित स्थिति से निम्न पाई गई।

एस.डब्ल्यू.एम. के लिए मानकों की कम प्राप्ति मुख्य रूप से त्रुटिपूर्ण योजना; एस.डब्ल्यू. एम. के नियमों और बिहार सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और रणनीतियों का अनुपालन न करना; मानवबल की कमी आदि के कारण थी।

अनुशंसा

शहरी विकास एवं आवास विभाग, प्रभावी निगरानी द्वारा, एसडब्ल्यूएम नियमों और एसडब्ल्यूएम के लिए बनाई गई नीति और रणनीति के पालन; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्याप्त और वस्तुनिष्ठ रूप से सत्यापन योग्य दस्तावेजों के रखरखाव एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बेंचमार्क की उपलब्धि सुनिश्चित कर सकता है।

(कंडिका 5.2)

नमूना जांचित 28 श.स्था.नि. में से तेरह के पास एस.डब्ल्यू.एम. के लिए कोई योजना नहीं थी। शेष 15 श.स्था.नि. के पास योजना के रूप में एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन था, जिसमें केवल वर्ष 2018 के लिए बुनियादी ढाँचे/निधि की आवश्यकताओं की गणना की गई थी (पटना नगर निगम और गया नगर निगम के मामले को छोड़कर, जहां आवश्यकताओं की गणना क्रमशः वर्ष 2023 और 2015 से 2032 तक के लिए की गई थी)। योजना के अभाव में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया गया व्यय, आवश्यकता–आधारित विश्लेषण के आधार पर न होकर निधियों की उपलब्धता से प्रेरित था और जोखिम भरा था।

अपर्याप्त योजना का प्रमाण, ₹ 19.41 करोड़ की लागत वाले डस्टबिनों के क्रय, जिन्हें स्रोत पर पृथक्करण और कचरे के प्रसंस्करण को सुनिश्चित किए बिना ही घरों में वितरित किए गए थे; ₹ 13.65 करोड़ की लागत से आवश्यकता से अधिक 213 ऑटो टिपर का क्रय; ₹ 3.11 करोड़ में वैसे वाहनों का क्रय, जो स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं थे और आठ से 62 महीनों तक अनुपयोगी पड़े हुए थे; ₹ 5.24 करोड़ में एस.डब्ल्यू. एम. उपकरण का क्रय, जो अप्रयुक्त रह गए; उठाने वाले आवश्यक उपकरणों के बिना, ₹ 1.97 करोड़ में 1,100 लीटर कूड़ेदान का क्रय; और आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां) गतिविधियों पर ₹ 4.23 करोड़ के अनियोजित व्यय आदि से मिला।

अनुशंसा

विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सभी श.स्था.नि. नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एमएसडब्ल्यूएम) हस्तक में उल्लिखित तरीके से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए योजना का निर्माण करें। विभाग अपशिष्टों के प्रसंस्करण और निपटान के संबंध में उपयुक्त प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के चयन के लिए एक प्रभावी एमएसडब्ल्यूएम योजना की तैयारी सुनिश्चित कर सकता है, जिसमें अपशिष्ट की वर्तमान और भविष्य की गुणवत्ता

और मात्रा, भविष्य के अनुमान और अंतराल की पहचान और विश्लेषण शामिल हो। बजट निर्माण के समय, श.स्था.नि. यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि निर्धारित तंत्र/संस्थानों के माध्यम से और निर्धारित समय–सीमा के अनुरुप नागरिकों के इनपुट प्राप्त किए जाएं।

(कंडिका 5.4)

नमूना जांच किए गए श.स्था.नि. में से किसी ने भी आधारभूत अध्ययन/सर्वेक्षण और वार्ड मैपिंग नहीं किया था, जो पृथक्कृत अपशिष्ट के डोर–टू–डोर संग्रहण के लिए पूर्व–आवश्यकताएं थी। इसके अलावा, स्रोत पृथक्करण के प्रति श.स्था.नि. का उदासीन दृष्टिकोण, एकल कूड़ेदानों का क्रय/वितरण, जोड़ा में कूड़ेदानों वितरण नहीं होना और नगरपालिका भंडारो में उनके पड़े रहने से भी स्पष्ट था।

नमूना जांच किए गए श.स्था.नि. में केवल 24 प्रतिशत घरों ने स्रोत पृथक्करण किया था। मिश्रित अपशिष्ट लैंडफिल में डाला जा रहा था। वाणिज्यिक स्थानों, सामुदायिक कूड़ेदानों और सड़क की सफाई से एकत्र किए गए अपशिष्ट का भी पृथक्करण नहीं किया जा रहा था और इसे बिना ढके वाहनों में लैंडफिल/डंपिंग साइटों पर ले जाया जा रहा था।

नमूना के तौर पर लिए गए श.स्था.नि. ने एसडब्ल्यूएम गतिविधियों के लिए उपयोग किए जा रहे 2,067 वाहनों की एक सूची प्रस्तुत की। लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी वाहनों के पास वैध पंजीकरण संख्या, बीमा और 'प्रदूषण नियंत्रण' प्रमाणपत्र नहीं थे। कचरा संग्रहण और प्रबंधन के प्रयोजन से सड़कों पर ऐसे वाहनों को चलाना प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन है।

अनुशंसा

पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और प्रसंस्करण की सुविधा के लिए, श.स्था.नि. या तो निवारक उपायों को विकसित करने या पृथक्करण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, स्रोत पर कचरे का पृथक्करण, घर–घर जाकर पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण एवं पृथक्करण को सख्ती से सुनिश्चित कर सकते हैं। शहरी स्थानीय निकायों कों बिना ढके अपशिष्ट के परिवहन से बचना चाहिए। श.स्था.नि. पंजीकरण, बीमा और 'प्रदूषण नियंत्रण' प्रमाणपत्र के बिना वाहनों का उपयोग करने से भी बच सकते हैं। पृथ्क्कृत अपशिष्ट के संग्रहण के लिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्राथमिक संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को कंटेनरीकृत या विभाजित किया गया है, पृथ्क्कृत अपशिष्ट के भंडारण को सुगम बनाने हेतु, गीले और सूखे अपशिष्टों के लिए अलग–अलग बैग/टोकरी ले जाया जाए।

(कंडिका 5.5)

कचरे का प्रसंस्करण 18 शहरी स्थानीय निकायों में नहीं किया जा रहा था। सात शहरी स्थानीय निकायों में, अपशिष्ट प्रसंस्करण की सीमा केवल 14 प्रतिशत तक थी, जबकि, तीन शहरी स्थानीय निकायों में, संबंधित अभिलेखों के अभाव में अपशिष्ट प्रसंस्करण की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकी।

गया नगर निगम में अपशिष्ट के केंद्रीकृत प्रसंस्करण में गंभीर अनियमितताएं देखी गईं। जिनमें, (i) संसाधित कचरे की मात्रा के प्रसंस्करण/सत्यापन के बिना, एजेंसी को ₹ 11.54 करोड़ का भुगतान और (ii) अनुश्रवण की कमी; एजेंसी द्वारा वाहन फेरों की वास्तविक संख्या से अधिक संख्या के लिए फर्जी दावा; वाहनों के अवास्तविक प्रवेश और निकास समय और गैर–मौजूद/ऑफ–रोड वाहनों द्वारा कचरे का परिवहन के लिए ₹ 17.02 लाख का अतिरिक्त भुगतान शामिल थे।

किसी भी चयनित शहरी स्थानीय निकाय में अधिकृत सेनेटरी लैंडफिल साइट उपलब्ध नहीं था। इसलिए, शहरी स्थानीय निकायों ने अपनी सुविधा के अनुसार लैंडफिल/डंपिंग साइटों को चुना था। अपशिष्ट निपटान के संबंध में एसडब्ल्यूएम नियमों का पालन न

करने के गंभीर मामले थे। माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिरण के 1 नवंबर 2019 से पुराने कचरे का निपटान प्रारंभ करने के आदेश के बाद भी 28 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल चार ने पुराने कचरे का निपटान प्रारंभ किया था।

अनुशंसा

यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यूनतम कचरा लैंडफिल तक पहुंचे, शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्रों के संचालन में तेजी ला सकते हैं। राज्य सरकार पुराने खुले डंपसाइटों के गैर–जैव–उपचार के संबंध में जिम्मेदारी तय कर सकती है, जो कि निर्धारित समय–सीमा के भीतर और मौजूदा परिचालन डंपसाइटों में जैव–खनन और जैव–उपचार की उनकी क्षमता के लिए आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार लैंडफिल प्रबंधन और अपशिष्ट निपटान के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन न करने के मामलों में जिम्मेदारी तय कर सकती है।

(कंडिका 5.6)

नमूना जांच किए गए 28 शहरी स्थानीय निकायों में से 27 ने ई–कचरे के संग्रहण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी और नमूना जांच किए गए 22 शहरी स्थानीय निकायों ने घरेलू जैव–चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण के लिए कोई अनुबंध नहीं किया था। परिणामस्वरूप, आठ श.स्था.नि. में प्रयुक्त सिरिंज और सुइयों को ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित पाए जाने के मामले देखे गए।

नमूना जांच किए गए किसी भी श.स्था.नि. में प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण/चैनलिंग नहीं किया जा रहा था। सम्पूर्ण प्लास्टिक अपशिष्ट को बिना किसी पृथक्करण और उपचार के, डंपिंग साइट पर डंप किया गया था। आगे, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ₹ 5.12 करोड़ के आवंटन के बावजूद, पटना नगर निगम प्लास्टिक अपशिष्ट श्रेडिंग इकाई स्थापित करने में विफल रहा, जिसके कारण, सड़क निर्माण में कटे हुए श्रेडेड प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग नहीं हो सका।

अनुशंसा

राज्य सरकार स्रोत पर अन्य नगरीय अपशिष्ट से जैव–चिकित्सा अपशिष्ट का पृथक्करण न करने और संग्रहण और भंडारण केन्द्रों पर अपशिष्ट के अनुचित प्रबंधन के संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित और तय कर सकती है। शहरी स्थानीय निकाय ई–अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित कर सकते हैं, ताकि वे नगरीय अपशिष्ट के साथ मिश्रित न हों और स्वास्थ्य जोखिम को टाला जा सके। स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। शहरी स्थानीय निकाय अभिलेख संधारित कर सकते हैं, जिसमें उन स्रोतों का विवरण दिया गया हो जहां से संनिर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, उनके श्रोत, उनकी मात्रा और उनके निपटान स्थल का विवरण दिया गया हो।

(कंडिका 5.9)

विभिन्न संस्थानों यथा जिला स्तरीय समीक्षा एवं अनुश्रवण समितियां, वार्ड स्तरीय समितियां एवं विषय समितियां की गैर–मौजूदगी के साथ–साथ सशक्त स्थायी समितियों की बैठकों में कमियों से अनुश्रवण की कमी स्पष्ट थी। नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों ने नगरीय ठोस अपशिष्टों से होने वाले जोखिम का आकलन नहीं किया था और प्रदूषण स्तर (वायु और पानी की गुणवत्ता) का भी अनुश्रवण नहीं कर रहे थे, हालांकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में इसकी परिकल्पना की गई थी।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समर्पित कर्मचारियों की कमी 90 से 100 प्रतिशत तक थी। नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों ने अपने कर्मचारियों और कचरा बीनने वालों के लिए कोई क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया था। आगे, नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी कचरा बीनने वालों को पंजीकृत

नहीं किया था (दरभंगा और दानापुर को छोड़कर) और केवल दो शहरी स्थानीय निकायों (दानापुर और दलसिंहसराय नगर परिषद्) ने पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं की वसूली के लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को नियुक्त किया था।

अनुशंसा

शहरी स्थानीय निकाय अनुश्रवण समितियों को सक्रिय कर सकते हैं और अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को भी मजबूत कर सकते हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डिजाईनिंग, निपटान, उपचार और प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए पर्यावरणीय आवश्यकताओं का अनुश्रवण न करने के संबंध में जिम्मेदारी तय कर सकता है। विभाग शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए स्वच्छता निरीक्षक/मुख्य स्वच्छता निरीक्षक/सफाई जमादार, सहायक लोक स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी/लोक स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी और लिपिक के पदों को भरने के लिए प्रभावी उपाय कर सकता है।

(कंडिका 5.10)

अन्य महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों में, निधि आधारित लेखांकन की अनुपस्थिति; ₹ 17.07 करोड़ के उपभोक्ता शुल्क की कम वसूली; अपशिष्ट प्रसंस्करण के अभाव में, अपशिष्ट स्टैकिंग के लिए अर्थ मूवर मशीनों को किराए पर लेने पर, पटना नगर निगम द्वारा ₹ 10.29 करोड़ का परिहार्य व्यय; समान उद्देश्यों के लिए विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई निःशुल्क राज्य सेवा की उपलब्धता के बावजूद, क्लाउड सर्वर पर ₹ 1.25 करोड़ का व्यय; वाहनों के पंजीकरण में विलम्ब के कारण ₹ 70.89 लाख का परिहार्य व्यय; पटना और गया नगर निगम द्वारा अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक दर पर भुगतान के कारण ₹ 56.62 लाख का अतिरिक्त भुगतान; और पटना एवं गया नगर निगम द्वारा राज्य सरकार (बी.एस.डब्ल्यू.ए.एन.) नेटवर्क की उपलब्धता के बावजूद एक निजी वेन्डर को नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए ₹ 23.16 लाख का परिहार्य भुगतान, सम्मिलित हैं।

पंचायती राज संस्थान

अध्याय-I

पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकलापों, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित विषयों की रुपरेखा

अध्याय - I
पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकलापों, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित विषयों की रुपरेखा

1.1 परिचय

तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम (73वें सी.ए.ए.), 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया व इनके संबंध में निम्नलिखित स्थापित किए: (i) एकसमान त्रि–स्तरीय संरचना (ii) निर्वाचन तंत्र (iii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण (iv) पंचायती राज संस्थाओं को राशि प्रतिनिधायन हेतु व्यवस्था तथा (v) पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिनिधायित किए जाने वाले कार्य। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, राज्यों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को ऐसी शक्तियों, कार्यों व दायित्वों को सौंपना था जो उन्हें स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाती हों। पंचायती राज संस्थाओं का उद्देश्य (क) जन भागीदारी तथा (ख) भारत के संविधान की ग्याहरवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29[1] विषयों से संबंधित योजनाओं सहित आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय हेतु ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना है।

बिहार सरकार ने बिहार पंचायत राज अधिनियम (बी.पी.आर.ए.), 1993 अधिनियमित किया (तत्पश्चात्, समय–समय पर यथासंशोधित बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के द्वारा प्रतिस्थापित) तथा पं.रा.सं. की त्रि–स्तरीय प्रणाली यथा: ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति (पं.स.) एवं जिला स्तर पर जिला परिषद् (जि.प.) का गठन किया गया। जमीनी स्तर पर प्रभावी विकेन्द्रीकरण के लिए, ग्राम पंचायत को वार्डों में विभाजित किया गया तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा[2] व वार्ड स्तर पर वार्ड सभा[3] के प्रावधान किए गए।

आर्थिक सर्वेक्षण, 2022–23, बिहार सरकार के अनुसार, राज्य में 8,629 पं.रा.सं.[4] थे जिनमें 2,47,426 निर्वाचित प्रतिनिधि[5] थे। महिलाओं को पं.रा.सं. के निर्वाचित निकायों की कुल सीटों में से पचास प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया था। राज्य में पं.रा.सं. के निर्वाचित निकायों के लिए पिछला आम चुनाव सितंबर–दिसंबर 2021 के दौरान हुआ था।

---

[1] *कृषि, कृषि विस्तार सहित; भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी एवं मृदा संरक्षण; लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं वाटरशेड विकास; पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन; मछली पालन; सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी; लघु वन उपज; खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित लघु उद्योग; खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग; ग्रामीण आवास; पेय जल; ईंधन एवं चारा; सड़क, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग एवं संचार के अन्य साधन; बिजली के वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण; गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोत; गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम; प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा; तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा; वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा; पुस्तकालय; सांस्कृतिक गतिविधियाँ; बाजार एवं मेला; अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं औषधालय सहित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता; परिवार कल्याण; महिला एवं बाल विकास; विकलांगों एवं मानसिक रूप से मंद लोगों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण; कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का कल्याण; सार्वजनिक वितरण प्रणाली; सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव।*

[2] *ग्राम सभा का आशय एक निकाय से है जिसमें मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, जो ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित गांव से संबंधित होते हैं।*

[3] *वार्ड की मतदाता सूची के अंतर्गत पंजीकृत सभी व्यक्ति संबंधित वार्ड सभा के सदस्य होंगे।*

[4] *38 जिला परिषद, 533 पंचायत समिति एवं 8,058 ग्राम पंचायत*

[5] *मुखिया: 8,058; ग्राम पंचायत सदस्य: 1,09,528; पंचायत समिति के सदस्य: 11,094; जिला परिषद् के सदस्य: 1,160; पंच: 1,09,528 एवं सरपंच: 8,058*

1.1.1 राज्य की रूपरेखा

बिहार 94,163 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल (कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.86 प्रतिशत) के साथ देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। विगत दशक (2001–2011) में बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर 25.4 प्रतिशत थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल 10.41 करोड़ जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या 8.77 करोड़ (84 प्रतिशत) थी। राज्य के जनसांख्यिकीय व विकासात्मक आँकड़े **तालिका 1.1** में दिए गए हैं:

तालिका 1.1
राज्य के महत्वपूर्ण आँकड़े

सूचक	इकाई	राज्य के आँकड़े
जनसंख्या	करोड़	10.41
जनसंख्या घनत्व	प्रति वर्ग कि.मी.	1,106
ग्रामीण जनसंख्या	करोड़	8.77
लिंगानुपात	प्रति 1000 पुरूष पर महिलाएं	918
साक्षरता	प्रतिशत	61.80
जिलों की संख्या	संख्या	38
पं.रा.सं. की संख्या	संख्या	8,629
दशकीय वृद्धि दर	प्रतिशत	25.42
ग्रामीण लिंगानुपात	प्रति 1000 पुरूष पर महिलाएं	921

(***स्रोतः*** *जनगणना 2011 एवं आर्थिक सर्वेक्षण, 2022–23, बिहार सरकार)*

1.2 पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा

राज्य स्तर पर, पं.रा.सं. के कार्यों का समन्वय एवं अनुश्रवण पंचायती राज विभाग (पी.आर.डी.) करता है। जि.प. की अध्यक्षता, अध्यक्ष के द्वारा जबकि पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत की अध्यक्षता क्रमशः प्रमुख एवं मुखिया के द्वारा किया जाता है जो संबंधित पं.रा.सं. के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। मुखिया ग्राम पंचायत के वित्तीय एवं कार्यकारी प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी या अपर जिला पदाधिकारी के स्तर का) एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–कार्यपालक पदाधिकारी क्रमशः जिला परिषद् तथा पंचायत समिति के कार्यकारी प्रधान होते हैं। आगे, जून 2022 से जिला पंचायत राज पदाधिकारी जिला परिषद् के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, जबकि, उन प्रखंडों में जहाँ प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पदस्थापित हैं, वे पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की भूमिका व दायित्व का निर्वहन करते हैं। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत कार्यालय के प्रभारी होते हैं एवं ग्राम पंचायत स्तर पर लेखाओं व अन्य अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी होते हैं।

1.3 पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली

1.3.1 पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां एवं कार्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जी एवं 243 एच में प्रावधान है कि किसी राज्य की विधायिका, कानून द्वारा, पं.रा.सं. को स्व–शासित संस्था के रूप में कार्य करने योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्वों को पं.रा.सं. को प्रदान कर सकती है :

- संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट विषयों के साथ–साथ आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ, जो उन्हें सौंपा जाए, को तैयार करना एवं उनका कार्यान्वयन करना; तथा

- करारोपण की शक्तियाँ एवं पंचायतों के सभी राशियों को जमा करने हेतु निधियों का गठन।

इसके अतिरिक्त, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 22, 47 एवं 73 क्रमशः ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों की शक्तियों तथा कर्तव्यों की प्रकृति का वर्णन करते हैं।

1.3.2 राज्य सरकार की शक्तियां

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006, राज्य सरकार को, पंचायती राज संस्थाओं के समुचित कार्यकलापों के अनुश्रवण के लिए सक्षम बनाने हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान करता है। पं.रासं. के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियों एवं भूमिकाओं का एक सार नीचे **तालिका 1.2** में दिया गया है:

तालिका 1.2
राज्य सरकार की शक्तियां

प्राधिकार	राज्य सरकार की शक्तियां
धारा 11	सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, जिला पदाधिकारी, जिला राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी स्थानीय क्षेत्र, जिसमें एक गांव या सन्निहित गांवों का एक समूह या उसका हिस्सा शामिल है, को ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकता है, जिसकी जनसंख्या इसकी सीमा के भीतर लगभग सात हजार हो।
धारा 146	**नियम बनाने की शक्ति** : राज्य सरकार, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में विर्निदिष्ट कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य विधायिका के अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।
धारा 150, 152 एवं 153	**मानक नियमावली बनाने, पृच्छा एवं निरीक्षण की शक्ति** : राज्य सरकार, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मानक नियम बना सकती है तथा यह पं.रा.सं. के नियंत्रणाधीन किसी भी कार्यालय या अभिलेखों के निरीक्षण की शक्ति रखती है।
धारा 167	**जिला योजना समिति** : राज्य सरकार प्रत्येक जिला में, जिला के अंतर्गत पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने तथा संपूर्ण जिले के लिए एक प्रारूप विकास योजना को तैयार करने हेतु एक जिला योजना समिति का गठन करेगी।
धारा 168	**पंचायतों के लिए वित्त आयोग**: राज्य सरकार प्रत्येक पाँच वर्षों में, पं.रा.सं. की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, निधियों के प्रतिनिधायन तथा उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार के उपाय हेतु सुझाव देने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगी।
धारा 27, 55 एवं 82	**कराधान**: पं.रा.सं., राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकतम दर के अधीन होल्डिंग व पेशाओं पर करारोपण तथा टोल, शुल्क एवं दर अध्यारोपित कर सकती है।
धारा 172	**कठिनाईयों का निराकरण**: यदि अधिनियम के उपबंधों को प्रभाव में लाने में कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, आदेश निर्गत कर, कठिनाईयों के निराकरण हेतु, जो आवश्यक है, कर सकती है।
धारा 18(5), 44(4) एवं 70(5)	**पद से निष्कासन**: बैठकों में अनुपस्थित रहने, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन न करने, अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करने या दोषी घोषित किए जाने व छः माह से ज्यादा समय के लिए फरार होने के आधार पर, उनको अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, राज्य सरकार मुखिया/उप–मुखिया, प्रमुख/उप–प्रमुख व अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को उनके पद से पदच्युत कर सकती है।

*(**स्रोत**: बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006)*

1.3.3 पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों, निधियों तथा कर्मियों का प्रतिनिधायन

तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम में यह परिकल्पना की गई है कि संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 विषयों को, निधियों एवं कर्मियों के साथ, राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त विधि निर्माण कर पं.रा.सं. को हस्तांतरित किया जाएगा।

(i) कार्यों का प्रतिनिधायन

बिहार सरकार के विभागों/विंगों[6] ने (सितंबर, 2001) संविधान की ग्याहरवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों/कार्यों के संदर्भ में अपने संबंधित कार्य पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया तथा इन कार्यों/उप–कार्यों का स्तर–वार गतिविधि मानचित्रण (एक्टिविटी मैपिंग) तैयार किया। पं.रा.सं. को समय–समय पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा 621 प्रकार के उत्तरदायित्व सौंपे गये थे। हालांकि, बिहार के मुख्य सचिव ने पाया कि पं.रा.सं. के तीनों स्तरों द्वारा किए जाने वाले कार्यों व दायित्वों के प्रतिनिधायन के संबंध में विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं, पं.रा.सं. द्वारा अपनाए जाने के लिए स्पष्ट एवं व्यवहारिक नहीं थे व पं.रा.सं. को शक्तियों के प्रभावी प्रतिनिधायन के लिए संबंधित विभागों को स्पष्ट कार्य संबंधी दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश (जुलाई 2014 एवं अप्रैल 2019) दिया। हालांकि, मई 2022 तक इस संबंध में कोई प्रगति नहीं देखी गई। आगे, यह पाया गया कि संबंधित कार्यात्मक विभागों को पं.रा.सं. को प्रतिनिधायित हुए कार्यों को पूरा करने के लिए बजटीय आवंटन प्राप्त होते रहे। इस प्रकार, पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए कार्यों में राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों का ओवरलैप था। षष्ठम राज्य वित्त आयोग ने भी यह पाया कि: (i) पं.रा.सं. द्वारा केवल कुछ ही कार्य किए जा रहे थे तथा (ii) अधिकांश कार्यों का गतिविधि मानचित्रण (एक्टिविटी मैपिंग) कागज पर ही था तथा उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस प्रकार, राज्य सरकार के संबंधित विभागों ने प्रतिनिधायन हुए अधिकांश कार्यों के संबंध में पं.रा.सं. को परिचालन नियंत्रण हस्तांतरित नहीं किया था।

(ii) निधियों का प्रतिनिधायन

73वें संविधान संशोधन अधिनियम का मूल उद्देश्य कार्यात्मक एवं वित्तीय प्रतिनिधायन के माध्यम से स्थानीय निकायों (स्था.नि.) को सशक्त बनाना था ताकि वे स्वशासन की जीवंत इकाईयों के रूप में कार्य कर सकें। तद्नुसार, पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों के निष्पादनार्थ पंचायती राज विभाग के माध्यम से केन्द्र/राज्य सरकार, राज्य योजना शीर्ष इत्यादि से अनुदान/प्रतिनिधायन के रूप में निधियां प्राप्त हो रहीं थीं। वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को जारी की गई निधियां **तालिका 1.3** में दी गई हैं:

तालिका 1.3

विभिन्न स्तरों पर पं.रा.सं. को अनुदान (वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22)

(₹ करोड़ में)

मद	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद्
राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	138.00	0	0
केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान	19,616.8	1,595.6	1,076.6
राज्य वित्त आयोग अनुदान	7,054.1	1,033.1	574.2
पंचायत सरकार भवन का निर्माण	555.7	-	-
आकस्मिक अनुदान	95.0	-	-
पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों/कर्मियों को भुगतान व भत्ता	608.2	121.2	23.9
कुल	**28,067.80**	**2,749.9**	**1,674.70**

*(**स्रोत**: वर्ष 2022–23 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार सरकार)*

[6] *कृषि; राजस्व एवं भूमि सुधार; जल संसाधन (लघु सिंचाई); पशुपालन एवं मत्स्य पालन; पर्यावरण एवं वन; उद्योग; लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग; ग्रामीण विकास; ग्रामीण अभियंत्रण; ऊर्जा; प्राथमिक शिक्षा; वयस्क शिक्षा; साक्षरता; सांस्कृतिक गतिविधियां; चिकित्सा; परिवार कल्याण; समाज कल्याण; विकलांगों का कल्याण; सार्वजनिक वितरण प्रणाली; राहत और पुनर्वास।*

इसके अतिरिक्त, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 27, 55 एवं 82 के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं को होल्डिंग, व्यवसायों पर कर लगाने एवं राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम दरों के अधीन टोल, शुल्क एवं दरें लगाने के लिए अधिकृत किया गया था। राज्य वित्त आयोगों ने यह भी अनुशंसा की थी कि राज्य सरकार करों की अधिकतम दरों को निर्दिष्ट करे ताकि पं.रा.सं. प्राथमिकता के आधार पर संसाधन जुटा सकें। हालांकि, जिन दरों पर कर/गैर–कर राजस्व एकत्र किये जाने थे, वे बिहार सरकार द्वारा निर्दिष्ट नहीं किए गए थे। इन दरों के अभाव में पं.रा.सं. अपने स्वयं के संसाधनों से राजस्व लगाने एवं एकत्र करने में सक्षम नहीं थे (अगस्त 2021 तक)।

इस ओर ध्यान आकृष्ट कराए जाने पर विभाग ने बताया (अगस्त 2021) कि बिहार पंचायत (ग्राम पंचायत, लेखापरीक्षा, बजट एवं कराधान) नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने इस संबंध में पाया कि उपर्युक्त नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया 10 वर्षों से अधिक समय से चल रही थी। विभाग द्वारा अद्यतन स्थिति उपलब्ध नहीं कराई गई (अप्रैल 2023)।

(iii) कर्मियों का प्रतिनिधायन

ग्राम पंचायत स्तर पर, पंचायत सचिव एकमात्र पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी थे जो ग्राम पंचायत को अपने अधिदेशित कार्यों को करने में सुविधा प्रदान करने के लिए उपलब्ध थे। हालांकि, यह पाया गया कि : (i) अगस्त 2021 तक, पंचायत सचिवों के 6,055 पद (8,419 की स्वीकृत संख्या का 71.92 प्रतिशत) रिक्त थे (ii) प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (बी.पी.आर.ओ.) को पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में काम करने के लिए प्रखंड में नियुक्त किया गया था तथा (iii) प्रखंड के कर्मी पंचायत समितियों से संबंधित कार्य भी कर रहे थे। जून 2022 तक, राज्य के 534 प्रखंडो में 308 बी.पी.आर. ओ. कार्य कर रहे थे। जिला परिषदों के स्वीकृत बल व कार्यरत बल की स्थिति विभाग स्तर पर उपलब्ध नहीं थी।

इस प्रकार, पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त कर्मी उपलब्ध नहीं कराया गया था और वे कम मानवबल के साथ कार्य करने को विवश थे। षष्ठम राज्य वित्त आयोग ने पाया था कि विभागों ने यद्यपि कार्यों के प्रतिनिधायन के संबंध में गतिविधि मानचित्रण (एक्टिविटी मैपिंग) के आदेश जारी किए थे, परन्तु उन्होनें इन गतिविधियों को संभालने वाले कर्मियों की सेवाओं (आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं व शिक्षकों पर सीमित प्रशासनिक नियंत्रण को छोड़कर) को पं.रा.सं. को स्थानांतरित नहीं किया था।

इस प्रकार, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में परिकल्पित पं.रा.सं. को कार्यों, निधियों व कर्मियों का प्रतिनिधायन संतोषप्रद नहीं था।

1.4 विभिन्न समितियों का गठन

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में यह प्रावधान है कि अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए पंचायती राज संस्थाएं अपने सदस्यों के बीच निर्वाचन द्वारा विभिन्न समितियों का गठन करेंगी।

1.4.1 स्थायी समिति

बिहार पचांयत राज अधिनियम, 2006 की धारा 25, 50 एव 77 के अनुसार पं.रा.सं. सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए विभिन्न स्थायी समितियों का गठन करेंगी। त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में गठित की जाने वाली स्थायी समितियां तथा इन समितियों के कार्य **तालिका 1.4** में दिए गए हैं:

तालिका 1.4
पंचायती राज संस्थाओं में स्थायी समितियां

समितियां	ग्रा.पं.	पं.स.	जि.प.	कार्य
सामान्य स्थायी समिति	नहीं	हाँ	हाँ	सामान्य कार्य, अन्य समितियों के कार्यों का समन्वय व सभी शेष कार्य जो अन्य समितियों के प्रभार के अधीन नहीं हैं।
योजना, समन्वय एवं वित्त समिति	हाँ	नहीं	नहीं	ग्राम पंचायतों से संबंधित सामान्य कार्य, अन्य समितियों के कार्यों का समन्वय व सभी शेष कार्य जो अन्य समितियों के प्रभार के अधीन नहीं हैं।
वित्त, अंकेक्षण व योजना समिति	नहीं	हाँ	हाँ	वित्त, अंकेक्षण एवं बजट तथा योजना से संबंधित कार्य।
उत्पादन समिति	हाँ	हाँ	हाँ	कृषि; भूमि सुधार; लघु सिंचाई तथा जल प्रबंधन; पशुपालन; डेयरी, कुक्कुट पालन व मत्स्य पालन; वानिकी से संबंधित क्षेत्र; खादी, ग्राम व कुटीर उद्योग; तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित कार्य।
सामाजिक न्याय समिति	हाँ	हाँ	हाँ	शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक संवर्धन तथा बाल एवं महिला कल्याण के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण से संबंधित कार्य।
शिक्षा समिति	हाँ	हाँ	हाँ	प्राथमिक, माध्यमिक व जनशिक्षा सहित शिक्षा, पुस्तकालयों तथा सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित कार्य।
लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति	हाँ	हाँ	हाँ	सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण व ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित कार्य।
लोक कार्य समिति	हाँ	हाँ	हाँ	ग्रामीण आवास, जलापूर्ति के स्रोतों, सड़कों व आवागमन के अन्य माध्यमों, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं संबंधित कार्यों सहित सभी प्रकार के निर्माण व रखरखाव से संबंधित कार्य।

*(**स्रोतः** बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 25, 50 एवं 77)*

विभाग इस तथ्य से अनभिज्ञ था कि कितने पं.रा.सं. ने उपर्युक्त स्थायी समितियों का गठन किया था व कितनी समितियां वास्तव में कार्य कर रही थीं।

1.5 लेखापरीक्षा व्यवस्था

1.5.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक

ग्यारहवीं वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) को पंचायतों के सभी श्रेणियों/स्तरों के लेखाओं के समुचित रखरखाव एवं लेखापरीक्षा पर नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए। तेरहवीं एवं चौदहवीं वित्त आयोग ने भी अनुशंसा की थी कि सी.ए.जी. को प्रत्येक श्रेणी/वर्ग के सभी स्थानीय निकायों (स्था.नि.) की लेखापरीक्षा के लिए तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग (टी.जी.एस.) सौंपा जाना चाहिए एवं उनके वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (ए.टी.आई.आर.) के साथ–साथ निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा (डी.एल.एफ.ए.) के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

तद्नुसार, टी.जी.एस. व्यवस्था के तहत स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए नियम एवं शर्तों, जैसा कि लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 में निर्धारित किया गया था, को बिहार सरकार द्वारा दिसंबर 2015 में स्वीकार किया गया। तत्पश्चात्, टी.जी.एस. के तहत स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा जनवरी 2017 से सी.ए.जी. द्वारा प्रारम्भ की गई एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय ने (वित्त विभाग, बिहार सरकार के अधीन) जनवरी 2017 से स्थानीय निकायों के लिए प्राथमिक बाह्य लेखापरीक्षक की भूमिका का निर्वहन आरंभ किया।

1.6 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया

1.6.1 स्थानीय निकायों पर महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा लेखापरीक्षा के पूर्ण होने के बाद लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ निरीक्षण प्रतिवेदनों को संबंधित पं.रा.सं. को तथा इसकी एक प्रति संबंधित विभाग को भेजे गए थे। जिला परिषदों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों, पंचायत समितियों के कार्यपालक पदाधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों के मुखियागण को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देना था तथा तीन माह के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना था। हालांकि, लेखापरीक्षा कंडिकाओं के अनुपालन की स्थिति संतोषप्रद नहीं थी, जो लंबित कंडिकाओं की बढ़ती हुए संख्या से स्पष्ट है। विगत पाँच वर्षों (2017–18 से 2021–22) में अनुपालन हेतु लंबित कंडिकाओं की विवरणी नीचे **तालिका 1.5** में दी गई है:

तालिका 1.5
विगत पाँच वित्तीय वर्षों (2017–18 से 2021–22) से लंबित लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

वर्ष	नि. प्र. की संख्या	नि.प्र. में कंडिकाओं की संख्या	शामिल राशि *(₹ करोड़ में)*	निपटान किए गए कंडिकाओं की संख्या	निपटान की राशि *(₹ करोड़ में)*	लंबित कंडिकाओं की संख्या	लंबित कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य *(₹ करोड़ में)*
1	2	3	4	5	6	7(3-5)	8(4-6)
2017-18	1,365	8,475	1,173.853	23	1.301	8,453	1,172.552
2018-19	156	1,069	72.88	0	0	1,069	72.88
2019-20	113	874	222.57	26	22.293	848	200.277
2020-21	14	212	158.13	0	0	212	158.13
2021-22	99	996	3.50	0*	0	996	3.50
कुल	**1,747**	**11,627**	**1,634.933**	**49**	**23.594**	**11,578**	**1,607.339**

*(**स्रोत**: निरीक्षण प्रतिवेदन)*
**वर्ष 2021–22 में 847 कंडिकाओं का निपटान हुआ जो 2021–22 से पूर्व के वर्षों से संबंधित थे।*

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग ने जवाब दिया (मई 2023) कि लंबित लेखापरीक्षा कंडिकाओं के निपटान को सुनिश्चित करने हेतु कंडिकाओं के अनुपालन व दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिला पदाधिकारियों को समय–समय पर (मई 2019, अगस्त 2019, फरवरी 2020 व फरवरी 2021) पत्र लिखे गए थे।

निपटान हेतु लंबित लेखापरीक्षा कंडिकाओं की वृहत् संख्या पं.रा.सं. व विभाग के उदासीन रवैये का सूचक था।

1.6.2 वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन/स्थिति

जनवरी 2017 से पूर्व, बिहार में स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा, स्थानीय लेखापरीक्षक द्वारा, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के समग्र नियंत्रण में, संचालित किया जाता था। निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समेकित करते हुए वार्षिक प्रतिवेदन 2005–06 से 2013–14 की अवधि के लिए तैयार की गई थी तथा इस प्रतिवेदन को 'स्थानीय निकायों पर स्थानीय लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन' शीर्षक दिया गया था।

तदुपरांत, 2014–15 व 2015–16 की अवधि के लिए, सी.ए.जी. द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया गया।

आगे, टी.जी.एस. व्यवस्था के तहत स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा जनवरी 2017 से प्रारंभ हुई। परिणामतः, प्राथमिक लेखापरीक्षक की भूमिका सी.ए.जी. से स्थानांतरित हो कर वित्त विभाग (बिहार सरकार) के अधीन कार्यरत डी.एल.एफ.ए. के पास चली गयी। इसके उपरांत, 2017–19 की अवधि के लिए एक वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (ए.टी.आई.आर.) तैयार किया गया व राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने हेतु राज्य के राज्यपाल को सौंपा गया। वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 की अवधि के लिए भी वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर राज्य विधायिका के समक्ष रखी जा चुकी हैं (जुलाई 2023)।

(i) स्थानीय लेखापरीक्षक का वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त विभाग, बिहार सरकार ने स्थानीय लेखापरीक्षक के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा/अनुपालन के लिए त्रि–स्तरीय समितियों–उच्च स्तरीय, विभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय का गठन (मार्च 2010) किया था। जिला स्तरीय समिति[7] का उत्तरदायित्व, उस जिले के पं.रा.सं. एवं श.स्था.नि. से प्राप्त लेखापरीक्षा कंडिकाओं/प्रतिवेदनों के अनुपालन को सुनिश्चित करना था। विभाग स्तरीय समिति[8] को जिला स्तरीय समितियों द्वारा तैयार किए गए लेखापरीक्षा कंडिकाओं/प्रतिवेदनों के अनुपालन की समीक्षा करनी थी। जिला एवं विभाग स्तरीय समितियों के कार्यकलापों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति[9] की बैठक छः महीने में एक बार होनी थी।

अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग ने जवाब दिया (मार्च 2022) कि : (i) वर्ष 2020 में दो जिलों में व वर्ष 2021 में छः जिलों में जिला स्तरीय समिति की बैठकें आयोजित की गई थीं, (ii) सभी जिलों से जिला स्तरीय समितियों की बैठकों की कार्यवाही प्राप्त करने के बाद विभाग स्तरीय समिति की बैठकें आयोजित की जाएंगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जुलाई 2015 से विभाग स्तरीय समिति की कोई बैठक नहीं हुई थी एवं उच्च स्तरीय समिति की कोई बैठक अगस्त 2013 से नहीं हुई थी।

इस प्रकार, त्रि–स्तरीय समितियों के गठन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। मार्च 2013 एवं मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर स्थानीय लेखापरीक्षक के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मार्च 2016 में राज्य विधायिका के समक्ष उपस्थापित किए गए थे।

इस प्रकार, त्रि–स्तरीय समितियों के गठन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और स्थानीय लेखापरीक्षक के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर चर्चा नहीं की गई।

(ii) सी.ए.जी. का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 31(4), 59(4) और 86(4) में प्रावधान है कि भारत के सी.ए.जी. या उनके द्वारा अधिकृत किसी प्राधिकारी का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधायिका के दोनों सदनों के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2014–15 की अवधि के लिए बिहार सरकार के स्थानीय निकायों पर पहला सी.ए.जी. प्रतिवेदन 4 अप्रैल 2016 को राज्य विधायिका के समक्ष रखा गया था। पंचायती राज विभाग से संबंधित प्रतिवेदन की तीन कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति की अनुशंसाएं (मार्च 2022 तक) प्राप्त नहीं हुईं थीं। आगे, बिहार में स्थानीय निकायों पर वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सी.ए.जी. प्रतिवेदन 23 अगस्त 2017 को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा गया था।

---

[7] *जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में*

[8] *प्रधान सचिव/सचिव, पं.रा.वि., बिहार सरकार की अध्यक्षता में*

[9] *वित्त विभाग के प्रधान सचिव, बिहार सरकार की अध्यक्षता में व प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) एक सदस्य के रूप में*

1.7 जवाबदेही तंत्र

1.7.1 लोकप्रहरी (लोकपाल)

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 152(5) के अनुसार पंचायतों के लिए एक लोक प्रहरी (लोकपाल) की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जानी थी और राज्य सरकार को लोक प्रहरी की सेवा शर्तों, कर्तव्यों और शक्तियों आदि का निर्धारण करना था।

हालांकि, पंचायतों के लिए लोकप्रहरी (लोकपाल) की नियुक्ति हेतु बिहार स्थानीय सरकार लोकपाल नियमावली, 2014 के प्रारूप को अंतिम रूप (मार्च 2022 तक) नहीं दिया गया था।

1.7.2 सामाजिक अंकेक्षण

बिहार ग्राम सभा (बैठक का समन्वय एवं संचालन की प्रक्रिया) नियमावली, 2012 का नियम 2(ए), ग्राम सभा द्वारा गांव में किए गए सभी विकास कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त, पंचम राज्य वित्त आयोग की कंडिका 2.1.7 यह अनुशंसा करती है कि पं.रा.सं. को 'स्मार्ट' स्वशासन की संस्था बनाने के लिए सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

सामाजिक अंकेक्षण का मूल उद्देश्य सामाजिक परियोजनाओं, कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

बिहार सरकार ने सामाजिक अंकेक्षण समिति के क्रियान्वयन के लिए अनुबंध के आधार पर विभिन्न पदों का सृजन किया था (जून 2015) व अप्रैल 2017 में सामाजिक अंकेक्षण समिति का गठन किया था। सामाजिक अंकेक्षण समिति को पंचायती राज संस्थाओं में मनरेगा तथा अन्य विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नीर निर्मल परियोजना व राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (प्रखंडों व जिलों द्वारा कार्यान्वित) का सामाजिक अंकेक्षण सौंपा गया था। हालांकि, मनरेगा के लेखापरीक्षा के अलावा, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार (मार्च 2022 तक) द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के लिए कोई सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया। पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार ने अन्य योजनाओं के लेखापरीक्षा के लिए सामाजिक अंकेक्षण समिति से प्रभावी रूप से कोई संपर्क नहीं किया। इसका कारण विभाग द्वारा नहीं बताया गया।

1.7.3 उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 342 में निहित प्रावधानों के साथ पठित बिहार सरकार के अनुदेशों के अनुसार, विशिष्ट उद्देश्यों हेतु स्वीकृत अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र के समर्पित किए जाने की समय–सीमा, अनुदान के आवंटन की तिथि से 18 माह है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पंचायती राज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2021–22 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न योजना शीर्षों के तहत ₹ 59,995.90 करोड़ का अनुदान दिया था, परन्तु पंचायती राज संस्थाओं ने केवल ₹ 34,129.49 करोड़ (56.89 प्रतिशत) की राशि के लिए ही (मार्च 2023 तक) उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किए थे, जैसा कि **तालिका 1.6** में दर्शाया गया है:

तालिका–1.6
वित्तीय वर्ष 2021–22 तक आवंटित निधियों हेतु पं.रा.सं. द्वारा समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र
2003-04 से 2021-22	59,995.90	34,129.49	25,866.41

*(**स्रोत**: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना)*

1.7.4 पंचायती राज संस्थाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

सतत् सुधार के लिए पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में सनदी लेखाकार (सी.ए.) को अनुबंधित करने के अतिरिक्त योग्य लेखाकारों को अंतरिम उपाय के रूप में नियमित रूप से नियुक्त किया जाना था। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग, बिहार सरकार ने चौदहवीं वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्थानीय निकायों के लिए दूसरी और बाद की किस्तें जारी करने के लिए पिछले वर्ष के अनुदानों के यू.सी. के साथ व्यय लेखे और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य (फरवरी 2016) कर दिया। इसके कारण विभाग में एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की स्थापना आवश्यक हो गयी।

पंचायती राज विभाग के निर्देशों (मई 2020) के अनुसार, पं.रा.सं. व ग्राम कचहरी के लेखाओं की लेखापरीक्षा हेतु योग्य सी.ए. फर्मों के चयन के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों को अधिकृत किया गया था।

सी.ए. फर्मों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं व ग्राम कचहरी की संपन्न हुई लेखापरीक्षा की स्थिति **तालिका 1.7** में दी गई है:

तालिका–1.7

सनदी लेखाकार द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति*

वित्तीय वर्ष	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	लेखापरीक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम कचहरियों की कुल संख्या	लेखापरीक्षित ग्राम कचहरियों की संख्या	पंचायत समितियों की कुल संख्या	लेखापरीक्षित पंचायत समितियों की संख्या	जिला परिषदों की कुल संख्या	लेखापरीक्षित जिला परिषदों की संख्या
2019-20	8,387	8,207	8,387	7,594	534	502	38	32
2020-21	8,387	7,924	8,387	7,063	534	485	38	28
2021-22	8,058	3,709	8,057	2,627	533	232	38	14

*(**स्रोतः** पंचायती राज विभाग तथा आर्थिक सर्वेक्षण, 2022–23, बिहार सरकार)*

** विभाग द्वारा मई 2023 में उपलब्ध कराए गए आँकड़े*

विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया था (जनवरी 2020) कि पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों के लेखाओं की वर्ष 2018–19 तक की अवधि की लेखापरीक्षा जनवरी 2020 तक पूरा कर लें। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 तक की लेखापरीक्षा (फरवरी 2022 तक) पूरी नहीं हुई थी। विभाग द्वारा जवाब दिया गया (नवंबर 2022) कि कोविड–19 महामारी के कारण सी.ए. द्वारा किया गया लेखापरीक्षा आच्छादन कम था।

पंचायती राज विभाग के अनुश्रवण पदाधिकारी ने यह बताया (मार्च 2022) कि लेखापरीक्षा कार्य में असहयोग अथवा कर्तव्यों के निष्पादन में लापरवाही के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने व इसकी सूचना विभाग को देने के निर्देश जारी (नवंबर 2021) किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, (i) सी.ए. के कार्य की समीक्षा (ii) पर्यवेक्षण (iii) जिले से प्राप्त प्रतिवेदनों के राज्य स्तर पर संकलन (iv) आपत्तियों के अनुपालन एवं (v) विभाग स्तर के अन्य लेखापरीक्षा से संबंधित कार्यों के लिए एक राज्य स्तरीय लेखापरीक्षा एवं वित्तीय प्रबंधन सलाहकार को नियुक्त किया जाना था। हालांकि, विभाग ने इस कार्य के लिए किसी सलाहकार की नियुक्ति नहीं (मई 2023 तक) की। इसके फलस्वरूप, सी.ए. के कार्य की समीक्षा, पर्यवेक्षण, राज्य स्तर पर जिले से प्राप्त प्रतिवेदनों का संकलन, आपत्तियों का अनुपालन एवं अन्य लेखापरीक्षा से संबंधित कार्य सुनिश्चित नहीं किए जा सके।

1.7.5 *जिला पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण*

भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) योजना के अंतर्गत, विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता वृद्धि के लिए संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने और उन्हें अवसंरचना, सुविधाओं, मानव संसाधनों और परिणाम आधारित प्रशिक्षण में पर्याप्त गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, जिला पंचायत संसाधन केन्द्रों (डी.पी.आर.सी.) के निर्माण हेतु निधि उपलब्ध कराया गया था। इस योजना के अंतर्गत मौजूदा डी.पी.आर.सी. को सुदृढ़ किया जाना था या नए केंद्र स्थापित किए जाने थे। प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विश्लेषण, प्रलेखन एवं संचार के संचालन तथा समन्वय के लिए इन केंद्रों को केंद्र बिंदु होने की उम्मीद की गई थी तथा इनसे शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ प्रशिक्षण नेटवर्क विकसित करने की अपेक्षा की गई थी।

पंचायती राज विभाग ने पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में सितंबर 2018 एवं फरवरी 2019 के दौरान डी.पी.आर.सी. के निर्माण के लिए राज्य के जिला परिषदों को ₹ 194.05 करोड़ जारी किया। 24 जिलों के लिए डी.पी.आर.सी. की अनुमानित लागत ₹ 5.1479 करोड़ प्रति इकाई थी और शेष 14 जिलों के लिए यह ₹ चार करोड़ प्रति इकाई थी। इस प्रकार, राज्य के सभी डी.पी.आर.सी. के लिए कुल अनुमानित लागत ₹179.55 करोड़ थी। जिला परिषदों को ई–निविदा प्रक्रिया के माध्यम से डी.पी.आर.सी. के निर्माण को निष्पादित करना था। तीन मंजिलों (भू–तल, पहली मंजिल व दूसरी मंजिल) का निर्माण किया जाना था। हालांकि, अप्रैल 2023 तक पाँच जिलों में डी.पी.आर.सी. का निर्माण पूर्ण हो चुका था; 17 जिलों में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था; चार जिलों में पहली व दूसरी मंजिल का निर्माण पूर्ण हो चुका था; तथा शेष 12 जिलों में निर्माण कार्य प्रारंभिक चरणों में था।

1.7.6 *पंचायत सरकार भवन का निर्माण*

बिहार सरकार ने राज्य के प्रत्येक पंचायत में एक पंचायत सरकार भवन (पी.एस.बी.) का निर्माण करने का निर्णय लिया था जिसका उद्देश्य था कि पंचायत सरकार भवन निर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए ग्राम पंचायतों के कार्यालय के रूप में कार्य करें, जैसे प्रमाण पत्र, परमिट एवं लाइसेंस जारी करना, ग्राम सभाओं के आयोजन जैसे कार्यों के लिए एक केंद्रीय बिंदु के रूप में उपयोग करना, सूचना प्रदान करना, आदि।

वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2018–19 के दौरान बिहार सरकार ने 3,200 पी.एस.बी. के निर्माण को मंजूरी दी थी जिसे तीन अलग–अलग कार्यान्वयन एजेंसियों[10], द्वारा निष्पादित किया जाना था। तदुपरांत, 244 पी.एस.बी. के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई थी। हालांकि, बिहार सरकार द्वारा राज्य में 8,058 पी.एस.बी. के निर्माण करने की योजना बनाई गई है। 3,444 पी.एस.बी. के स्वीकृत लक्ष्य के विरूद्ध, केवल 1,488 पी.एस.बी. का निर्माण किया गया था व इनमें से 1,399 को 23 नवंबर 2022 तक कार्यशील बनाया गया था।

1.8 वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित मामले

1.8.1 निधियों के स्रोत

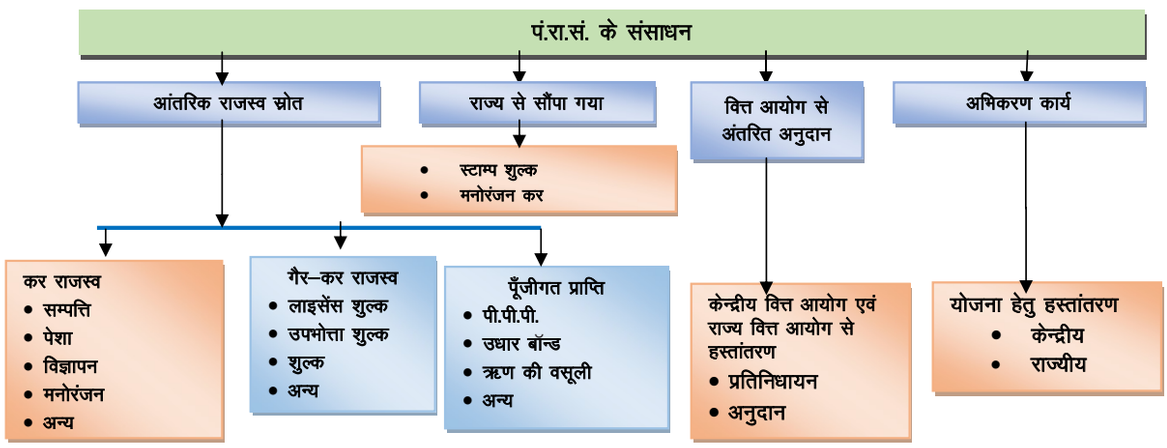
पं.रा.सं. के संसाधन में सम्मिलित हैं:– (i) कर एवं गैर–कर राजस्वों के संग्रहण के माध्यम से प्राप्त 'स्वयं के राजस्व' (ii) राज्य एवं केंद्रीय वित्त आयोगों की अनुशंसा के अनुसार निधियों का प्रतिनिधायन, (iii) बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था हेतु अनुदान सहित,

[10] *बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी, (बी.जी.एस.वाई.एस.) पंचायती राज विभाग के अधीन एक सोसाइटी; स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (एल.ए.ई.ओ.) एवं ग्राम पंचायतें, पी.एस.बी. के निर्माण के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां थी। पी.एस.बी. का निर्माण उक्त तीन विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया जा रहा था। बी.जी.एस.वाई.एस. ने विश्व बैंक से प्राप्त धन से पी.एस.बी. का निर्माण शुरू किया था, जबकि पंचायती राज विभाग द्वारा एल.ए.ई.ओ. को पी.एस.बी. के निर्माण के लिए लगाया गया था एवं ग्राम पंचायत भी निर्माण कार्य कर रहे थे।*

रखरखाव एवं अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए केंद्रीय व राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान तथा (iv) अन्य प्राप्तियाँ।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 27, 55 तथा 82 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकतम दर के अधीन होल्डिंगों, पेशाओं पर करारोपण तथा टोल, शुल्कों एवं दरों को अध्यारोपित करने के लिए पं.रा.सं. अधिकृत थे। पं.रा.सं. के वित्त स्रोतों का फ्लो चार्ट नीचे **चार्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.1: वित्त के स्रोत



*(**स्रोत**: बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के प्रावधान एवं पंचम राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन)*

पं.रा.सं. के तीन स्तरों में से केवल जिला परिषदों के पास ही स्वयं के गैर–कर राजस्व स्रोत थे जैसे कि दुकानों/निरीक्षण बंगलों का किराया, तालाबों/बस स्टैंड को पट्टे पर देना आदि, जबकि पं.रा.सं. ने करों एवं शुल्कों का आरोपण नहीं किया क्योंकि राज्य सरकार ने करों, टोल एवं शुल्कों आदि की अधिकतम दरों को अभी तक (मार्च 2022) अधिसूचित नहीं किया था।

1.8.1.1 राज्य बजट आवंटन की तुलना में व्यय

राज्य सरकार का वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 के लिए पंचायती राज विभाग का बजट प्रावधान, जिसमें भारत सरकार की योजनाओं के लिए राज्यांश तथा केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत प्राप्त अनुदान शामिल है, नीचे **तालिका 1.8** में दिया गया है।

तालिका 1.8
बजट आवंटन की तुलना में व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8 (3 से 7)
1. बजट आवंटन	राजस्व	9,148.71	10,245.17	13,376.35	12,597.84	13,224.87	58,592.94
	पूँजीगत	0.01	1.00	250	480.00	321.00	1052.01
	कुल	**9,148.72**	**10,246.17**	**13,626.35**	**13,077.84**	**13545.87**	**59644.95**
2. व्यय	राजस्व	8,540.95	8,408.50	8,689.62	8,236.01	8057.27	41932.35
	पूँजीगत	0.00	0.00	45.12	166.40	121.58	333.10
	कुल	**8,540.95**	**8,408.50**	**8,734.74**	**8,402.41**	**8178.85**	**42265.45**
3. बचत (1-2)		**607.77**	**1,837.67**	**4,891.61**	**4,675.43**	**5367.02**	**17,379.50**
4. बचत का प्रतिशत		**7**	**18**	**36**	**36**	**40**	**29**

*(**स्रोत**: वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 के लिए विनियोजन लेखे, बिहार सरकार)*

तालिका 1.8 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2017 से 2022 के दौरान पंचायती राज विभाग, बजटीय आवंटन का पूर्ण उपयोग नहीं कर सका तथा बचत सात प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच थी। आगे, पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय, उक्त शीर्ष के अंतर्गत हुए कुल आवंटन का मात्र 32 प्रतिशत था। आगे, पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत आवंटित निधियों के नहीं/कम उपयोग के फलस्वरूप पंचायत सरकार भवन, संसाधन केन्द्र आदि जैसी परिसंपत्तियों का सृजन नहीं हुआ, जिनका उपयोग ग्राम पंचायत कार्यालयों व संसाधन केन्द्रों के रूप में किया जाना था। इससे पं.रा.सं. को प्रतिनिधायित हुए कार्य, यथा प्रमाण पत्र, परमिट व लाइसेंस जारी करना, के निर्वहन को तथा ग्राम सभाओं के आयोजन, जनता को सूचना प्रदान करने, विभिन्न प्रकार की सेवाओं को प्रदान करने, वृहत् संख्या में जन–प्रतिनिधियों, अधिकारियों के प्रशिक्षण इत्यादि के लिए एक केंद्र बिन्दु के रूप में उपयोग किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

1.8.2 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं

संविधान के अनुच्छेद 243 आई. एवं बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 की धारा 168 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति के आकलन एवं इन स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करने के अधिदेश के साथ बिहार सरकार ने समय–समय पर राज्य वित्त आयोगों[11] का गठन किया था। षष्ठम राज्य वित्त आयोग ने पहली बार जनवरी 2020 में एक अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें वित्तीय वर्ष 2020–21 को शामिल किया गया था तथा फिर अप्रैल 2021 में वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2024–25 तक की अवधि को सम्मिलित कर अपना अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

षष्ठम राज्य वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2024–25 के दौरान स्थानीय निकायों को ₹ 29,876 करोड़[12] हस्तांतरित किए जा सकते हैं, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं का हिस्सा ₹ 19,419 करोड़ होगा। वित्तीय वर्ष–वार आवंटन **तालिका 1.9** में दिया गया है।

तालिका 1.9
पं.रा.सं. को विमुक्ति हेतु अनुशंसित अनुदान व प्रतिनिधायन

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुमानित				
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2021-25
स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग द्वारा कुल हस्तांतरण	6,008	7,014	7,883	8,971	29,876
पं.रा.सं को हस्तांतरण	3,905	4,559	5,124	5,831	19,419

*(**स्रोत** : षष्ठम राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन)*

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2024–25 तक की अवधि के लिए षष्ठम राज्य वित्त आयोग की महत्वपूर्ण अनुशंसाओं को निम्नलिखित तरीके से लागू करने का निर्णय (अगस्त 2021) लिया था:

- प्रतिनिधायन की राशि राज्य के स्वयं के कर राजस्व (एस.ओ.टी.आर.) का 10 प्रतिशत होगी।
- अनुदान की राशि पिछले वित्तीय वर्ष के लिए राज्य के वास्तविक व्यय का 2.5 प्रतिशत होगी। अनुदान की कुल राशि में से 50 प्रतिशत सीधे स्थानीय निकायों को जारी किया जाएगा तथा शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार के कार्यात्मक विभागों को जारी किया जाएगा जिसका उद्देश्य स्थानीय निकायों के विकास के लिए योजनाओं को निष्पादित करना है।

[11] *प्रथम रा.वि.आ.–अप्रैल 1994, द्वितीय रा.वि.आ.–जून 1999, तृतीय रा.वि.आ.–जुलाई 2004, चतुर्थ रा.वि.आ. –जून 2007 पंचम रा.वि.आ.–दिसम्बर 2013 एवं षष्ठम रा.वि.आ.–फरवरी 2019*

[12] *प्रतिनिधायन: ₹ 11,713 करोड़ तथा अनुदान: ₹ 18,163 करोड़*

- प्रतिनिधायन व अनुदान के अंतर्गत निधियाँ पं.रा.सं. एवं श.स्था.नि. के बीच क्रमशः 65:35 के अनुपात में आवंटित किया जाएगा।
- जिला परिषदों, पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों के बीच निधियों का पारस्परिक वितरण क्रमशः 15:15:70 के अनुपात में होगा।
- अनुदान एवं प्रतिनिधायन निम्नलिखित तीन शीर्षों के अंतर्गत पं.रा.सं. को हस्तांतरित की जाएंगी– (i) विकास निधि (30 प्रतिशत) (ii) अनुरक्षण निधि (20 प्रतिशत) (iii) सामान्य निधि (50 प्रतिशत)।
- षष्ठम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत स्थानीय निकायों को निधियों का क्षैतिज वितरण जनसंख्या व क्षेत्रफल पर आधारित होगा जिसका भारांक क्रमशः 90 प्रतिशत व 10 प्रतिशत होगा।

1.8.3 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसाएं

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(3)(बीबी) तथा 280(3)(सी), वित्त आयोग को पंचायतों व नगरपालिकाओं के संसाधनों को बढ़ाने के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के उपायों की अनुशंसा का अधिदेश प्रदान करता है।

भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 15वीं वित्त आयोग का गठन (27 नवंबर 2017) 1 अप्रैल 2020 से प्रारम्भ होने वाले पाँच वर्ष की अवधि के लिए अनुशंसा करने हेतु किया था। आयोग ने अपना प्रतिवेदन दो भागों में प्रस्तुत किया: (i) नवंबर 2019 में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एक अंतरिम प्रतिवेदन, एवं (ii) अक्टूबर 2020 में वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 के लिए मुख्य प्रतिवेदन। अपने अंतरिम प्रतिवेदन के तहत आयोग ने अनुशंसा की कि ग्रामीण स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले अनुदान का 50 प्रतिशत असंबद्ध हो सकता है, जबकि शेष 50 प्रतिशत (यानि स्वच्छता व जल आपूर्ति के लिए अनुदान) संबंद्ध हो सकता है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु अनुदान जारी करने के लिए कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई थी। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2021–22 से इन अनुदानों को प्राप्त करने वाले ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए लेखापरीक्षित लेखाओं को समय पर जमा करना प्रवेश स्तर की शर्त होगी। वित्तीय वर्ष 2021–22 (11 मार्च 2022 तक) के दौरान भारत सरकार से प्राप्त एवं पं.रा.सं. को जारी किए गए अनुदानों का विवरण **तालिका 1.10** में दिया गया है:

तालिका 1.10

भारत सरकार से प्राप्त एवं इकाईयों को जारी किए गए अनुदानों का विवरण

(राशि करोड़ ₹ में)

वित्तीय वर्ष	भारत सरकार से प्राप्ति				इकाईयों को विमुक्त अनुदान			
	संबद्ध अनुदान		असंबद्ध अनुदान		संबद्ध अनुदान		असंबद्ध अनुदान	
	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि
2021-22	27/8/21	1,112.70	10/5/21	741.80	6/9/21	1,112.70	18/5/21	741.80
	11/3/22	1,112.70	23/12/21	741.80	15/3/22	1,112.70	28/12/21	741.80
कुल		**2,225.40**		**1,483.60**		**2,225.40**		**1,483.60**

*(**स्रोतः** पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)*

1.8.4 पं.रा.सं. द्वारा लेखाओं का संधारण

1.8.4.1 पं.रा.सं. द्वारा लेखाओं का संधारण/मानक लेखांकन प्रणाली

भारत सरकार ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से पं.रा.सं. के लेखाओं के संधारण के लिए मानक लेखांकन प्रणाली (एम.ए.एस.) को निर्धारित (2009) किया था। परिणामतः, पंचायती राज विभाग ने अधिसूचित किया (जुलाई 2010) कि अप्रैल 2010 से पं.रा.सं. के लेखाओं को एम.ए.एस. के प्रारूप में संधारित किया जाएगा। मानक लेखांकन

प्रणाली में आठ प्रारूप थे व प्रियासॉफ्ट (पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित एक लेखांकन सॉफ्टवेयर) में डेटा की प्रविष्टि की जानी थी।

विभाग ने पं.रा.सं.[13] में पंचायत इन्टरप्राईजेज सूट (पी.ई.एस.) एप्लीकेशन पर आधारित ई–पंचायत लागू करने का निर्णय लिया (अगस्त 2018), जिसमें पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित विभिन्न उद्देश्यों के लिए 10 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समाहित हैं, इन एप्लीकेशनों में से प्रियासॉफ्ट एक है। हालांकि, ई–पंचायत को लागू नहीं किया गया एवं पंचायती राज मंत्रालय ने ई–ग्राम स्वराज प्रारम्भ किया (अप्रैल 2020) जिसमें ई–पंचायत का विलय कर दिया गया। ई–ग्राम स्वराज एकल मंच है जिसका उद्देश्य पंचायतों की योजना व लेखांकन जरूरतों के सभी पहलुओं को शामिल करना है। हालांकि, बिहार में केवल 15वीं वित्त आयोग के अनुदान के संबंध में ऑनलाइन लेखांकन लागू किया गया था।

1.8.5. ए.सी./डी.सी. बिलों से संबंधित मामले

बिहार कोषागार संहिता (बी.टी.सी.), 2011 का नियम 177 प्रावधानित करता है कि आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि (i) आकस्मिक बिलों पर निकासी की गई धनराशि को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय कर दिया जाएगा और (ii) अव्ययित राशि को वर्ष के 31 मार्च से पहले कोषागार को प्रेषित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बी.टी.सी., 2011 के नियम 194 के अनुसारः (i) प्रतिहस्ताक्षरित डिटेल्ड कंटिजेंट (डी.सी.) बिल उस माह के बाद छः माह के अन्दर जिसमें एब्सट्रैक्ट कंटिंजेंट (ए.सी) बिल तैयार किया गया था, महालेखाकार (ले. एवं हक.) को प्रस्तुत किए जाएंगे, और (ii) कोई ए.सी. बिल छः माह की इस अवधि की समाप्ति के बाद भुनाया नहीं जाएगा जब तक संबंधित डी.सी. बिल जमा नहीं किया जाता है।

जुलाई 2022 तक, वित्तीय वर्ष 2002–03 से 2021–22 के दौरान ए.सी. बिलों के माध्यम से निकासी की गई 97.18 करोड[14] की राशि (30 सितंबर 2021 तक) समायोजन के लिए लंबित थी।

इस प्रकार, ए.सी. बिलों के माध्यम से निकासी की गई पूरी राशि के उपयोग को सुनिश्चित करने व साथ ही साथ डी.सी. बिलों को समय पर प्रस्तुत करने में पंचायती राज विभाग विफल रहा।

निर्धारित अवधि के भीतर डी.सी. बिल जमा नहीं करना वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन है। इसके अलावा, लंबी अवधि के लिए अग्रिमों का समायोजन न करना, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के जोखिम से भरा होता है।

1.8.6 लेखापरीक्षा का प्रभाव

वित्तीय वर्ष 2021–22 में पंचायती राज संस्थाओं की 13 इकाईयों की लेखापरीक्षा के दौरान ₹ 8.48 करोड़ की राशि की वसूली हेतु सुझाव दिया गया था जिसमें से ₹ 6.30 करोड़ केवल तीन इकाईयों यथा– जिला परिषद्, सिवान (₹ 176.23 लाख); जिला परिषद्, बेगूसराय (₹ 290.92 लाख); एवं जिला परिषद्, भागलपुर (₹ 162.44 लाख) से संबंधित थे। हालांकि, अभी तक किसी राशि की वसूली नहीं हुई है।

---

[13] *पंचायती राज मंत्रालय ने ई–गवर्नेंस पहल को प्रभावी ढ़ंग से अपनाने के लिए देश भर में पं.रा.सं. में ई–गवर्नेंस प्रारम्भ करने व इन्हें मजबूत करने एवं पं.रा.सं. से संबंधित क्षमताओं का निर्माण करने के उद्देश्य से ई–पंचायत मिशन मोड परियोजना की शुरूआत की। पंचायत इंटरप्राइज सूट, जिसमें 11 कोर कॉमन एप्लीकेशन सम्मिलित हैं, को इस परियोजना के तहत अवधारणाबद्ध किया गया है।*

[14] *ए.सी. बिलों के माध्यम से पं.रा.सं. द्वारा निकासी की गई कुल ₹ 1,292.19 करोड़ की राशि थी एवं उनके विरुद्ध राज्य सरकार ने समायोजन के लिए महालेखाकर (ले0 एवं हक0) को ₹ 1,195.01 करोड़ के डी.सी. बिल प्रस्तुत किए थे। जुलाई 2022 तक, शेष ए.सी. बिलों के विरुद्ध ₹ 97.18 करोड़ राशि के डी.सी. बिल समायोजन हेतु लंबित थे।*

अध्याय-II
अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय - II
अनुपालन लेखापरीक्षा

पंचायती राज विभाग

2.1 कपटपूर्ण भुगतान

ग्राम पंचायत, बुधुआ, वित्त आयोग के अनुदानों से वित्तपोषित किए जाने वाले कार्यों की निगरानी करने में विफल रहा और ₹ 12.50 लाख का भुगतान अभिकर्त्ता को उन कार्यों के लिए किया जो कार्यान्वित नहीं किए गये थे।

बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता की धारा 244 में प्रावधानित है कि मापी पुस्त (एम.बी.) को सबसे महत्त्वपूर्ण अभिलेख माना जाएगा, क्योंकि यह सभी परिमाण खातों का आधार है, चाहे वह दैनिक श्रम द्वारा किया गया कार्य हो या नगवार द्वारा या अनुबंध द्वारा या प्राप्त सामग्री जिसे गिना या मापा जाना है। सक्षम प्राधिकारी {अनुमंडल पदाधिकारी (एस.डी.ओ.) से नीचे के रैंक का नहीं}, को यह सुनिश्चत करना है कि किया गया भुगतान वास्तव में निष्पादित कार्य की मात्रा से अधिक न हो। आगे, बिहार पंयाचत राज अधिनियम की धाारा 17(1) में यह प्रावधानित है कि ग्राम पंचायत का मुखिया ग्राम पंचायत के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन के लिए उत्तरदायी है और ग्राम पंचायत के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ–साथ उन कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण और प्रशासनिक नियंत्रण करेगा जिनकी सेवाएं किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के अधीन सौंपी गयी हों। आगे, बिहार पंचायत (अधिकारियों का निरीक्षण तथा कार्यकलापों की जांच, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन) नियमावली (बि.पं.नि.) 2014 के अनुसार प्रखंड और जिला स्तर के पदाधिकारी[15] निर्धारित अंतराल[16] पर ग्राम पंचायत कार्यालयों के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी हैं।

पंचायत समिति, अकबरपुर (नवादा) अंतर्गत ग्राम पंचायत बुधुआ के अभिलेखों की वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2021–22 (मार्च 2023 तक अद्यतन) की अवधि के लिए हुए लेखापरीक्षा (जुलाई 2022) से पता चला कि ग्राम पंचायत ने पंचम राज्य वित्त आयोग अनुदान से नाला निर्माण[17] और चौदहवीं वित्त आयोग अनुदान से पी.सी.सी. सड़क निर्माण[18] (फरवरी 2020 से जुलाई 2020) के कार्य कराए थे जिसकी कुल अनुमानित लागत ₹15.93 लाख[19] थी। ग्राम पंचायत ने उपरोक्त दोनों कार्यों को कराने के लिए ग्राम पंचायत के तत्कालीन पंचायत सचिव को इस निर्देश के साथ कार्यकारी अभिकर्त्ता

---

[15] *प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रमंडलीय उप निदेशक (पंचायत), उप विकास आयुक्त, जिला पदाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त।*

[16] *प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम एक ग्राम पंचायत प्रति माह, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम दो ग्राम पंचायत प्रति माह, अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम दो ग्राम पंचायत प्रति तीन माह में, प्रमंडलीय उप निदेशक (पंचायत) एवं उप विकास आयुक्त द्वारा न्यूनतम दो ग्राम पंचायत प्रति छः माह में, जिला पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम दो ग्राम पंचायत प्रति वर्ष एवं प्रमंडलीय आयुक्त अपनी सुविधानुसार।*

[17] *योजना संख्या 01/19–20 (पंचम राज्य वित्त आयोग अनुदान) तेलभद्रो में राजेश ठाकुर के घर से रविन्द्र ठाकुर के घर तक नाला एवं ढक्कन निर्माण।*

[18] *योजना संख्या 02/19–20 (चौदहवी वित्त आयोग अनुदान) तेलभद्रो में पिन्टु यादव के घर से सुनील यादव के घर तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण।*

[19] *योजना संख्या 01/19–20 की प्राकलित राशि ₹ 5.95 लाख और .योजना संख्या 02/19–20 की प्राकलित राशि ₹ 9.98 लाख थी, इस प्रकार दो कार्यों की प्राकलित राशि ₹ 5.95 लाख + ₹ 9.98 लाख = ₹ 15.93 लाख थी।*

नामित किया (अप्रैल और मई 2019) कि पूर्वोक्त कार्य, कार्यादेश निर्गत होने की तिथि[20] से एक वर्ष के भीतर (क्रमशः मई और अप्रैल 2019) पूर्ण किए जाएं।

कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्त मे दर्ज कार्य मूल्य ₹13.05 लाख[21] के विरुद्ध अभिकर्त्ता को, मई से जुलाई 2020 के दौरान, ₹12.50 लाख[22] का भुगतान किया गया था। हालांकि, तकनीकी सहायक और ग्राम पंचायत के वर्त्तमान पंचायत सचिव के साथ लेखापरीक्षा (जुलाई 2022) द्वारा किए गये संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि अभिकर्त्ता द्वारा कार्यों को नहीं किया गया था।

कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्त में दर्ज और कार्यपालक अभियंता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नवादा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मापी के आधार पर मुखिया (ग्राम पंचायत निधि से राशि निकालने के लिए पंचायत सचिव संयुक्त हस्ताक्षरकर्त्ता थे) द्वारा कार्यकारी अभिकर्त्ता को राशि का भुगतान किया गया था। ग्राम पंचायत के मुखिया ने कार्यों के वास्तविक क्रियान्वयन का अनुश्रवण नहीं किया और स्थल पर कार्य सत्यापन किए बिना ही तत्कालीन पंचायत सचिव को ₹12.50 लाख का भुगतान कर दिया। इसके अतिरिक्त, बि.पं.नि. 2014 के प्रावधानों के विपरीत प्रखंड और जिला स्तर के प्राधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण का कोई साक्ष्य नही था। लेखापरीक्षा (मार्च 2023) में यह इंगित किए जाने पर वर्त्तमान पंचायत सचिव ने उत्तर दिया कि तत्कालीन पंचायत सचिव, जो सेवानिवृत हो चुके थे, से स्पष्टीकरण माँगा जाएगा।

कार्यों के वास्तविक क्रियान्वयन के बिना भुगतान संभव हो पाया था, क्योंकि प्राधिकारियों, अर्थात कार्य के निष्पादन के अनुश्रवण एवं निरीक्षण के लिए जिम्मेदार मुखिया एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों ने कार्य का अनुश्रवण नहीं किया, कनीय अभियंता ने मापी पुस्त में कार्यों की गलत प्रविष्टियाँ की और कार्यपालक अभियंता ने मापी पुस्त को प्रतिहस्ताक्षरित किया, जिसके फलस्वरुप ग्राम पंचायत निधि से ₹12.50 लाख का फर्जी भुगतान हुआ।

मामला मार्च 2023 में राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया था, परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2023 तक)।

---

[20] *योजना संख्या 01/19–20 के लिए कार्यादेश निर्गत की तिथि 01/05/2019 थी, जबकि योजना संख्या 02/19–20 के लिए कार्यादेश की तिथि 01/04/2019 थी।*

[21] *योजना सख्या 01/2019–20 में किए गए कार्य का मूल्य (मापी पुस्त के अनुसार) ₹ 5.95 लाख था और योजना संख्या 02/2019–20 मे किए गए कार्य का मूल्य ₹ 7.10 लाख था, इस प्रकार मापी पुस्त में दर्ज मापी के अनुसार किए गए कार्य का मुल्य ₹ 5.95 लाख+ ₹ 7.10 लाख = ₹ 13.05 लाख था।*

[22] *योजना सख्या 01/2019–20 के लिए ₹ 5.50 लाख का भुगतान किया गया था और योजना संख्या 02/2019–20 के लिए ₹ 7.00 लाख का भुगतान किया गया था, इस प्रकार कुल भुगतान ₹ 5.50 लाख+ ₹ 7.00 लाख= ₹ 12.50 लाख था।*

शहरी स्थानीय निकाय

अध्याय-III

शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकलापों, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित विषयों की रुपरेखा

अध्याय - III
शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकलापों, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित विषयों की रुपरेखा

3.1 परिचय

चौहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम (74वां सी.ए.ए.), 1992 में शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के लिए स्थानीय स्वशासन के गठन की परिकल्पना की गई थी। तद्नुसार, नगरपालिकाओं को शासन हेतु संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, राज्यों द्वारा ऐसी शक्तियों, कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को नगरपालिकाओं को सौंपा जाना था जिससे वे स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें तथा संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 विषयों[23] सहित प्रदत्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकें।

बिहार सरकार ने बिहार नगरपालिका अधिनियम, (बि0एम0ए0) 2007 (समय–समय पर संशोधित) को अधिनियमित किया जिसके माध्यम से नगरपालिकाओं को कार्यों एवं उत्तरदायित्वों तथा इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए शक्तियों का प्रतिनिधायन किया गया। आगे, बिहार सरकार ने राज्य के नगरपालिकाओं में लेखाओं को तैयार करने व संधारण करने हेतु बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली (बी.एम.ए.आर.), 2014, बिहार नगरपालिका लेखा हस्तक (बी.एम.ए.एम.) तथा बिहार नगरपालिका बजट हस्तक तैयार किया।

3.1.1 राज्य की रूपरेखा

बिहार देश के सबसे कम शहरीकृत राज्यों में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार की शहरी जनसंख्या 1.18 करोड़ थी। हालांकि, बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण, 2022–23 के अनुसार, संशोधन (2020) के आलोक में अतिरिक्त शहरी जनसंख्या होने के कारण, 2022 में बिहार की अनुमानित शहरी जनसंख्या 2.02 करोड़ थी। 2022 में बिहार में शहरी जनसंख्या भारत की कुल शहरी जनसंख्या का लगभग 4.2 प्रतिशत है। लेकिन, बिहार के जिलों में काफी आर्थिक असमानता के अलावा शहरीकरण के स्तर के संदर्भ में व्यापक भिन्नता है, जो 44.3 प्रतिशत (पटना) से 3.6 प्रतिशत (मधुबनी) के बीच में परिलक्षित होती है। आगे, राज्य के केवल एक शहर (पटना) की जनसंख्या दस लाख से अधिक थी। राज्य के तुलनात्मक जनसांख्यिकीय व विकास के आँकड़े नीचे **तालिका 3.1** में दिए गए हैं:

---

[23] *(i) नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है (ii) भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण (iii) आर्थिक और सामाजिक विकास योजना (iv) सड़कें और पुल (v) घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय (vi) लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता सफाई और कूड़ा–करकट प्रबंध (vii) अग्निशमन सेवाएं (viii) नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिक आयामों की अभिवृद्धि (ix) समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा (x) गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन (xi) नगरीय निर्धनता उन्मूलन (xii) नगरीय सुख–सुविधाओं और सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था (xiii) सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि (xiv) शवाधान और कब्रिस्तान; शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह (xv) कांजी हाउस; पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण (xvi) जन्म–मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु पंजीकरण भी है (xvii) सार्वजनिक सुख–सुविधाएं जिसके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं भी हैं (xviii) वधशालाओं और चर्मशोधन शालाओं का विनियमन।*

तालिका 3.1
राज्य के महत्वपूर्ण आँकड़े

क्रम सं0	संकेतक	इकाई	राज्य	संपूर्ण भारत
1	शहरी जनसंख्या	मिलियन	11.76	377.11
2	शहरी जनसंख्या घनत्व	व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	4,811	3,836
3	शहरी साक्षरता	*प्रतिशत*	76.86	84.11
4	शहरी लिंगानुपात	महिलाएँ प्रति हजार पुरूषों पर	895	900
5	शहरी निर्धनता का स्तर	*प्रतिशत*	31.2	13.7
6	प्रति व्यक्ति नगरपालिका स्व–राजस्व	₹	58	2,540
7	जिलों की संख्या	संख्या	38	765

*(**स्रोत**: जनगणना 2011 तथा इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित स्थानीय शासन निर्देशिका)*

3.2 शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा

शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा कंडिका 5.1.1 में दिया गया है।

3.3 शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली

3.3.1 राज्य सरकार की शक्तियां

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 श.स्था.नि. के समुचित कार्यकलापों की निगरानी हेतु राज्य सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान करती है। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में प्रावधानित सेवाएं प्रदत्त करने हेतु श.स्था.नि. को कुछ शक्तियां हस्तांतरित की गयी थीं परन्तु सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिए जा रहे थे। राज्य सरकार की शक्तियों का एक संक्षिप्त सार **तालिका 3.2** में दिया गया है:

तालिका 3.2
राज्य सरकार की शक्तियां

प्राधिकार	राज्य सरकार की शक्तियां
धारा 3 एवं 6	**नगरपालिका क्षेत्र का गठन:** इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार जांचोपरांत, जैसा वह उचित समझे, अधिसूचना द्वारा किसी शहरी क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या का घनत्व, ऐसे क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व को ध्यान में रखते हुए बड़े शहरी क्षेत्र, शहर, नगर या अंतर्वर्ती क्षेत्र या उसके अन्य निर्दिष्ट भाग को एक नगरपालिका क्षेत्र के रूप में गठित कर सकती है।
धारा 44	**राज्य नगरपालिका निगरानी प्राधिकार:** राज्य सरकार नगरपालिका के मुख्य/उप मुख्य पार्षदों/पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, कदाचार, सत्यनिष्ठा के अभाव या अनाचार या कुशासन अथवा बदसलूकी के किसी आरोप की जांच करने के लिए एक लोक प्रहरी की नियुक्ति करेगी।
धारा 65 एवं 66	**कार्यालय के निरीक्षण करने, अभिलेखों की मांग करने इत्यादि की शक्ति:** राज्य सरकार श.स्था.नि. के नियंत्रणाधीन किसी भी कार्यालय के निरीक्षण करने या अभिलेखों की मांग करने हेतु पदाधिकारी को नियुक्त कर सकती है।
धारा 87	**हस्तक का निर्माण:** राज्य सरकार नगरपालिकाओं में सभी वित्तीय एवं लेखांकन मामले व प्रक्रियाओं के विवरण से युक्त एक्रुअल आधारित द्वि–प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु एक हस्तक यथा: बिहार नगरपालिका लेखा हस्तक तैयार कर इसका संधारण करेगी।
धारा 419	**नियम बनाने की शक्ति:** राज्य सरकार, राज्य विधायिका के अनुमोदन के अध्यधीन, अधिसूचना द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
धारा 421 एवं 423	**विनियम बनाने की शक्ति:** राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नगरपालिका विनियम बना सकती है।
धारा 487	**कठिनाईयों का निवारण:** बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के उपबंधों को कार्यान्वित करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, उस कठिनाई के निराकरण करने के लिए जो भी आवश्यक हो, कर सकती है।

*(**स्रोत**: बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007)*

3.3.2 कार्यों, निधियों व कर्मियों का प्रतिनिधायन

(i) कार्यों का प्रतिनिधायन

74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, श.स्था.नि. को संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 18 विषयों से संबंधित कार्य करने में सक्षम बनाता है। तद्नुसार, बिहार सरकार ने बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में 18 विषयों में से 17 (अग्निशमन सेवाओं को छोड़कर) से संबंधित कार्यों के लिए प्रावधान किए, जिन्हें श.स्था.नि. द्वारा किया जाना था। हालांकि, यह पाया गया कि श.स्था.नि. द्वारा 17 में से केवल 13 कार्य किए जा रहे थे, जबकि शेष चार कार्य/गतिविधियां 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रभावी होने के 28 वर्षों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी संबंधित विभागों द्वारा किए जा रहे थे।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान यह देखा गया कि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन से संबंधित कार्य एक साथ श.स्था.नि., बुडको एवं पी.एच.ई.डी. को सौंपे गए थे। इससे पता चलता है कि कार्यों का ओवरलैपिंग अभी भी बना हुआ है।

कार्यों के प्रतिनिधायन के संबंध में विभाग ने बताया (नवंबर 2021) कि: (i) इन चार कार्यों/गतिविधियों को वांछित मानवबल की भर्ती के बाद लागू किया जाएगा (ii) आवश्यक भर्ती प्रक्रियाधीन है। आगे की प्रगति के संबंध में लेखापरीक्षा को अद्यतन नहीं किया गया (अप्रैल 2023)।

(ii) निधियों का प्रतिनिधायन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 72(3) में यह प्रावधान है कि नगरपालिका के वार्षिक विकास योजना में सम्मिलित किसी योजना के पूर्ण अथवा आंशिक भाग के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार नगरपालिकाओं को अनुदान प्रदान करेगी। केन्द्र/राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को उनके अधिदेशित कार्यों को पूर्ण करने में सहायता करने के लिए विभिन्न शीर्षों, यथा केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग व राज्य योजना, योजना विशिष्ट अनुदान आदि के अंतर्गत निधियाँ प्रदान की थीं।

केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग व राज्य योजना आदि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2020–21 के दौरान निर्गत निधियों का ब्यौरा **तालिका 3.3** में दिया गया है:

तालिका 3.3

केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग व केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत विमुक्त अनुदान

क्रम सं0	अनुदान शीर्ष	वित्तीय वर्ष	विमुक्त राशि (₹ करोड़ में)
1.	15वी वित्त आयोग	2020-2021	1,412.00
2.	पंचम राज्य वित्त आयोग	2015-16 से 2020-21	5,729.27
3.	स्मार्ट सिटी	2015-16 से 2020-21	952.00
4.	स्वच्छ भारत मिशन	2015-16 से 2020-21	1,009.36
5.	अटल मिशन ऑफ रेजूवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमरूत)	2015-16 से 2020-21	1,616.47
6.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.)	2015-16 से 2019-20	248.92

*(**स्रोत**: षष्ठम राज्य वित्त आयोग प्रतिवेदन एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के आवंटन पत्र)*

इसके अलावा, विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत श.स्था.नि. को जारी अनुदान का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था (अप्रैल 2023)।

आगे, यह पाया गया कि अपनी स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की सरकारी अनुदान पर निर्भरता बढ़ रही थी, जैसा कि श.स्था.नि. की स्व-प्राप्तियों व विभाग द्वारा स्थापना पर व्यय के अनुमान से परिलक्षित होता है।

(iii) कर्मियों का प्रतिनिधायन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 36 में श.स्था.नि. के लिए कई पदों का प्रावधान किया गया था, परन्तु इनमें से अधिकांश पद रिक्त थे। विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना (मई 2023) के अनुसार प्रशासनिक एवं तकनीकी पदों के लिए स्वीकृत बल के विरूद्ध कार्यरत बल को **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4

प्रशासनिक व तकनीकी पदों के स्वीकृत बल के विरूद्ध कार्यरत बल

क्रम सं.	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति	रिक्ति की प्रतिशतता
प्रशासनिक पद					
(i)	नगर आयुक्त	18	18	00	0
(ii)	उप नगर आयुक्त	55	21	34	62
(iii)	कार्यपालक पदाधिकारी	253	155	98	39
(iv)	नगर प्रबंधक	391	62 (3 नियमित एवं 59 अनुबंध पर)	329	84
उप–योग (क)		**717**	**256**	**461**	**64**
तकनीकी पद					
(v)	मुख्य अभियंता	**07**	**02**	**05**	**71**
(vi)	अधीक्षण अभियंता	23 (सिविल) + 02 (यांत्रिक) = 25	14 (सिविल)	11	44
(vii)	कार्यपालक अभियंता	93 (सिविल) + 06 (यांत्रिक) + 12 (विद्युत) =111	36 (सिविल) + 04 (यांत्रिक) + 01 (विद्युत) = 41	70	63
(viii)	सहायक अभियंता	237 (सिविल) + 68 (यांत्रिक) + 06 (विद्युत) =311	92 (सिविल) + 31 (यांत्रिक) + 02 (विद्युत) = 125	186	60
(ix)	कनीय अभियंता	486 (सिविल) + 70 (यांत्रिक) + 50 (विद्युत) = 606	67 (सिविल) + 08 (यांत्रिक) + 00 (विद्युत) = 75	531	87
उप–योग (ख)		**1,060**	**257**	**803**	**76**
कुल योग (क+ख)		**1,777**	**513**	**1,264**	

***(स्रोत** : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना)*

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शहरी स्थानीय निकायों के लिए 717 प्रशासनिक पद स्वीकृत किए गए थे जिनमें से केवल 256 पद भरे गए थे और 461 पद (64 प्रतिशत) रिक्त थे, जबकि 1,060 स्वीकृत तकनीकी पदों में से केवल 257 पद भरे गए थे और 803 पद (76 प्रतिशत) रिक्त थे।

षष्ठम राज्य वित्त आयोग ने भी उल्लेख किया है कि राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के नियंत्रणाधीन मानवबल अधिदेशित कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए निहायत ही अपर्याप्त थे।

3.4 विभिन्न समितियों का गठन

3.4.1 सशक्त स्थायी समिति

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 21 एवं 22 में यह प्रावधान है कि (i) प्रत्येक नगरपालिका में एक सशक्त स्थायी समिति (ई.एस.सी.) होगी, (ii) नगरपालिका की कार्यकारी शक्तियां ई.एस.सी. में निहित होंगी तथा (iii) मुख्य पार्षद् ऐसी शक्तियों एवं कार्यों का प्रयोग करेंगे जैसा ई.एस.सी. द्वारा उन्हें सौंपा गया हो। सशक्त स्थायी समिति की संरचना को **तालिका 3.5** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.5

सशक्त स्थायी समिति

श.स्था.नि. की श्रेणी	पीठासीन पदाधिकारी	ई.एस.सी. की संरचना
नगर निगम	महापौर	महापौर, उप–महापौर एवं सात अन्य पार्षद्
श्रेणी 'क' अथवा 'ख' नगर परिषद्	नगर सभापति	नगर सभापति, नगर उपसभापति एवं पाँच अन्य पार्षद्
श्रेणी 'ग' नगर परिषद्	नगर सभापति	नगर सभापति, नगर उपसभापति एवं तीन अन्य पार्षद्
नगर पंचायत	नगर अध्यक्ष	नगर अध्यक्ष, नगर उपाध्यक्ष एवं तीन अन्य पार्षद्

*(**स्रोत**: बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 21)*

सशक्त स्थायी समिति सामूहिक रूप से नगर निगम, नगर परिषद् व नगर पंचायत, जैसा भी मामला हो, के प्रति उत्तरदायी है। सशक्त स्थायी समिति के गठन पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने जवाब दिया (जनवरी 2022) कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 21 के आलोक में, राज्य के सभी नगरपालिकाओं में सशक्त स्थायी समिति का गठन कर लिया गया था।

3.4.2 नगरपालिका लेखा समिति

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 98 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका प्रत्येक वर्ष अपनी पहली बैठक में या तत्पश्चात् यथाशीघ्र किसी भी बैठक में, एक नगरपालिका लेखा समिति का गठन करेगी। समिति के महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं :

- नगरपालिका द्वारा अपने व्यय के लिए प्रदान की गई राशियों के विनियोग व वार्षिक वित्तीय लेखाओं को दर्शाते हुए नगरपालिका के लेखाओं की जांच करना;
- बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा नगरपालिका के लेखाओं पर प्रतिवेदन की जांच व संवीक्षा करना; तथा
- लेखापरीक्षक व आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा जारी प्रत्येक प्रतिवेदन के बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट की समीक्षा व अनुमोदन करना।

श.स्था.नि. में नगरपालिका लेखा समिति के गठन के संबंध में परियोजना पदाधिकारी –सह–अपर निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग ने बताया (जनवरी 2022) कि श.स्था.नि. में नगरपालिका लेखा समिति का गठन नहीं किया गया था। हालांकि, नगरपालिका लेखा समितियों का गठन नहीं होने का कारण नहीं बताया गया। आगे की प्रगति के संबंध में लेखापरीक्षा को अद्यतन नहीं किया गया (अप्रैल 2023)।

नगरपालिका लेखा समितियों के गठन नहीं होने के कारण नगरपालिकाओं के लेखाओं की आवश्यक जांच सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

3.4.3 विषय समिति

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 32 में यह प्रावधान है कि नगर निगम अथवा श्रेणी 'क' नगर परिषद् (क) जलापूर्त्ति, जल निकासी व सीवरेज एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (ख) शहरी पर्यावरण प्रबंधन व भू–उपयोग नियंत्रण तथा (ग) स्लम उन्नयन व शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं से संबंधित मामलों से निपटने के लिए समय–समय पर पार्षदों को शामिल करते हुए एक विषय समिति का गठन कर सकती है। विषय समिति की अनुशंसाओं को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है।

नगर विकास एवं आवास विभाग ने बताया (जनवरी 2022) कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 32 के आलोक में गठित होने वाली विषय समितियों का गठन नहीं किया गया था। हालांकि, विषय समिति का गठन न किए जाने का कारण नहीं बताया गया। आगे की प्रगति के संबंध में लेखापरीक्षा को अद्यतन नहीं किया गया (अप्रैल 2023)।

विषय समिति का गठन न होने के कारण समितियों को सौंपे जाने वाले कार्यों/मामलों के संबंध में विशेष सलाह/अनुशंसाएं सशक्त स्थायी समिति को अनुपलब्ध रहीं।

3.4.4 वार्ड्स समिति

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा 30 में यह प्रावधान है कि तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक नगर निगम, पार्षदों के चुनाव के बाद अपनी पहली बैठक में या उसके तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सके, निगम के वार्डों को इस तरह समूहीकृत करें कि प्रत्येक समूह में कम से कम तीन वार्ड हों व ऐसे प्रत्येक समूह के लिए एक वार्ड्स समिति का गठन करे। प्रत्येक वार्ड्स समिति में समूह का गठन करने वाले वार्डों से चुने गए पार्षदों को शामिल किया जाना है।

सशक्त स्थायी समिति के सामान्य पर्यवेक्षण व नियंत्रण के अधीन रहते हुए वार्ड्स समिति से, आपूर्ति–पाईप व जल निकास एवं परिसर से सीवरेज कनेक्शन; सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर वर्षा व अन्य वजहों से हुए जलजमाव को हटाना; ठोस अपशिष्टों का संग्रहण व निवारण; कीटाणुशोधन; स्वास्थ्य प्रतिरक्षण सेवाओं; स्लम सेवाओं का प्रावधान; प्रकाश–व्यवस्था का प्रावधान इत्यादि से संबंधित नगरपालिका कार्यों का वार्डों के समूह के स्थानीय सीमाओं के अंदर निर्वहन करने की अपेक्षा की गई थी। हालांकि, षष्ठम राज्य वित्त आयोग ने पाया था कि राज्य में वार्ड्स समितियां कार्यशील नहीं थीं।

इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग ने जवाब दिया (जनवरी 2022) कि शहरी स्थानीय निकायों में वार्ड्स समिति का गठन नहीं किया गया था। हालांकि, विभाग द्वारा वार्ड्स समिति का गठन न किए जाने का कारण नहीं बताया गया। आगे की प्रगति के संबंध में लेखापरीक्षा को अद्यतन नहीं किया गया (अप्रैल 2023)।

3.5 लेखापरीक्षा व्यवस्था

3.5.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 91(1) में प्रावधान है कि विशेष निधियों के लेखाओं सहित, यदि कोई हो, वित्तीय विवरणी एवं बैलेंस शीट में निहित लेखाओं की जांच व लेखापरीक्षा, निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा (डी.एल.एफ.ए.) अथवा समतुल्य प्राधिकार या पेशेवर सनदी लेखाकार के पैनल से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हुए लेखापरीक्षक के द्वारा किया जाएगा। आगे, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (2014 में संशोधित) की धारा 91(2) के अनुसार (i) श.स्था.नि. के लेखाओं के समुचित संधारण एवं लेखाओं के अंकेक्षण पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक, तकनीकी मार्गदर्शन व सहयोग (टी.जी.एस.) प्रदान करेंगे (ii) टी.जी.एस. के आधार पर तैयार

वार्षिक प्रतिवेदन को नगरपालिका के सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा जाएगा तथा (iii) भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक उक्त प्रतिवेदन को स्व–विवेक से राज्य विधानमंडल के समक्ष रख सकते हैं।

निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के रूप में कार्य करने हेतु राज्य सरकार ने महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार कार्यालय के स्थानीय लेखापरीक्षक को प्राधिकृत किया (नवंबर 2007)। तद्नुसार, स्थानीय निकायों (स्था.नि.) के लेखाओं की लेखापरीक्षा हेतु टी.जी.एस. प्रणाली को अपनाए (दिसंबर 2016) जाने तक, श.स्था.नि. के लेखापरीक्षा को स्थानीय लेखापरीक्षक द्वारा संचालित किया गया।

आगे, केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा हेतु वित्त विभाग, बिहार सरकार के अधीन मुख्य लेखा नियंत्रक–सह–निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय की अध्यक्षता में स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय के गठन की अधिसूचना जारी की (जून 2015)। यह निदेशालय तब से (11 जून 2015 से) कार्यशील है। लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 में प्रावधानित टी.जी.एस. व्यवस्था के तहत स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा कि लिए दिसंबर 2015 में बिहार सरकार द्वारा नियम व शर्त्तें स्वीकृत की गईं एवं बाद में टी.जी.एस. के तहत स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा सी.ए.जी. द्वारा जनवरी 2017 से प्रारम्भ की गई। परिणामतः, जनवरी 2017 से डी.एल.एफ.ए. स्थानीय निकायों के लिए प्राथमिक बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत है।

3.5.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

ग्यारहवें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि: (i) लेखाओं के समुचित संधारण पर नियंत्रण व पर्यवेक्षण करने का दायित्व सी.ए.जी. को सौंपा जाय तथा (ख) स्थानीय निकायों के सभी श्रेणियों/स्तरों की लेखापरीक्षा हेतु उनका वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ–साथ, डी.एल.एफ.ए के वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

वित्त विभाग, बिहार सरकार ने महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सूचित किया (दिसंबर 2015) कि राज्य सरकार ने टी.जी.एस. व्यवस्था के तहत स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के तहत मानक नियम व शर्त्तों को स्वीकार कर लिया है। फलस्वरुप, राज्य में टी.जी.एस. व्यवस्था के तहत लेखापरीक्षा जनवरी 2017 से प्रारंभ हुई। टी.जी.एस. व्यवस्था के तहत महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 28 श.स्था.नि. इकाईयों[24] का लेखापरीक्षा किया।

3.6 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया

3.6.1 महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों पर असंतोषप्रद प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) की एक प्रति बिहार सरकार के संबंधित विभाग सहित लेखापरीक्षित इकाईयों को प्रेषित की जानी थी। संबंधित लेखापरीक्षित इकाईयों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों को (i) नि.प्र. में शामिल लेखापरीक्षा टिप्पणियों का जवाब देना था तथा (ii) नि.प्र. की प्राप्ति तिथि से तीन माह के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों ने नि.प्र. में शामिल लेखापरीक्षा टिप्पणियों का अनुपालन हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाया जो वर्ष–दर–वर्ष लंबित लेखापरीक्षा कंडिकाओं की बढ़ती संख्या से स्पष्ट था। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग, बिहार सरकार ने (मार्च 2010) लेखापरीक्षा कंडिकाओं की समीक्षा/अनुपालन के लिए

[24] *नगर निगम (05), नगर परिषद् (21) एवं नगर पंचायत (02)*

त्रि–स्तरीय यथा–उच्च स्तरीय, विभाग स्तरीय व जिला स्तरीय समितियों का गठन किया। परन्तु, विगत तीन वर्षों से अर्थात 2019–20 से 2021–22 तक, जिला स्तरीय समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। यह लेखापरीक्षा कंडिकाओं का अनुपालन न होने के कारणों में से एक था। विगत पाँच वित्तीय वर्षों के लेखापरीक्षा कंडिकाओं के निपटान की स्थिति (मार्च 2023 तक) **तालिका 3.6** में दी गई है:

तालिका 3.6

विगत पाँच वित्तीय वर्षों (2017–18 से 2021–22) में लंबित लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	नि.प्र. की सं.	नि.प्र. में कंडिकाओं की सं.	सम्मिलित राशि	निपटारित कंडिकाओं की सं.	निपटान की राशि	लंबित कंडिकाओं की सं.	लंबित कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 (3-5)**	**8 (4-6)**
2017-18	32	884	957.61	315	3.36	569	954.25
2018-19	31	644	383.46	4	0.086	640	383.37
2019-20	27	826	731.90	1	0.0072	825	731.89
2020-21	01	58	536.36	0	0	58	536.36
2021-22	28	474	1,488.97	0	0	474	1,488.97
कुल	**119**	**2,886**	**4,098.30**	**320**	**3.4532**	**2,566**	**4,094.85**

*(**स्रोत**: श.स्था.नि. का निरीक्षण प्रतिवेदन)*

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 119 नि.प्र. में शामिल कुल 2,886 लेखापरीक्षा कंडिकाओं में से केवल 320 कंडिकाओं (11 प्रतिशत) का निपटान किया गया था, जबकि ₹ 4,094.85 करोड़ की 2,566 कंडिकाएँ (मार्च 2023 तक) लंबित पड़ी हुई थीं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन में कार्रवाई की कमी, गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के बने रहने के जोखिमों से युक्त थी, जैसा की इन प्रतिवेदनों में बताया गया है।

3.6.2 स्थानीय लेखापरीक्षक एवं सी.ए.जी. के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

बिहार में स्थानीय लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2013-14 तक की अवधि के लिए तैयार किए गए थे व तदुपरांत, वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 की अवधि हेतु स्थानीय निकायों पर सी.ए.जी. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को तैयार किया गया था। इसके बाद, वित्तीय वर्ष 2017–19 के लिए पहला वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया गया व राज्य के राज्यपाल को सौंपा गया था। प्रतिवेदन को राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था (16 दिसंबर 2022)। 2019–20 एवं 2020–21 की अवधि के लिए वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं (जुलाई 2023)।

(i) स्थानीय लेखापरीक्षक का वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वित्त विभाग, बिहार सरकार ने स्थानीय लेखापरीक्षक द्वारा तैयार वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा/अनुपालन हेतु त्रि–स्तरीय समितियों यथा–उच्च स्तरीय, विभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय का गठन (मार्च 2010) किया था। जिला स्तरीय समिति[25] का उत्तरदायित्व, जिले के शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा कंडिकाओं/प्रतिवेदनों के अनुपालन को सुनिश्चित करना था। विभाग स्तरीय समिति[26] को जिला

[25] *जिलाधिकारी/उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में*

[26] *प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में*

स्तरीय समितियों द्वारा किए गए अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करनी थी जबकि जिला स्तरीय एवं विभाग स्तरीय समितियों के कार्यकलापों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति[27] की बैठक छः महीने में एक बार होनी थी।

हालांकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान जिला स्तरीय समिति की कोई भी बैठक (प्रस्तावित 57 बैठकों[28] के विरूद्व) आयोजित नहीं की गई थी। इस प्रकार, स्थानीय लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में निहित लेखापरीक्षा कंडिकाओं का निपटान नहीं हो पाया। आगे, वित्तीय वर्ष 2021–22 से अप्रैल 2023 तक के दौरान विभाग स्तरीय एवं उच्च स्तरीय समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। उच्च स्तरीय समिति व विभाग स्तरीय समिति की अंतिम बैठकें क्रमशः अगस्त 2013 व जुलाई 2015 में आयोजित हुई थीं।

इस प्रकार, इन तीन स्तरीय समितियों के गठन का उद्देश्य विफल हो गया एवं स्था.ले.प. की वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दिया गया।

(ii) सी.ए.जी. के स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन का अनुपालन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (जनवरी 2014 में यथा संशोधित) की धारा 91 (2) में निहित प्रावधानों के अनुसार सी.ए.जी. द्वारा तैयार किए गए श.स्था.नि. के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखा जायेगा।

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के स्थानीय निकायों पर प्रथम सी.ए.जी. प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल के पटल पर 4 अप्रैल 2016 को रखा गया। प्रतिवेदन की पाँच कंडिकाओं पर अप्रैल 2016 से फरवरी 2023 के दौरान हुए लोक लेखा समिति की 16 बैठकों में चर्चा की गई परन्तु किसी भी लेखापरीक्षा टिप्पणी का निपटान (मार्च 2023 तक) नहीं किया गया।

आगे, मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष हेतु स्थानीय निकायों पर सी.ए.जी. प्रतिवेदन को राज्य विधान मंडल के पटल पर 23 अगस्त 2017 को रखा गया। लेकिन, प्रतिवेदन की किसी भी कंडिका पर मार्च 2023 तक चर्चा नहीं की गई।

3.7 जवाबदेही तंत्र

3.7.1 लोकप्रहरी (लोकपाल)

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 44(1), श.स्था.नि. के प्राधिकारियों के भ्रष्टाचार, सत्यनिष्ठा का अभाव, कदाचार इत्यादि के किसी आरोप की जांच करने के लिए लोकप्रहरी (लोकपाल) की नियुक्ति का प्रावधान करती है। अधिनियम के अनुसार, लोकप्रहरी (लोकपाल) की नियुक्ति के लिए योग्यता, शर्त्तें व नियम एवं नियुक्ति की अवधि तथा लोकप्रहरी (लोकपाल) के अधिकार व कर्तव्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी। 13वीं वित्त आयोग व पंचम राज्य वित्त आयोग ने भी स्था.नि. के लिए एक स्वंतत्र लोकप्रहरी (लोकपाल) की नियुक्ति की अनुशंसा की थी। आगे, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने बिहार में श.स्था.नि. के लिए ''लोक प्रहरी (लोकपाल)'' की नियुक्ति के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार सरकार को एक पत्र जारी किया (फरवरी 2018) था।

नगर विकास एवं आवास विभाग ने बताया (अप्रैल 2022) कि लोक प्रहरी की नियुक्ति अभी प्रक्रियाधीन है। आगे की प्रगति के संबंध में लेखापरीक्षा को अद्यतन नहीं किया गया (अप्रैल 2023)।

---

[27] *वित्त विभाग, बिहार सरकार के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एवं प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) एक सदस्य के रूप में*

[28] *सात जिलों ने कुल 57 जिला स्तरीय समिति की बैठकों का प्रस्ताव दिया था जो इस प्रकार हैं: अरवल–14, बिहारशरीफ–09, गोपालगंज–01, जमुई–12, कैमूर–09, किशनगंज–09, समस्तीपुर–03*

3.7.2 सामाजिक अंकेक्षण

जन सहभागिता के माध्यम से परियोजनाओं, कानूनों व नीतियों के कार्यान्वयन में सार्वजनिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना सामाजिक अंकेक्षण का मूल उद्देश्य है। पंचम राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि स्लम व गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य करने के साथ ही शहरी स्थानीय निकायों में उत्तरदायित्व के उपाय के रूप में सामाजिक अंकेक्षण का संचालन कराया जाय। षष्ठम राज्य वित्त आयोग ने भी यह अनुशंसा की थी कि शहरी स्थानीय निकायों में सामाजिक अंकेक्षण प्रारम्भ किया जाय।

हालांकि, श.स्था.नि. द्वारा (नवंबर 2021 तक) कार्यान्वित योजनाओं का कोई सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया था। नगर विकास एवं आवास विभाग ने सामाजिक अंकेक्षण नहीं कराने का कोई कारण नहीं बताया। आगे की प्रगति के संबंध में लेखापरीक्षा को अद्यतन नहीं किया गया (अप्रैल 2023)।

3.7.3 संपत्ति कर बोर्ड

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 138(A) में संपत्ति कर के निर्धारण, संग्रहण व वसूली को इष्टतम बनाने हेतु स्वतंत्र एवं पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए एक राज्य स्तरीय संपत्ति कर बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। 13वीं वित्त आयोग ने भी संपत्ति कर के निर्धारण हेतु एक स्वतंत्र एंव पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने में श.स्था.नि. को सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तरीय संपत्ति कर बोर्ड की स्थापना की अनुशंसा की थी।

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने बिहार संपत्ति कर बोर्ड नियमावली, 2013 बनाया व अधिसूचित (मई 2013) किया था, जिसने संपत्ति कर बोर्ड के गठन को आवश्यक बना दिया। हालांकि, बोर्ड का गठन (नवंबर 2021 तक) नहीं किया गया था। नगर विकास एवं आवास विभाग ने जवाब दिया (नवंबर 2021) कि समुचित कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आगे की प्रगति के संबंध में लेखापरीक्षा को अद्यतन नहीं किया गया (अप्रैल 2023)।

संपत्ति कर बोर्ड नियमों के बनने के दस वर्ष बीत जाने के बाद भी, संपत्ति कर बोर्ड का गठन न होने के कारण, कर दायरा बढ़ाने व श.स्था.नि. में संपत्ति कर के संग्रह व वसूली को इष्टतम नहीं किया जा सका। आगे, प्रत्येक श.स्था.नि. के कार्य–निष्पादन का सतत् आधार पर मूल्यांकन, जैसा कि परिकल्पित था, नहीं किया जा सका।

3.7.4 फायर हजार्ड रिस्पाँस

13वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार दस लाख से अधिक (2001 की जनगणना) की जनसंख्या वाले सभी नगर निगमों को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्रों के लिए फायर हजार्ड रिस्पाँस व मिटिगेशन प्लान करना आवश्यक था। 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार में मात्र एक श.स्था.नि. (पटना नगर निगम) की जनसंख्या दस लाख से अधिक थी।

पटना नगर निगम के लिए, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने फायर हजार्ड रिस्पाँस एंड मिटिगेशन प्लान को अधिसूचित (मार्च 2011) किया था। पटना नगर निगम में फायर हजार्ड रिस्पाँस एंड मिटिगेशन प्लान के कार्यकलाप व कार्यान्वयन पर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम ने जवाब दिया (अप्रैल 2019) कि यथाशीघ्र आवश्यक अनुपालन किया जाएगा। लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किए जाने पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने कहा (नवंबर 2021) कि समुचित कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी। आगे की प्रगति के संबंध में लेखापरीक्षा को अद्यतन नहीं किया गया (अप्रैल 2023)।

3.7.5 उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण

बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 342 (1) प्रावधानित करता है कि अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों (यू.सी.) को अनुदान प्राप्ति के 18 माह के अंदर अनुदेयी संस्थानों को समर्पित

किया जाना है। श.स्था.नि. को विमुक्त हुए अनुदानों के आवंटन पत्रों में निहित निर्देशों के अनुसार, आगे के अनुदान विमुक्ति में होने वाले विलंब से बचने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) सामयिक रूप से राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना द्वारा संकलित यू.सी. से संबंधित आँकड़ों के आधार पर यह पाया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2021–22 की अवधि के दौरान ₹ 31,564.70 करोड़ के सहायक अनुदान की स्वीकृति दी थी, जिसके विरूद्ध ₹ 19,445.30 करोड़ के यू.सी. समर्पित किए गए जबकि ₹ 12,119.42 करोड़ (38 प्रतिशत) के यू.सी. समायोजन हेतु लंबित पड़े थे (मार्च 2023), जैसा कि **तालिका 3.7** में दिया गया है:

तालिका 3.7
लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रतिशतता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र	समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रतिशत
2003-04 से 2021-22	31,564.70	19,445.30	12,119.42	38

*(**स्रोत:** महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार का कार्यालय)*

लंबी अवधि से वृहत् तौर पर यू.सी. का लंबित रहना कमजोर आंतरिक नियंत्रण व खराब निगरानी व्यवस्था का द्योतक था एवं यह निधियों के दुरूपयोग की संभावित जोखिम से युक्त था।

3.7.6 आंतरिक लेखापरीक्षा व लेखाओं का संधारण

(i) आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग ने वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 के लिए 140 नगरपालिकाओं के लेखाओं के आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु 17 सी.ए. को नियुक्त किया (अप्रैल 2016) था। वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए, विभाग द्वारा इस उद्देश्य हेतु छः सी.ए. फर्मों (जनवरी 2019) को नियुक्त किया गया था। श.स्था.नि. के लेखाओं की लेखापरीक्षा सितंबर 2020 तक पूरी की जानी थी। मई 2023 तक लेखापरीक्षा की स्थिति **तालिका 3.8** में दी गई है:

तालिका 3.8
सी.ए. फर्मों द्वारा लेखापरीक्षित इकाईयाँ व समर्पित प्रतिवेदन

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	किये जाने वाले लेखापरीक्षाओं की संख्या	लेखापरीक्षा संपन्न	सी.ए. फर्मों द्वारा समर्पित प्रतिवेदन	अपलोडेड प्रतिवेदनों की संख्या
1.	2017-18	141	141	141	141
2.	2018-19	141	141	141	141
3.	2019-20	141	104	104	104
4.	2020-21	46	46	45	45
5.	2021-22	46	43	25	25
	कुल	**515**	**475**	**456**	**456**

*(**स्रोत:** नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना)*

पिछले तालिका से यह स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान होने वाले 515 आंतरिक लेखापरीक्षाओं में से वास्तव में 475 आंतरिक लेखापरीक्षा ही संपन्न किये गये एवं केवल 456 प्रतिवेदन ही अंततः अपलोड हुए (मई 2023 तक)।

(ii) श.स्था.नि. द्वारा द्वि–प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली के तहत लेखाओं का संधारण

श.स्था.नि. द्वारा एक्रुअल आधारित लेखाओं के संधारण हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने सी.ए.जी. के परामर्श से राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा हस्तक तैयार किया

था (2004)। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 86, 87 एवं 88 में यह प्रावधान है कि (i) राज्य सरकार, एक्रुअल आधारित द्वि–प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली को लागू करने हेतु नगरपालिका लेखा हस्तक तैयार करेगी तथा (ii) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी वर्ष की समाप्ति के चार माह के अंदर पूर्ववर्ती वर्ष के लिए एक वित्तीय विवरणों को तैयार करेगा जिसमें रोकड़ प्रवाह विवरणी, आय–व्यय लेखा, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा तथा एक तुलन–पत्र शामिल होंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2014 के प्रभाव से नगरपालिकाओं में एक्रुअल आधारित द्वि–प्रविष्टि प्रणाली के आधार पर वित्तीय विवरणों की तैयारी और रखरखाव के लिए 'बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014' अधिसूचित किया (जनवरी 2014)। यह नियमावली शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा हस्तक (एन.एम.ए.एम.) पर आधारित थी।

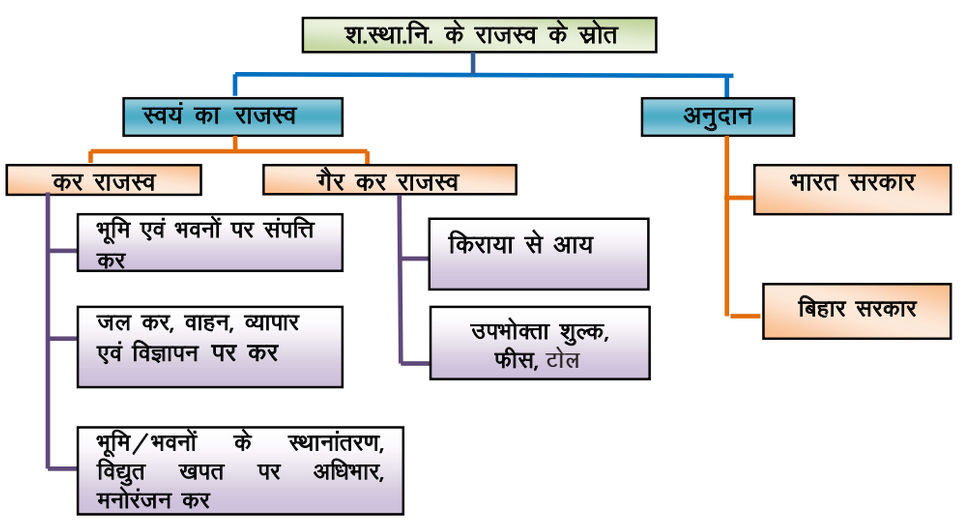
द्वि–प्रविष्टि लेखा प्रणाली के कार्यान्वयन की वर्त्तमान स्थिति के विषय में विभाग ने बताया (मई 2023) कि कुल 261 श.स्था.नि. में से द्वि–प्रविष्टि लेखा प्रणाली में लेखाओं का पूर्ण कार्यान्वयन केवल 63 श.स्था.नि. में किया गया था, जबकि 76 श.स्था.नि. में इसे आंशिक रूप से लागू किया गया था एवं शेष 122 श.स्था.नि. में इसे प्रारंभ नहीं किया गया था।

3.8 वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित मामले

3.8.1 निधियों के स्रोत

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 उन करों को सूचीबद्ध करता है, जिन्हें नगरपालिकाएं राजस्व बढ़ाने के लिए अधिरोपित कर सकती हैं। नगरपालिकाएं, अधिनियम में उल्लिखित विभिन्न सेवाओं को प्रदान करने के लिए, अतिरिक्त रूप से उपभोक्ता शुल्क लगा सकती हैं। इसके अलावा, भवन योजनाओं की स्वीकृति, भूमि के उपयोग के लिए नगरपालिका लाइसेंस आदि पर भी शुल्क व जुर्माना लगाया जा सकता है। बिहार नगरपालिका अधिनियम, केन्द्रीय वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर नगरपालिकाओं के लिए सहायता अनुदान का प्रावधान करता है। श.स्था.नि. के निधियों के स्रोतों को **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: निधियों के स्रोत



(**स्रोत:** *बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127 एवं आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार सरकार*)

3.8.2 राज्य बजट आवंटन की तुलना में व्यय

वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग (श.स्था.नि. सहित) हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए बजट प्रावधान, भारत सरकार की योजनाओं के लिए राज्य का अंश व केन्द्रीय वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्राप्त अनुदान **तालिका 3.9** में दिए गए हैं:

तालिका 3.9
बजट आवंटन की तुलना में व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम.सं.	विवरण	शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
	1	2	3	4	5	6	7	8 (3 से 7)
1.	बजटीय आवंटन	राजस्व	5,047.93	5,361.29	6,235.04	9,343.20	10,031.62	36,019.08
		पूँजीगत	0.00	3.00	160.00	250.00	1,550.00	1,963.00
		कुल	**5,047.93**	**5,364.29**	**6,395.04**	**9,593.20**	**11,581.62**	**37,982.08**
2.	व्यय	राजस्व	3,236.04	3,297.02	2,984.53	5,590.39	5,883.84	20,991.82
		पूँजीगत	0.00	3.00	160.00	50.00	1,057.59	1270.59
		कुल	**3,236.04**	**3,300.02**	**3,144.53**	**5,640.39**	**6,941.43**	**22,262.41**
3.	बचत (1-2)		**1,811.89**	**2,064.27**	**3,250.51**	**3,952.81**	**4,640.19**	**15,719.67**
4.	बचत की प्रतिशतता		**36**	**38**	**51**	**41**	**40**	

*(**स्रोत**: बिहार सरकार के विनियोजन लेखे)*

पूर्ववर्त्ती **तालिका** से यह स्पष्ट है कि नगर विकास एवं आवास विभाग अपने संपूर्ण बजटीय आवंटन का उपयोग नहीं कर सका तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान बचत की प्रतिशतता 36 प्रतिशत से 51 प्रतिशत के बीच थी। इसके अतिरिक्त, यद्यपि पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत कुल आवंटन, वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान हुए कुल आवंटन का 5.2 प्रतिशत था, तथापि इसका पूर्ण उपयोग नहीं किया गया था।

3.8.3 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा

भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होने वाली पाँच वित्तीय वर्षों की अवधि हेतु अनुशंसा करने के लिए 15वीं वित्त आयोग का गठन (27 नवंबर 2017) किया था। आयोग ने अपना प्रतिवेदन दो भागों में प्रस्तुत किया (i) दिसंबर 2019 में, केवल वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अंतरिम प्रतिवेदन (ii) नवंबर 2020 में, वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 के लिए मुख्य प्रतिवेदन। 15वीं वित्त आयोग ने श.स्था.नि. के लिए अनुदानों को दो श्रेणियों में विभाजित करने की अनुशंसा की थी: (क) मिलियन प्लस शहरी समूह/शहर तथा (ख) दस लाख से कम जनसंख्या वाले अन्य सभी शहर व नगर। गैर मिलियन प्लस शहरों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान असंबद्ध थे तथा शेष 50 प्रतिशत पेयजल व स्वच्छता के लिए समान अंश के साथ संबद्ध थे। आयोग ने श.स्था.नि. के लिए 2020–21 में किसी भी शर्त की अनुशंसा नहीं की थी परन्तु बाद के वर्षों में अनुदान जारी करने के लिए दो प्रारंभिक शर्तों की अनुशंसा की थी: (i) अपने राजस्व में सुधार करने हेतु संपत्ति कर की न्यूनतम दरों को अधिसूचित करना एवं (ii) लेखापरीक्षित लेखाओं को समय पर जमा करना। 15वीं वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु बिहार के श.स्था.नि. के लिए ₹ 2,416.00 करोड़[29] के अनुदान की अनुशंसा की। बिहार को भारत सरकार से ₹ 2,416.00 करोड़ (25 मार्च 2021 तक गैर–मिलियन शहरों के लिए ₹ 2,008 करोड़ व 31 मार्च 2021 तक मिलियन प्लस शहरों के लिए ₹ 408 करोड़) का अनुदान प्राप्त हुआ तथा मई 2020 से अप्रैल 2021 के दौरान इसे श.स्था.नि. को जारी किया गया।

[29] *मिलियन प्लस शहरी अनुदान– ₹ 408.00 करोड़, गैर–मिलियन प्लस शहरी अनुदान– ₹ 2,008.00 करोड़*

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान भारत सरकार ने श.स्था.नि. के लिए ₹ 1,827 करोड़ की अनुशंसित राशि के विरुद्ध राज्य सरकार को ₹ 836.25 करोड़ की राशि जारी की। इस प्रकार, राज्य अपना पूरा हिस्सा प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि उसने अनिवार्य मानदंडों को पूरा नहीं किया।

3.8.4 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के साथ पठित 243 वाई तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 71 में निहित प्रावधानों के अनुसार बिहार सरकार ने राज्य वित्त आयोगों का गठन किया था ताकिः (i) स्था.नि. की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जा सके तथा (ii) राज्य एवं स्थानीय निकायों के बीच करों, शुल्कों आदि की निवल आय के वितरण के लिए सिद्धांतों की अनुशंसा की जा सके।

वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 के लिए बिहार सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के साथ पठित अनुच्छेद 243 वाई एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 71 के आलोक में षष्ठम राज्य वित्त आयोग का गठन (फरवरी 2019) किया। षष्ठम राज्य वित्त आयोग ने दो भागों में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 8 जनवरी 2020 को एक अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा फिर वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2024–25 तक की अवधि के लिए, अप्रैल 2021 में अपना अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। बिहार सरकार द्वारा अंतिम प्रतिवेदन को अगस्त 2021 में स्वीकार किया गया था। षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2024–25 तक की अवधि में श.स्था.नि. को ₹ 10,457 करोड़ हस्तांतरित की जानी थी, जैसा कि **तालिका 3.10** में दिया गया है।

तालिका 3.10

श.स्था.नि. को विमुक्त किए जाने वाले अनुदान एवं प्रतिनिधायन (अनुमानित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुमानित				
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2021-25
स्थानीय निकायों को एस.एफ.सी. द्वारा कुल हस्तांतरण	6,008	7,014	7,883	8,971	29,876
शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरण	2,103	2,455	2,759	3,140	10,457

*(**स्रोतः** षष्ठम राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन)*

इसके अलावा, 2021–22 के दौरान ₹ 3,751.74 करोड़ की कुल प्रावधानित राशि (प्रतिनिधायन– ₹ 1,898.69 करोड़ एवं अनुदान– ₹ 1,853.05 करोड़) में से केवल ₹ 1,125.52 करोड़ (30 प्रतिशत) श.स्था.नि. को आवंटित किए गए थे जबकि षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर 2021–22 से 2024–25 की अवधि के लिए पं.रा.सं. एवं श.स्था.नि. के लिए निधियों के प्रावधान हेतु राज्य सरकार ने 65:35 का फार्मूला अपनाया था।

3.8.5 ए.सी./डी.सी. बिलों से संबंधित मामले

बिहार कोषागार संहिता (बी.टी.सी.), 2011 के नियम 177 में प्रावधानित है कि आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी (डी.डी.ओ.) द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि आकस्मिक बिलों पर निकासी की गई राशि उसी वित्तीय वर्ष में व्यय की जाएगी व अव्ययित राशि वर्ष के 31 मार्च से पहले कोषागार में जमा कर दी जाएगी। आगे, बी.टी.सी., 2011 के नियम 194 के अनुसार: (i) प्रतिहस्ताक्षरित डी.सी. बिल उस माह के बाद, जिसमें ए.सी. बिल का आहरण हुआ था, के छः माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत किया जाएगा व (ii) इस छः माह की अवधि के बाद ए.सी. बिल पर कोई आहरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित डी.सी. बिल जमा न कर दिया गया हो। असमायोजित ए.सी. बिलों का विवरण **तालिका–3.11** में दिया गया है।

तालिका -3.11
समायोजन के लिए लंबित ए.सी. बिलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	ए.सी. बिल से निकासी की गई राशि	समायोजित ए.सी. बिल	असमायोजित ए.सी. बिल	असमायोजित ए.सी. बिलों की प्रतिशतता
2003-04 से 2019-20	51.74	17.46	34.29	66

*(**स्रोत** : नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)*

जैसा कि पूर्ववर्ती तालिका से स्पष्ट है, ₹ 34.29 करोड़ (ए.सी. बिलों के माध्यम से निकासी की गई कुल राशि का 66 प्रतिशत) समायोजन के लिए (मई 2023 तक) लंबित था।

समायोजन/वसूली के लिए लंबे समय से लंबित ए.सी. बिल कमजोर आंतरिक नियंत्रण व खराब निगरानी व्यवस्था के द्योतक थे।

3.8.6 लेखापरीक्षा प्रभाव

12 नमूना जांचित श.स्था.नि[30] में, लेखापरीक्षा ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 5.74 करोड़ की राशि की वसूली का सुझाव दिया था। इसमें से पाँच श.स्था.नि[31] (नवंबर 2022 तक) द्वारा पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, धन प्राप्ति, विविध प्राप्तियाँ व संपत्ति कर के मद में ₹ 5.42 लाख जमा किए गए थे।

[30] ***नगर निगम*** *– भागलपुर एवं गया;* ***नगर परिषद्*** *– औरंगाबाद, जमालपुर, खगड़िया, खगौल, शेरघाटी व तेघरा;* ***नगर पंचायत****– बड़हिया, बिहिया, पीरो व शाहपुर*

[31] ***नगर परिषद्****– जमालपुर (₹ 0.03 लाख), खगड़िया (₹ 3.08 लाख), तेघरा (₹ 0.14 लाख);* ***नगर पंचायत****– बिहिया (₹ 0.15 लाख), बड़हिया (₹ 2.02 लाख)*

अध्याय-IV

अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय - IV
अनुपालन लेखापरीक्षा

नगर विकास एवं आवास विभाग

4.1 ब्याज और जुर्माने का परिहार्य व्यय

कर्मचारी भविष्य निधि में वैधानिक अंशदान का ससमय प्रेषण सुनिश्चित करने में नगर परिषद्, सहरसा की विफलता के फलस्वरूप दंडात्मक शुल्क एवं ब्याज के रुप में ₹1.14 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, सहपठित भविष्य निधि योजना, 1952 की कंडिका 30 और 38 के प्रावधानों के अनुसार, सीधे नियोजित कर्मचारियों के साथ–साथ ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के संबंध में, भविष्य निधि अंशदान के साथ प्रशासनिक शुल्क[32] भुगतान करने की जिम्मेदारी प्रधान नियोक्ता की है। कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) में अंशदान मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता[33] (यदि कोई हो) के कुल योग का दस प्रतिशत होना है। आगे, यह नियोक्ता का कर्तव्य है कि वह ई.पी.एफ. पेंशन योजना और बीमा योजना के लिए कर्मचारी अंशदान/वैधानिक देय राशि की कटौती कर्मचारी के वेतन से करे और वसूली गयी राशि को 15 दिनों के अंदर नियोक्ता के हिस्से के साथ, ई.पी.एफ. योजना 1952 की कंडिका 38 के अनुसार निधि में जमा करे। इसके अलावा, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7Q और 14B में निर्दिष्ट दरो[34] पर, विलंबित प्रेषण पर क्रमशः ब्याज और जुर्माना लगाने का प्रावधान है ।

नगर परिषद्, सहरसा के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2022) में पाया गया कि जनवरी 2016 से नवंबर 2020 एवं जनवरी 2021 की अवधि के लिए, कर्मचारियों के दैनिक वेतन से ई.पी.एफ., कर्मचारी पेंशन योजना एवं बीमा योजना में अंशदान[35], 58 महीने तक के विलंब से, अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान ई.पी.एफ. कार्यालय, भागलपुर द्वारा संधारित ई.पी.एफ. खाते में प्रेषित किया गया। परिणामस्वरूप, ई.पी.एफ. कार्यालय ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत नोटिस (अगस्त 2021) जारी करने के बाद, ₹ 37.60 लाख के ब्याज के साथ नुकसान हेतु ₹ 76.78 लाख का जुर्माना लगाया ***(परिशिष्ट– 4.1)***।

---

[32] *प्रशासनिक शुल्क का अर्थ है वेतन का ऐसा प्रतिशत (मूल वेतन, महंगाई भत्ता, प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो, और उस पर स्वीकार्य खाद्य रियायतों का नकद मूल्य) जो एक बहिष्कृत कर्मचारी के अलावा अन्य कर्मचारियों को देय हो, और जिसके संबंध में भविष्य निधि अंशदान देय है जैसा कि केन्द्र सरकार केंद्रीय बोर्ड के परामर्श से और अपने सामान्य प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए निधि के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करे।*

[33] *प्रतिधारण भत्ता का मतलब किसी कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान के कर्मचारी को किसी भी अवधि के दौरान, जिसमें फर्म काम नहीं कर रही है, उसकी सेवाओं को बनाए रखने के लिए देय भत्ता है।*

[34] *नियोक्ता 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज या ऐसी उच्च दर पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि योजना में निर्दिष्ट किया जा सकता है और ई.पी.एफ. अधिनियम, 1952 के अनुसार क्षति हेतु 5 प्रतिशत (दो महीने से कम विलंब) से लेकर 25 प्रतिशत (छः महीने एवं उससे अधिक के विलंब) तक।*

[35] *नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का अंशदान।*

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के ई.पी.एफ. खातों में अंशदान जमा करने में हुए विलंब के संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए नगर परिषद् को ई.पी.एफ. कार्यालय द्वारा (माह सितंबर 2021 से दिसंबर 2021 तक) कई मौके दिए गए। हालांकि, वह अंशदान के विलंबित प्रेषण के लिए कोई कारण बताने में विफल रहा।

परिणामस्वरूप, नगर परिषद् ने राज्य सरकार से प्राप्त स्टाम्प ड्यूटी से आवंटित राजस्व (नगरपालिका के राजस्व का एक स्रोत) से ई.पी.एफ. कार्यालय को ₹ 1.14 करोड़[36] की दंड राशि का भुगतान (जनवरी 2022) ब्याज एवं जुर्माना के रुप में किया।

नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी ने जवाब में बताया (मई 2022) कि जनवरी 2016 से कर्मचारियों का अंशदान समय–समय पर नगरपालिका बोर्ड की स्वीकृति के बाद ई.पी.एफ. कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि अंशदान ई.पी.एफ. कार्यालय को विलंब से प्रेषित किया गया था, जिसके कारण अंततः ₹1.14 करोड़ की दंड राशि ब्याज और जुर्माना के रुप में लगाया गया।

इस प्रकार, वैधानिक प्रावधानों का पालन करने और ई.पी.एफ. कार्यालय को अंशदान का ससमय प्रेषण सुनिश्चित करने में नगर परिषद् की विफलता के फलस्वरूप ब्याज और जुर्माने के रुप में ₹ 1.14 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया था, परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2023 तक)।

4.2 कपटपूर्ण भुगतान

सौर ऊर्जा संयंत्रों (रूफ टॉप) की आपूर्ति के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लेने वाली एक निजी फर्म को भुगतान करते समय नगर परिषद्, शेखपुरा की जांच करने में विफलता के कारण ₹ 91.14 लाख का फर्जी भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त, तकनीकी बोली में एक पात्र फर्म को अनियमित रुप से अयोग्य घोषित करने के कारण नगर परिषद् को ₹ 1.37 करोड़ की हानि हुई।

बिहार वित्तीय नियमावली (बी.एफ.आर.) के नियम 126 में प्रावधानित है कि सभी प्राधिकारी जिन्हें लोकहित में सामग्रियों के क्रय हेतु वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं, लोक अधिप्राप्ति से संबंधित मामलों में दक्षता, मितव्ययिता, पारदर्शिता लाने हेतु जिम्मेदार एवं उत्तरदायी होगें। आगे, बी.एफ.आर. का नियम 12 निर्धारित करता है कि प्रत्येक नियंत्री पदाधिकारी को न केवल स्वयं को यह आश्वस्त करना चाहिए कि लोक धन एवं सामग्रियों के अपव्यय और हानि से रक्षा के लिए, केवल विभागीय संगठन में सुव्यवस्थित आंतरिक जांच हेतु पर्याप्त उपबंध हैं, बल्कि विहित आंतरिक जांच प्रभावी रूप से कार्यरत हैं। सरकारी ई–मार्केट प्लेस (जेम पोर्टल) के माध्यम से सामग्रियों के क्रय हेतु सामान्य नियम और शर्तों के अनुसार, सूक्ष्म और लघु उद्यम (एम.एस.ई.), जो प्राथमिक उत्पाद श्रेणी के निर्माता हैं या प्राथमिक सेवा श्रेणी के सेवा प्रदाता हैं और उपयुक्त दस्तावेजों के साथ इस आशय की विशिष्ट पुष्टि करते हैं, निविदा प्रस्तुत करने के समय अग्रधन जमा (ई.एम.डी.) करने से मुक्त हैं।

नगर परिषद्, शेखपुरा के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2022) में पता चला कि 40–40 किलोवाट क्षमता के चार 'सौर ऊर्जा संयंत्र (रूफ टॉप) ओ.एन.जी.आर.आई.डी सिस्टम (एस.पी.पी.ओ.एस.) तीन फेज' के क्रय हेतु जिसकी अनुमानित लागत ₹ 2.50 करोड़ थी, जेम पोर्टल के माध्यम से एक निविदा अप्रैल 2021 में आमंत्रित की गयी थी।

[36] *'ब्याज शुल्क' ₹ 37.60 लाख और 'दंडात्मक शुल्क' ₹ 76.78 लाख*

निविदा प्रक्रिया में 11 फर्मों ने भाग लिया और केवल तीन फर्मों को तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया गया और उनकी बोलियाँ वित्तीय निविदा के लिए खोली गईं। 'ग्रीन इंडिया एनवायरन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (जी.आई.ई.आई.)' फर्म ने एस.पी.पी.ओ.एस. का सबसे कम दर बताया और इसलिए ₹ 49 लाख प्रति एस.पी.पी.ओ.एस. की दर से ₹ 1.96 करोड़ में चार एस.पी.पी.ओ.एस. की आपूर्ति और अधिष्ठापन के लिए कंपनी को एक कार्यादेश (28 अप्रैल 2021) दिया गया। कार्यादेश के अनुसार चार एस.पी.पी.ओ.एस. की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्यादेश की तिथि से 20 दिनों के भीतर अर्थात 18 मई 2021 तक किए जाने थे।

फर्म (जी.आई.ई.आई.) ने दो एस.पी.पी.ओ.एस. की आपूर्ति की और नगर परिषद् ने 18 जून 2021 को कंपनी (जी.आई.ई.आई.) को ₹ 91.14 लाख[37] का भुगतान किया। लेखापरीक्षा ने नगर परिषद् के कनीय अभियंता के साथ एक संयुक्त भौतिक सत्यापन किया (29 जून 2022) और पाया कि दो एस.पी.पी.ओ.एस. टाउन हॉल और नगर परिषद् भवन की छत पर अधिष्ठापित थे। शेष दो एस.पी.पी.ओ.एस. की आपूर्ति जून 2022 तक अर्थात कार्यादेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि नगर परिषद् ने दो एस.पी.पी.ओ.एस. की लागत राशि ₹ 91.14 लाख का भुगतान (30 जून 2021) एक फर्म 'अनवी रिवाइवल एंटरप्राइजेज (ए.आर.ई)' को किया, जिसने एस.पी.पी.ओ.एस. आपूर्ति की निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था और नगर परिषद् ने कंपनी को कोई आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया था। इस प्रकार नगर परिषद् ने एक अनधिकृत फर्म को फर्जी भुगतान किया।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया (जुलाई 2022) कि तकनीकी जानकारी के अभाव में गलती से भुगतान दो अलग–अलग कम्पनियों को कर दिया गया। आगे बताया गया कि फर्म के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उसे काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाएगी। कार्यपालक पदाधिकारी का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि भुगतान उस फर्म को किया गया था जिसने निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था।

यह भी पाया गया कि फर्म 'सनस्टोन सोलर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (एस.एस.एस.पी.एल.)' जिसने निविदा में भाग लिया था, ने चार एस.पी.पी.ओ.एस की आपूर्ति के लिए ₹ 59.30 लाख का न्यूनतम दर बताया था, लेकिन तकनीकी निविदा में अग्रधन राशि (ई.एम.डी.) जमा नहीं करने के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया जबकि फर्म को कोई ई.एम.डी. जमा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह एम.एस.ई श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत थी। फर्म ने एम.एस.ई. के रूप में, अन्य तीन कम्पनियों की तरह जिन्हें तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया गया था, पंजीकृत फर्म होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था।

यदि नगर परिषद्, शेखपुरा ने तकनीकी निविदा में कंपनी 'एस.एस.एस.पी.एल' को अयोग्य घोषित नहीं किया होता, तो इसके द्वारा चार एस.पी.पी.ओ.एस. के क्रय हेतु केवल ₹ 59.30 लाख का व्यय किया जाता और चार एस.पी.पी.ओ.एस. के क्रय पर ₹ 1.37 करोड़ की बचत की जा सकती थी। लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया (जुलाई 2022) कि ई.एम.डी. छूट की शर्तों की जानकारी न होने के कारण फर्म को तकनीकी निविदा में अयोग्य घोषित किया गया था। कार्यपालक

[37] *कुल राशि – ₹ 98,00,000 (49 लाख X 2) – ₹ 1,96,000 (जी.एस.टी.) – ₹ 4,90,000 (परफॉरमेंस सिक्योरिटी) = ₹ 91,14,000*

पदाधिकारी का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अग्रधन (ई.एम.डी.) प्रस्तुत करने से छूट के नियम और शर्तें जेम पोर्टल पर क्रय के सामान्य नियम और शर्तों में विस्तृत रुप से वर्णित थे।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि नगर परिषद्, शेखपुरा में संबंधित अधिकारियों ने एक अनधिकृत फर्म को ₹ 91.14 लाख का कपटपूर्ण भुगतान किया। इसके अलावा, उन्होंने सामग्रियों के क्रय हेतु वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया और जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्रियों के क्रय हेतु सामान्य नियम और शर्तों का पालन नहीं किया, जिसके फलस्वरुप नगर परिषद् को ₹ 1.37 करोड़ की हानि हुई।

मामला राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया था, परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2023 तक)।

अध्याय-V

निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय - V
निष्पादन लेखापरीक्षा

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार के शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

निष्पादन लेखापरीक्षा की संरचना

कंडिका 5.1: प्रस्तावना– यह कंडिका निष्पादन लेखापरीक्षा के विषय से परिचय कराती है और संगठनात्मक ढांचे, लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदंडों, कार्यप्रणाली और सीमाओं का वर्णन करती है।

कंडिका 5.2: बिहार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति– इस कंडिका में बिहार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति की चर्चा शहरी विकास मंत्रालय (एम.ओ.यू.डी.) तथा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा विकसित किये गये सेवा स्तर के आठ मानकों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संकेतकों के संदर्भ में की गई है।

कंडिका 5.3: वित्तीय प्रबंधन– यह कंडिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निधि आधारित लेखांकन का अभाव, उपभोक्ता शुल्क को लगाने और वसूल करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित अनुदानों से वंचित रहने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित अनुदानों के उपयोगिता पर चर्चा करती है।

कंडिका 5.4: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना और रणनीति– यह कंडिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा कैसे योजना बनाई गई, उनके द्वारा कैसे बजट की व्यवस्था की गई, कैसे उन्होंने सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों को क्रियान्वित किया और अपशिष्ट सृजन का आकलन किया, इस पर चर्चा करती है।

कंडिका 5.5: ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण और परिवहन– यह कंडिका अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण और परिवहन तथा इसकी प्रभावशीलता हेतु शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए गए प्रयासों पर चर्चा करती है।

कंडिका 5.6: ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण और निपटान– यह कंडिका उत्पादित अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता, अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं एवं उनकी कार्यक्षमता और मौजूदा नियमों/दिशानिर्देशों के अनुरूप अपशिष्ट का निपटान कैसे किया जा रहा था इस पर चर्चा करती है।

कंडिका 5.7: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत क्रय– यह कंडिका निविदा प्रक्रिया में अनियमितताओं, आवश्यकता के बिना उपकरणों के क्रय और स्थानीय स्थितियों के प्रतिकूल क्रय पर चर्चा करती है।

कंडिका 5.8: इंटेलिजेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन– यह कंडिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में दो शहरों– पटना तथा गया द्वारा किये गये तकनीकी प्रयासों (यथा घरों को क्यूआर कोड प्रदान करना, क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए हाथ से संचालित मोबाइल उपकरण खरीदना आदि) पर चर्चा करती है।

कंडिका 5.9: विशिष्ट अपशिष्ट प्रबंधन– यह कंडिका चर्चा करती है कि कैसे नमूना जांच में लिए गये शहरी स्थानीय निकायों ने विशिष्ट अपशिष्ट यथा संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (सी.एंड डी.), ई–अपशिष्ट, जैव–चिकित्सा अपशिष्ट और प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन किया।

कंडिका 5.10: अनुश्रवण और मूल्यांकन– यह कंडिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु विभिन्न संस्थानों द्वारा किये जा रहे अनुश्रवण और शहरी स्थानीय निकाय में कर्मचारियों की पर्याप्तता की चर्चा करती है।

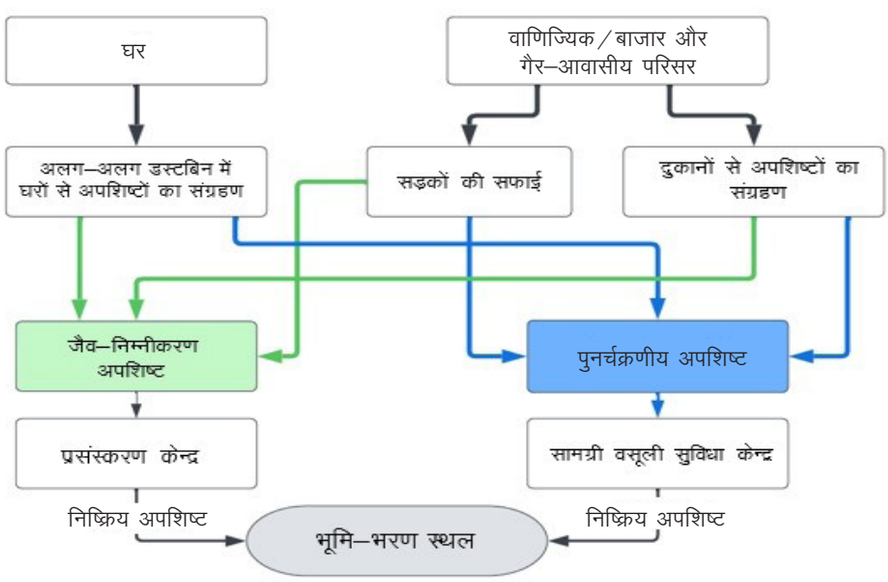
5.1 प्रस्तावना

ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत किसी क्षेत्र में उत्पन्न ठोस या अर्द्धठोस अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, सांस्थानिक अपशिष्ट, केटरिंग और बाजार अपशिष्ट तथा अन्य गैर–आवासीय अपशिष्ट, गली की सफाई, सतही नालियों से एकत्रित गाद, उद्यान अपशिष्ट, कृषि और डेयरी अपशिष्ट तथा उपचारित जैव चिकित्सक अपशिष्ट आते हैं।

नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन देश में सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले प्रमुख कार्यों में से एक है। शहरी स्थानीय निकायों को शहरी सेवा वितरण की सभी प्रणालियों, विशेष रूप से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से संबंधित प्रणालियों की सतर्कतापूर्वक योजना बनाने, कार्यान्वयन और अनुश्रवण करने की आवश्यकता है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय के कर्तव्य और उत्तरदायित्व, अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं को निदेशित करते हैं कि वे अन्य बातों के साथ–साथ अधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को पृथक्कृत अपशिष्ट सौपें, सभी घरों, वाणिज्यिक, संस्थागत और अन्य गैर–आवासीय परिसर से पृथक्कृत ठोस अपशिष्टों के डोर–टू–डोर संग्रहण हेतु एक प्रणाली स्थापित करें; पुनर्चक्रणीय सामग्री की छंटाई के लिए सामग्री वसूली सुविधाएं[38] (एम.आर.एफ.) स्थापित करें; विकेन्द्रीकृत कम्पोस्ट संयंत्रों की स्थापना को बढावा दें; स्वास्थ्यकर भरण स्थलों के निर्माण/प्रचालन/अनुरक्षण को शामिल करें, जैसा कि **चार्ट 5.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 5.1:ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया का चार्ट



*(**स्रोत**: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में उल्लिखित प्रावधानों और शर्तों के अनुसार)*

शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन शहरी शासन की एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रबंधन रहित ठोस अपशिष्ट का प्रभाव न केवल सौंदर्य और पर्यावरण पर पड़ता है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी एक खतरा है। लेखापरीक्षा ने राज्य में अपनाई जा रही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को समग्र स्वरुप देने का प्रयास किया। चयनित शहरी

[38] *सामग्री वसूली सुविधाओं का अभिप्राय एक ऐसी सुविधा से है जहां गैर–कम्पोस्टीय ठोस अपशिष्ट को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है, ताकि अपशिष्ट के प्रसंस्करण या निपटान के लिए उसे देने या लेने के पूर्व अपशिष्ट के विभिन्न संघटकों से पृथक्करण, छंटाई और पुनर्चक्रण योग्य की पुनर्प्राप्ति हो सके।*

स्थानीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान अपनाए गए ठोस अपशिष्ट प्रथाओं के प्रबंधन पर एक आकलन तैयार किया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में कई समस्याओं और कमियों को पाया गया, जिसकी चर्चा इस प्रतिवेदन के आगे की कंडिकाओं में की गई है।

5.1.1 संगठनात्मक ढांचा

शहरी स्थानीय निकाय स्व–शासित संस्थाएं हैं और इसमें नगर निगम[39], नगर परिषद्[40] और नगर पंचायत शामिल हैं। शहरी स्थानीय निकाय की सभी सीटें[41] क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों, जिन्हें वार्ड कहा जाता है, से प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गए व्यक्तियों से भरी जाती हैं। इसके अलावा, नगरपालिका क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा के सदस्य/संसद के सदस्य[42] भी शहरी स्थानीय निकाय के सदस्य होते हैं। नगर निगम, नगर परिषद् और नगर पंचायत के मामले में पीठासीन अधिकारी क्रमशः महापौर, नगर सभापति और नगर अध्यक्ष होते हैं। सशक्त स्थायी समिति शहरी स्थानीय निकाय की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करती है। सशक्त स्थायी समिति की संरचना, जहाँ तक इसके सदस्यों से संबंधित है, **तालिका 5.1** में दर्शाई गई है।

तालिका 5.1

शहरी स्थानीय निकाय में सशक्त स्थायी समिति की संरचना

नगर निगम	नगर परिषद्	नगर पंचायत
महापौर, उप–महापौर एवं सात पार्षद्	नगर सभापति, नगर उप सभापति एवं पाँच पार्षद्	नगर अध्यक्ष, नगर उपाध्यक्ष एवं तीन पार्षद्

*(**स्रोत**: बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 21)*

इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकाय, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में रहता है, जिसके प्रधान विभाग के सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव होते हैं। नगर आयुक्त नगर निगम के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, जबकि नगर परिषद् और नगर पंचायत के कार्यकारी प्रमुख राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं।

शहरी स्थानीय निकाय के संगठनात्मक ढांचा को ***परिशिष्ट 5.1*** में दर्शाया गया है।

अपशिष्ट प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला नियामक ढांचा

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नियामक निकायों की भूमिका और उत्तरदायित्वों को **तालिका 5.2** में विस्तार से बताया गया है।

---

[39] *दो लाख से अधिक शहरी आबादी का नगर निकाय*

[40] *40000 से उपर और दो लाख तक की शहरी आबादी क्षेत्र*

[41] *महापौर/नगर सभापति/नगरपालिका अध्यक्ष और उप–महापौर/नगर उप–सभापति/नगरपालिका उपाध्यक्ष 2022 से प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जा रहे हैं।*

[42] *इसमें नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत राज्य परिषद् के सदस्य और राज्य विधान परिषद् के सदस्य और नगरपालिका क्षेत्र के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए राज्य विधान परिषद् के सदस्य शामिल हैं।*

तालिका 5.2
नियामक निकायों की भूमिका

क्र. सं.	नियामक निकाय	निकाय का कर्तव्य
1	शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित कर, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में सुधार हेतु राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा किए गए उपायों और मंत्रालय तथा बाहरी एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार करनी है और किये जाने वाले सुधारात्मक उपाय पर सलाह देनी है।
2	नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार	राज्य में शहरी विकास विभाग के सचिव को नगरपालिका प्रशासन के आयुक्त या निदेशक अथवा स्थानीय निकायों के निदेशक के माध्यम से, अपशिष्ट चुनने वाले, स्वयं–सहायता समूह और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले अन्य समूह के प्रतिनिधि सहित हितधारकों के परामर्श से राज्य के लिए एक नीति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति तैयार करना है, जो इन नियमों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के राष्ट्रीय नीति के अनुरूप हो।
3	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों के साथ समन्वय करना है और स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के माध्यम से वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा करनी है, साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं या उपचार प्रौद्योगिकियों के लिए निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के कार्यान्वयन और उनके द्वारा किए गए अनुश्रवण के आँकड़ों का संकलन करना है।
4	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को बिहार राज्य में, स्थानीय निकायों के माध्यम से, अपने अधिकार क्षेत्र में इन नियमों को लागू करना है और संबंधित नगरपालिका प्रशासन निदेशालय या राज्य शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव के साथ समन्वय कर, वर्ष में कम से कम दो बार इन नियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करनी है। अपशिष्ट प्रसंस्करण, उपचार या निपटान सुविधाओं की स्थापना के लिए प्राप्त प्राधिकार के प्रस्तावों की जांच करना है और साठ दिनों के अंदर इन प्राधिकारों को जारी भी करनी है।

*(**स्रोत**: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016)*

5.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या :

- शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की ''रणनीति और योजना'' उत्पन्न अपशिष्टों के प्रकार और मात्रा के अनुरूप थी और मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुकूल थी।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े नगरपालिका कार्यों, जिसमें अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, निपटान और अनौपचारिक अपशिष्ट कामगारों का सामाजिक समावेश प्रभावी, कुशल और किफायती थी।
- शहरी स्थानीय निकाय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का आयोजन, योजना, निर्माण, चालू करना, संचालन और रख–रखाव प्रभावी, कुशल और वित्तीय रूप से टिकाऊ थे।

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का अनुश्रवण और मूल्यांकन, जिसमें पर्याप्त जागरूकता का सृजन, व्यावहारिक परिवर्तन के लिए नागरिकों की सहभागिता, नागरिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र, पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन और 'आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण' तंत्र का कार्यान्वयन, पर्याप्त और प्रभावी था।

5.1.3 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किये गये थे:

- बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (समय–समय पर अधिसूचित किये गये संशोधनों के साथ)
- भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में निर्गत किये गये नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हस्तक, 2016 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
- मॉडल बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2019
- संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
- सेवा स्तर मानक दिशानिर्देशों में निर्धारित कार्यक्षमता मापदंड
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम और नियम 1986
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008
- बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014
- बिहार नगरपालिका लेखा हस्तक
- बिहार नगरपालिका बजट हस्तक
- बिहार वित्तीय नियमावली
- बिहार शहरी स्थानीय निकाय (सामुदायिक भागीदारी) नियमावली, 2013; स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देश और स्वच्छ भारत मिशन दिशानिर्देश
- मोटर वाहन अधिनियम, 1988
- बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994
- बिहार में शहरी स्थानीय निकाय के लिए नागरिक अधिकार–पत्र
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु जारी निर्देश, दिशानिर्देश, नीतियां; और
- स्वतंत्र विशेषज्ञ की सलाह और उनका अनुभव।

5.1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली और सीमाएं

बिहार राज्य में 31 मार्च 2022 तक 258 शहरी स्थानीय निकाय[43] (18 नगर निगम, 83 नगर परिषद् और 157 नगर पंचायत) थे। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान बिहार में केवल 141 शहरी स्थानीय निकाय कार्यशील थे। इनमें राज्य के नौ प्रमंडलों/38 जिलों के 18 नगर निगम, 75 नगर परिषद् और 48 नगर पंचायतें शामिल थे।

[43] *वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 117 शहरी स्थानीय निकायों का गठन किया गया। साथ ही दिसंबर 2020 में डुमरा नगर पंचायत का विलय सीतामढी नगर निगम में कर दिया गया।*

लेखापरीक्षा इकाइयों का चयन आईडिया एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके सिंपल रैण्डम सैम्पलिंग (राजस्व प्रमंडल–वार) लागू करके किया गया था। शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर से, लेखापरीक्षित इकाईयों के नमूने इस तरह से लिए गए हैं कि प्रत्येक प्रमंडल का समान प्रतिनिधित्व हो। प्रत्येक प्रमंडल से एक नगर निगम, 10 प्रतिशत नगर परिषदें और पाँच प्रतिशत नगर पंचायतें इस प्रकार चयनित की गईं हैं कि नमूना इकाईयों की जनसंख्या का कवरेज संपूर्ण बिहार के शहरी आबादी के 25 प्रतिशत से कम न हो।

उपरोक्त कार्यप्रणाली के आधार पर, आठ नगर निगमों[44], 11 नगर परिषदों[45] और नौ नगर पंचायतों[46] का चयन किया गया, जो राज्य के 46 प्रतिशत शहरी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

निष्पादन लेखापरीक्षा अगस्त 2022 से जनवरी 2023 के दौरान संचालित की गई, जिसमें नमूना के तौर पर शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से अप्रैल 2017 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति को शामिल किया गया। इसके अलावा, नगर विकास और आवास विभाग और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी प्रासंगिक जानकारी एकत्र की गई।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जांच, प्रारूप में प्राप्त जानकारी, 1,408 लाभुकों (949 घरों और 459 दुकानदारों) का सर्वेक्षण और प्रसंस्करण (कंपोस्टिंग स्थल, सामग्री वसूली केन्द्रों आदि) स्थलों, डंपिंग स्थलों आदि का संयुक्त भौतिक सत्यापन शामिल था।

अपशिष्ट संग्रहण/परिवहन की मात्रा, अपशिष्ट प्रसंस्करण और उसमें उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी, शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न समितियों, भूमि–भरण स्थलों, उपभोक्ता शुल्क का संग्रहण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित सेवा स्तर मानकों की स्थिति, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा संचालित जागरूकता कार्यक्रम, स्वीकृत पदों/कार्यरत पदों, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की स्थिति, प्रदूषण स्तर की अनुश्रवण और स्वास्थ्य जोखिम मूल्यांकन, प्रशिक्षण और क्षमता वर्द्धन आदि की जानकारी नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों से मांगी गई।

सर्वेक्षण में, उत्तरदाताओं से उनके द्वारा अपनायी गई अपशिष्ट निपटान की पद्धति, नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उन्हें आपूर्ति किये गये डस्टबिन, नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उनसे संग्रहित किये गये पृथक्कृत अपशिष्ट, वसूल किये गये उपभोक्ता शुल्क की राशि, सामुदायिक डस्टबिन की उपलब्धता और इन डस्टबिनों के आसपास की स्वच्छता, नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सड़क के सफाई की स्थिति, अपशिष्ट का ढक कर/बिना ढके परिवहन, नालियों की सफाई/गाद निकालने, अपशिष्ट के निपटान के संबंध में चलाये गये जागरूकता कार्यक्रम, शिकायतें दर्ज कराना और उनका निवारण, स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान सेवाओं आदि से समग्र संतुष्टि के संबंध में पूछा गया।

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ दिनांक 01/08/2022 को एक अंतर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंड और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर चर्चा करने और उनके विचार प्राप्त करने के लिए विभाग

[44] *भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत कोई नगर निगम नहीं था।*

[45] *दलसिंहसराय, दानापुर, गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, राजगीर, रामनगर, सहरसा और सुल्तानगंज।*

[46] *अमरपुर, बहादुरगंज, बड़हिया, बेलसंड, जगदीशपुर, झंझारपुर, महाराजगंज, मखदुमपुर और मुरलीगंज।*

के साथ एक बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित की गई थी। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग ने आश्वासन दिया कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों को रचनात्मक आलोचना के रूप में लिया जाएगा और ये शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया के समग्र सुधार में सहायक होगें। नमूना इकाईयों के जवाबों को प्रतिवेदन में उचित स्थानों पर शामिल किया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा की सीमाओं में महत्वपूर्ण अभिलेखों की अनुपलब्धता/आंशिक उपलब्धता शामिल है। अनुपलब्ध अभिलेखों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विशिष्ट लेखा, वास्तविक अपशिष्ट संग्रहण के समर्थन से संबंधित अभिलेख आदि शामिल थे। इन अभिलेखों की अनुपलब्धता ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित योजना, प्राप्ति और व्यय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया की दक्षता का सटीक आकलन करने में लेखापरीक्षा के प्रयास को प्रभावित किया। इसलिए, कई स्थानों पर, परंपरागत/उदारवादी दृष्टिकोण का उपयोग करके, वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाया गया है।

5.1.5 अभिलेखों का संधारण/प्रस्तुतीकरण नहीं करना

अभिलेखों की अनुपलब्धता/*आंशिक* उपलब्धता के कारण लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र सीमित था, जिसका सार निम्न प्रकार है:

(i) नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मानकों की स्थिति (घरों का कवरेज, अपशिष्ट के संग्रह की क्षमता, अपशिष्ट के पृथक्करण का विस्तार, अपशिष्ट की वसूली का विस्तार, अपशिष्ट के निपटान में वैज्ञानिक तरीके का विस्तार, लागत वसूली का विस्तार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क के वसूली की दक्षता, शिकायतों के निवारण में दक्षता) विभाग को प्रतिवेदित की थी। हालांकि, प्रतिवेदित स्थिति को सत्यापित करने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ रूप से सत्यापन योग्य आधार अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाया गया।

(ii) नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा एक वर्ष में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क की वसूलनीय राशि की गणना नहीं की गई थी, जबकि बिहार नगरपालिका लेखा नियम, 2014 के अनुसार यह आवश्यक था।

(iii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अलग से निधि आधारित लेखांकन का संधारण नहीं किया गया था, जबकि बिहार नगरपालिका लेखा हस्तक और बिहार नगरपालिका लेखा नियम, 2014 के अनुसार यह आवश्यक था।

(iv) नमूना जांच किए गए 23 शहरी स्थानीय निकायों ने खरीद से संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया। लेखापरीक्षा को जेम पोर्टल की पहुंच प्रदान नहीं की गई।

(v) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य के लिए नियुक्त आउटसोर्सिंग एजेंसियों की कार्य योजना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया/प्रस्तुत नहीं की गयी।

(vi) कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के अंतर्गत नामांकित मजदूरों का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया/प्रस्तुत नहीं किया गया। शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों के क्रय के समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया।

(vii) बजट प्रक्रिया अपारदर्शी पायी गई क्योंकि नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बजट तैयार करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश/नीति, उत्तरवर्ती चर्चाओं के माध्यम से उत्तरोत्तर सुधार; सनदी लेखाकार/कर्मियों को दिए गए सुझावों का कार्यान्वयन इत्यादि, को अभिलेखित नहीं किया जा रहा था। बजट अभिलेख में कोई योजना दस्तावेज़/सूचना पत्रक उपलब्ध नहीं था।

5.2 बिहार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति

शहरी विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर चार प्रमुख क्षेत्रों– जलापूर्ति, मल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी की सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु सेवा स्तर मानकों का निर्धारण किया है।

तेरहवीं वित्त आयोग ने भी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सभी आवश्यक सेवाओं के लिए उत्तरोत्तर मानक स्थापित करने की अनुशंसा राज्य सरकारों से की थी। तद्नुसार, नगर विकास एवं आवास विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सेवाओं के लिए सेवा स्तर मानकों को अधिसूचित (मार्च 2011) किया था।

5.2.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित सेवा स्तर मानक

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत सेवा स्तर मानक की हस्त–पुस्तिका में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित सेवाओं में सुधार एवं निष्पादन के अनुश्रवण के लिए आठ मानक संकेतकों[47] को परिकल्पित किया गया है। इन संकेतकों का उपयोग शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वस्तुनिष्ठ कार्य–विश्लेषण करने के लिए एक साधन के रूप में किया जाना है जिससे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्यकलापों में व्यापक सुधार हो सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मानकों और उन मानकों के विरूद्ध उपलब्धि का उल्लेख अपने बजट में किया था और इसे नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रतिवेदित किया था। प्रतिवेदित स्थिति[48] (मार्च 2017/2018 एवं मार्च 2022) और उसकी तुलना में वास्तविक स्थिति, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया, को **तालिका 5.3** में दर्शाया गया है और विस्तृत विवरणी ***परिशिष्ट 5.2*** में दी गयी है।

तलिका–5.3

नमूना जांच किये गये बिहार के शहरी स्थानीय निकायों में सेवा स्तर मानकों की प्रतिवेदित एवं वास्तविक स्थिति

(स्थिति प्रतिशत में)

क्र0 सं0	सेवा स्तर का विवरण	मानक	प्रतिवेदित स्थिति (मार्च 2017/2018)#		प्रतिवेदित स्थिति (मार्च 2022)*		नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में वास्तविक स्थिति, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया[49]	शून्य मानक संकेतक स्थिति वाले शहरी स्थानीय निकायों की संख्या (कुल 28 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से)
			विस्तार	माध्यिका[50]	विस्तार	माध्यिका		
1	घरेलू स्तर पर कवरेज	100	0-100	70	50-100	95	76	--
2	ठोस अपशिष्ट संग्रहण की दक्षता	100	0-100	60	50-100	92.5	84	--
3	नगरीय ठोस अपशिष्ट पृथक्करण का दायरा	100	0-50	25	0-100	50	20	10

[47] *1. घरेलू स्तर पर कवरेज, 2. ठोस अपशिष्ट संग्रहण की दक्षता, 3. नगरीय ठोस अपशिष्ट पृथ्क्करण का विस्तार, 4. नगरीय ठोस अपशिष्ट पुनर्प्राप्ति का दायरा, 5. वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट निपटान का विस्तार, 6. लागत वसूली, 7. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क संग्रहण में दक्षता एवं 8. उपभोक्ता शिकायत निवारण में दक्षता।*

[48] *नगर विकास एवं आवास विभाग को समर्पित बजट में प्रतिवेदित अथवा लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयी सूचना।*

[49] *घरों/दुकानदारों का सर्वेक्षण, संयुक्त भौतिक सत्यापन एवं नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के दस्तावेजों के आधार पर।*

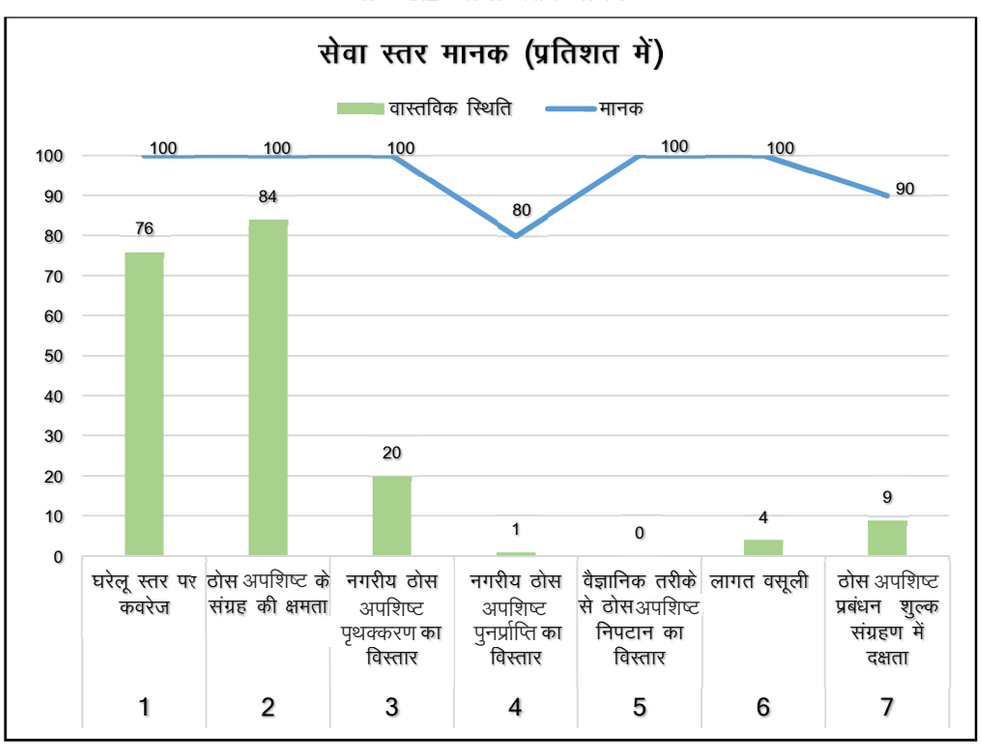
[50] *माध्यिका एक आँकड़ा समुच्चय के केन्द्रीय प्रवृत्ति को सुनिश्चित करने का एक सांख्यिकीय माप है। यह एक ऐसा बिन्दु है जिसके ऊपर और नीचे उस आँकड़ा समुच्चय के आधे (50 प्रतिशत) आँकड़े होते हैं और इस प्रकार यह उस आँकड़ों के बीच के बिन्दु का द्योतक होता है।*

क्र0 सं0	सेवा स्तर का विवरण	मानक	प्रतिवेदित स्थिति (मार्च 2017/2018)#		प्रतिवेदित स्थिति (मार्च 2022)*		नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में वास्तविक स्थिति, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया[49]	शून्य मानक संकेतक स्थिति वाले शहरी स्थानीय निकायों की संख्या (कुल 28 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से)
			विस्तार	माध्यिका[50]	विस्तार	माध्यिका		
4	नगरीय ठोस अपशिष्ट पुनर्प्राप्ति का दायरा	80	0-70	5	0-80	20	1	18
5	वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट निपटान का दायरा	100	0-50	0	0-100	0	0	28
6	लागत वसूली	100	0-90	0	0-100	3.5	4	13
7	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क संग्रहण में दक्षता	90	0-80	5	0-90	0	9[51]	17
8	उपभोक्ता शिकायत निवारण में दक्षता	80	0-70	25	0-90	60	नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय द्वारा समुचित रूप से शिकायत पंजी के संधारण नहीं किये जाने के कारण गणना नहीं की जा सकी।	--

(स्रोतः नमूना जांच किये शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समर्पित किये गये प्रतिवेदन, घरों/दुकानदारों का सर्वेक्षण एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन)

*# नमूना जांच किये गये 18 शहरी स्थानीय निकायों मे उपलब्ध सूचना पर आधारित। * नमूना जांच किये गये 24 शहरी स्थानीय निकायों मे उपलब्ध सूचना पर आधारित*

चार्ट 5.2: सेवा स्तर मानक



(स्रोतः नमूना शहरी स्थानीय निकाय का सर्वेक्षण)

* *यह चार्ट यहां सात बेंचमार्क दर्शाता है, उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में दक्षता की गणना नहीं की जा सकी, क्योंकि नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा समुचित तरीके से शिकायत पंजी का संधारण नहीं किया गया था।*

[51] *पटना, गया, मुरलीगंज एवं मुंगेर को गणना से बाहर रखा गया है। पटना एवं गया के आँकड़ों को सम्मिलित करने से सही परिणाम प्राप्त नहीं होता। मुरलीगंज एवं मुंगेर के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं थी।*

तालिका 5.3 से स्पष्ट है कि नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा, स्वयं प्रतिवेदित किये गये प्रतिवेदन के अनुसार, मार्च 2022 तक (दरभंगा नगर निगम को छोड़कर) सेवा स्तर मानकों के सभी आठ संकेतकों के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान वास्तविक स्थिति, प्रतिवेदित स्थिति से कम थी।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित स्थिति पाया गया:

1. सत्यापन योग्य आँकड़ों/सूचनाओं का अभाव– नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिवेदित उपलब्धि को सत्यापित नहीं किया जा सका, क्योंकि इन शहरी स्थानीय निकायों ने अपने दावों के समर्थन में समुचित दस्तावेज संधारित नहीं किये थे। इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मानक स्तरों की उपलब्धि का प्रतिवेदन, बिना किसी वस्तुनिष्ठ सत्यापन योग्य आधार पर की गयी थी।

2. घरेलू स्तर पर कवरेज– शहरी विकास मंत्रालय के सेवा स्तर मानक हस्त–पुस्तिका, के अनुसार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के घरेलू स्तर पर कवरेज को उन घरों और संस्थाओं के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्रतिदिन द्वार से अपशिष्ट संग्रह व्यवस्था द्वारा कवर किये जाते हैं। घरेलू स्तर पर कवरेज का मानक 100 प्रतिशत निर्धारित था। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दावा किया गया था कि मार्च 2022 तक घरेलू स्तर पर कवरेज 50 से 100 प्रतिशत था।

घरेलू स्तर पर कवरेज के आकलन हेतु लेखापरीक्षा द्वारा घरों/दुकानदारों का सर्वेक्षण किया गया। घरों/दुकानदारों के संयुक्त सर्वेक्षण मे 1,408 उत्तरदाताओं में से 333 (24 प्रतिशत) ने बताया कि नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा डोर–टू–डोर अपशिष्ट संग्रहण सेवा के अभाव में उनके द्वारा खुले स्थान में अपशिष्टों को फेंका जाता था। इस प्रकार, नमूना घरों/दुकानदारों के सर्वेक्षण के दौरान संग्रहित किये गये आँकड़ों के अनुसार घरेलू स्तर पर कवरेज मात्र 76 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 16 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दो से 62 प्रतिशत तक अधिक घरेलू स्तर पर कवरेज को प्रतिवेदित किया गया था, जैसा कि **तालिका 5.4** में दर्शाया गया है।

तलिका 5.4
नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अधिक प्रतिवेदित किये गये घरेलू स्तर पर कवरेज

(स्थिति प्रतिशत में)

क्र0 स0	शहरी स्थानीय निकाय	प्रतिवेदित स्थिति (मार्च 2022)	लेखापरीक्षा के अनुसार स्थिति	अधिक दावा	क्र0 स0	शहरी स्थानीय निकाय	प्रतिवेदित स्थिति (मार्च 2022)	लेखापरीक्षा के अनुसार स्थिति	अधिक दावा
1	भागलपुर	100	93	7	9	रामनगर	80	68	12
2	मुजफ्फरपुर	100	82	18	10	राजगीर	95	69	26
3	दरभंगाा	100	72	28	11	दलसिंहसराय	100	38	62
4	छपरा	100	98	2	12	बहादुरगंज	80	47	33
5	सहरसा	95	77	18	13	झंझारपुर	85	43	42
6	किशनगंज	100	49	51	14	मुरलीगंज	70	30	40
7	जहानाबाद	95	72	23	15	अमरपुर	50	13	37
8	गोपालगंज	100	97	3	16	बेलसंड	80	43	37

*(**स्रोत**: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख एवं नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में किये गये घरों/दुकानदारों का संयुक्त सर्वेक्षण)*

3. ठोस अपशिष्ट के संग्रहण की दक्षता– शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत सेवा स्तर मानक हस्त–पुस्तिका के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के संग्रहण की दक्षता का तात्पर्य, शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत उत्पन्न कुल अपशिष्ट की तुलना में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा संग्रहित किये गये कुल अपशिष्ट से है। इसके लिए निर्धारित मानक 100 प्रतिशत था। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इस संबंध में दावा किया गया था कि ठोस अपशिष्ट के संग्रहण की दक्षता मार्च 2022 तक 50 से 100 प्रतिशत थी।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में प्रतिदिन कुल 3,107 टन अपशिष्ट उत्पन्न होता था जिसमें से कुल 2,608 टन प्रतिदिन (84 प्रतिशत) अपशिष्ट का संग्रहण किया जाता था। अर्थात् ठोस अपशिष्ट के संग्रहण की दक्षता 84 प्रतिशत थी। वास्तविक स्थिति 84 प्रतिशत से काफी नीचे हो सकती है, क्योंकि नमूना जांच किये गये सभी शहरी स्थानीय निकायों के घरों/दुकानदारों के सर्वेक्षण एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि इन निकायों में सड़कों के किनारे/खुले स्थानों में अपशिष्टों को फेंकने का प्रचलन मौजूद था।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नौ नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सात से 76 प्रतिशत तक अधिक अपशिष्ट के संग्रहण की दक्षता प्रतिवेदित की गई थी, जैसा कि **तालिका 5.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.5
नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अधिक प्रतिवेदित किये गये ठोस अपशिष्ट संग्रहण की दक्षता

(स्थिति प्रतिशत में)

क्र0 स0	शहरी स्थानीय निकाय	प्रतिवेदित स्थिति (मार्च 2022)	लेखापरीक्षा के अनुसार स्थिति	अधिक दावा	क्र0 स0	शहरी स्थानीय निकाय	प्रतिवेदित स्थिति (मार्च 2022)	लेखापरीक्षा के अनुसार स्थिति	अधिक दावा
1	दरभंगाा	100	60	40	6	झंझारपुर	80	40	40
2	सहरसा	95	41	54	7	मुरलीगंज	70	31	39
3	किशनगंज	100	66	34	8	अमरपुर	70	63	7
4	बहादुरगंज	80	70	10	9	बेलसंड	80	57	23
5	जगदीशपुर	100	24	76		-	-	-	-

*(**स्रोतः** : नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)*

4. अपशिष्ट पृथक्करण का दायरा– शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत सेवा स्तर मानक हस्त–पुस्तिका के अनुसार, अपशिष्ट पृथक्करण का दायरा से तात्पर्य घरों एवं संस्थाओं से प्राप्त पृथक्कृत अपशिष्टों की प्रतिशतता से है। अपशिष्टों का पृथक्करण निम्नलिखित श्रेणियों में किया जाना है– जैव–निम्नीकरण अपशिष्ट; गैर जैव विघटनीय अपशिष्ट; एवं घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट जैसे बैट्रियाँ इत्यादि। पृथक्करण का स्तर, घरेलू या संस्थान स्तर पर कम से कम, स्रोत पर गीले और सूखे अपशिष्ट के पृथक्करण तक होना चाहिए। इसके लिए निर्धारित मानक 100 प्रतिशत था। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मार्च 2022 तक नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण का दायरा शून्य से 100 प्रतिशत होने का दावा किया गया था।

घरों और दुकानदारों के संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान कुल उत्तरदाताओं में से 80 प्रतिशत लोगों ने बताया कि स्रोत पर अपशिष्टों के पृथक्करण का प्रचलन नहीं था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि शहरी स्थानीय निकाय या तो मिश्रित अपशिष्ट संग्रह कर रहे थे या उनके द्वारा बिना पृथक्करण के ही मिश्रित अपशिष्ट डंपिंग स्थल पर गिराया जा रहा था। इस प्रकार, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पृथक्करण का वास्तविक दायरा, वास्तव में नगण्य था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 18 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पृथक्करण दायरा का उच्चतर प्रतिशतता का दावा किया था (मार्च 2022), जो एक से 100 प्रतिशत था, जैसा कि **तालिका 5.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.6
नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अधिक पृथक्करण दायरा का प्रतिवेदन

(स्थिति प्रतिशत में)

क्र0 स0	शहरी स्थानीय निकाय	प्रतिवेदित स्थिति (मार्च 2022)	लेखापरीक्षा के अनुसार स्थिति	अधिक दावा	क्र0 स0	शहरी स्थानीय निकाय	प्रतिवेदित स्थिति (मार्च 2022)	लेखापरीक्षा के अनुसार स्थिति	अधिक दावा
1	पटना	50	39	11	10	रामनगर	50	0	50
2	गया	50	49	1	11	दलसिंहसराय	50	4	46
3	भागलपुर	60	1	59	12	बहादुरगंज	50	0	50
4	मुजफ्फरपुर	25	5	20	13	जगदीशपुर	100	0	100
5	दरभंगा	100	25	75	14	मखदुमपुर	100	53	47
6	छपरा	70	3	67	15	झझारपुर	25	0	25
7	हाजीपुर	25	2	23	16	अमरपुर	5	0	5
8	किशनगंज	80	0	80	17	महाराजगंज	50	35	15
9	गोपालगंज	80	0	80	18	बेलसंड	50	0	50

*(**स्रोतः** नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख एवं नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में घरों/दुकानदारों का संयुक्त सर्वेक्षण)*

5. नगरीय ठोस अपशिष्ट पुनर्प्राप्ति का दायराः शहरी विकास मंत्रालय के सेवा स्तर मानक की हस्त–पुस्तिका के अनुसार, 'अपशिष्ट पुनर्प्राप्ति का दायरा' से तात्पर्य, वैसे संग्रहित अपशिष्ट की मात्रा से है जिसे पुनर्चक्रित अथवा प्रसंस्कृत किया जाता है। इसे संग्रहित अपशिष्ट के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इसके लिए निर्धारित मानक 80 प्रतिशत था। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के पुनर्प्राप्ति का दायरा के संबंध में दावा किया गया था कि मार्च 2022 तक नगरीय ठोस अपशिष्ट की पुनर्प्राप्ति का दायरा शून्य से 80 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सिर्फ सात शहरी स्थानीय निकायों[52] के कम्पोस्टिंग स्थल[53] ही कार्यशील थे (दिसंबर 2022)। प्रतिदिन संग्रहित किये गये कुल 1,204 टन अपशिष्ट में से मात्र 13 टन[54] नगरीय ठोस अपशिष्ट (एक प्रतिशत) का प्रसंस्करण ही प्रतिदिन किया जा रहा था, जबकि शेष अपशिष्ट को डंपिंग साइट पर गिराया जा रहा था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट की पुनर्प्राप्ति के दायरा का उच्चतर प्रतिशतता का दावा किया गया था (मार्च 2022), जो 20 से 78 प्रतिशत तक था, जैसा कि **तालिका 5.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.7
नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अधिक प्रतिवेदित किये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट की पुनर्प्राप्ति का दायरा

(स्थिति प्रतिशत में)

क्र0 स0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	प्रतिवेदित स्थिति (मार्च 2022)	लेखापरीक्षा के अनुसार स्थिति	अधिक दावा	क्र0 स0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	प्रतिवेदित स्थिति (मार्च 2022)	लेखापरीक्षा के अनुसार स्थिति	अधिक दावा
1	भागलपुर	60	0	60	7	रामनगर	50	1	49
2	दरभंगा	80	2	78	8	बहादुरगंज	50	0	50
3	मुंगेर	40	0	40	9	जगदीशपुर	50	0	50

[52] *बड़हिया, बेलसंड, दलसिंहसराय, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रामनगर तथा सुल्तानगंज।*

[53] *शहरी स्थानीय निकायों के गीले अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु 20 कम्पोस्टिंग पिट वाले प्रसंस्करण स्थल का निर्माण किया जाना था।*

[54] *इसमें गया, पटना और दानापुर से संबंधित आँकड़ा शामिल नहीं है, क्योंकि प्रसंस्करण की सही मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकी। हालाँकि, पटना, दानापुर और गया में अपशिष्ट प्रसंस्करण पाया गया।*

क्र0 स0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	प्रतिवेदित स्थिति (मार्च 2022)	लेखापरीक्षा के अनुसार स्थिति	अधिक दावा	क्र0 स0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	प्रतिवेदित स्थिति (मार्च 2022)	लेखापरीक्षा के अनुसार स्थिति	अधिक दावा
4	छपरा	70	0	70	10	अमरपुर	20	0	20
5	किशनगंज	60	0	60	11	महाराजगंज	40	0	40
6	गोपालगंज	20	0	20	-	-	-	-	-

*(**स्रोतः** नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख एवं कम्पोस्टिंग स्थल का संयुक्त भौतिक सत्यापन)*

6. वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट निपटान का दायरा– शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत सेवा स्तर मानक हस्त–पुस्तिका के अनुसार, 'वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट निपटान का दायरा' से तात्पर्य अपशिष्ट की उस मात्रा से है जिसका निपटान ऐसे भूमि–भरण स्थल में किया जाता है जिसे केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार डिजाईन, निर्मित, संचालित और रख–रखाव किया गया हो। अनुपालन का दायरा खुले डंपिंग स्थलों सहित भूमि–भरण स्थलों में निपटाये गये अपशिष्ट की कुल मात्रा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका निर्धारित मानक 100 प्रतिशत है। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट निपटान के दायरा के संबंध में दावा किया गया था कि मार्च 2022 तक वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट निपटान का दायरा शून्य से 100 प्रतिशत था।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में स्वास्थ्यकर भरण स्थल[55] उपलब्ध नहीं था। इसकी जगह खुले डंपिंग स्थल में संबंधित शहरों के सारे अपशिष्ट गिराये जा रहे थे (दिसंबर 2022)। इस प्रकार, स्वास्थ्यकर भरण स्थल में वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट निपटान का दायरा शून्य था। हालांकि, नमूना जांच किये गये आठ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पाँच से 100 प्रतिशत तक नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान का दावा किया गया था (मार्च 2022), जैसा कि **तालिका 5.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.8
नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अधिक प्रतिवेदित किये गये वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट निपटान का दायरा

(स्थिति प्रतिशत में)

क्र0 स0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	प्रतिवेदित स्थिति (मार्च 2022)	लेखापरीक्षा के अनुसार स्थिति	अधिक दावा	क्र0 स0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	प्रतिवेदित स्थिति (मार्च 2022)	लेखापरीक्षा के अनुसार स्थिति	अधिक दावा
1	पटना	50	0	50	5	दलसिंहसराय	5	0	5
2	गया	50	0	50	6	जगदीशपुर	55	0	55
3	भागलपुर	70	0	70	7	मखदुमपुर	80	0	80
4	दरभंगाा	100	0	100	8	महाराजगंज	40	0	40

*(**स्रोतः** नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)*

7. लागत वसूली– शहरी विकास मंत्रालय के सेवा स्तर मानक हस्त–पुस्तिका के अनुसार, 'लागत वसूली' उस मात्रा को दर्शाती है जो शहरी स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित सेवाओं के समस्त परिचालन व्यय की वसूली, सिर्फ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित स्रोतों के परिचालन राजस्व से कर सकता है। इसका निर्धारित मानक 100 प्रतिशत है। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 'लागत वसूली' के संबंध में दावा किया गया था कि मार्च 2022 तक 'लागत वसूली' शून्य से 100 प्रतिशत थी।

हालांकि, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के वास्तविक परिचालन लागत की गणना नहीं की गई थी। अतः 'परिचालन लागत'

[55] *स्वास्थ्यकर भरण स्थल से तात्पर्य अवशेष ठोस अपशिष्ट एवं निष्क्रिय अपशिष्ट का अंतिम और सुरक्षित निपटान एक ऐसे स्थान पर किये जाने से है जिसकी संरचना भूजल, सतही जल और उड़ने वाले धूल कण, हवा से उड़ने वाले कूड़ा–करकट, दुर्गन्ध, अग्नि परिसंकट, पशुओं का खतरा, पक्षियों का खतरा, कीट या कुतरने वाले जीव, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, सतत् जैव प्रदूषणकारी तत्वों, ढलान अस्थिरता तथा क्षरण के प्रदूषण के प्रति संरक्षात्मक उपायों सहित डिजाईन की गई सुविधा से युक्त हो।*

की गणना के लिए न्यूनतम दृष्टिकोण अपनाते हुए, लेखापरीक्षा द्वारा सिर्फ आउटसोर्सिंग एजेंसी एवं सफाई मजदूरों को किये गये भुगतान (जैसा कि उपलब्ध अभिलेखों से ज्ञात हो सका) को शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में, नमूना जांच किये गये नौ[56] शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ₹ 4.37 करोड़ उपभोक्ता शुल्क के रूप में वसूल किया गया था, जबकि लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि उनका परिचालन लागत ₹ 46.39 करोड़ था। इस प्रकार, इन नौ शहरी स्थानीय निकायों में लागत वसूली की मात्रा सिर्फ 9.42 प्रतिशत थी।

इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किये गये 12 शहरी स्थानीय निकायों[57] का परिचालन लागत ₹ 53.95 करोड़ था, लेकिन इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने परिचालन लागत की वसूली के लिए उपभोक्ता शुल्क की वसूली नहीं की जा रही थी। इसके अलावा, नमूना जांच किये गय शेष सात शहरी स्थानीय निकायों[58] द्वारा संबंधित अभिलेखों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण लेखापरीक्षा द्वारा परिचालन लागत अथवा उपभोक्ता शुल्क की गणना नहीं की जा सकी।

इस प्रकार, नमूना जांच किये गये 21 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 100.34 करोड़ के परिचालन लागत के विरूद्ध मात्र ₹ 4.37 करोड़ (चार प्रतिशत) के उपभोक्ता शुल्क की ही वसूली की गयी थी।

साथ ही, नमूना जांच किये गये आठ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 10 से 90 प्रतिशत तक अधिक लागत वसूली का दावा किया गया था, जैसा कि **तालिका 5.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.9

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अधिक प्रतिवेदित किये गये लागत वसूली

(स्थिति प्रतिशत में)

क्र0 स0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	प्रतिवेदित स्थिति (मार्च 2022)	लेखापरीक्षा के अनुसार स्थिति	अधिक दावा	क्र0 स0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	प्रतिवेदित स्थिति (मार्च 2022)	लेखापरीक्षा के अनुसार स्थिति	अधिक दावा
1	भागलपुर	70	0	70	5	जहानाबाद	90	0	90
2	दरभंगाा	100	14	86	6	राजगीर	90	1	89
3	सहरसा	90	7	83	7	महाराजगंज	10	0	10
4	किशनगंज	70	15	55	8	बेलसंड	70	5	65

*(**स्रोतः** नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)*

8. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क संग्रहण में दक्षता– शहरी विकास मंत्रालय के सेवा स्तर मानक हस्त–पुस्तिका के अनुसार, 'संग्रहण मे दक्षता' से तात्पर्य वर्तमान वर्ष के राजस्व वसूली की तुलना में उसी अवधि में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कुल परिचालन राजस्व (अर्थात, बिहार के शहरी स्थानीय निकाय के संदर्भ में उपभोक्ता शुल्क) की प्रतिशतता से है। इसका निर्धारित मानक 90 प्रतिशत है। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क संग्रहण में दक्षता' के संबंध में दावा किया गया था कि मार्च 2022 तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क का संग्रहण शून्य से 90 प्रतिशत था।

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम 53(1)[59] के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकायों को उपभोक्ता शुल्क के वास्तविक माँग की गणना करनी थी, लेकिन नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इसकी गणना नहीं की गई थी। अतः लेखापरीक्षा द्वारा घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा संस्थानो की संख्या मे उनके श्रेणी

---

[56] *गया, दरभंगा, मुंगेर, सहरसा, किशनगंज, जहानाबाद, राजगीर, दलसिंहसराय तथा बेलसंड।*

[57] *भागलपुर, पूर्णिया, छपरा, दानापुर, जमुई, सुल्तानगंज, बड़हिया, बहादुरगंज, मखदुमपुर, झंझारपुर, अमरपुर एवं महाराजगंज।*

[58] *पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गोपालगंज, रामनगर, जगदीशपुर एवं मुरलीगंज।*

[59] *बिहार नगरपालिका लेखा नियम 2014 के नियम 53 (1) के अनुसार, जहां किसी भी कर का भुगतान करदाताओं द्वारा किया जाना है, संबंधित विभाग को बीएमएआर फॉर्म 23 में एक माँग पंजी बनाया जाना चाहिए।*

(यथा घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा संस्थानों) के लिए निर्धारित न्यूनतम उपभोक्ता शुल्क की दर से गुणा करके न्यूनतम संग्रहणीय उपभोक्ता शुल्क की राशि निकाली गई।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में पाई गई स्थिति **तालिका 5.10** में दर्शायी गई है।

तालिका 5.10
वित्तीय वर्ष 2021–22 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क (उपभोक्ता शुल्क) संग्रहण में दक्षता

(₹ करोड़ में)

क्र0 स0	विवरण	उपभोक्ता शुल्क की न्यूनतम संग्रहणीय राशि (लेखापरीक्षा के अनुसार)	संग्रहित उपभोक्ता शुल्क की वास्तविक राशि
1	नमूना जांच किये गये 16 शहरी स्थानीय निकाय[60]	7.11	शून्य
2	नमूना जांच किये गये आठ शहरी स्थानीय निकाय[61]	5.99	1.21
3	नमूना जांच किये गये दो शहरी स्थानीय निकाय[62]	11.49	25.03
4	नमूना जांच किये गये दो शहरी स्थानीय निकाय[63]	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

*(**स्रोत**: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)*

तालिका 5.10 से निम्नलिखत स्पष्ट हैं:

(i) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान नमूना जांच किये गये 16 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा न्यूनतम ₹ 7.11 करोड़ उपभोक्ता शुल्क की राशि वसूलनीय थी, लेकिन इनके द्वारा उपभोक्ता शुल्क की कोई भी राशि वसूल नहीं की गई थी।

(ii) आठ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा न्यूनतम वसूलनीय उपभोक्ता शुल्क की राशि ₹ 5.99 करोड़ की तुलना में मात्र ₹ 1.21 करोड़ के उपभोक्ता शुल्क की ही वसूली की गई थी।

इस प्रकार, नमूना जांच किये गये 24 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क के संग्रहण की दक्षता लगभग नौ प्रतिशत[64] ही थी।

(iii) पटना एवं गया नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुमानित उपभोक्ता शुल्क की न्यूनतम वसूलनीय राशि ₹ 11.49 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान वास्तविक वसूल की गयी राशि ₹ 25.03 करोड़ थी। चूँकि, लेखापरीक्षा में वित्तीय वर्ष 2021–22 के वास्तविक वसूलनीय राशि को प्रस्तुत नहीं किया गया, इसीलिए लेखापरीक्षा द्वारा उपभोक्ता शुल्क संग्रहण की दक्षता पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकी।

(iv) मुंगेर नगर निगम तथा मुरलीगंज नगर पंचायत द्वारा उपभोक्ता शुल्क संग्रहण से संबंधित आँकड़ों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किये गये पाँच शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अधिक उपभोक्ता शुल्क संग्रहण के दक्षता का दावा किया गया था, जो कि 10 से 80 प्रतिशत तक था, जैसा कि **तालिका 5.11** में दर्शाया गया है।

---

[60] *भागलपुर, पूर्णिया, छपरा, दानापुर, हाजीपुर, जमुई, गोपालगंज, सुल्तानगंज, रामनगर, बड़हिया, बहादुरगंज, जगदीशपुर, मखदुमपुर, झंझारपुर, अमरपुर एवं महाराजगंज।*

[61] *मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, किशनगंज, जहानाबाद, राजगीर, दलसिंहसराय एवं बेलसंड।*

[62] *गया एवं पटना*

[63] *मुंगेर एवं मुरलीगंज*

[64] *1.21/(7.11+5.99) = 9.24 ~ 9 प्रतिशत*

तालिका 5.11
नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अधिक प्रतिवेदित किये गये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क संग्रहण में दक्षता

(स्थिति प्रतिशत में)

क्र0 स0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	प्रतिवेदित स्थिति (मार्च 2022)	लेखापरीक्षा के अनुसार स्थिति	अधिक दावा
1	दरभंगाा	90	65	25
2	किशनगंज	90	72	18
3	दलसिंहसराय	80	15	65
4	मखदुमपुर	80	0	80
5	महाराजगंज	10	0	10

*(**स्रोतः** नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)*

9. उपभोक्ता शिकायत निवारण में दक्षता– शहरी विकास मंत्रालय के सेवा स्तर मानक हस्त–पुस्तिका के अनुसार, 'उपभोक्ता शिकायत निवारण में दक्षता' से आशय है कि किसी समयावधि में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधित प्राप्त शिकायतों मे से कितने प्रतिशत शिकायतो का निवारण इन शिकायतों के मिलने के 24 घंटों के अंदर किया जाता है। इसका निर्धारित मानक 80 प्रतिशत है। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 'उपभोक्ता शिकायत निवारण में दक्षता' के संबंध में दावा किया गया था कि मार्च 2022 तक उपभोक्ता शिकायत निवारण में उनकी दक्षता शून्य से 90 प्रतिशत थी।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गयाः

i. सिर्फ चार[65] शहरी स्थानीय निकायों में शिकायत निवारण पंजी का संधारण किया जा रहा था, जबकि उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए पटना एवं हाजीपुर में कॉम्बैट सेल का गठन किया गया था।

ii. दरभंगाा नगर निगम द्वारा शिकायत पंजी का संधारण किया गया था तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान तीन शिकायतें दर्ज की गईं थीं, लेकिन पंजी में उनके निवारण की तिथि दर्ज नहीं की गई थी। इसके कारण सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि शिकायतों का निवारण 24 घंटे के भीतर कर लिया गया था।

iii. बहादुरगंज नगर पंचायत द्वारा शिकायत पंजी का संधारण किया गया था, लेकिन, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान इस पंजी में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं पाया गया।

iv. दलसिंहसराय नगर परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान शिकायत पंजी में 10 शिकायतें दर्ज की गई थीं और उनका निवारण भी कर लिया गया था, लेकिन निवारण 24 घंटों के भीतर नहीं किया गया था।

v. नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए पटना नगर निगम तथा हाजीपुर नगर परिषद् द्वारा कॉम्बैट सेल का गठन किया गया था, लेकिन पटना नगर निगम द्वारा दर्ज शिकायतों एवं उनके निपटान से संबंधित आँकड़ों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। हाजीपुर नगर परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 226 शिकायतें दर्ज की गईं थीं लेकिन, अभिलेखों में शिकायतों के निवारण के विरूद्ध तिथि उपलब्ध नहीं थी। इसके कारण सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि शिकायतों का निवारण 24 घंटे के भीतर कर लिया गया था।

इसके अतिरिक्त, घरों/दुकानदारों के संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि 51 प्रतिशत उत्तरदाता अपने शहरी स्थानीय निकायों मे शिकायत दर्ज कराने के तरीके से परिचित नहीं थे।

[65] *दरभंगा– फरवरी 2021 से, पूर्णिया– फरवरी 2021 से, दलसिंहसराय– नवंबर 2021 से एवं बहादुरगंज– जनवरी 2021 से ।*

इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकायों में उपभोक्ता शिकायत निवारण की स्थिति अत्यधिक असंतोषप्रद थी।

10. संयुक्त भौतिक सत्यापन– निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान (अगस्त 2022–जनवरी 2023) वार्डों, बाजारों, रेलवे स्टेशन परिसरों के बाहर, बस स्टैंड इत्यादि में (क) सड़कों की सफाई (ख) स्वच्छता और (ग) कूड़ा संग्रहण की स्थिति के आकलन के लिए लेखापरीक्षा एवं शहरी स्थानीय निकायों के कर्मियों द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया था।

इसके अतिरिक्त, प्रसंस्करण स्थलों तथा भरण स्थलों का भी संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया था। इस कार्य द्वारा डोर–टू–डोर अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण एवं परिवहन में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता की पुष्टि हुई।

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा डोर–टू–डोर कूड़ा संग्रहण के दावों के बावजूद भी सड़कों के किनारे अथवा खुले स्थानों में कूड़ा फेंके जाने के कई मामले देखे गए। पर्याप्त प्रसंस्करण के अभाव में लगभग सभी अवशेष अपशिष्ट डंपिंग स्थल पर फेंके हुए देखे गये। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाए गए शहरी स्थानीय निकायों की स्थिति को ***परिशिष्ट– 5.3*** के छायाचित्रों में दर्शाया गया है।

सत्रह[66] शहरी स्थानीय निकायों ने अपने जवाब में आश्वासन दिया कि सुधार हेतु प्रयास किया जाएगा। इन 17 शहरी स्थानीय निकायों में से तीन[67] शहरी स्थानीय निकायों ने मानक संकेतकों को प्राप्त नहीं करने का कारण मानवबल का अभाव बताया।

5.2.2 निष्कर्ष

नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सेवा स्तर मानकों के आठ मानदंडों में से किसी भी मानक को प्राप्त नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति को बढ़ाकर विभाग को प्रतिवेदित किया गया था तथा वे सत्यापन के योग्य भी नहीं थे क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने दावों के समर्थन में कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया था।

5.2.3 अनुशंसा

नगर विकास एवं आवास विभाग प्रभावी अनुश्रवण द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निर्मित नीति एवं रणनीति का अनुपालन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु पर्याप्त एवं वस्तुनिष्ठ रूप से सत्यापन योग्य अभिलेखों का संधारण तथा मानकों की प्राप्ति सुनिश्चित कर सकता है।

---

[66] *गया, छपरा, जहानाबाद, राजगीर, मखदुमपुर, महाराजगंज, किशनगंज, बहादुरगंज, दानापुर, रामनगर, बेलसंड, हाजीपुर, पूर्णिया, भागलपुर, जमुई, सुल्तानगंज एवं मुंगेर।*

[67] *बेलसंड, हाजीपुर एवं मुंगेर।*

5.3 लेखांकन प्रक्रिया और वित्तीय प्रबंधन

शहरी स्थानीय निकाय अपनी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों को सरकारी अनुदान और आंतरिक राजस्व के संयुक्त स्रोतों से वित्तपोषित करते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की उचित योजना बनाने के लिए, सभी प्रासंगिक लागतों और राजस्व को ध्यान में रखते हुए सटीक वित्तीय गणना की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं तभी स्थायी होती हैं, जब वे स्वयं वित्तीय रूप से व्यवहारिक हों। इस कंडिका में, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपनाई गई लेखांकन प्रक्रिया, उपभोक्ता शुल्क के संग्रह के लिए उनके द्वारा किये गए प्रयास के साथ ही शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अन्य अनुदानों की प्राप्ति और उपयोग की स्थिति पर भी चर्चा की गई है।

5.3.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पृथक लेखांकन

बिहार नगरपालिका लेखा मैनुअल का अनुच्छेद 4.7 और बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 का नियम 5, निधि–आधारित लेखांकन का प्रावधान करता है, अर्थात् ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अलग लेखांकन का प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निधि–आधारित लेखांकन का पालन नहीं किया था। परिणामस्वरूप, शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अलग रोकड़ बही या लेखाओं का संधारण नहीं किया गया था। इसीलिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपलब्ध निधि के साथ ही उससे किये गये व्यय की सही स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों को आंतरिक राजस्व के स्रोतों, पंचम और छठे राज्य वित्त आयोग अनुदानों, चौदहवीं और पंद्रहवीं वित्त आयोग अनुदानों, स्वच्छ भारत मिशन अनुदान और राज्य योजना (नागरिक सुविधायें–स्वच्छता) से वित्त पोषित किया गया था। इन अनुदानों के उपयोग के लिए निर्गत निर्देशों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर खर्च किये जाने वाले राशि के विशिष्ट प्रतिशत का उल्लेख नहीं किया गया था। किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अपने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए पूंजीगत और राजस्व निधि की आवश्यकताओं का आकलन नहीं किया गया था और इसलिए वे इस संबंध में अपने संसाधन की कमी से अवगत नहीं थे।

शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर भी, निधियों का कोषवार आवंटन नहीं किया गया था, जिसके कारण निधि–आधारित लेखांकन का संधारण नहीं किया गया था।

पाँच शहरी स्थानीय निकायों[68] ने आश्वासन दिया कि सुधारात्मक कदम उठाये जायेंगे। चार शहरी स्थानीय निकायों[69] ने जवाब दिया कि विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरांत सुधारात्मक उपाय किये जायेंगे। दो शहरी स्थानीय निकायों[70] ने बताया कि मामला विभागीय स्तर पर विचाराधीन है।

दो शहरी स्थानीय निकायों[71] ने कोष–आधारित लेखांकन के अभाव के लिए मानवबल की कमी और/या जानकारी की कमी को कारण बताया। नगर पंचायत, बड़हिया ने जवाब दिया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अलग से निधि प्राप्त नहीं हुई थी, इसीलिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अलग से लेखा का संधारण नहीं किया गया था।

नगर परिषद्, सहरसा ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राशि विभागीय निर्देशानुसार रखी गई थी और तदनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जा रहा था। नगर निगम, पूर्णिया ने जवाब दिया कि निधि–आधारित लेखांकन से कार्य का दोहराव और मानवबल का अनावश्यक उपयोग होगा।

---

[68] *दरभंगा, सुल्तानगंज, भागलपुर, जमुई और रामनगर।*

[69] *जहानाबाद, मखदुमपुर, महाराजगंज और छपरा।*

[70] *किशनगंज और बहादुरगंज।*

[71] *बेलसंड और हाजीपुर।*

सुधारात्मक उपाय अपनाने के आश्वासन के अलावा अन्य नगर निकायों के द्वारा दिया गया जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि, वे बिहार नगरपालिका लेखा मैनुअल और बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली के प्रावधानों के विरूद्ध हैं।

5.3.2 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपभोक्ता शुल्क लगाना और वसूलना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 128 (ii) और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (च) में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु राजस्व के स्थायी स्रोत सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों पर उपभोक्ता शुल्क लगाने और वसूल करने का प्रावधान है। उपभोक्ता शुल्क का उद्देश्य ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए सेवाएं प्रदान करने की लागत को पूर्ण या आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति करना है।

विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना (जुलाई 2013) के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से उपभोक्ता शुल्क की वसूली नहीं की जानी थी। विभाग द्वारा अधिसूचित उपभोक्ता शुल्क की न्यूनतम दरें **तालिका 5.12** में दी गई हैं।

तालिका 5.12

उपभोक्ता शुल्क की न्यूनतम दरें

क्र0 सं०	विवरण	उपभोक्ता शुल्क के लिए न्यूनतम दरें (₹ प्रतिमाह)		
		नगर निगम	नगर परिषद्	नगर पंचायत
1	आवासीय	30	25	20
2	गैर–आवासीय	100	75	50
3	संस्थान	500	250	150

*(**स्रोत:** बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, जुलाई 2013)*

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं पर लगाये जाने वाले और वसूल किये जाने वाले उपभोक्ता शुल्क के मांग की गणना नहीं की थी। परिणामतः, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय वसूल किये जाने वाले उपभोक्ता शुल्क की वास्तविक राशि से अनभिज्ञ थे।

इसके अलावा, उपभोक्ता शुल्क लगाने और वसूल करने के उद्देश्य से अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के वर्गीकरण/श्रेणियों (जैसे रेस्तरां, बैंक, कोचिंग कक्षाएं, अस्पताल आदि) से सम्बंधित अभिलेखों को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा संधारित नहीं किया गया था। बिहार सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना (जुलाई 2013) के विपरीत नमूना जांच किये गये 28 शहरी स्थानीय निकायों में से 15[72] द्वारा 2020-22 के दौरान उपभोक्ता शुल्क वसूल नहीं किया गया था। संबंधित अभिलेखों के अभाव के कारण 2017-20 के लिए उपभोक्ता शुल्क की वसूल की जाने वाली राशि की गणना लेखापरीक्षा द्वारा नहीं की जा सकी।

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/सूचनाओं[73] के आधार पर, लेखापरीक्षा ने वसूली योग्य न्यूनतम उपभोक्ता शुल्क, वसूल की गई राशि और वसूल किये जाने वाले शेष (गरीबी रेखा से नीचे के घरों के लिए समायोजित[74]) राशि की गणना की जिसे **तालिका 5.13** में दिखाया गया है और विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 5.4*** में दिया गया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2020-22 के दौरान ₹ 17.07 करोड़ उपभोक्ता शुल्क की कम वसूली की गई।

---

[72] *भागलपुर, पूर्णिया, दानापुर, हाजीपुर, जमुई, गोपालगंज, सुल्तानगंज, रामनगर, बड़हिया, बहादुरगंज, जगदीशपुर, मखदुमपुर, झंझारपुर, अमरपुर और महाराजगंज।*

[73] *नगर निकायों द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपी गई रिपोर्ट, या नगर निकायों द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत की गई जानकारियों से घरों, वाणिज्यिक उद्यमों और संस्थानों की संख्या ली गई है।*

[74] *गरीबी रेखा से नीचे के घरों का सर्वेक्षण 2007 में किया गया था तथा इससे संबंधित आँकड़ा वेबसाईट :http://rcueslucknow.org/states/Compendium%20of%20Urban%20Data%20(Bihar)/_44_%20ULB%20WISE%20BPL%20FAMILIES%20IN%20BIHAR%20_AS%20PER%202007%20BPL%20SURVEY_.pdf से प्राप्त किया गया।*

तालिका 5.13
वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान उपभोक्ता शुल्क की कम वसूली

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं०	विवरण (संख्या)	न्यूनतम वसूलनीय उपभोक्ता शुल्क	वसूल किये गये उपभोक्ता शुल्क	उपभोक्ता शुल्क की कम वसूली
1	पटना नगर निगम	17.28	25.30	--
2	गया नगर निगम	3.18	3.20	--
3	नगर निगम (6), पटना और गया नगर निगम को छोड़कर	10.67	1.03	9.64
4	नगर परिषद् (11)	7.63	1.30	6.33
5	नगर पंचायत (8)[75]	1.11	0.008	1.102
कुल			**30.838**	**17.07**

(***स्रोत:*** *नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)*

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपभोक्ता शुल्क का भुगतान नहीं करने की स्थिति में, घरों से उपभोक्ता शुल्क की वसूली के लिए नियमों/उपनियमों में कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं किया गया था।

नौ शहरी स्थानीय निकायों[76] ने आश्वासन दिया कि इस सम्बन्ध में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी और उपभोक्ता शुल्क की वसूली में धीरे–धीरे सुधार किया जाएगा। छः शहरी स्थानीय निकायों[77] ने जवाब दिया कि उनके नगरपालिका बोर्डों द्वारा अनुमोदन के बाद, उपभोक्ता शुल्क लगाया और वसूल किया जाएगा। नगर परिषद्, सहरसा ने अपने जवाब में माना कि कई घरों से उपभोक्ता शुल्क नहीं वसूला जा रहा था। नगर पंचायत, बेलसंड ने सूचित (अक्टूबर 2022) किया कि उपभोक्ता शुल्क की वसूली अब शुरू की गई थी। जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि उपभोक्ता शुल्क, शहरी स्थानीय निकायों के लिए स्वयं के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है।

5.3.3 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के लिए अनुदान

भारत सरकार ने एक प्रमुख योजना 'स्वच्छ भारत मिशन–शहरी' प्रारंभ (अक्टूबर 2014) किया और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इसके छः घटकों में से एक था। स्वच्छ भारत मिशन–शहरी के दिशानिर्देशों की कंडिका 7.2 और 7.3 के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को राज्य सरकार के परामर्श से अपने–अपने शहरों से संबंधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना था।

(i) उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण केन्द्रांश की हानि – ₹ 74.20 करोड़

भारत सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दो चरणों (2017 में चरण–I और 2019 में चरण–II) में बिहार के 48 शहरों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति दी और परियोजना लागत का एक निश्चित प्रतिशत[78] अनुदान के रूप में देने की प्रतिबद्धता जताई। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, के निर्देशानुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में शामिल कार्यों को मार्च 2021 तक पूर्ण किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 708.04 करोड़ की परियोजना लागत के विरूद्ध भारत सरकार का अंश ₹ 231.73 करोड़ (भारत सरकार द्वारा संशोधित) था, जबकि भारत सरकार ने अप्रैल 2019 तक केवल ₹ 157.53 करोड़ विमुक्त किया था, जैसा कि **तालिका 5.14** में दर्शाया गया है।

---

[75] *सूचना के अभाव में, नगर पंचायत, मुरलीगंज को इस गणना से बाहर रखा गया है।*

[76] *किशनगंज, बहादुरगंज, जहानाबाद, मखदुमपुर, गया, छपरा, राजगीर, हाजीपुर और रामनगर।*

[77] *सुल्तानगंज, जमुई, पूर्णिया, भागलपुर, महाराजगंज और बड़हिया।*

[78] *केन्द्रीय सहायता–35 प्रतिशत, राज्य सहायता–23.30 प्रतिशत और शहरी स्थानीय निकायों का अंश–41.70 प्रतिशत।*

तालिका 5.14
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के लिए केन्द्रांश की हानि

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं०	परियोजना	संशोधित परियोजना लागत / परियोजना लागत	प्रतिबद्ध भारत सरकार का अंश	भारत सरकार द्वारा विमुक्त अंश	भारत सरकार का शेष अंश
1	चरण–I (छः शहर)[79]	150.57	52.70	52.70	शून्य
2	चरण–II (22 गंगा शहर)[80]	227.81	79.73	39.87	39.86
3	चरण–II: पटना नगर निगम	199.08	68.69	34.35	34.34
4	चरण–II: 19 अन्य शहर[81]	130.58	30.61	30.61	शून्य
	कुल	**708.04**	**231.73**	**157.53**	**74.20**

*(**स्रोत:** नगर विकास एवं आवास विभाग)*

केन्द्रीय सहायता की हानि का कारण राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों की विफलता थी, जो पूर्व में विमुक्त अनुदानों के लिए भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र (जनवरी 2023) जमा करने में विफल रहे, जिसके कारण ये शहरी स्थानीय निकाय ₹ 74.20 करोड़ की राशि के अनुदान से वंचित रह गए।

(ii) नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को ₹ 64.02 करोड़ का केन्द्रांश विमुक्त नहीं किया जाना

नगर विकास एवं आवास विभाग को विमुक्त (वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2019-20) किये गये केन्द्रांश की राशि ₹ 157.53 करोड़ में से नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा केवल ₹ 93.51 करोड़ (59 प्रतिशत) शहरी स्थानीय निकायों को विमुक्त (वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20) किया गया, जैसा की **तालिका 5.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.15
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को विमुक्त नहीं किया गया केन्द्रांश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	परियोजना	भारत सरकार द्वारा विमुक्त अंश	शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित केन्द्रीय अंश
1	चरण–I (छः शहर)	52.70	19.29
2	चरण–II (22 गंगा शहर)	39.87	39.87
3	चरण–II: पटना नगर निगम	34.35	34.35
4	चरण–II: 19 अन्य शहर	30.61	0
	कुल	**157.53**	**93.51**

*(**स्रोत:** नगर विकास एवं आवास विभाग)*

यह मुख्य रूप से स्वच्छ भारत मिशन–शहरी अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय घटक के लिए ₹ 28 करोड़ के हस्तांतरण (मार्च 2018) के कारण था, जो निधि के विचलन का संकेत था। शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित नहीं की गई शेष राशि का कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाया गया।

(iii) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ₹ 87.70 करोड़ का उपयोग नहीं किया जाना

नगर विकास एवं आवास विभाग ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 29 शहरी स्थानीय निकायों (चरण–II: 19 शहरों को छोड़कर) को (वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक) ₹156.08 करोड़ हस्तांतरित किया। इसमें केन्द्रांश के साथ–साथ राज्यांश का क्रमशः ₹ 93.51 करोड़ और ₹ 62.57 करोड़ शामिल था।

---

[79] *बेतिया, बोधगया, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और सीवान।*

[80] *छपरा, मुंगेर, बेगुसराय, भागलपुर, बाढ़, हाजीपुर, मोकामा, बख्तियारपुर, बक्सर, फतुहा, खगड़िया, जमालपुर, सुल्तानगंज, दानापुर, तेघड़ा, मनेर, बड़हिया, मनिहारी, सोनपुर, नवगछिया, कहलगांव और दिघवारा।*

[81] *दाउदनगर, रक्सौल, गोपालगंज, अररिया, औरंगाबाद, बगहा, डालमियानगर, फुलवारीशरीफ, सासाराम, फारबिसगंज, डुमराव, मधुबनी, नरकटियागंज, मसौढ़ी, सिलाव, राजगीर, कॉटी, सिमरी–बख्तियारपुर और मखदुमपुर।*

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुल राशि ₹156.08 करोड़ में से, इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मात्र राशि ₹ 68.38 करोड़ (44 प्रतिशत) का ही उपयोग (जनवरी 2023) किया गया। निधियों का उपयोग नहीं करने के कारण इन शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया में कमियां पाई गईं।

इसके अलावा, व्यय की गई राशि ₹ 68.38 करोड़ में से, इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ₹ 36.03 करोड़ (जनवरी 2023 तक) का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया था।

(iv) अपशिष्ट के प्रसंस्करण और स्वास्थ्यकर भरण स्थल के विकास के लिए अनुदान का उपयोग नहीं किया जाना

शहरी स्थानीय निकायों को विमुक्त राशि का उपयोग, अपशिष्ट के प्राथमिक संग्रहण के लिए वाहनों/उपकरणों की खरीद, द्वितीयक भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण हेतु पिट और अन्य सुविधाओ के निर्माण तथा स्वास्थ्यकर भरण स्थलों के विकास के लिए किया जाना था।

चयनित शहरी स्थानीय निकायों में से चार[82] द्वारा किये गए व्यय की जांच करने पर (जिन निकायों द्वारा किये गए व्यय का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया था) पाया गया कि नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराये गये ₹ 96.26 करोड़ में से किसी भी राशि का उपयोग अपशिष्टों के प्रसंस्करण या स्वास्थ्यकर भरण स्थलों के विकास के लिए नहीं किया गया था। राशि ₹ 15.32 करोड़ का व्यय मुख्य रूप से प्राथमिक संग्रहण, द्वितीयक भंडारण और परिवहन तक ही सीमित था, जबकि, ₹ 61.46 करोड़ की राशि विशेष रूप से प्रसंस्करण एवं स्वास्थ्यकर भूमि भरण स्थलों के स्थापना के लिए निर्धारित की गई थी।

अनुदानों का उपयोग प्रसंस्करण एवं स्वास्थ्यकर भूमि भरण स्थलों के विकास के लिए नहीं करने के कारण इन शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों को डंपिंग स्थलों में गिराया गया था और ये खुले स्थलों में अप्रसंस्कृत पड़े हुए थे।

5.3.4 अनुदान का व्यपगत होना

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने पंचम राज्य वित्त आयोग, चौदहवीं वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन तथा 'राज्य योजना' (नागरिक सुविधाएं–स्वच्छता) मद से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए चार शहरी स्थानीय निकायों[83] को ₹ 34.13 करोड़ विमुक्त (जुलाई 2018 से अगस्त 2019) किया था। हालांकि, यह राशि संबंधित कोषागारों से नहीं निकाली गई थी। परिणामस्वरूप, ₹ 34.13 करोड़ का अनुदान व्यपगत हो गया था।

केवल एक शहरी स्थानीय निकाय नगर पंचायत, बेलसंड ने जवाब (अक्टूबर 2022) दिया कि उसने व्यपगत अनुदान के पुनः आवंटन के लिए विभाग के साथ पत्राचार किया था। हालांकि, व्यपगत अनुदान का पुनः आवंटन होना बाकी था (अक्टूबर 2022)। इसके अलावा, नगर पंचायत को भी कोषागार से राशि निकासी नहीं होने के कारणों के बारे में जानकारी नहीं थी। इस राशि के व्यपगत होने का कारण समय पर आवंटन पत्र का नहीं मिलना या नगर पंचायत के नियमित कार्यपालक पदाधिकारी का नहीं होना बताया गया।

इस संबंध में न तो कोई अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया गया और न ही शेष तीन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इस संबंध में लेखापरीक्षा प्रश्नावली का जवाब लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराय गया। इसीलिए, लेखापरीक्षा निकासी नहीं होने के कारणों को ज्ञात नहीं कर सका।

---

[82] *भागलपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, और सुल्तानगंज।*

[83] *दरभंगा: ₹ 25.89 करोड़ (पंचम राज्य वित्त आयोग– ₹ 14.23 करोड़, चौदहवीं वित्त आयोग– ₹ 11.66 करोड़), मुंगेर: ₹ 0.01 करोड़ (स्वच्छ भारत मिशन), बड़हिया: ₹ 5.13 करोड़ (पंचम राज्य वित्त आयोग – ₹ 3.99 करोड़, चौदहवीं वित्त आयोग– – ₹ 1.14 करोड़), बेलसंड: ₹ 3.10 करोड़ (पंचम राज्य वित्त आयोग – ₹ 1.78 करोड़, चौदहवीं वित्त आयोग – ₹ 1.02 करोड़, नागरिक सुविधा सफाई व्यवस्था– ₹ 0.30 करोड़)।*

5.3.5 उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित नही किया जाना

वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत किये गए (अक्टूबर 2011) निर्देशों के अनुसार सरकारी अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अनुदान विमुक्त किये जाने के 18 महीने के अंदर जमा करना है। बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम 69 (9) के अनुसार अनुदान की कोई भी अवशेष राशि, उक्त अनुदान की प्राप्ति की तारीख से तीन साल से अधिक समय तक अप्रयुक्त रहने पर उसी स्रोत को वापस कर दिया जाना है जहां से अनुदान प्राप्त हुआ था।

(i) 2017-22 के दौरान चौदहवीं वित्त आयोग, पंद्रहवीं वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, राज्य योजना (नागरिक सुविधाएं–स्वच्छता) मदों से प्राप्त ₹ 269.96 करोड़ ***(परिशिष्ट–5.5)*** का उपयोगिता प्रमाण पत्र नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा एक से छतीस माह के विलम्ब से विभाग में जमा किया गया था।

(ii) उपरोक्त अवधि के लिए, अगस्त 2022 से दिसंबर 2022 तक कुल राशि ₹ 1,180.29 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग में जमा नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट–5.6)***।

तीन शहरी स्थानीय निकायों[84], ने अपने जवाब में विभिन्न कारणों जैसे कि मानवबल की कमी, कोविड महामारी इत्यादि के कारण कार्यों/योजनाओं के पूरा होने में विलंब को उपयोगिता प्रमाण पत्र के विलंब/नहीं जमा होने के लिए जिम्मेवार बताया। कार्यपालक पदाधिकारी, सुल्तानगंज ने बताया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया गया था।

जवाब मान्य नहीं थे, क्योंकि संबंधित अनुदान की प्राप्ति के 18 से 63 महीने बीत जाने के बाद भी उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किये गए थे।

5.3.6 वस्तु एवं सेवा कर का परिहार्य भुगतान – ₹ 5.95 करोड़

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना (जून 2017) के अनुसार, किसी भी गतिविधि के माध्यम से, संविधान के अनुच्छेद 243डब्ल्यू के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय को सौंपे गये किसी भी कार्य के संबंध में, शहरी स्थानीय निकाय को प्रदान की जाने वाली शुद्ध सेवाओं[85] (कार्य अनुबंध सेवाओं या अन्य समग्र आपूर्ति जिसमें किसी वस्तु की आपूर्ति शामिल है, को छोड़कर) को वस्तु और सेवा कर से छूट प्रदान की गई है।

इसीलिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रदान की गई सेवाओ को 'शुद्ध सेवा' माना गया और वे वस्तु एवं सेवा कर से छूट प्राप्त करने के योग्य थे।

इसके बावजूद, लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जांच किये गये चार शहरी स्थानीय निकायों[86] में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और उससे संबंधित कार्यों के लिए मानव संसाधन सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसियों को भुगतान किये गये विपत्रों में वस्तु एवं सेवा कर की राशि ₹ 5.95 करोड़ शामिल थी।

इस सम्बन्ध में, नगर आयुक्त, मुंगेर ने जवाब दिया कि अतिरिक्त भुगतान की वसूली/समायोजन के लिए संबंधित संवेदक को नोटिस जारी किया जायेगा और स्रोत पर काटे गए वस्तु एवं सेवा कर को पहले ही वाणिज्यिक कर विभाग के पास जमा कर दिया गया था।

उप नगर आयुक्त, दरभंगा ने जवाब दिया कि एजेंसी को नोटिस जारी कर दिया गया था और एजेंसी के जवाब के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

---

[84] *भागलपुर, जमुई और मुंगेर।*

[85] *'शुद्ध सेवा' शब्द उन सभी अनुबंधों को शामिल करता है जहां वस्तु की आपूर्ति नहीं होती है, यानि, कोई भी आपूर्ति जिसे या तो केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की अनुसूची II के तहत 'सेवाएं' माना जाता है या कोई भी आपूर्ति जो 'वस्तु' की परिभाषा में शामिल नहीं होती है। 'शुद्ध सेवा' शब्द संविधान की धारा 243W के तहत नगरपालिका या किसी अन्य सार्वजनिक निकाय को सौंपे गए कार्य को भी संदर्भित करता है।*

[86] *दानापुर: ₹ 357.03 लाख, दरभंगा: ₹ 89.41 लाख, मुंगेर: ₹ 85.37 लाख और मुजफ्फरपुर: ₹ 63.01 लाख।*

5.3.7 निष्कर्ष

वित्तीय प्रबंधन अपर्याप्त था, जैसा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निधि–आधारित लेखांकन का रखरखाव नहीं करने, उपभोक्ता शुल्क कम वसूल करने, उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने, कोषागार से आवंटन की निकासी नहीं करने, निधियों का उपयोग नहीं करने, वस्तु और सेवा कर का परिहार्य भुगतान करने आदि के रूप में पाया गया।

5.3.8 अनुशंसाएं

- ***शहरी स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अलग लेखा का संधारण कर सकते हैं। विभाग स्तर पर या शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निधियों को विभाजित/निर्धारित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।***
- ***शहरी स्थानीय निकाय निर्धारित दरों से उपभोक्ता शुल्क वसूल कर सकते हैं, और उपभोक्ता शुल्कों की वसूली में सुधार लाने के लिए दंड/प्रोत्साहन का प्रावधान कर सकते हैं।***

5.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना एवं रणनीति

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली नगरपालिका सेवाओं का एक अभिन्न अंग है, जो किसी शहर के सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए, एक रणनीतिक और विस्तृत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना की तैयारी और कार्यान्वयन आवश्यक है।

यह कंडिका, नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्र में उत्पन्न ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु योजना बनाने के तरीके पर प्रकाश डालती है।

5.4.1 योजना

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट हस्तक के अनुच्छेद 1.4.4.1.1 के अनुसार, योजना तैयार करने वाली मुख्य टीम में शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त या मुख्य कार्यकारी शामिल होंगे जो नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए उत्तरदायी और जवाबदेह होंगे। वार्ड स्तर के कर्मी योजना बनाने की प्रक्रिया के दौरान क्षेत्र स्तर के सुझाव और जानकारी को सूचित करेंगे।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 नियत करता है कि प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय एक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करेगी। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट हस्तक के अनुच्छेद 1.4.5.1 के अनुसार, भविष्य में जनित होने वाले अपशिष्ट की मात्रा[87] और उसकी संरचना का अनुमान लगाना, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। नगरपालिका ठोस अपशिष्टों के प्रसंस्करण, उपचार या निपटान परियोजनाओं हेतु योजना सुविधानुसार, सामान्यतः 20 से 30 वर्षों के लिए बनाया जाना चाहिए।

आगे, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट हस्तक, 2016 के अनुच्छेद 1.1 के अनुसार, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 20–25 वर्षों वाली एक दीर्घकालिक योजना पर विचार करना है एवं कार्यान्वयन में सुगमता के लिए इस योजना को, पाँच वर्षों वाली अल्पावधि योजनाओं में विभाजित किया जाना है। मध्यावधि सुधार के लिए अल्पावधि योजनाओं को आवश्यतानुसार प्रत्येक 2–3 वर्षों के अंतराल पर समीक्षा कर अद्यतन किया जाना है। स्थानीय प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि अल्पावधि योजनाएं, दीर्घकालिक योजना एवं उसके कार्यान्वयन के अनुरूप हों।

[87] *भविष्य में अपशिष्ट उत्पादन = प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन x अनुमानित जनसंख्या*

इसके अतिरिक्त, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट हस्तक, 2016 के अनुच्छेद 1.4.3 के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को आधारभूत सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए, जिसका उद्देश्य, यथासंभव, मौजूदा ठोस अपशिष्ट व्यवस्था को ठीक–ठीक समझना तथा व्यवस्था की कमियों का आकलन कर, इन सूचनाओं को अग्रेतर योजना की तैयारी, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण प्रक्रिया के लिए उपयोग करना है। इसके अलावा, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट हस्तक, 2016 के अनुच्छेद 5.2.3 के अनुसार, सभी बुनियादी ढांचा आधारित सुविधाओं हेतु पर्याप्त विवरण के साथ एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की आवश्यकता है जिससे परियोजना का समयबद्ध तथा कुशल तरीके से मूल्यांकन, अनुमोदन एवं अग्रेतर कार्यान्वयन सुनिश्चित हो।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित पाया गया;

- नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा (गया नगर निगम को छोड़कर) दीर्घकालिक योजना तैयार नहीं किया गया था। इसके अलावा, किसी भी चयनित शहरी स्थानीय निकाय में जनित अपशिष्टों तथा उसके प्रबंधन की वास्तविक स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत अध्ययन नहीं किया गया था।
- लेखापरीक्षा के समय (अगस्त 2022 से जनवरी 2023) तक, नमूना जांच किये गये 13 शहरी स्थानीय निकायों[88] द्वारा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट हस्तक के अनुरूप विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन या अन्य कोई योजना तैयार नहीं किया गया था, जबकि नमूना जांच किये गये शेष 15 शहरी स्थानीय निकायों[89] द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया था। हालांकि, इन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के जांच में पाया गया कि गया नगर निगम, जहाँ के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में 2032 तक का विश्लेषण (जैसे– जनसंख्या, अपशिष्ट जनित प्रस्तावित आधारभूत संरचना, अक्रिय अपशिष्ट की मात्रा आदि) था, को छोड़कर, सभी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में 2018 के अनुमानित जनसंख्या[90] के आधार पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सिर्फ आधारभूत संरचना/राशि की आवश्यकता को ही शामिल किया गया था एवं कोई दीर्घावधि या अल्पावधि योजना जैसा कि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट हस्तक में उल्लेखित है, को शामिल नहीं किया गया था।

अतः, इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बिना किसी योजना के ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों को कार्यान्वित किया जा रहा था। फलस्वरूप ये शहरी स्थानीय निकाय आवश्यकता–आधारित विश्लेषण के बजाय धन की उपलब्धतानुसार तदर्थ आधार पर व्यय करने के लिए विवश थे।

लेखापरीक्षा में पाये गए त्रुटिपूर्ण योजना के उदाहरणों का सार इस प्रकार है:

क) स्रोत पर अपशिष्टों के पृथक्करण और उसके बाद अपशिष्टों के प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किये बिना ही (यथा; पृथक्करण के बिना अपशिष्टों को अस्वीकार करना, निर्देश न मानने वाले घरों पर जुर्माना लगाना आदि) घरों में वितरण हेतु ₹ 19.41 करोड़ की लागत से डस्टबिन, खरीदे गए थे। इसका विस्तृत विवरण आगे की ***कंडिका 5.5.2.2*** में उपलब्ध है।

ख) राशि ₹ 13.65 करोड़ की लागत से 213 अधिक ऑटो टीपरों का क्रय किया गया था एवं वैसे वाहनों (₹ 3.11 करोड़) को खरीदा गया था जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकुल नहीं थे। इस प्रकार क्रय किए गए वाहन अनुपयोगी पड़े हुए थे और आठ से लेकर 62 महीनों से खड़े थे।

---

[88] *दलसिंहसराय, झंझारपुर, सहरसा, मुरलीगंज, बहादुरगंज, पूर्णिया, जमुई, अमरपुर, रामनगर, जगदीशपुर, बेलसंड, जहानाबाद एवं महाराजगंज।*

[89] *दरभंगा, दानापुर, किशनगंज, भागलपुर, मुंगेर, सुल्तानगंज, बड़हिया, पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गोपालगंज, राजगीर, छपरा, गया एवं मखदुमपुर।*

[90] *पटना नगर निगम को छोड़कर, जिसके विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में आधार वर्ष 2019 तथा डिजाइन वर्ष 2023 लेते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निधि/आधारभूत संरचना की आवश्यक्ता का आकलन किया गया था।*

ग) लेखापरीक्षा के दौरान (अगस्त 2022–जनवरी 2023) पाया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपकरण यथा, श्रेडिंग मशीन, ई–रिक्शा, ठेला, हाथ ठेला, ट्राई–साईकल, डस्टबिन, पशु शवदाह मशीन आदि का क्रय (लागत ₹ 5.63 करोड़) किया गया था, जो कि क्रय के समय से ही अनुपयोगी रखे हुए थे; विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में निर्धारित आवश्यकता से अधिक कूड़ेदानों का क्रय (₹ 2.31 करोड़); एवं उठाने वाले उपकरणों के बिना ही 1100 लीटर डस्टबिन का क्रय (₹ 1.97 करोड़) किया गया था। इनका विस्तृत विवरण ***कंडिका 5.7*** में दिया गया है।

घ) राज्य प्रदत निःशुल्क सेवा उपलब्ध होने के बावजूद क्लाउड सर्वर पर ₹ 1.25 करोड़ का व्यय किया गया (विस्तृत विवरण आगे की ***कंडिका 5.8.5*** में उपलब्ध है); तथा बिना किसी योजना के सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों पर ₹ 4.23 करोड़ का व्यय किया गया था (विस्तृत विवरण आगे की ***कंडिका 5.4.4*** में उपलब्ध है), इत्यादि।

कार्यपालक पदाधिकारी, बेलसंड ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नहीं बनाने का कारण नगर प्रबंधक एवं नगर अभियंता के अनुपलब्धता को बताया। उप नगर आयुक्त, छपरा, ने बताया कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में भविष्य की आवश्यकताओं का विचार किया गया था तथा वर्ष 2018 की स्थिति के अनुसार सिर्फ परियोजना लागतों की गणना की गई थी।

उप–नगर आयुक्त, छपरा का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में सिर्फ यह उल्लेखित था कि स्वास्थकर भरणस्थल 10 वर्षों के लिए होगा एवं वर्ष 2018 के लिए आधारभूत संरचना/राशि की आवश्यकता बतायी गयी थी। इस प्रकार, भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्ण विचार नहीं किया गया था जैसा कि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट हस्तक में बताया गया था।

5.4.2 बजट

(i) बिहार नगरपालिका बजट हस्तक के कंडिका 7.2 के अनुसार, बजट दिशानिर्देश तैयार करने एवं जारी करने की जिम्मेवारी मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अथवा बजट निर्माण टास्क फोर्स[91] की है।

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में पाया गया कि बजट या तो चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा या शहरी स्थानीय निकायों के कर्मियों द्वारा स्वयं तैयार किया जा रहा था। इसके अलावा, नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा नगरपालिका कर्मियों को बजट तैयार करने के लिए कोई विशिष्ट नियम एवं शर्त अथवा दिशानिर्देश नहीं दिये गये थे।

इसके अतिरिक्त, बजट तैयार करने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी क्योंकि किसी भी नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में बजट तैयार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश/नीति; क्रमबद्ध चर्चाओं के द्वारा सुधार; चार्टर्ड एकाउंटेंट/कर्मियों को दिए गए सुझावों के कार्यान्वयन आदि का दस्तावेजीकरण नहीं किया जा रहा था।

(ii) बजट हस्तक का कंडिका 5.2 एवं 7.5 नियत करता है कि सेवाओं (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित) के मौजूदा एवं वांछित स्तर के आकलन के लिए एक नागरिक सर्वेक्षण किया जाना है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में सर्वेक्षण से, घरों द्वारा अपशिष्ट निपटान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया; अपशिष्ट निपटान की बारंबारता; अपशिष्ट संग्रहण हेतु भुगतान की जा रही राशि; घरों से नगरीय अपशिष्ट डस्टबिन की दूरी; साफ–सफाई प्रक्रिया से नागरिकों के संतुष्टि के स्तर आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। सर्वेक्षण के परिणाम

[91] *मुख्य नगरपालिका अधिकारी के अध्यक्षता में, शहरी स्थानीय निकायों के लेखा प्रमुख अथवा नामित बजट अधिकारी के समन्वय से सर्कल, कार्यवार आंचलिक कार्यालय एवं/या केन्द्रीय कार्यालय के वरिष्ठ कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाता है।*

को प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर माह के अन्त तक उपलब्ध कराना है ताकि, सेवाओं के स्तरों एवं वास्तविक स्थिति के संदर्भ मे सर्वेक्षण से प्राप्त परिणामों को शहरी स्थानीय निकायों को बजट निर्माण करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले उपलब्ध हो।

अभिलेखों के जांच में पाया गया कि किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा इस प्रकार का सर्वेक्षण नहीं किया गया था। नागरिक सर्वेक्षण की जगह, छः शहरी स्थानीय निकायों[92] द्वारा बजट बनाने हेतु नागरिकों का सुझाव प्राप्त करने के लिए, समाचार पत्रों मे आम सूचना का प्रकाशन किया गया था और इसके जवाब में सिर्फ कुछ नागरिकों की ही प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी। बजट तैयार करने की प्रक्रिया में इनके सुझावों को शामिल करने से संबंधित साक्ष्य अभिलेखों में नहीं पाया गया।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किये गये बजट संचिकाओं में सर्वेक्षण नहीं किये जाने का कारण नहीं पाया गया। इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मौजूदा एवं वांछित स्तर के आकलन के लिए सर्वेक्षण नहीं किया गया था। इसलिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित नगरीय सेवाओं को प्रदान करने और आधारभूत संरचनाओं में निवेश की कुशलता और प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

(iii) उपरोक्त हस्तक की कंडिका 5.1.2 के अनुसार, आगामी बजट वर्ष के लिए वार्ड समिति अथवा इस तरह के अन्य सार्वजनिक मंचों के द्वारा वार्ड वार सुझाव लिया जाना है। जबकि, नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा इस प्रकार के सुझाव नहीं मांगे गये थे या बजट निर्माण में इसको शामिल नहीं किया गया था।

(iv) बजट हस्तक की कंडिका 7.3 नियत करता है कि प्रत्येक सेवा के लिए कुल बजट की गणना, उस सेवा के अंतर्गत प्रत्येक लागत केन्द्र के लिए निर्मित बजट के आधार पर किया जाना है। हालांकि, केन्द्र वार/सेवा वार बजट लागत, जैसा कि उपरोक्त कंडिका 7.3 मे उल्लेखित है, तैयार नहीं किया गया था। साथ ही, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सूचना सहित, कार्यवार बजट (बिहार नगरपालिका बजट हस्तक के फार्मेट बीयूडी-5 में) सार के साथ तैयार नहीं किया गया था।

(v) लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में विभिन्न विभागों (शहरी स्थानीय निकायों के अंदर के), लोगों एवं वार्डों से सूचना प्राप्त करने हेतु कार्यपत्रक (बिहार नगरपालिका बजट हस्तक में उल्लेखित बजट सूचना पत्रक) संलग्न नहीं थे।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये बजट अभिलेखों में, बजट बनाने की योजना से संबंधित अभिलेखों/चर्चा टिप्पणियों आदि (बजट बनाने की प्रक्रिया के अन्तिम समय में बजट अनुमोदन के लिए नगरपालिका बोर्ड और सशक्त स्थाई समिति के कार्यवृत को छोड़कर) जिसके आधार पर बजट तैयार किये गये थे, नहीं पाए गये, जो इस बात का द्योतक था कि बजट निर्माण (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बजट निर्माण सहित) संबंधी कार्य यथोचित रूप से नहीं किया गया था। अर्थात् शहरी स्थानीय निकाय बिना किसी सोची समझी रणनीति के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य कर रहे थे, जिसके कारण इसमें कई कमियां थीं।

नगर पंचायत बेलसंड ने अपने जवाब में बताया कि अपर्याप्त मानवबल के कारण बजट की तैयारी में कमियां थीं। नगर निगम, पूर्णिया ने सर्वेक्षण हेतु विशेष निधि के अभाव को नागरिक सर्वेक्षण नहीं कराये जाने का कारण बताया तथा यह भी बताया कि नागरिकों के सुझाव को प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक सूचना वेबसाईट पर प्रकाशित की गई थी।

---

[92] *दरभंगा, मुंगेर, सुल्तानगंज, किशननगंज एवं दानापुर। इसके अतिरिक्त पूर्णिया नगर निगम ने बताया कि बजट निर्माण हेतु सुझाव प्राप्त करने के लिए, वेबसाईट पर जनसूचना का प्रकाशन किया गया था। हालांकि, किस समय सूचना का प्रकाशन किया गया था यह लेखापरीक्षा को नहीं बताया गया था।*

नगर निगम, पूर्णिया का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि, नागरिक सर्वेक्षण, नगरपालिका निधि के आंतरिक/स्वयं के स्रोतों से की जा सकती थी। नागरिकों के सुझाव को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक सूचना का वेबसाईट पर प्रकाशन, बजट हस्तक में निर्दिष्ट तरीके से नागरिक सर्वेक्षण किये जाने का विकल्प नहीं है।

5.4.3 क्षमता वर्द्धन

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का नियम 11(ञ), 15(ठ) एवं 15(यग), नगर विकास एवं आवास विभाग/शहरी स्थानीय निकायों को अपशिष्टों के पृथक्करण का प्रबंधन एवं परिवहन अथवा प्रसंस्करण करने वाले कर्मियों (संविदा कामगारों सहित) के क्षमता वर्द्धन के साथ–साथ अपशिष्ट चुननेवालों एवं संग्रहित करने वालों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु विनिर्दिष्ट करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कर्मियों एवं अपशिष्ट चुननेवालों के लिए कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया था। हालांकि, यह देखा गया कि दो शहरी स्थानीय निकायों[93] में नगरपालिका कर्मियों द्वारा कुछ अनौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया गया था। इस प्रकार, लगभग सभी नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्षमता वर्द्धन अपर्याप्त था।

5.4.4 सूचना, शिक्षण और संचार गतिविधियाँ

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट हस्तक 2016 के अनुच्छेद 1.4.5.13 के अनुसार, नागरिकों को उनके अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी व्यवहार में बदलाव लाने के लिए जागरूकता एवं शिक्षण अभियान आवश्यक है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15(यछ), के अनुसार भी, शहरी स्थानीय निकायों को सूचना, शिक्षण और संचार अभियानों के द्वारा लोगों को जागरूक करना है, तथा अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों को, अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित के बारे में शिक्षित करना हैः कचरा नहीं फैलाने; जैविक, अजैविक (पुनर्चक्रण योग्य तथा दहन योग्य), स्वास्थ्यकर अपशिष्ट तथा घरेलु परिसंकटमय अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण; स्रोत पर पृथक्कृत कचरे का विभिन्न अपशिष्ट डस्टबिनों में भंडारण तथा पृथक्कृत कचरे को अपशिष्ट संग्राहकों अथवा पुनर्चक्रणकर्त्ताओं को हस्तगत कराना आदि।

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट हस्तक 2016 के अनुच्छेद 1.4.5.13 के अनुसार, सूचना, शिक्षण एवं संचार अभियान को सिर्फ घरों, दुकानों तथा व्यावसायिक एवं संस्थागत परिसरों को ही नहीं बल्कि अन्य सभी हितधारकों जैसे नगरपालिका के कर्मियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, विद्यालयों, गैर–सरकारी संस्थाओं, अनौपचारिक क्षेत्रों, मीडिया इत्यादि को भी लक्षित करना चाहिए जिससे वे अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निर्वहन कर शहर के अपशिष्ट प्रबंधन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

नगर विकास एवं आवास विभाग ने भी शहरी स्थानीय निकायों को, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को सम्मिलित करते हुए नागरिकों को स्रोत पर अपशिष्टों के पृथ्ककरण के लिए जागरूक करने का निर्देश (मई 2019) दिया।

लेखापरीक्षा ने इस संबंध में निम्नलिखित पाया;

(i) नमूना जांच किये गये 15 शहरी स्थानीय निकायों[94] ने सूचना, शिक्षण और संचार संबंधी गतिविधियाँ (यथा नुक्कड़ नाटक, दिवालों पर चित्रकारी आदि) की थी। इसके अतिरिक्त, छः शहरी स्थानीय निकायों[95] ने बताया कि उनके द्वारा सूचना, शिक्षण और संचार गतिविधियाँ की गयी थीं लेकिन, लेखापरीक्षा को संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने में विफल रहे।

---

93 *दानापुर एवं दरभंगा।*

94 *भागलपुर, दरभंगा, दानापुर, हाजीपुर, किशनगंज, जमुई, गोपालगंज, रामनगर, राजगीर, दलसिंहसराय, बहादुरगंज, झंझारपुर, मुरलीगंज, अमरपुर एवं महाराजगंज।*

95 *बेलसंड, छपरा, जगदीशपुर, जहानाबाद, मखदुमपुर एवं पटना।*

पाँच शहरी स्थानीय निकायों[96] में इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं थी। नमूना जांच किये गये शेष दो शहरी स्थानीय निकायों[97] ने वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान कोई भी सूचना, शिक्षण और संचार गतिविधियाँ नहीं की थी ***(परिशिष्ट– 5.7)***।

(ii) इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि जिन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा, वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान, ₹ 4.23 करोड़ के व्यय से सूचना, शिक्षण और संचार गतिविधियाँ (नुक्कड़ नाटक, दिवाल पेंटिंग आदि) की गयी थी, वह बिना किसी योजना के ही की गयी थी, जैसा कि ***परिशिष्ट–5.7*** में दर्शाया गया है।

हालांकि, घरों के संयुक्त सर्वेक्षण तथा संयुक्त भौतिक सत्यापन में 77 प्रतिशत लोगों ने कराये गये सूचना, शिक्षण और संचार गतिविधियों के विषय में अनभिज्ञता जताया जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि चलाये गये सूचना, शिक्षण और संचार गतिविधियाँ अप्रभावी थे। सड़क किनारे, तालाब किनारे अथवा तालाब में, नदी किनारे आदि कई स्थानों पर, मिश्रित अपशिष्ट पड़ा हुआ पाया गया। अपशिष्ट में आग लगाने की घटनाएँ भी बड़े पैमाने पर देखी गयी।



कृष्णा नगर क्षेत्र, स्टेशन चौक से मीर टोला, सहरसा में सड़क किनारे अपशिष्ट के ढ़ेर में लगाई गई आग।



सड़क किनारे अपशिष्ट (अलपट्टी चौक से दोनार रोड) दरभंगा।

(iii) तीन शहरी स्थानीय निकायों[98] ने बताया कि, उनके द्वारा अपशिष्टों को स्रोत पर पृथक्करण के लिए जागरूकता फैलाने हेतु स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सम्मिलित किया गया था। हालांकि, ये शहरी स्थानीय निकाय, लेखापरीक्षा को संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने में विफल रहे।

5.4.5 अपशिष्ट न्यूनीकरण के प्रयासों का अभाव

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट हस्तक, 2016 के अनुच्छेद 1.2 एवं 2.1, पर्यावरण प्राथमिकता के क्रम में एक चरणबद्ध दृष्टिकोण को विहित करता है, जिसमें अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, अपशिष्ट के रोक–थाम को सर्वाधिक तरजीह जबकि निपटान को सबसे कम तरजीह दिया जाना है। यह तीन आर[99] दृष्टिकोण के साथ नजदीकी रूप से संबद्ध है, जो अपशिष्ट की मात्रा, उनके संचालन का खर्च तथा पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट हस्तक 2016[100] में, उल्लेखित निर्णय लेने वालों के लिए मुख्य सुझावों में कहा गया है कि तीन आर सिद्धांत के प्रचार एवं प्रसार में शहरी स्थानीय निकाय अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं।

---

96 *गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया एवं सुल्तानगंज।*

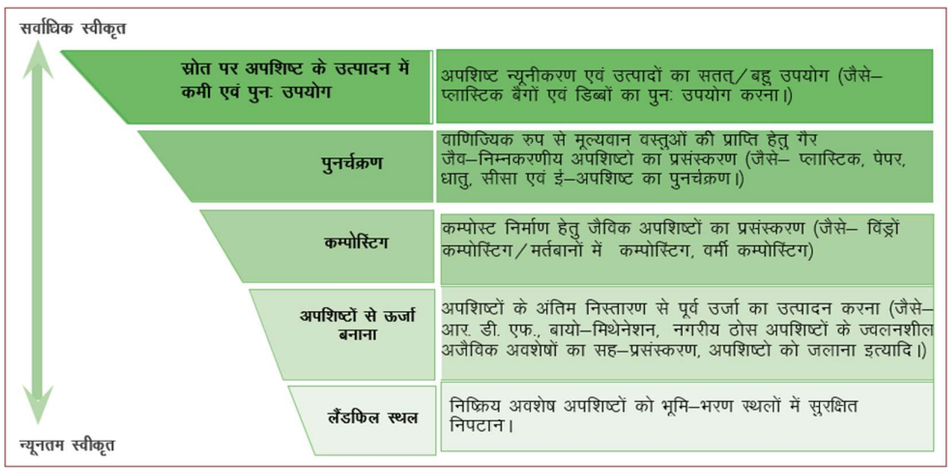
97 *बड़हिया एवं सहरसा।*

98 *दलसिंहसराय, मुंगेर एवं किशनगंज।*

99 *उत्पादन में कमी, पुनः उपयोग एवं पुनर्चक्रण (रेडयूस, रियुज एवं रिसाइकल)*

100 *नगरपालिका ठोस अपशिष्ट हस्तक, 2016 भाग–1 का खंड 3.1*

चार्ट 5.3: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अनुक्रम



*(**स्रोत** : नगरपालिका ठोस अपशिष्ट हस्तक, 2016)*

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, मार्च 2022 तक, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्टों के रोक–थाम, उत्पादन में कमी, पुनः उपयोग एवं पुनर्चक्रण के लिए कोई कारगर नीति/रणनीति नहीं अपनाई थी, जो वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, संग्रहित अपशिष्ट में से 78 प्रतिशत (लगभग 2,033 टन प्रतिदिन)[101] अपशिष्ट को, बिना प्रसंस्करण के ही भरण स्थल/डंपिंग स्थल पर जमा करने की स्थिति को रोक सकता था।

5.4.6 अपशिष्टों का उत्पादन एवं आकलन

शहरी सीमा में विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के उत्पादन का एक विश्वसनीय आकलन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के योजना एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। हालांकि, अपशिष्टों के उत्पादन के आकलन में निम्नलिखित कमियां देखी गयीं–

5.4.6.1 उत्पन्न अपशिष्ट का अपर्याप्त आकलन

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट हस्तक, 2016 के अनुच्छेद 1.4.3.3.1 विहित करता है कि, दीर्घकालिक योजना के लिए, विशिष्ट श्रेणी के उत्पादकों द्वारा निपटाये गये अपशिष्ट के औसत मात्रा का आकलन, विविध नमूनों में से केवल संकलित औसत आँकड़ों के आधार पर किया जा सकता है। इन नमूनों का संग्रह, तीन प्रमुख ऋतुओं, यथा, ग्रीष्म, सर्दी एवं वर्षा में से प्रत्येक में, संबंधित नगर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न चयनित स्थानों से लगातार सात दिनों की अवधि तक किया जाना था। सात दिनों तक अपशिष्ट को एकत्रित कर, वजन करके, उनका औसत किया जाना था। प्राप्त मात्राओं को संपूर्ण शहरी स्थानीय निकाय के लिए विस्तारित करके प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन का आकलन किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों ने विहित कार्यप्रणाली का पालन नहीं किया था। इसके बदले, उनके द्वारा उत्पादित औसत अपशिष्ट की गणना करने के लिए जनसंख्या आधारित आकलन/प्रति–व्यक्ति पद्धति को अपनाया गया था, जो कि विश्वसनीय आकलन नहीं था। इसके अतिरिक्त, अपशिष्ट उत्पादन के आकलन के लिए अपनायी गयी इस पद्धति में, शहरी सीमा के अंदर, अपशिष्ट उत्पादन के आकलन में हुये सामयिक उतार–चढ़ावों (सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक कारकों; जैसे– त्योहारों/समारोहों आदि) को सम्मिलित नहीं किया गया था।

[101] *शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बीएसपीसीबी को सौंपी गई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार; 28 नमूना शहरी स्थानीय निकायों में प्रति दिन एकत्रित अपशिष्ट = 2,608 टन प्रति दिन और प्रसंस्कृत अपशिष्ट = 575 टन प्रति दिन। (2,608–575=2,033 टन प्रतिदिन)*

नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश (अक्टूबर 2021) के आलोक में, 14 शहरी स्थानीय निकायों[102] द्वारा अपशिष्टों का वर्गीकरण एवं मात्रा का अध्ययन कराया (अक्टूबर 2021–दिसंबर 2021) गया था। हालांकि, इन शहरी स्थानीय निकायों ने संग्रहित अपशिष्टों का वजन नहीं कराया था, जिसके कारण इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किये गये अपशिष्टों का आकलन, केवल एक अनुमान था और यह वास्तविक आँकड़ा नहीं था। परिणामस्वरूप, शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट उत्पादन के वास्तविक मात्रा से अनभिज्ञ थे।

तलिका–5.16
अपशिष्टों के वर्गीकरण एवं मात्रा के अध्ययन के आकलन के साथ शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किये गये अपशिष्टों के आकलन की तुलना

(मात्रा टन प्रतिदिन में)

क्र. स.	शहरी स्थानीय निकाय	अपशिष्टों के वर्गीकरण एवं मात्रा के अध्ययन के अनुसार अपशिष्ट की मात्रा	जून 2021 मे, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समर्पित प्रतिवेदन/लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, अपशिष्ट की मात्रा	जून 2022 मे, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समर्पित प्रतिवेदन/लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, अपशिष्ट की मात्रा
1	पटना	1,250	850	1000
2	मुजफ्फरपुर	182	उपलब्ध नहीं	180
3	दरभंगा	201	120	120
4	मुंगेर	89	65	88*
5	छपरा	87 से 92	उपलब्ध नहीं	87.5*
6	सहरसा	70 से 80	39	31
7	दानापुर	91	95	95
8	किशनगंज	38	25	25
9	गोपालगंज	23	3	23
10	दलसिंहसराय	24 से 28	14	24[103]
11	बहादुरगंज	18 से 22	6.5	14
12	जगदीशपुर	17	6	4
13	मुरलीगंज	14 से 18	5	उपलब्ध नहीं
14	हाजीपुर	92	7	92

*(**स्रोत**: अपशिष्टों के वर्गीकरण एवं मात्रा का अध्ययन, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समर्पित प्रतिवेदन, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना; *लेखापरीक्षा के दौरान शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना पर आधारित)*

वर्ष 2021 के लिए, इन अध्ययन प्रतिवेदनों में अपशिष्टों के आकलन के साथ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किये गये अपशिष्ट उत्पादन के अनुमानों की तुलना से ज्ञात हुआ कि 11 चयनित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किये गये अपशिष्ट उत्पादन का अनुमान, शहरी स्थानीय निकायों में किये गये अपशिष्टों के वर्गीकरण एवं मात्रा का अध्ययन के अपशिष्टों के आकलन से कम था।

इसी प्रकार की प्रवृत्ति वर्ष 2022 में भी देखी गयी। अपशिष्टों के वर्गीकरण एवं मात्रा के अध्ययन के आलोक में, सुधारात्मक कार्रवाई नहीं किये जाने के संबंध में कोई कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। परिणामस्वरूप, असंग्रहित अपशिष्ट, भरण स्थल/डंपिंग स्थल के अलावा अन्य स्थानों जैसे– खुले स्थलों, सड़क किनारे, तालाबों/नदियों के किनारे इत्यादि स्थानों पर फेंके गये थे, जैसा कि आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

दो शहरी स्थानीय निकाय[104] ने अपने जवाब मे बताया कि, उनके द्वारा अपशिष्टों का आकलन, ढुलाई वाले वाहनों के ट्रीप के आधार पर किया गया था। नगर पंचायत,

[102] *इसके अलावे, गया और राजगीर ने अपने–अपने विस्तृत योजना प्रतिवेदन मे क्रमशः वर्ष 2015 तथा 2018 में अपशिष्ट उत्पादन का आकलन किया था।*

[103] *हालांकि, 19 टन प्रतिदिन संग्रहण प्रतिवेदित किया गया था।*

[104] *जमुई एवं पूर्णिया*

बड़हिया ने अपशिष्टों के उत्पादन/संग्रहण का आकलन नहीं करने का कारण प्रशिक्षित मानवबल एवं आवश्यक तकनीक का अभाव बताया। जबकि नगर निगम, भागलपुर ने अपशिष्टों के उत्पादन/संग्रहण का आकलन नहीं करने का कारण प्रशिक्षित मानवबल की कमी बताया, साथ ही यह भी बताया कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अपना प्रतिवेदन समर्पित करते समय, अपशिष्ट का आकलन किया जाता रहा है।

नगर निगम, भागलपुर का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि, उसने अपशिष्ट आकलन (उत्पादन या संग्रहण) किये जाने के समर्थन में कोई भी अभिलेखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया।

5.4.7 निष्कर्ष

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट हस्तक में बताये गये तरीके से तैयार की गई कोई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना नहीं थी। शहरी स्थानीय निकायों ने बजट बनाने के लिए, नागरिक सर्वेक्षण तथा वार्ड समिति के माध्यम से, वार्डवार सुझाव प्राप्त कर, सेवाओं के मौजूदा एवं वांछित स्तर का आकलन नहीं किया था। उन्होंने, वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान, अपने कर्मियों और अपशिष्ट चुननेवालों के लिए नियमित तौर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी नहीं किया था। सूचना, शिक्षण एवं संचार गतिविधियों का संचालन बिना किसी योजना के किया गया था। लागत केन्द्रित बजट नहीं बनाया गया था। फलस्वरूप, शहरी स्थानीय निकाय आवश्यकता–आधारित विश्लेषण के बजाय धन की उपलब्धतानुसार तदर्थ आधार पर व्यय करने के लिए विवश थे।

5.4.8 अनुशंसाएं

- ***विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि, शहरी स्थानीय निकाय, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट हस्तक में बताये गये तरीके से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए योजना बनाये।***
- ***विभाग अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान के संबंध में उचित पद्धति और तकनीक के चयन के लिए अपशिष्ट की वर्तमान और भविष्य की गुणवत्ता और मात्रा, भविष्य के अनुमानों और कमियों की पहचान और विश्लेषण के साथ एक प्रभावी नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करना सुनिश्चित कर सकता है।***
- ***शहरी स्थानीय निकाय बजट बनाने के लिए, तय समय–सीमा के अनुसार, विहित प्रक्रिया/संस्थानों के माध्यम से नागरिकों का सुझाव प्राप्त करना सुनिश्चित कर सकते हैं।***
- ***विभाग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबधित कर्मियों, पंजीकृत अपशिष्ट चुनने वालों एवं स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के क्षमता वर्द्धन के लिए प्रयास कर सकता है।***
- ***शहरी स्थानीय निकाय आवश्यकता आधारित सूचना, शिक्षण एवं संचार गतिविधियों को सुनिश्चित कर सकते हैं एवं तद्नुसार सूचना, शिक्षण एवं संचार गतिविधियों के लिए रणनीति/साधन तैयार कर सकते हैं।***

5.5 नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण और परिवहन

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, पृथक्कृत अपशिष्टों का डोर–टू–डोर संग्रह करना अनिवार्य है। आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत क्षेत्रों से पृथक्कृत अपशिष्टों के संग्रहण की योजना नगर निकायों द्वारा बनाई जानी है। इस कंडिका में ठोस अपशिष्टों को पृथक करने के साथ उसके संग्रहण और परिवहन के संबंध में शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों पर चर्चा की गयी है।

		
अपशिष्टों का स्रोत पर पृथक्करण	पृथक्कृत अपशिष्टों का संग्रहण	हाइड्रोलिक कंटेनर के साथ मिनी ट्रक (बंद टिपर)

5.5.1 विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश जारी करने में विलंब

(i) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु राज्य नीति और रणनीति माह अप्रैल 2017 तक तैयार कर लेनी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने फरवरी 2019 में, यानी लगभग दो वर्ष की विलंब से, राज्य शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति और रणनीति तैयार की थी।

(ii) इस राज्य नीति और रणनीति (फरवरी 2019) के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना था कि फरवरी 2020 तक सभी वार्डों से पृथक्कृत अपशिष्टों को एकत्र किया जाए, जैसा कि **तालिका 5.17** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.17

पृथक्कृत अपशिष्ट संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए समय–सीमा

नगर निगम	नगर परिषद्	नगर पंचायत
छः माह के भीतर, यानि अगस्त 2019 तक	12 माह के भीतर, यानि फरवरी 2020 तक	12 माह के भीतर, यानि फरवरी 2020 तक

*(**स्रोत**: राज्य शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति और रणनीति)*

इस प्रकार, विभाग ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति और रणनीति बनाने में विलंब की थी और शहरी स्थानीय निकायों को अगस्त 2019 से फरवरी 2020 की अवधि के बीच डोर–टू–डोर अपशिष्ट संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए कहा था।

हालांकि, माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण[105] के हस्तक्षेप (मार्च 2019) के बाद, नगर विकास एवं आवास विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों को बिना किसी विलंब के डोर–टू–डोर अपशिष्ट संग्रहण प्रारम्भ करने के लिए कहा (मई 2019)।

5.5.2 अपशिष्टों का पृथक्करण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, 'पृथक्करण' को ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों, अर्थात् विघटनीय अपशिष्ट, गैर–विघटनीय अपशिष्ट, गैर–पुनर्चक्रणीय दहनशील अपशिष्ट, स्वच्छ अपशिष्ट, घरेलू खतरनाक अपशिष्ट इत्यादि के छंटाई और पृथक भंडारण के रूप में परिभाषित करता है।

[105] *चूंकि स्वच्छ पर्यावरण अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है और स्थानीय निकायों के साथ–साथ राज्य को भी सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका से उत्पन्न हुई, जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी, जिसमें नगर निकायों के ठोस अपशिष्टों का संग्रहण, भंडारण, परिवहन, निपटान उपचार और पुर्नचक्रण की प्रणाली में सुधार के लिए कदम उठाने के लिए दिशा–निर्देश मांगे गए थे।*

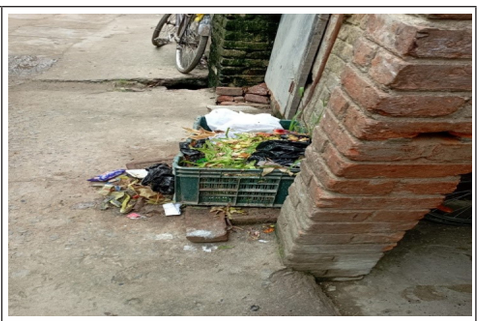
स्रोत पर अपशिष्ट को पृथक करने से यह सुनिश्चित होता है कि अपशिष्ट कम दूषित होगा और इसे संग्रहित करके आगे प्रसंस्करण के लिए ले जाया जा सकता है। अपशिष्टों का पृथक्करण अपशिष्ट प्रसंस्करण और उपचार प्रौद्योगिकियों को भी अनुकूलित करता है।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हस्तक, 2016 के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को कम से कम गीला और सूखा अपशिष्ट अलग–अलग संग्रहित करना आवश्यक है।

5.5.2.1 डोर–टू–डोर अपशिष्टों के पृथक्करण के लिए पूर्व आवश्यकताएँ

अपशिष्टों का डोर–टू–डोर पृथक्कृत संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए, नगर विकास एवं आवास विभाग (फरवरी 2019) ने वार्ड मैपिंग के साथ–साथ आधारभूत अध्ययन करने की रणनीति तैयार की। इस रीति से, अन्य बातों के अलावा, घरों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों/संस्थाओं; मौजूदा बुनियादी ढांचा और मानवबल क्षमता; संग्रहण करने वाले वाहनों की संख्या; संग्रहण करने वाले वाहनों का मार्ग; प्रति टिपर कवर किए गए घरों की संख्या; स्क्रैप विक्रेताओं की संख्या; कूड़े स्थलों की संख्या आदि को ज्ञात करने की उम्मीद थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किए गए किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने आधारभूत अध्ययन और वार्ड मैपिंग नहीं किया था। फलस्वरूप, शहरी स्थानीय निकाय डोर–टू–डोर से अनियोजित तरीके से पृथक्कृत अपशिष्ट संग्रहण करने के लिए विवश थे, इस कारण अपशिष्टों के संग्रहण में कमियां थीं, जैसा कि इस अध्याय के अग्रेतर कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

	
सहरसा में सड़क किनारे अपशिष्ट (प्लास्टिक और जैव–विघटनीय अपशिष्ट)।	दरभंगा के वार्ड 48 में एक परिवार द्वारा रखा गया मिश्रित अपशिष्ट

5.5.2.2 स्रोत/घरों के स्तर पर अपशिष्टों का पृथक्करण

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हस्तक, 2016 में तीन पृथक रंगों के डिब्बे (एक गीले अपशिष्टों के लिए, एक सूखे अपशिष्टों के लिए और एक घरेलू खतरनाक अपशिष्टों के लिए) की अनुशंसा की गई है। पृथक किए गए अपशिष्टों के संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए नगर आवास एवं विकास विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों को दो रंगों के अटूट घरेलू डस्टबिन हरा (जैव–विघटनीय अपशिष्टों के लिए) और नीला (गैर–जैव–विघटनीय अपशिष्टों के लिए); 10–12 लीटर की क्षमता के साथ, की आपूर्ति पाँच सदस्यों वाले प्रत्येक घर के लिए पहली बार निःशुल्क करने के लिए कहा (फरवरी 2019)।

(i) पटना नगर निगम क्षेत्र में (2021 तक) 2,72,936 घर थे। हालांकि, डस्टबिन का क्रय और वितरण घरों को नहीं किया गया। इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकाय ने घरों के स्तर पर स्रोत पृथक्करण की सुविधा प्रदान नहीं की।

(ii) गया नगर निगम के मामले में दोहरा क्रय किया गया, पहले एक लाख जोड़ी डस्टबिनों का क्रय (फरवरी 2018) किया गया और उसके बाद ₹ 6.80 करोड़ की लागत से 75,000 घरों में वितरण के लिए एक लाख ट्रिपल डस्टबिनों (मार्च 2021 से सितंबर 2021) का क्रय फिर से किया गया।

गया नगर निगम ने घरों में 87,500 जोड़े और 82,943 ट्रिपल सेट डस्टबिनों का वितरण किया। राशि ₹ 69.08 लाख के मूल्य की शेष डस्टबिनें, क्रय के बाद से (अक्टूबर 2022 तक) भंडार में पड़े हुए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्य की नीति और रणनीति के अनुसार, डस्टबिनों का वितरण (निःशुल्क) एक बार ही किया जाना था।

(iii) पृथक्करण के उद्देश्य से, नमूना जांच किये गये अन्य शहरी स्थानीय निकायों ने घरों के लिए डस्टबिन का क्रय और वितरण किया था, जैसा कि **तालिका 5.18** में दर्शाया गया है और ***परिशिष्ट 5.8*** में विस्तृत विवरण दिया गया है।

तालिका 5.18
घरेलू डस्टबिनों का क्रय एवं वितरण

शहरी स्थानीय निकाय #	घरों की कुल संख्या	वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान क्रय किये गए डस्टबिनों के सेट (जोड़े / ट्रिपल)	वितरित डस्टबिनों के सेट (जोड़े / ट्रिपल)	अभियुक्ति
पाँच शहरी स्थानीय निकाय[106]	1,08,221	1,35,708 जोड़ा	आँकड़ा अनुपलब्ध	लेखापरीक्षा को विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
19 शहरी स्थानीय निकाय[107]	4,17,995	3,46,950 जोड़ा	2,64,449 जोड़ा	82,501 जोड़े भंडार में पड़े हुए थे। मखदुमपुर में 565 डस्टबिन न तो भंडार में उपलब्ध थे और न ही उनके वितरण का ब्यौरा संधारित किया गया था।
एक शहरी स्थानीय निकाय[108]	6,073	4,200 एकल डस्टबिन	3,500 एकल डस्टबिन	भंडार में 700 एकल डस्टबिन पड़े हुए थे।
गया	75,000	1,00,000 जोड़ा 1,00,000 ट्रिपलेट	87,500 जोड़ा 82,943 ट्रिपलेट	भंडार में 12,500 जोड़े और 17,057 ट्रिपल सेट डस्टबिन पड़े हुए थे।

*(**स्रोत**: शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)*
नगर परिषद्, दानापुर द्वारा क्रय एवं वितरित किये गये डस्टबिनों की संख्या की जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी।

तालिका 5.18 शहरी स्थानीय निकायों के स्रोत पर पृथक्करण के प्रति उदासीन दृष्टिकोण को इंगित करता है, जैसा कि डस्टबिनों का उपयोग नहीं करने से, जो कि 12 माह से 82 माह की अवधि तक घरों को वितरण किये बिना भंडारों में पड़े रहे तथा एकल डस्टबिनों के क्रय और उनके वितरण से स्पष्ट होता है।

[106] *मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, जमुई, गोपालगंज, एवं बड़हिया*
[107] *भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, छपरा, सहरसा, हाजीपुर, किशनगंज, सुल्तानगंज, रामनगर, राजगीर, दलसिंहसराय, बहादुरगंज, जगदीशपुर, मुरलीगंज, अमरपुर, मखदुमपुर, महराजगंज एवं बेलसंड*
[108] *झंझारपुर*

			
बड़हिया, नगर परिषद में बिना ढक्कन वाले घरेलू डस्टबिन (दो रंगों का सेट)	भागलपुर, नगर निगम में अवितरित घरेलू डस्टबिन	पूर्णिया, नगर निगम में अवितरित घरेलू डस्टबिन	हाजीपुर, नगर परिषद में अवितरित घरेलू डस्टबिन

(iv) संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि, नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्टों के संग्रहण और परिवहन के लिए विभाजित और अविभाजित दोनों टिपरों का उपयोग किया जा रहा था। इसके अलावा, चयनित शहरी स्थानीय निकायों के घरों के सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त 949 प्रतिक्रियाओं के आधार पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल 232 (24 प्रतिशत) घरों ने स्रोत पृथक्करण किया था। कई मामलों में पाया गया कि बिना कोई पृथक्करण किये, अपशिष्टों को संग्रहित करते समय मिश्रित किया जा रहा था, अथवा बाद में डंपिंग स्थल पर, सभी अपशिष्टों को मिश्रित कर डंप किया जा रहा था। इस प्रकार, अपशिष्ट पृथक्करण के परिकल्पित प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा था।

		
जगदीशपुर में सड़क किनारे से मिश्रित अपशिष्ट संग्रहित करते सफाई कर्मचारी	पूर्णिया में सड़क किनारे से मिश्रित अपशिष्ट संग्रहित करते सफाई कर्मचारी	सहरसा में सड़क किनारे से उठाया जा रहा मिश्रित अपशिष्ट
		
गोपालगंज में सड़क किनारे से मिश्रित अपशिष्ट संग्रहित करते सफाई कर्मचारी	जहानाबाद में सड़क किनारे से मिश्रित अपशिष्ट संग्रहित करते सफाई कर्मचारी	भागलपुर में सड़क किनारे से उठाया जा रहा मिश्रित अपशिष्ट

इस प्रकार, डस्टबिनों के क्रय पर किया गया व्यय, ₹ 19.41 करोड़ (***परिशिष्ट–5.8***) निष्फल था।

दस शहरी स्थानीय निकायों[109] ने अपने जवाब में कहा कि, स्रोत पर अपशिष्टों को पृथक करने के लिए डस्टबिनों का वितरण और सूचना, शिक्षण और संचार गतिविधियों के बावजूद, अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं द्वारा मिश्रित अपशिष्ट दिया जा रहा था। नगर परिषद्, राजगीर ने जवाब दिया कि पृथक्करण स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा किया जा रहा था।

शहरी स्थानीय निकायों के जबाब स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अनुसार, अपशिष्टों का स्रोत पर पृथक्करण एक पूर्व आवश्यकता थी और, इसके लिए डस्टबिनों का क्रय करने के बावजूद, पृथक्करण प्रक्रिया को कई नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया था। नगर परिषद् राजगीर द्वारा किया जा रहा प्रयास कुछ वार्डों तक ही सीमित था।

5.5.2.3 वाणिज्यिक स्थानों से संग्रहित किये गये पृथक्कृत अपशिष्ट

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (ख) के अनुसार, वाणिज्यिक परिसरों सहित सभी स्रोतों से पृथक्कृत अपशिष्टों को संग्रहित करना शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हस्तक, 2016, के अनुच्छेद 2.2.1.2.2 के अनुसार, ''दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और व्यवसायों को स्थल पर ही अपशिष्टों का पृथक भंडारण किया जाना चाहिए''। संग्रहण से पूर्व, संग्रहित किए जाने वाले अपशिष्टों की मात्रा और अतिरिक्त 100 प्रतिशत भंडारण पर विचार करके आवश्यक डस्टबिनों की संख्या और क्षमता की गणना की जा सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग (फरवरी 2019) की नीति और रणनीति व्यवसायिक स्थानों पर अपशिष्टों को पृथक करने के लिए, वाणिज्यिक उपक्रमों को डस्टबिन का वितरण करने के संबंध में कुछ नहीं कहता है। परिणामस्वरूप, वाणिज्यिक उपक्रमों को डस्टबिन वितरण करने के संबंध में शहरी स्थानीय निकायों के निर्णय में एकरूपता नहीं थी।

नमूना जांच किए गए पंद्रह शहरी स्थानीय निकायों[110] ने वाणिज्यिक उपक्रमों को कोई डस्टबिन वितरित नहीं किया था। शेष 13 नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों ने दुकानदारों को या तो जोड़ा डस्टबिन या एकल डस्टबिन वितरित किए थे।

संयुक्त भौतिक सत्यापन और दुकानदारों के सर्वेक्षण के दौरान, यह देखा गया कि, सामान्यतः, दुकानदार अपने दुकानों के बाहर खुले में अपशिष्ट रख रहे थे, जहाँ से नगरपालिका के वाहन इसे एकत्र करते थे। सड़क के किनारे अपशिष्टों के छोटे–छोटे ढेर रखने का प्रचलन था, जो कि एक अरूचिकर दृश्य था।

इससे वाणिज्यिक दुकानों के अंदर और आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरणीय रूप से संकटमय स्थिति बनी हुईं थी।

---

[109] *सुल्तानगंज, भागलपुर, सहरसा, किशनगंज, बहादुरगंज, दानापुर, जहानाबाद, मखदुमपुर, छपरा एवं महराजगंज*

[110] *पटना, गया, भागलपुर, छपरा, हाजीपुर, किशनगंज, जमुई, दलसिंहसराय, दरभंगा, बहादुरगंज, झंझारपुर, बेलसण्ड, अमरपुर, बडहिया एवं राजगीर*

		
सड़क किनारे डंप किये हुए अपशिष्ट (हटियागाछी बाजार, सहरसा)	मुरलीगंज में सड़क के किनारे अपशिष्टों का ढेर (10/11/2022)	सड़क पर बिखरे अपशिष्ट (गोल बाजार से सिनेमा हॉल चौक रोड), मुरलीगंज (10/11/2022)

इसके अलावा, दुकानदारों को डस्टबिन का वितरण करने और दुकानदारों से अपशिष्ट संग्रहण करने के बावजूद, कई मामलों में, सड़कों के किनारे कचरा डंप किया हुआ पाया गया।

इस प्रकार, वाणिज्यिक उपक्रमों से अपशिष्ट संग्रहण के प्रभाव को सुव्यवस्थित करने और इस संबंध में एक स्पष्ट, राज्य–व्यापी नीति तैयार करने की आवश्यकता है।

5.5.2.4 घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को पृथक नहीं करना

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हस्तक के अनुसार, 'घरेलू खतरनाक' अपशिष्ट[111] सहित 'विशेष अपशिष्ट'[112] को नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ नहीं मिलाना चाहिए। 'घरेलू खतरनाक अपशिष्टों' का सुरक्षित निपटान करने के लिए इसे अलग से अपशिष्ट संग्रहकणर्ताओं को या घरेलू खतरनाक अपशिष्ट निक्षेपण केंद्रों पर सौंपा जाना चाहिए।

इसके अलावा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों की यह जिम्मेदारी है कि वे घरेलू खतरनाक अपशिष्टों के लिए अपशिष्ट निक्षेपण केंद्र स्थापित करें और अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं को निर्देश दें कि सुरक्षित निपटान के लिए वे अपने घरेलू खतरनाक अपशिष्टों को इन केंद्रों पर जमा करें। ऐसी सुविधा किसी शहर या कस्बे में इस प्रकार स्थापित की जानी है कि बीस वर्ग किलोमीटर या उसके भाग के क्षेत्र के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाए और ऐसे केंद्रों पर घरेलू खतरनाक अपशिष्ट प्राप्त करने के समय को अधिसूचित किया जाए।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया :

(i) चयनित 28 शहरी स्थानीय निकायों में से 27 में, घरेलू खतरनाक अपशिष्ट निक्षेपण केंद्र स्थापित नहीं किए गए थे। इसलिए, घरेलू खतरनाक अपशिष्टों को अंतिम रूप से डंपिंग स्थलों पर डंप किया जा रहा था।

(ii) नगर निगम, दरभंगा ने माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देश के अनुपालन में एक घरेलू खतरनाक अपशिष्ट निक्षेपण केंद्र स्थापित (मार्च 2021) करने को प्रतिवेदित किया था और इसके संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन नगर विकास एवं आवास विभाग को दिया था। इस स्थल के संयुक्त भौतिक सत्यापन में, ऐसा कोई अपशिष्ट निक्षेपण केन्द्र

---

[111] *ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार, 'घरेलू खतरनाक अपशिष्ट' का अर्थ घरेलू स्तर पर उत्पन्न संक्रामक अपशिष्ट जैसे फेंके गए पेंट ड्रम, कीटनाशक के डिब्बे, सी.एफ.एल बल्ब, ट्यूब लाइट, समाप्त हो चुकी दवाएं, टूटे हुए पारा थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरी, प्रयुक्त सुई और सिरिंज और संदूषित पट्टियाँ आदि से है।*

[112] *'विशेष अपशिष्ट' में कोई भी ठोस अपशिष्ट या ठोस अपशिष्टों का संयोजन शामिल होता है, जिसे मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण की रक्षा और पुनर्चक्रण की क्षमता का दोहन से रोकने के लिए इसकी मात्रा, विशेषताओं आदि के कारण विशेष प्रबंधन और निपटान की आवश्यकता होती है। 'विशेष अपशिष्ट' में प्लास्टिक अपशिष्ट, जैव–चिकित्सा अपशिष्ट, ई–अपशिष्ट आदि शामिल हैं।*

नहीं पाया गया। घरेलू खतरनाक अपशिष्ट निक्षेपण केंद्र के रूप में केवल एक डस्टबिन रखा गया था और वह डस्टबिन भी खाली पाया गया।

इसके अलावा, ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था जिससे सत्यापित हो सके कि इस केंद्र के बारे में आम जनता को जागरूक किया गया था।

	
दरभंगा नगर निगम द्वारा स्थापित घरेलू खतरनाक अपशिष्ट निक्षेपण केंद्र। निक्षेपण केंद्र के स्थान पर एक डस्टबिन पाया गया और डस्टबिन खाली था।	डंपिंग स्थल, बैरिया, पटना में मिश्रित अपशिष्ट (सब्जी अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और ट्यूबलाइट सहित)।

5.5.2.5 केंद्रीय छंटाई सुविधा/सामग्री वसूली सुविधा केंद्र में अपशिष्टों का पृथक्करण नहीं किया जाना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (ज) के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों को पुनर्चक्रणीय सामग्री के छंटाई के लिए सामग्री वसूली सुविधाएं या गौण भंडारण सुविधाएं[113] स्थापित करनी हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में स्रोत–स्तरीय पृथक्करण की अनुपस्थिति/कमी थी। इसलिए, अपशिष्टों का प्रसंस्करण/भरण स्थल तक पहुंचने से पूर्व इनका पृथक्करण सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी। नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायो में, यह देखा गया कि, अपशिष्टों को मिश्रित रूप में, प्राथमिक संग्रह केंद्रों[114] से, गौण भंडारण सुविधा में, और गौण भंडारण से भरण स्थल में स्थानांतरित किया जा रहा था। प्राथमिक भंडारण, गौण भंडारण और सामग्री वसूली सुविधा केंद्रों पर अपशिष्टों को पृथक करने में विफलता के परिणामस्वरूप अपशिष्टों से पुनर्चक्रणीय सामग्री की पुनर्प्राप्ति नहीं हुई, जिसके कारण अप्रसंस्कृत अपशिष्टों को भरण/डंपिंग स्थलों पर डंप किया गया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जांच किये गये छः शहरी स्थानीय निकायों[115] द्वारा सामग्री वसूली सुविधा केंद्रों/गौण भंडारण स्थलों पर आंशिक रूप से सामग्री की वसूली की जा रही थी।

तीन शहरी स्थानीय निकायों[116] में सामग्री वसूली सुविधाएं थीं, लेकिन इन केंद्रों पर अपशिष्टों के छंटाई की प्रथा नहीं थी। इन तीन केंद्रों के लिए क्रय किए गए उपकरण अधिष्ठापित नहीं किए गए थे और बेकार पड़े हुए थे, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र अक्रियाशील थे।

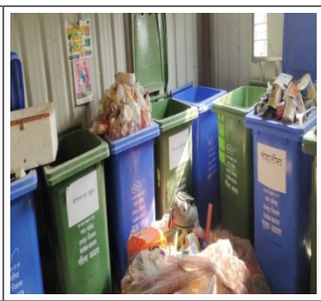
---

[113] *'गौण भंडारण' का अर्थ है, द्वितीयक अपशिष्ट भंडारण डिपो या एम.आर.एफ या डिब्बे में संग्रह के बाद, प्रसंस्करण या निपटान सुविधा एवं अपशिष्टों के परिवहन के लिए, ठोस अपशिष्टों का अस्थायी संदूषक।*

[114] *''प्राथमिक संग्रहण'' का अर्थ है पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को उसके उत्पादन के श्रोत जिसके अंतर्गत घरों, दुकानों, कार्यालयों और किसी अन्य गैर–आवासीय परिसर या किसी भी संग्रह बिंदु या स्थानीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य अवस्थान से संग्रहीत करना, उठाना या हटाना।*

[115] *पटना, दानापुर, राजगीर, दलसिंहसराय, सुल्तानगंज और अमरपुर*

[116] *दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया*

		
दानापुर में मिश्रित अपशिष्टों से पुनर्चक्रणीय अपशिष्टों को पृथक करते हुए, स्वयं सहायता समूह के कामगार	दानापुर में मिश्रित अपशिष्टों से पुनर्चक्रणीय सामग्री की प्राप्ति	भागलपुर में अक्रियाशील सामग्री वसूली सुविधा केन्द्र

5.5.2.6 अंतरण स्थल के निर्माण पर निष्क्रिय व्यय ₹16.23 लाख

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हस्तक के अनुसार, क्षेत्रीय सुविधाओं तक कम मात्रा में अपशिष्टों को ले जाने के व्यय को कम करने की दृष्टि से, अंतरण स्थल स्थापित किए जा सकते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का नियम 3, 'अंतरण स्थल' को परिभाषित करता है कि, संग्रह क्षेत्रों से ठोस अपशिष्ट प्राप्त करने के लिए सृजित सुविधा, जहाँ से बड़ी मात्रा में अपशिष्टों को कवर किये गये वाहनों या कंटेनरों में प्रसंस्करण और, या निपटान सुविधा हेतु परिवहन कर ले जाया जा सकता है।

मुजफ्फरपुर नगर निगम ने ₹16.23 लाख के लागत से चंदवारा में एक अंतरण स्थल का निर्माण (फरवरी 2022) किया, जिसका उद्देश्य इस अंतरण स्थल पर संग्रहित अपशिष्टों को छोटे वाहनों से गिराना और उन अपशिष्टों को बड़े वाहनों जैसे हाइवा[117] में डालकर थोक परिवहन कर रौतिनिया के डंपिंग स्थल तक अंतरण करना था। ।

हालांकि, लेखापरीक्षा (सितंबर 2022) में पाया गया कि छोटे वाहनों के माध्यम से अपशिष्ट अंतरण स्थल पर नहीं आ रहा था। इसके बजाय, इसे सीधे प्राथमिक संग्रह स्थलों से रौतिनिया डंपिंग स्थल तक ले जाया जा रहा था। इस प्रकार, अंतरण स्थल के निर्माण का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका, क्योंकि उसके निर्माण पर ₹ 16.23 लाख व्यय करने के बावजूद यह निष्क्रिय पड़ा रहा।

5.5.2.7 सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक डस्टबिनों से अपशिष्टों का संग्रहण

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हस्तक के अनुच्छेद 2.2.1.2.3 के अनुसार, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अपशिष्ट नहीं फैले, महत्वपूर्ण सड़कों, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, पर्यटन स्थलों, बस और रेलवे स्टेशनों, बड़े वाणिज्यिक परिसरों आदि पर स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर डस्टबिन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इन डस्टबिनों से संग्रहित किए गए अपशिष्टों को गीले और सूखे अपशिष्टों में पृथक किया जाना है।

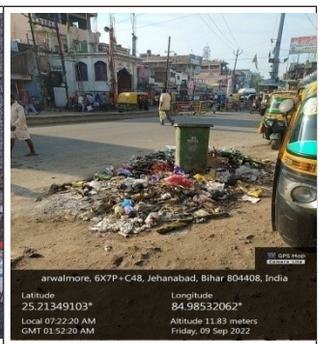
इसके अलावा, नगर विकास एवं आवास विभाग के दिशानिर्देशों/निर्देशों (फरवरी 2019 और मई 2019) के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को शहर को डस्टबिन मुक्त बनाने के लिए, समयांतराल में सामुदायिक डस्टबिनों को हटाने का प्रयास करना है।

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों ने ₹ 30.92 करोड़ का व्यय सामुदायिक डस्टबिनों/कूड़ेदानों के क्रय पर किया था (***परिशिष्ट 5.9***)। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सामुदायिक डस्टबिनों की आवश्यकता और उन डस्टबिनों को रखने के जगहों के संबंध में

[117] *हाइवा, ट्रक जैसा एक वाहन है, जिसका उपयोग अपशिष्टों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है।*

कोई कार्य योजना तैयार नहीं किए जाने के कारण, भंडारण के लिए रखे गये ये डस्टबिन पृथक्कृत अपशिष्टों के प्रभावी संग्रहण के लिए अनुकूल नहीं थे।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, इन डस्टबिनों के बाहर, मिश्रित अपशिष्ट बिखरे होने की पुष्टि हुई। ये डस्टबिन उचित तरीके से रखे भी नहीं गए थे और नियमित रूप से इन्हें साफ नहीं किया जा रहा था।

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>भागलपुर में सामुदायिक डस्टबिन के बाहर फैला कूड़ा</td>
<td>मुजफ्फरपुर में सड़क किनारे पलटा हुआ डस्टबिन और कूड़े का बिखराव</td>
<td>जहानाबाद में डस्टबिन के बाहर फैला हुआ कूड़ा</td>
</tr>
</table>

5.5.3 सड़क की सफाई

राज्य सरकार द्वारा विकसित किये गये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति और नीति (फरवरी 2019) के अनुसार, सड़कों की सफाई के लिए गतिविधियॉ सुबह जल्दी शुरू करनी है और सुबह 8 बजे से पहले पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कम से कम धूल फैले और यातायात के भीड़ से बचा जा सके।

नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में सड़कों की सफाई के संयुक्त भौतिक सत्यापन में निम्नलिखित दृष्टांत पाये गये।

- सड़कों के किनारे कूड़ा–कचरा रखे जाने की प्रथा देखी गई।
- हालांकि आवश्यकतानुसार सड़कों की सफाई सुबह जल्दी की गयी थी, लेकिन सफाई के दौरान एकत्र किये गये कूड़े–कचरे का ढेर दिन में लंबी समयावधि तक पड़े हुए थे।
- ढेर किये गये कूड़े मिश्रित कूड़े थे, जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट आदि शामिल थे।

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>दलसिंहसराय में सड़क के किनारे (बलान नदी पुल से पिपल पेड़ तक) प्लास्टिक और जैव–अपघटनीय अपशिष्ट सहित मिश्रित कुड़े का लगा हुआ ढेर।</td>
<td>सड़क किनारे से उठाया जा रहा कूड़ा (सुबह 11:15 बजे), सहरसा</td>
</tr>
</table>

- नदियों और तालाबों के किनारे भी कूड़ा फेंका हुआ पाया गया।
- कई नालियाँ कूड़ों, जिनमें प्लास्टिक अपशिष्ट भी शामिल था, से जाम पाई गईं।
- शहरी स्थानीय निकाय के वाहनों द्वारा मध्याह्न में कूड़ा उठाने के कारण यातायात की गति धीमी थी।



एकता मार्केट, स्टेशन रोड, दरभंगा में दोपहर (12:16 बजे) के दौरान कूड़ा संग्रहित किये जाने के कारण यातायात की धीमी गति।

- कई स्थानों पर कूड़ा जलते हुए देखा गया।



विद्यालय के सामने फैले हुए कूड़ा–कचरा और विद्यालय आते छात्र (सुबह 10:08 बजे), कन्या उच्च/मध्य विद्यालय, सहरसा

उपरोक्त उल्लिखित मुद्दे सभी नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में व्याप्त थे, जैसा कि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखा गया।

5.5.4 सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग किए बिना अपशिष्टों का संग्रहण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (यघ) के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना है कि प्रसुविधा का संचालक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसमें वर्दी, हाथ के दस्ताने, बरसाती, उचित जूते और मास्क शामिल हैं, को ठोस अपशिष्ट के हथालन में लगे सभी कर्मियों को उपलब्ध कराया है एवं कर्मियों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, नगर विकास एवं आवास विभाग की नीति और रणनीति (फरवरी 2019) भी यह निर्धारित करती है कि शहरी स्थानीय निकाय सफाईकर्मियों और अपशिष्ट संग्रहणकर्ताओं को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जैसे सुरक्षा जूते, मास्क, दस्ताने, जैकेट आदि प्रदान करेंगें।

नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट संग्रहणकर्ताओं के सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों के क्रय के समर्थन में कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया। लेखापरीक्षा ने, नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया कि कर्मियों द्वारा अपशिष्टों का निपटान हाथ से किया जा रहा था, किसी भी सुरक्षात्मक उपकरण, विशेष रूप से दस्तानों और जूतों का उपयोग

नहीं किया जा रहा था। सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग नहीं करना जोखिम भरा था और इससे गंभीर स्वास्थ्य खतरे हो सकते थे।

		
पूर्णिया में बिना सुरक्षा उपकरण के अपशिष्टों का उठाव करते सफाई कर्मी	दलसिंहसराय में बिना सुरक्षा उपकरण के अपशिष्टों का निपटान करते सफाई कर्मी	बिना सुरक्षा उपकरण के कामगारों द्वारा की जा रही नाली की सफाई, सहरसा

5.5.5 अपशिष्ट प्रबंधन में अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहकों का एकीकरण नहीं

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (ग) में शहरी स्थानीय निकायों को अपशिष्ट चुनने वालों या अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं के संगठनों को मान्यता प्रदान करने की प्रणाली स्थापित करने और डोर–टू–डोर जाकर अपशिष्ट संग्रह करने सहित ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में इनकी भागीदारी को सुगम बनाने के लिए इन प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट संग्रहणकर्ताओं के एकीकरण के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है। बिहार सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों में अपशिष्ट चुनने वालों/अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहणकर्ताओं के एकीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किया (फरवरी 2019)।

हालांकि, किसी भी शहरी स्थानीय निकाय (दरभंगा और दानापुर को छोड़कर) ने अपशिष्ट प्रबंधन में अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहणकर्ताओं के एकीकरण की दिशा में प्रयास नहीं किया था। उपरोक्त शहरी स्थानीय निकायों के प्रयास, अपशिष्ट चुनने वालों के साथ केवल एक बैठक आयोजित करने, 21 अपशिष्ट चुनने वालों को पंजीकृत करने और उन्हें विभिन्न विकासात्मक योजनाओं जैसे जन धन योजना, आयुष्मान भारत आदि के तहत जोड़ने तक सीमित थे। इस प्रकार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहणकर्ताओं के एकीकरण का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

5.5.6 अपशिष्टों का परिवहन

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हस्तक के अनुच्छेद 2.3.2 के अनुसार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं में परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपशिष्टों को पृथक रूप में (गीला और सूखा) प्राथमिक और गौण संग्रहण/थोक संग्रहण स्थलों से वाहनों के माध्यम से निपटान केंद्रों तक पहुंचाया जाना है। गीले, सूखे और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट का पृथक संग्रहण, पुनर्चक्रणीय सामग्रियों की अधिकतम वसूली सुनिश्चित करता है। द्वार स्तर पर पृथक किए गए प्राथमिक अपशिष्टों को ढके हुए ऐसे मशीनीकृत वाहनों के माध्यम से एकत्र किया जाना है, जिसमें जैविक और अजैविक अपशिष्टों के संग्रहण के लिए अलग–अलग भाग बनें हों।

परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को ढका होना चाहिए और अपशिष्ट नागरिकों को दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। प्रसंस्करण या निपटान सुविधा के रास्ते में वाहनों से अपशिष्ट और निक्षालन को फैलने से रोकने की सुविधा भी होनी आवश्यक है।

5.5.6.1 खुले वाहनों में अपृथक्कृत अपशिष्ट का परिवहन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में, अपशिष्टों के संग्रहण और परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों, जैसे ठेला–गाडी, ट्राई–साइकिल,

ई–कार्ट, ऑटो टिपर, ट्रैक्टर, टिपर ट्रक आदि का उपयोग किया जा रहा था। घरों/ दुकानदारों के सर्वेक्षण और संयुक्त भौतिक सत्यापन से ज्ञात हुआ कि बिना पृथक्करण के अपशिष्टों का परिवहन किया जा रहा था।

आगे यह देखा गया कि ठोस अपशिष्टों को डंपिंग स्थलों तक परिवहन करने वाले वाहनों को कवर नहीं किया गया था। परिवहन किया गया अपशिष्ट दृष्यमान था और पर्यावरण के संपर्क में था। बिना ढके ये वाहन, परिवहन के दौरान दुर्गन्ध फैलाने के अलावा, अपशिष्टों को भी फैला रहे थे, जिसके कारण जनता को असुविधा हो रही थी, इस प्रकार ठोस अपशिष्टों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वच्छ तरीके से स्थानांतरित करने का उद्देश्य विफल हो गया।

		
झंझारपुर में ट्रैक्टर से अपशिष्ट का खुला परिवहन	बहादुरगंज में ट्रैक्टर के माध्यम से मिश्रित अपशिष्टों का परिवहन	सहरसा में ट्राइसाइकिल से ले जाया जा रहा मिश्रित अपशिष्ट

5.5.6.2 पंजीकरण, बीमा और 'प्रदूषण नियंत्रण' प्रमाणपत्र के बिना वाहनों का उपयोग किया जाना

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति तबतक किसी भी मोटर वाहन को नहीं चलाएगा या मोटर वाहन का कोई भी मालिक किसी भी सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य स्थान पर वाहन चलाने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि वाहन पंजीकृत न हो। इसके अलावा, उपरोक्त अधिनियम की धारा 56 के अनुसार, एक परिवहन वाहन को तब तक वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके पास फिटनेस का प्रमाण पत्र न हो।

इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 147 और बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम 104 (6) में यह प्रावधान है कि नगरपालिका द्वारा उपयोग किये जा रहे सभी मोटर वाहनों का बीमा होना चाहिए।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 (7) में कहा गया है कि मोटर वाहन के पहली बार पंजीकृत होने के तारीख से एक वर्ष की अवधि के समाप्ति के बाद, ऐसे प्रत्येक वाहन को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी किया गया वैध ''प्रदूषण नियंत्रण'' प्रमाण पत्र रखना चाहिए।

चयनित शहरी स्थानीय निकायों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए उपयोग किए जा रहे 2,067 वाहनों की एक सूची प्रस्तुत की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी वाहनों के वैध पंजीकरण संख्या, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं थे, जैसा कि नीचे बताया गया है और विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 5.10*** में दिया गया है।

- 696 वाहनों (34 प्रतिशत) का पंजीकरण नहीं था।
- 1,121 वाहनों (54 प्रतिशत) के पास कोई बीमा प्रमाणपत्र नहीं था।
- 929 वाहनों (45 प्रतिशत) के पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं था।



पटना नगर निगम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अपंजीकृत वाहन का परिचालन

ये कमियां इंगित कर रही थीं कि नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में मोटर वाहन अधिनियम का पालन नहीं किया गया और आंतरिक नियंत्रण में कमियां थीं। इसके अलावा, नगर विकास एवं आवास विभाग (जनवरी 2020) के निर्देशों और माननीय पटना उच्च न्यायालय के फैसला[118] (सितंबर 2021) के विपरीत, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपंजीकृत वाहनों का परिचालन किया जा रहा था।

अपशिष्ट संग्रहण और प्रबंधन के उद्देश्य हेतु, सड़कों पर ऐसे वाहनों का परिचालन, प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन है।

चौदह शहरी स्थानीय निकायों[119] ने अपने जवाब में आश्वासन दिया कि आवश्यक अनुपालन किया जाएगा। नगर पंचायत, मखदुमपुर ने जवाब दिया कि वित्त विभाग के निर्देश के आलोक में सरकारी वाहनों का बीमा कराना आवश्यक नहीं था, इसलिए वाहनों का बीमा नहीं कराया गया था।

नगर पंचायत, मखदुमपुर का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली के अनुसार, नगरपालिका द्वारा संचालित सभी मोटर वाहनों का बीमा कराया जाना था।

5.5.6.3 वाहनों के विलंब से पंजीकरण के कारण परिहार्य व्यय ₹ 70.89 लाख

बिहार मोटर वाहन कराधान नियम, 1994 के नियम 4 (2) में कर अधिकारी द्वारा जुर्माना लगाने का प्रावधान है, यदि वाहन के संबंध में, किसी भी अवधि के लिए कर का भुगतान नहीं किया गया है, जैसा कि उपरोक्त नियमों के तहत आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चार शहरी स्थानीय निकायों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के उपयोग के लिए 932 वाहनों[120] का पंजीकरण, संबंधित जिला परिवहन प्राधिकरणों के साथ किया था। इन सभी वाहनों का पंजीकरण एक वर्ष से तीन वर्ष विलंब से कराया गया था। पंजीकरण में विलंब के कारण, संबंधित शहरी स्थानीय निकायो ने दण्ड शुल्क के रूप में ₹ 70.89[121] लाख का भुगतान किया था, समय पर इन वाहनों का पंजीकरण कराकर इससे बचा जा सकता था।

---

[118] *पटना उच्च न्यायालय सी डब्ल्यू जे सी संख्या 21017/2019 दिनांक 03/09/2021 – नगर निगम पटना, राज्य सरकार या उसके प्राधिकारियों का कोई भी वाहन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए नहीं चलाया जाएगा।*

[119] *सहरसा, किशनगंज, बहादुरगंज, बेलसंड, रामनगर, हाजीपुर, बरहिया, मुंगेर, जमुई, गया, जहानाबाद, राजगीर, छपरा और महाराजगंज।*

[120] *गयाः 52 वाहन, पटनाः 826 वाहन, जहानाबादः 04 वाहन और दरभंगाः 50 वाहन*

[121] *गयाः ₹ 10.23 लाख, पटनाः ₹ 54.85 लाख, जहानाबादः ₹ 0.59 लाख, दरभंगाः ₹ 5.22 लाख*

5.5.6.4 आकस्मिक दायित्व का सृजन

पटना नगर निगम ने शहर के छः प्रस्तावित अंतरण स्थलों पर पृथक किए गए अपशिष्टों को अपने डंपिंग स्थल[122] तक ले जाने की योजना बनाई थी। निविदा प्रक्रिया (अगस्त 2018) के बाद, सबसे कम बोली लगाने वाले निविदाकार[123] को कार्यादेश (जुलाई 2019) निर्गत किया गया, जिसमें प्रत्येक ठोस अपशिष्ट अंतरण स्थल के निर्माण, अधिष्ठापन और चालू करने की लागत ₹ 3.06 करोड़ थी।

निविदाकार और पटना नगर निगम के बीच कोई एकरारनामा नहीं किया गया। इसके बावजूद, निविदाकार ने पटना नगर निगम को सूचित किया (नवंबर 2020) कि उसने एक स्थल पर सिविल कार्य शुरू कर दिया था और इस उद्देश्य हेतु तीन हुक लोडर और पाँच कम्पेक्टर क्रय किया था।

पटना नगर निगम ने निविदाकार द्वारा कार्य स्थल पर लाये गये तीन हुक लोडर को अपने खर्च पर ₹ 2.22 लाख में पंजीकृत (दिसंबर 2020) कराया।

लगभग एक वर्ष बाद, पटना नगर निगम ने निविदा प्रक्रिया को इस आधार पर रद्द कर दिया (नवंबर 2021), कि निविदा को मुख्य नगर अभियंता की अध्यक्षता वाली निविदा समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया था, जो मात्र ₹ दो करोड़ तक के कार्य मूल्य के निविदाओं का ही निपटान करने में सक्षम थी, जबकि इस कार्य का मूल्य दो करोड़ रुपये से अधिक था। परिणामस्वरूप, निविदाकार ने पटना नगर निगम को एक कानूनी नोटिस भेजा (अगस्त 2022), जिसमें दावा किया गया कि किए गए काम का मूल्य, ब्याज सहित, ₹ 6.04 करोड़ था और एजेंसी को भुगतेय था।

इस प्रकार, पटना नगर निगम ने ₹ 6.04 करोड़ के आकस्मिक दायित्व का सृजन किया।

5.5.6.5 अपशिष्टों के परिवहन में लगे वाहनों को जी.पी.एस. के माध्यम से अनुश्रवण नहीं करना

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हस्तक के अनुच्छेद 2.3.12.1 में एक सरल और उन्नत प्रबंधन सूचना प्रणाली जैसे, भौगोलिक सूचना प्रणाली, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और जनरल पैकेट रेडियो सेवाओं की परिकल्पना की गई है, जो कि बड़े और वृहद शहरों में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए महत्वपूर्ण साधन हैं।

नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश (फरवरी 2016) के अनुसार, वाहनों के ट्रैकिंग के लिए शहरी स्थानीय निकायों के सभी वाहनों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित किया जाना था।

नगर विकास एवं आवास विभाग के उपर्युक्त निर्देश के विपरीत, नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों ने 36 प्रतिशत वाहनों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम प्रणाली स्थापित नहीं किया था, जैसा कि **तालिका 5.19** में दर्शाया गया है और ***परिशिष्ट 5.11*** में विस्तृत विवरण दिया गया है। नमूना जांच किए गए 17 शहरी स्थानीय निकायों में, अपशिष्टों के परिवहन के लिए, उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे वाहनों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम प्रणाली स्थापित नहीं किया गया।

नमूना जांच किये गये 11 अन्य शहरी स्थानीय निकायों में, 1,600 वाहनों में से 1,332 में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अधिष्ठापित (मार्च 2020 से मार्च 2022) किया गया था। हालांकि, नमूना जांच किए गए इन 11 शहरी स्थानीय निकायों में भी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम स्थापित होने के बावजूद, पटना, गया और मुजफ्फरपुर नगर निगमों को छोड़कर, शेष में वाहनों के परिचालन को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के माध्यम से ट्रैक नहीं किया जा रहा था।

---

[122] *रामाचक बैरिया में*

[123] *मैसर्स प्रभु दयाल ओमप्रकाश इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड*

तालिका 5.19
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु शहरी स्थानीय निकायों के वाहनों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का अधिष्ठापन

शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	वाहनों की कुल संख्या	वाहनों की संख्या जिसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अधिष्ठापित था
17[124]	467	**0**
11	1,600	**1,332**
कुल	**2,067**	**1,332 (64 प्रतिशत)**

*(**स्रोत**: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)*

वाहनों में ट्रैकिंग उपकरणों के अधिष्ठापन/उपयोग नहीं होने के कारण, वाहनों के परिचालन का अनुश्रवण करना कठिन था और डोर–टू–डोर से अपशिष्टों के संग्रहण और उसके बाद प्रसंस्करण केंद्र या डंपिंग स्थलों पर ऐसे अपशिष्टों का परिवहन सुनिश्चित करना संभव नहीं था।

नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में से ग्यारह[125] ने अपने जबाब में आश्वासन दिया कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अधिष्ठापित कर अनुश्रवण की जाएगी।

5.5.6.6 ईंधन पर अतिरिक्त व्यय – ₹ 62.82 लाख

सशक्त स्थायी समिति के निर्णय (अप्रैल 2019) और उसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दरभंगा नगर निगम के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की मंजूरी (जून 2019) के आलोक में, दरभंगा नगर निगम को 50 ऑटो टिपर खरीदने की आवश्यकता थी। टिपरों के तकनीकी विशिष्टियों के अन्वेषण के लिए, नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम ने एक तकनीकी समिति का गठन किया (अक्टूबर 2019), जिसमें मोटर वाहन निरीक्षक, दरभंगा; यांत्रिक अभियंता, दरभंगा नगर निगम; नगर प्रबंधक, दरभंगा नगर निगम और सहायक अभियंता, दरभंगा नगर निगम शामिल थे।

इस समिति ने ईंधन खपत[126] को 19 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर (कि.मी./लीटर) तक निर्दिष्ट किया (नवंबर 2019)। समिति के निर्णय के अनुरूप, निविदा आमंत्रित की गयी (नवम्बर 2019)। निविदा दस्तावेज में (मई 2020) ईंधन खपत की विशिष्टियाँ 18 कि.मी. प्रति लीटर शामिल थी। सफल बोलीदाता[127] के साथ अनुबंध (जून 2020) में उल्लेखित नियमों और शर्तों में भी 18 कि.मी. प्रति लीटर का ईंधन खपत शामिल था।

बुडको के दो सहायक अभियंताओं (यांत्रिक), सहायक नगर अभियंता, दरभंगा नगर निगम; नगर अभियंता, दरभंगा नगर निगम; नगर प्रबंधक, दरभंगा नगर निगम और उप नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम की एक समिति ने प्रमाणित किया (अगस्त 2020) कि क्रय किये गये वाहन अनुबंध में निर्धारित किये गये विशिष्टियों के अनुसार थे। तदनुसार, दरभंगा नगर निगम ने इस आश्वासन के बाद (अगस्त 2020) 50 ऑटो टिपर खरीदे, जिससे स्पष्ट था कि इन वाहनों का ईंधन खपत 18 कि.मी. प्रति लीटर था।

इस संबंध में दरभंगा नगर निगम/बुडको के अधिकारियों/अभियंताओं के प्रमाणीकरण को नजरअंदाज करते हुए, दरभंगा नगर निगम ने आठ कि.मी. प्रति लीटर की दर से

---

[124] *जहानाबाद, मखदुमपुर, महाराजगंज, बेलसंड, गोपालगंज, जगदीशपुर, सुल्तानगंज, अमरपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, दलसिंहसराय, मुरलीगंज, झंझारपुर (लेखापरीक्षा के समय जी.पी.एस. की वैधता समाप्त हो गई थी), किशनगंज, बहादुरगंज और दानापुर।*

[125] *गया, राजगीर, महाराजगंज, छपरा, जहानाबाद, मखदुमपुर, पुर्णिया, भागलपुर, जमुई, बरहिया एवं सुल्तानगंज।*

[126] *केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 के तहत मूल उपकरण निर्माता द्वारा परीक्षण एजेंसी को प्रमाणित घोषित किया गया।*

[127] *मे0 मौर्य मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड।*

टिपरों को ईंधन वितरित किया, जिससे ₹ 62.82 लाख[128] का अतिरिक्त व्यय हुआ जैसा कि नीचे **तालिका 5.20** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.20
ईंधन के भुगतान पर किया गया अतिरिक्त व्यय

(₹ करोड़ में)

ऑटो टिपरों की संख्या	दरभंगा नगर निगम के अभिलेखों के अनुसार		लेखापरीक्षा गणना के अनुसार		अतिरिक्त व्यय
	16 दिसंबर 2020 से जुलाई 2022 के दौरान 8 कि.मी./लीटर की दर से ईंधन की खपत (लीटर में)	किया गया व्यय	18 किलोमीटर प्रति लीटर की दर से स्वीकार्य खपत (लीटर में)	स्वीकार्य व्यय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3–5)
50	1,22,069	113.07	54,253	50.25	62.82

(*स्रोतः दरभंगा नगर निगम के अभिलेख*)

(विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 5.12*** में दिया गया है)

5.5.7 निष्कर्ष

नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी डोर–टू–डोर जाकर अपशिष्टों के संग्रहण के लिए आधारभूत अध्ययन/सर्वेक्षण और वार्ड–मैपिंग नहीं किया था। नमूना जांच किए गए सभी शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्टों का पृथक्करण या तो नहीं किया गया था या आंशिक किया गया था। मिश्रित अपशिष्टों को स्रोत पर एकत्र किया जा रहा था और तत्पश्चात भरण स्थल/डंपिंग स्थलों पर डंप किया जा रहा था।

अपशिष्टों का परिवहन खुले वाहनों से किया जा रहा था। बिना पंजीकरण, बीमा और 'प्रदूषण नियंत्रण' प्रमाणन के चलने वाले वाहनों के मामले भी देखे गए। तीन नगर निगमों (पटना, गया और मुजफ्फरपुर) को छोड़कर, नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्ट ले जाने वाले वाहनों को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के माध्यम से ट्रैक नहीं किया गया था।

5.5.8 अनुशंसाएं

- ***शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्टों का स्रोत पर पृथक्करण, डोर–टू–डोर संग्रहण और निवारक उपायों को विकसित कर, या पृथक्करण को प्रोत्साहित कर, पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट सामग्री का पृथक्करण कर, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और प्रसंस्करण की सुविधा को सुनिश्चित कर सकते हैं।***
- ***शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अपशिष्ट संग्रहण ऐसे तरीके से किया जाए जो जनता के लिए असहज न हो और पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकार्य हो।***
- ***शहरी स्थानीय निकाय बिना ढके अपशिष्टों के परिवहन से बच सकते हैं। वे बिना पंजीकरण, बीमा और 'प्रदूषण नियंत्रण' प्रमाणपत्र वाले वाहनों का उपयोग करने से भी बच सकते हैं।***
- ***पृथक किए गए अपशिष्टों के संग्रहण के लिए, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्राथमिक संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन कंटेनरीकृत या विभाजित हो, पृथक किए गए अपशिष्टों के भंडारण की सुविधा के लिए, गीले और सूखे अपशिष्टों के लिए पृथक.–पृथक डिब्बों/टोकरियों का उपयोग किया जाए।***

5.6 नगरीय ठोस अपशिष्टों का प्रसंस्करण और निपटान

अपशिष्टों का प्रसंस्करण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यह भरण स्थल पर गिराये जाने वाले अपशिष्टों की मात्रा को कम करने में मदद करता है। अपशिष्टों के पृथक्करण के पश्चात्, गीले अंश का उपयोग मुख्यतः कम्पोस्ट बनाने के

[128] *16 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2022 के दौरान 50 टिपरों के लिए।*

लिए किया जाना चाहिए और सूखे अपशिष्टों को पुनर्चक्रण के लिए भेजा जाना चाहिए। अपशिष्टों के प्रसंस्करण के लिए तकनीकी रूप से स्वीकार्य विकल्पों में कम्पोस्ट बनाना[129], अपशिष्टों से ऊर्जा बनाना[130], कचरा व्युत्पन्न ईंधन[131] आदि शामिल हैं। इस कंडिका में, अपशिष्टों के प्रसंस्करण और उसके निपटान की दिशा में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किये गये प्रयासों पर चर्चा की गई है।

5.6.1 नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तीन साल के अंदर यानि, अप्रैल 2019 तक तैयार करना था[132]।

सुल्तानगंज नगर परिषद को छोड़कर, नमूना जांच किये गये शेष शहरी स्थानीय निकायों में प्रसंस्कृत अपशिष्टों के सही मात्रा को ज्ञात करने के लिए, कोई क्रियाविधि/अभिलेख लेखापरीक्षा में नहीं पाये गये।

हालांकि, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजे गए प्रतिवेदन/लेखापरीक्षा को दी गई जानकारी से ज्ञात हुआ कि, नमूना जांच किए गए 10 शहरी स्थानीय निकायों[133] में, अपशिष्टों को बिल्कुल भी प्रसंस्कृत नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रतिवेदित स्थिति/लेखापरीक्षा को दी गई जानकारी के अनुसार शेष 18 शहरी स्थानीय निकायों में, प्रसंस्कृत अपशिष्टों की सीमा एक से 100 प्रतिशत तक थी।

हालांकि, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि प्रसंस्कृत अपशिष्टों की स्थिति, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजे गये प्रतिवेदन/लेखापरीक्षा को दी गई जानकारी के विपरीत थी, जैसा कि **तालिका 5.21** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.21

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया गया दावा एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाये गए अपशिष्ट प्रसंस्करण की स्थिति

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय	संग्रहण (टन प्रति दिन)	अपशिष्ट प्रसंस्करण टन प्रति दिन में		संयुक्त भौतिक सत्यापन के संबंध में टिप्पणियाँ
			शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिवेदित (जून 2022)	संयुक्त भौतिक सत्यापन/लेखापरीक्षा को प्रस्तुत सूचना के दौरान पायी गयी स्थिति	
1	पटना	1,000	100	प्रसंस्कृत अपशिष्टों की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकी।	
2	गया	309	309	प्रसंस्कृत अपशिष्टों की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकी। हालांकि, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दिन, खाद बनाने की प्रक्रिया चल रही थी।	
3	भागलपुर	267	2	0	संयुक्त भौतिक सत्यापन पर आधारित
4	मुजफ्फरपुर	180	19	5.72	कार्यशील पिटों की क्षमता के आधार पर

[129] *ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार, कंपोस्टिंग का अर्थ है जैविक पदार्थ के सूक्ष्मजीवी अपघटन से जुड़ी एक नियंत्रित प्रक्रिया।*

[130] *नगरीय ठोस अपशिष्ट हस्तक के अनुच्छेद 3.3 के अनुसार, 'अपशिष्ट से ऊर्जा,' नगरीय ठोस अपशिष्ट से ताप या बिजली के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा, ताप या जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।*

[131] *ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार, कचरा व्युत्पन्न ईंधन, ठोस अपशिष्ट के ज्वलनशील भाग, यथा प्लास्टिक, लकड़ी, लुगदी या जैविक अपशिष्ट, क्लोरीनयुक्त पदार्थों से इतर, को सुखाकर, कतरन, निर्जलीकरण और संघनन द्वारा गूटिका या रोंये के रूप मे प्राप्त किया जाना है।*

[132] *अप्रैल 2018 तक एक लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों के लिए। अप्रैल 2019 तक एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए।*

[133] *पूर्णिया, किशनगंज, जहानाबाद, गोपालगंज, बहादुरगंज, मखदुमपुर, झंझारपुर, मुरलीगंज, अमरपुर और महराजगंज*

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय	संग्रहण (टन प्रति दिन)	अपशिष्ट प्रसंस्करण टन प्रति दिन में		संयुक्त भौतिक सत्यापन के संबंध में टिप्पणियाँ
			शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिवेदित (जून 2022)	संयुक्त भौतिक सत्यापन/लेखापरीक्षा को प्रस्तुत सूचना के दौरान पायी गयी स्थिति	
5	दरभंगा	120	12	2.09	कार्यशील पिटों की क्षमता के आधार पर
6	मुंगेर	88	30	0	संयुक्त भौतिक सत्यापन पर आधारित
7	छपरा	87.50	10	0	संयुक्त भौतिक सत्यापन पर आधारित
8	सहरसा	31.33	8.6	0	संयुक्त भौतिक सत्यापन पर आधारित
9	दानापुर	95	5	प्रसंस्कृत अपशिष्टों की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकी। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दिन, कम्पोस्ट बनाने का काम नहीं चल रहा था। हालांकि, सामग्री वसूली सुविधा केंद्र में सूखा अपशिष्ट का पृथक्करण देखा गया।	
10	हाजीपुर	92	10	0	संयुक्त भौतिक सत्यापन पर आधारित
11	जमुई	24	1.2	0	संयुक्त भौतिक सत्यापन पर आधारित
12	सुल्तानगंज	26.05	15	0.50	लेखापरीक्षा को दी गई जानकारी के आधार पर
13	रामनगर	18	18	0.18	कार्यशील पिटों की क्षमता के आधार पर
14	राजगीर	22.76	15.93	0	संयुक्त भौतिक सत्यापन पर आधारित
15	दलसिंहसराय	19	2	1.76	कार्यशील पिटों की क्षमता के आधार पर
16	बड़हिया	18	16	2.5	लेखापरीक्षा को दी गई जानकारी के आधार पर
17	जगदीशपुर	4	0.50	0	संयुक्त भौतिक सत्यापन पर आधारित
18	बेलसंड	3	0.80	0.35	कार्यशील पिटों की क्षमता के आधार पर

*(**स्रोत**:– राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपी गई प्रतिवेदन, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दी गई जानकारी और संयुक्त भौतिक सत्यापन)*

जैसा कि **तालिका 5.21** में दर्शाया गया है, 18 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजे गये अपशिष्ट प्रसंस्करण से संबंधित प्रतिवेदन/लेखापरीक्षा में उपलब्ध करायी गई सूचना के विरूद्ध, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि आठ शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्टों को प्रसंस्कृत नहीं किया जा रहा था। सात शहरी स्थानीय निकायों[134] में, अपशिष्ट प्रसंस्करण की मात्रा केवल 14 प्रतिशत[135] तक थी। तीन शहरी स्थानीय निकायों में, अपशिष्ट प्रसंस्करण के सही मात्रा को ज्ञात नहीं किया जा सका।

कम अपशिष्ट प्रसंस्करण का कारण प्रसंस्करण केंद्रों की अपर्याप्त क्षमता; आवश्यक मशीनरी की अनुपलब्धता; उपलब्ध क्षमता का कम उपयोग; और क्रय की गई मशीनरी का उपयोग नहीं होना, आदि था, जिसकी चर्चा आगे की कंडिकाओं में की गई है।

[134] *रामनगर (एक प्रतिशत), दरभंगा (दो प्रतिशत), सुल्तानगंज (दो प्रतिशत), मुजफ्फरपुर (तीन प्रतिशत), दलसिंहसराय (सात प्रतिशत), बेलसंड (नौ प्रतिशत) और बड़हिया (14 प्रतिशत)*

[135] *प्रतिशत की गणना के लिए न्यूमरेटर अपशिष्ट प्रसंस्करण की मात्रा है, जैसा कि संयुक्त भौतिक सत्यापन/लेखापरीक्षा को दी गई जानकारी के आधार पर पाया गया है, और डिन्यूमरेटर अपशिष्ट संग्रह है।*

5.6.1.1 अपर्याप्त विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण केन्द्र

(i) ताजे गीले अपशिष्टों के प्रसंस्करण हेतु अपर्याप्त कम्पोस्ट पिट

अपशिष्टों के प्रसंस्करण और निपटान पर नगर विकास एवं आवास विभाग के दिशानिर्देशों (मई 2019) के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को क्लस्टर्ड विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र[136] या केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र[137] स्थापित करना था। राज्य शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति और रणनीति (फरवरी 2019) के अनुसार, नगर निगमों में तीन से चार वार्डों के लिए, नगर परिषदों में पाँच से छः वार्डों के लिए और नगर पंचायतों में नौ से 10 वार्डों के लिए एक प्रसंस्करण केंद्र की आवश्यकता थी। प्रत्येक विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र में गीले अपशिष्टों के प्रसंस्करण के लिए 20 कम्पोस्ट पिट और सूखे अपशिष्टों के प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण के लिए एक सामग्री वसूली सुविधा केंद्र होनी चाहिए थी।

चयनित शहरी स्थानीय निकायों में से, गया नगर निगम ने अपशिष्टों के केंद्रीकृत प्रसंस्करण का विकल्प चुना। मुरलीगंज नगर पंचायत ने कोई प्रसंस्करण पद्धति नहीं अपनाया। शेष शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्टों के विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण पद्धति को अपनाया।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण केंद्रों और कम्पोस्ट पिट की संख्या नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकता से कम थी, जैसा कि **तालिका 5.22** में दर्शाया गया है और ***परिशिष्ट 5.13*** में विवरण दिया गया है।

तालिका 5.22
विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण केन्द्रों की आवश्यकता

ब्यौरा	विवरण
नगर विकास एवं आवास विभाग की रणनीति	नगर निगमों में तीन से चार वार्डों के लिए, नगर परिषदों में पाँच से छः वार्डों के लिए और नगर पंचायतों में नौ से 10 वार्डों के लिए एक प्रसंस्करण केंद्र।
27 शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न गीला (कम्पोस्ट बनाने योग्य) अपशिष्ट टन प्रति दिन में (गया को छोड़कर, चयनित शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न कुल अपशिष्टों का आधा अंश मानते हुए)	1,399 टन प्रति दिन
27 नमूना शहरी स्थानीय निकायों में वार्डों की कुल संख्या	862
नगर विकास एवं आवास विभाग की रणनीति के अनुसार, विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण केंद्रों की आवश्यक संख्या	163
सूखे अपशिष्टों के प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक सामग्री वसूली सुविधा केंद्रों की संख्या	163
नगर विकास एवं आवास विभाग की रणनीति के अनुसार, अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए आवश्यक कम्पोस्ट पिट की संख्या	3,260
नगर विकास एवं आवास विभाग की रणनीति के अनुसार 3,260 पिट द्वारा प्रसंस्कृत किये जा सकने वाले गीला अपशिष्ट	143 टन प्रति दिन
शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विकसित किये गये विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्रों की वास्तविक संख्या	45 (28 प्रतिशत)
शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित कम्पोस्ट पिट की वास्तविक संख्या	1,094 (34 प्रतिशत)
क्रियाशील कम्पोस्ट पिट की संख्या	389 (12 प्रतिशत)
कुल उत्पादन के विरूद्ध उपलब्ध क्रियाशील पिट् द्वारा प्रसंस्कृत किए जा सकने वाले अपशिष्टों की मात्रा	17 टन प्रति दिन (एक प्रतिशत)

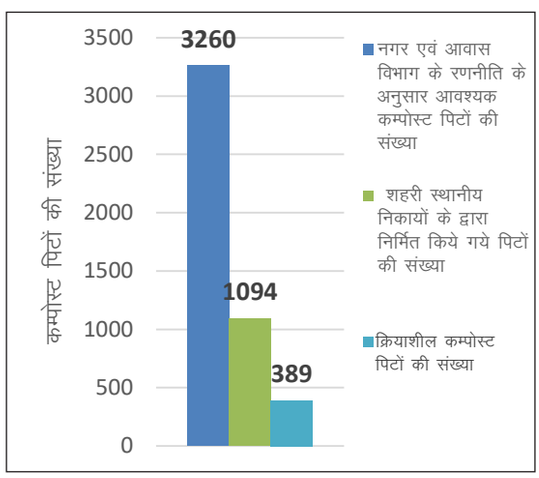
*(**स्रोतः** नगर विकास एवं आवास विभाग और नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)*

[136] *ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार, 'विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण' का अर्थ है जैव–अवक्रमणीय अपशिष्ट के प्रसंस्करण को अधिकतम करने के लिए बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्रोत से निकटतम पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों की प्रतिप्राप्ति करना, ताकि प्रसंस्करण या निपटान के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम परिवहन करना पड़े।*

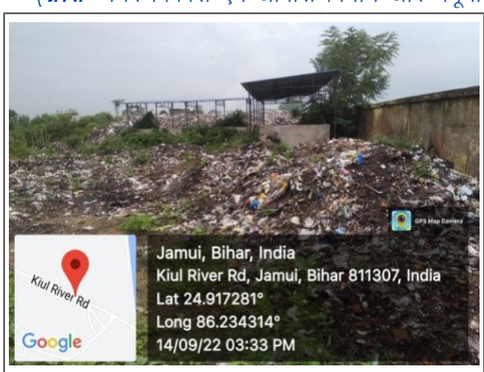
[137] *केंद्रीकृत प्रणालियों में अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा उपचार संयंत्रों जैसे कचरा व्युत्पन्न ईंधन संयंत्रों और नगरपालिका स्वास्थ्यकर भरण स्थलों (जो मितव्ययिता के पैमाने से लाभदायक हो सकता है) और आसान प्रबंधन एवं पर्यावरण अनुश्रवण को प्राथमिकता दी जाती है।*

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों ने भूमि की अनुपलब्धता के कारण, आवश्यक संख्या में पिट विकसित नहीं किए थे। 3,260 कम्पोस्ट पिट की आवश्यकता के विरूद्ध, शहरी स्थानीय निकाय केवल 1,094 पिट (34 प्रतिशत) का निर्माण कर सके। इनमें से 705 पिट (64 प्रतिशत) क्षतिग्रस्तता, मशीनरी की अनुपलब्धता, उपलब्ध मशीनरी का अधिष्ठापन नहीं होने, पृथक्कृत अपशिष्टों की अनुपलब्धता, मानवबल की कमी आदि के कारण परिचालित नहीं थे। इस प्रकार, केवल 389 पिट ही अधिकतम 17 टन प्रति दिन (एक प्रतिशत) अपशिष्टों के प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध थे, जबकि नगर विकास एवं आवास विभाग की रणनीति के अनुसार इन शहरी स्थानीय निकायों में कम से कम 143 टन प्रति दिन गीले अपशिष्टों को प्रसंस्कृत किया जा सकता था। इन 27 नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में कुल कम्पोस्ट बनाने योग्य अपशिष्ट का उत्पादन 1,399 टन प्रति दिन था।

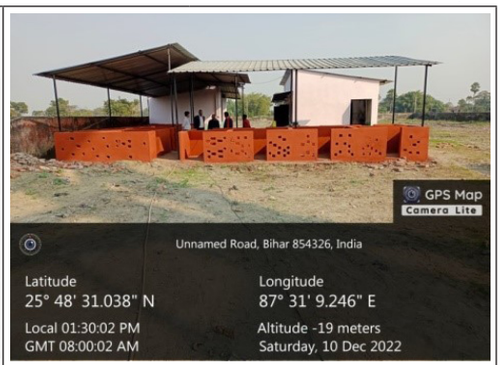
चार्ट 5.4:– कम्पोस्ट पिट की आवश्यकता एवं उपलब्धता



*(**स्रोत**: नगर विकास एवं आवास विभाग और नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)*



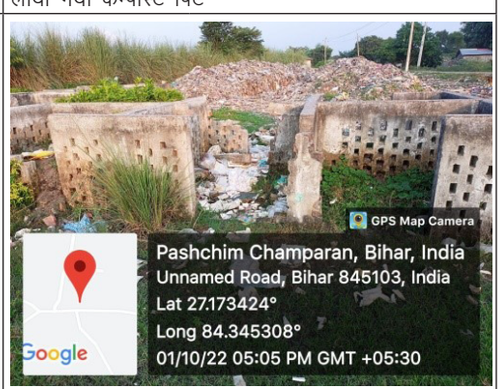
नगर परिषद्, जमुई में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पड़े हुए कम्पोस्ट पिट



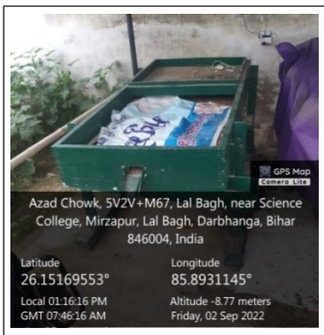
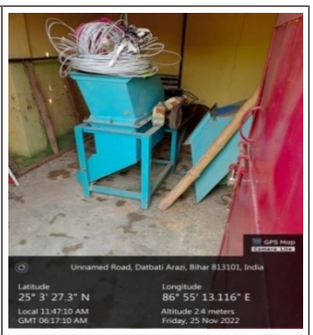
नगर निगम, पूर्णिया में निर्माण के बाद उपयोग में नहीं लाया गया कम्पोस्ट पिट



नगर परिषद्, सहरसा में जीर्ण–शीर्ण कम्पोस्ट पिट



नगर परिषद्, रामनगर में जीर्ण–शीर्ण कम्पोस्ट पिट

		
नगर निगम, दरभंगा में अकार्यशील इलेक्ट्रिक चलनी	नगर परिषद्, बड़हिया में जमीन पर पड़ी खराब बेलिंग मशीन	नगर पंचायत, अमरपुर में अधिष्ठापित नहीं किये गये श्रेडिंग मशीन

(ii) सूखे अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अपर्याप्त सामग्री वसूली सुविधा केन्द्र

अपशिष्टों के प्रसंस्करण और निपटान पर नगर विकास एवं आवास विभाग के दिशानिर्देशों (मई 2019) के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को कचरा चुनने वालों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से, प्रसंस्करण केंद्रों पर लाये गए सूखे अपशिष्टों से, उपयोगी और पुनर्चक्रणीय सामग्रियों यथा कागज, कार्डबोर्ड, कांच, एल्यूमीनियम कैन, बोतलें आदि के पुनर्प्राप्ति हेतु, सामग्री वसूली सुविधा केंद्र स्थापित करना था। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पुनर्प्राप्त किये गये सामग्रियों को कबाड़ीवालों को बेचा जाना था।

जैसा कि पूववर्ती कंडिका के **तालिका 5.22** में दर्शाया गया है, नमूना जांच किये गये 27 शहरी स्थानीय निकायों में 862 वार्ड थे, जिसके विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्रों पर सूखे अपशिष्टों को प्रसंस्कृत/पुनर्चक्रित करने के लिए 163 सामग्री वसूली सुविधा केंद्रों की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किए गए 20 शहरी स्थानीय निकायों ने कोई सामग्री वसूली सुविधा केंद्र विकसित नहीं किया था, जबकि सात शहरी स्थानीय निकायों[138] ने नौ सामग्री वसूली सुविधा केंद्र विकसित किए थे। जिनमें से मात्र चार ही क्रियाशील थे।

चयनित शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि किसी भी शहरी स्थानीय निकाय[139] में कोई भी पंजीकृत कचरा चुनने वाला नहीं था। केवल दो शहरी स्थानीय निकायों[140] ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सामग्रियों की पुनर्प्राप्ति के लिए लगाया था।

5.6.1.2 कंपोस्टर्स का इष्टतम उपयोग नहीं किया जाना

कंपोस्टिंग की प्रक्रिया के लिए बॉक्स बायो–कंपोस्टिंग तकनीक[141] के लिए 30 दिन के चक्र की आवश्यकता होती है और यांत्रिक बायो–कंपोस्टिंग तकनीक[142] के लिए 24 घंटे (एक दिन) की आवश्यकता होती है, अगर इसे लगातार चलाया जाए। इन तकनीकों का उद्देश्य जगह बचाना और सुयोग्य तरीके से, उन सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर, जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जैविक पदार्थों के अपघटन को तेज करना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित आठ शहरी स्थानीय निकायों[143] ने गीले अपशिष्टों के प्रसंस्करण के लिए, अन्य विकल्पों के अलावा, 75 कंपोस्टरों के माध्यम से बॉक्स/यांत्रिक बायो–कंपोस्टिंग तकनीक को अपनाया था।

---

[138] *भागलपुर–दो (अक्रियाशील), दरभंगा–एक (अक्रियाशील), पूर्णिया–एक (अक्रियाशील), दानापुर–एक (क्रियाशील), सुल्तानगंज–एक (क्रियाशील) और एक (अक्रियाशील), दलसिंहसराय–एक (क्रियाशील) और अमरपुर–एक (क्रियाशील)।*

[139] *दरभंगा और दानापुर को छोड़कर, जिन्होंने प्रतिवेदित किया था कि केवल 21 अपशिष्ट चुनने वालों को पंजीकृत किया था। हालांकि, अभिलेखों में कोई और विवरण उपलब्ध नहीं पाया गया।*

[140] *दानापुर और दलसिंहसराय*

[141] *बॉक्स कम्पोस्टिंग का उपयोग स्थानीय सामुदायिक स्तर पर किया जाता है और यह 3–5 टन तक अपशिष्टों का निपटान कर सकता है।*

[142] *यांत्रिक जैविक अपशिष्ट कंपोस्टर को कंपोस्टिंग को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यांत्रिक जैविक अपशिष्ट कंपोस्टर पूरी तरह से स्वचालित होता हैं और इनका बनावट सुगठित होता है।*

[143] *पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, हाजीपुर, जहानाबाद, बड़हिया और जमुई*

मई 2017 से नवंबर 2022 के दौरान इन 75 कंपोस्टरों के 22,704 टन कंपोस्ट उत्पादन की क्षमता के विरूद्ध, मात्र 0.75 टन कपोस्ट का उत्पादन हुआ था, जैसा कि **तालिका 5.23** में दर्शाया गया है और ***परिशिष्ट 5.14*** में विस्तृत विवरण दी गई है। इस प्रकार, कंपोस्टरों के क्रय पर ₹ 6.52 करोड़ का व्यय करने के बावजूद, क्रय किए गए कंपोस्टरों का इष्टतम उपयोग नहीं किया गया था।

तालिका 5.23
कंपोस्टरों का असंतोषजनक उपयोग

शहरी स्थानीय निकाय	क्रय किए गए कंपोस्टरों की संख्या (क्रय का महीना और वर्ष)	कंपोस्टर के क्रय पर व्यय (₹ लाख में)	कंपोस्ट की न्यूनतम मात्रा जिसका उत्पादन किया जाना चाहिए था (टन में)	क्रियाशील कंपोस्टरों की संख्या (अगस्त–नवंबर 2022)	लेखापरीक्षा के महीने तक (अगस्त–नवंबर 2022) कंपोस्टरों द्वारा वास्तविक उत्पादित कंपोस्ट की मात्रा (टन में)
पटना	22 (दिसंबर 2020 से फरवरी 2021)	317.02	11,508.60	3	शून्य
गया	10 (सितंबर 2018 से फरवरी 2020)	106.42	4,621.75	शून्य	शून्य
भागलपुर	2 (मई 2017)	38.00	3,894.00	शून्य	शून्य
दरभंगा	2*	..	39.50	शून्य	शून्य
हाजीपुर	8 (फरवरी 2021)	64.80	1,705.20	शून्य	शून्य
जहानाबाद	1 (जून 2022)	15.45	30.50	शून्य	शून्य
बड़हिया	20 (जुलाई 2019–फरवरी 2022)	85.65	857.41	2	0.70
जमुई	10 (फरवरी 2021 से मार्च 2021)	24.45	46.56	3	0.05
कुल	**75**	**651.79**	**22,703.52**	**8**	**0.75**

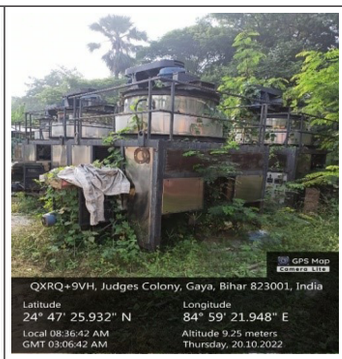
*(**स्रोत**: नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)*

** कम्पोस्टर मशीनों का भुगतान किया जाना बाकी था, (अगस्त–सितंबर 2022), हालांकि मशीनो की आपूर्ति आपूर्तिकर्ता द्वारा जून 2021 में कर दी गई थी)*

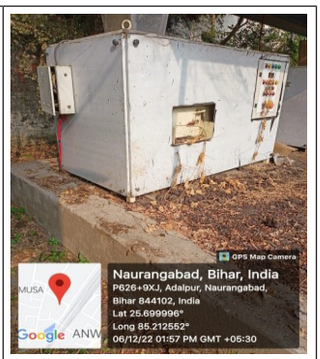
सर्वोत्तम उपयोग नहीं किये जाने के प्रमुख कारण, 67 कंपोस्टरों के क्रय के बाद दो से 64 महीनों की अवधि तक अक्रियाशील रहना, पृथक्कृत अपशिष्टों की अनुपलब्धता और अनुश्रवण की कमी था (जैसा कि मशीनों के परिचालन के लिए सुधारात्मक कार्रवाई के अभाव और प्रशिक्षित मानवबल की कमी से स्पष्ट था)।



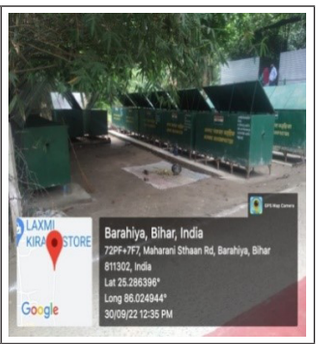
नगर निगम, भागलपुर में अधिष्ठापित नहीं किये गये यांत्रिक कंपोस्टर



नगर निगम, गया में अधिष्ठापित नहीं किये गये यांत्रिक कंपोस्टर



नगर परिषद्, हाजीपुर में अकार्यशील यांत्रिक कंपोस्टर

		
नगर निगम, पटना में अधिष्ठापित नहीं किये गये यांत्रिक कंपोस्टर	नगर परिषद्, जमुई में अधिष्ठापित किए गए बॉक्स कंपोस्टर	नगर परिषद्, बड़हिया में अधिष्ठापित किए गए बॉक्स कंपोस्टर

5.6.1.3 गया नगर निगम में केंद्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र

गया नगर निगम ने नगरपालिका अपशिष्टों के केंद्रीकृत प्रसंस्करण का विकल्प चुना और गया के नैली में एक केंद्रीकृत प्रसंस्करण इकाई की स्थापना और परिचालन के लिए एक एजेंसी[144] के साथ एकरारनामा किया (मार्च 2021)।

एजेंसी के साथ किए गए एकरारनामा के अनुसार, बुनियादी ढांचे के शुरूआत[145] होने के छः माह के भीतर पुराने अपशिष्टों का पुनर्ग्रहण और उपचार किया जाना था। इसके अंतर्गत किये जाने वाले कार्य का विवरण तथा किये गये कार्य का सार ***परिशिष्ट 5.15*** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा गया नगर निगम के केंद्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण में अनियमितताएं पाई गई, जिसकी चर्चा आगे की कंडिकाओं में की गई है, जबकि पुराने अपशिष्टों के निपटान से संबंधित अनियमितताओं की चर्चा ***कंडिका 5.6.2*** में की गई है।

(i) प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना के निविदा में अनियमितताएँ

(अ) बिहार वित्त नियमावली नियत करता है कि उच्च प्राधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए, किसी भी कार्य को विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। विभाग ने निविदाओं के निष्पादन के लिए विभिन्न प्राधिकारीयों को स्वीकृति देने की शक्ति प्रदान की (जुलाई 2015), जिसे **तालिका 5.24** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.24

निविदाओं के निष्पादन हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन

क्र. सं.	स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी	तकनीकी स्वीकृति की शक्ति	निविदा निष्पादन की शक्ति
1	सहायक अभियंता	₹ 10 लाख तक	शून्य
2	कार्यपालक अभियंता	₹ 10 लाख से ₹ 50 लाख	₹ 25 लाख तक
3	अधीक्षण अभियंता	₹ 50 लाख से ₹ 2 करोड़	₹ 25 लाख से ₹ 2 करोड़
4	मुख्य अभियंता	₹ 2 करोड़ तथा अधिक	₹ 2 करोड़ से ₹ 3.5 करोड़
5	विभागीय निविदा समिति	शून्य	₹ 3.5 करोड़ से अधिक

*(**स्रोतः** नगर विकास एवं आवास विभाग के अभिलेख)*

बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के विरूद्ध, गया नगर निगम ने समेकित नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना कार्य[146] को 11 भागों में विभाजित किया (विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 5.15*** में)। लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना की कुल लागत ₹ 29.46 करोड़

[144] *मेसर्स नैकोफ इंडिया*

[145] *आवश्यक ढाँचा, एकरारनामा की तारीख से छः माह के भीतर पूरा किया जाना था।*

[146] *समेकित नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना कार्य में ताजा अपशिष्ट प्रसंस्करण के साथ–साथ पुराने अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए सुविधा/प्रौद्योगिकी और मशीनरी की स्थापना के साथ–साथ 10 वर्षों की अवधि के लिए **स्वास्थ्यकर** भरण स्थलो का निर्माण, संचालन और रखरखाव भी शामिल है।*

थी। इसलिए, नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश (जुलाई 2015) के आलोक में, इस कार्य के निविदा को विभागीय निविदा समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाना चाहिए था। हालांकि, परियोजना को 11 भागों में विभाजित करने के कारण, कार्य के निविदा को मुख्य अभियंता[147] द्वारा अंतिम रूप दिया गया था। इस प्रकार, उच्च प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण और प्रशासनिक अनुमोदन से बचा गया।

(ब) समेकित नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के प्रस्ताव के लिए अनुरोध[148] के जांच के दौरान, यह देखा गया कि सिविल कार्यों से संबंधित विशिष्टियाँ/विस्तृत प्राक्कलन को कार्य के दायरे में शामिल नहीं किया गया था। मापी पुस्तिकाओं में विस्तृत प्रविष्टियाँ भी दर्ज नहीं की गई थीं। सिविल कार्यों की विशिष्टियों और विवरणियों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कार्य मानदंडों के अनुसार किए गए थे।

(स) परियोजना विवरण के अनुसार, सिविल कार्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्लेटफार्म, लीचेट टैंक, लीचेट के लिए नाला आदि का निर्माण एजेंसी द्वारा किया जाना था, लेकिन इसके लिए विशिष्टियाँ/विस्तृत प्राक्कलन, प्रस्ताव के लिए अनुरोध/एकरारनामा में शामिल नहीं किया गया था। साथ ही, एकरारनामा के विपरीत, सभी सिविल कार्य और संयंत्र और मशीनरी के चालू किये जाने की जांच एक विशेषज्ञ एजेंसी/तीसरे पक्ष (अक्टूबर 2022) द्वारा नहीं कराई गई थी, जबकि कार्य पूर्ण हो चुका था (फरवरी 2022)।

गया नगर निगम ने जवाब दिया कि कार्यों का विभाजन निधि की उपलब्धता पर आधारित था, क्योंकि कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया गया था। इसके अलावा, एजेंसी द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना के अनुसार, किये गये कार्यों का सत्यापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इन सभी कार्यों के लिए एकरारनामा एक ही तिथि को और एक ही एजेंसी के साथ निष्पादित किया गया था।

(ii) प्रसंस्करण–स्थल की स्थापना और भरण स्थल के निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्राधिकार प्राप्त नहीं करना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और समेकित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के लिए किए गए एकरारनामा (मार्च 2021) के अनुसार, प्रसंस्करण और भरण स्थल की स्थापना के लिए, सक्षम प्राधिकारों से प्राधिकार प्राप्त करना था। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एजेंसी ने सक्षम प्राधिकारों यथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण[149] और नागरिक उड्डयन विभाग[150] (अक्टूबर 2022) से आवश्यक मंजूरी प्राप्त नहीं किया था। विमानपत्तन प्राधिकरण[151] से ऊंचाई की मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त की गई थी (जुलाई 2021), जबकि दूरी की मंजूरी[152] का अनापत्ति प्रमाण–पत्र, जो कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार आवश्यक था अभी भी लंबित था।

---

147 *बुडको, गया प्रमंडल।*

148 *प्रस्ताव के लिए अनुरोध, अनुबंध का एक हिस्सा है।*

149 *पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1981 के अनुसार, नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण के संचालन से पहले राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से पर्यावरण मंजूरी ली जानी चाहिए।*

150 *नागरिक उड्डयन विभाग से मंजूरी की आवश्यकता थी क्योंकि स्वास्थ्यकर भरण स्थल गया हवाई अड्डे से केवल 4.2 कि.मी. दूर थी।*

151 *महाप्रबंधक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, क्षेत्रीय मुख्यालय, पूर्वी क्षेत्र, एन.एस.सी.बी.आई हवाई अड्डा, कोलकाता।*

152 *ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, स्वास्थ्यकर भरण स्थलें, हवाई अड्डे या एयरबेस से 20 कि.मी. दूर होनी चाहिए। हालांकि, किसी विशेष मामले में, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वायु सेना से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, जैसा भी मामला हो, भरण स्थल हवाई अड्डे/एयरबेस से 10 से 20 कि.मी. की दूरी के भीतर स्थापित की जा सकती है।*

गया नगर निगम ने जवाब दिया कि सक्षम प्राधिकारों से सभी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(iii) विंड्रो कम्पोस्टिंग तकनीक पर आधारित, नगरीय गीले अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा को नहीं अपनाया जाना

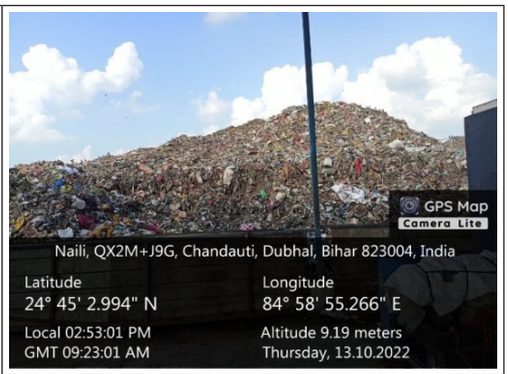
एकरारनामा (मार्च 2021) के अनुसार, एजेंसी को सितंबर 2021 तक 'विंड्रो कंपोस्टिंग' तकनीक[153] के आधार पर 300 टन प्रति दिन क्षमता वाले नगरीय मिश्रित अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा का डिजाइन, निर्माण, स्थापना, चालू करना और हस्तांतरण करना था। एक 'विंड्रो' में पूरे दिन के अपशिष्टों का संग्रह शामिल होता है। प्रति दिन, यही प्रक्रिया अपनाई जाती है और एक अलग विंड्रो बनाई जाती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ताजे मिश्रित अपशिष्टों को एकत्र किया जा रहा था और उसे तौलने के बाद प्रसंस्करण स्थल पर डंप किया जा रहा था। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान अपशिष्टों का बड़ा ढेर लगा हुआ पाया गया। इसके अलावा, प्रति दिन संग्रह किये गये अपशिष्टों के लिए कोई अलग विंड्रो नहीं था।

इस प्रकार, विंड्रो सुविधा पर (फरवरी 2022) ₹ 2.41 करोड़ का व्यय होने के बावजूद, विंड्रो कंपोस्टिंग तकनीक पूर्ण रूप से कार्यशील नहीं था (अक्टूबर 2022)।



मई 2022 का गूगल अर्थ प्रो का उपग्रह छवि, जब अपशिष्टों का प्रसंस्करण किया गया था। कोई विंड्रो का निर्माण नहीं देखा गया।



नैली में डंप किये गये ताजे अपशिष्ट और उसका विशाल ढेर। कोई विंड्रो का निर्माण नहीं देखा गया।

गया नगर निगम ने जबाव दिया कि बारिश के कारण दो महीने से छोटे विंड्रो ढेर नहीं बने थे। विंड्रो कंपोस्टिंग बाद में शुरू किया जाएगा। जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि अक्टूबर 2022 तक विंड्रो कम्पोस्टिंग से उत्पादित कम्पोस्ट की मात्रा मानक से कम[154] थी। इसके अलावा, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, प्रसंस्करण स्थल पर ताजे अपशिष्टों के विशाल ढेर भी पाए गए।

(iv) ताजे अपशिष्टों के प्रसंस्करण के बिना भुगतान

एकरारनामा (मार्च 2021) के अनुसार, एजेंसी को गया के नैली स्थित अपशिष्ट प्रसंस्करण स्थल पर आने वाले 300 टन प्रति दिन (औसतन) ताजे मिश्रित अपशिष्टों का प्रसंस्करण करना था। प्रारंभ में छः माह (अप्रैल 2021 से सितंबर 2021) की अवधि के लिए ₹ 3.24 करोड़ का एकरारनामा किया गया था, जिसे नवीनीकृत किया जा सकता था।

---

153 *'विंड्रो कम्पोस्टिंग' प्रक्रिया में पहले से संग्रहित अपशिष्ट को लंबे संकीर्ण ढेरों में रखना शामिल है, जिन्हें विंड्रो कहा जाता है, जिन्हें निष्क्रिय वायु–संचारण को बढ़ावा देने के लिए नियमित तौर पर घुमाया जाता है।*

154 *गया नगर निगम के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार अपशिष्ट वर्गीकरण में यह विश्लेषण किया गया था कि 39 प्रतिशत कम्पोस्ट नगरीय ठोस अपशिष्ट के कम्पोस्टींग/प्रसंस्करण से प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन, प्रसंस्करण के बाद मात्र चार प्रतिशत कम्पोस्ट ही एजेंसी द्वारा प्राप्त किया गया था।*

इसे सुनिश्चित करने के लिए, सिविल कार्य पूर्ण किया जाना था, मशीनों को स्थापित किया जाना था और निष्क्रिय अपशिष्टों के निपटान के लिए एक स्वास्थ्यकर भरण स्थल विकसित किया जाना था। प्रसंस्करण संयंत्र को सितंबर 2021 तक चालू किया जाना था। इसके अलावा, एजेंसी द्वारा प्रसंस्कृत ताजे अपशिष्टों की मात्रा के उचित सत्यापन के बाद अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने इस संबंध में निम्नलिखित पायाः

(क) प्रसंस्करण संयंत्र फरवरी 2022 में चालू किया गया था। हालांकि, संयंत्र के चालू होने के समय तक (अप्रैल 2021 से जनवरी 2022), अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए एजेंसी को ₹ 5.45 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था। हालांकि, प्रसंस्करण किये गये अपशिष्ट के समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

(ख) फरवरी 2022 में संयंत्र के चालू होने के बाद भी, एकरारनामा के विपरीत, प्रसंस्कृत ताजा अपशिष्टों की मात्रा का सत्यापन किए बगैर, फरवरी 2022 से सितंबर 2022 की अवधि के लिए एजेंसी को ₹ 6.09 करोड़ का भुगतान किया गया था।

(ग) दो प्रकार के वाहनों यथा–डंपर और कम्पेक्टर, के लॉग बुक के साथ–साथ जीपीएस और वजन मशीनों के डाटाबेस के विश्लेषण में पाया गया कि अनुश्रवण के अभाव के कारण ₹ 17.02 लाख (जून 2022 से सितंबर 2022 की अवधि के लिए) का अधिक भुगतान किया गया था, क्योंकि एजेंसी के द्वारा वाहनों के अवास्तविक प्रवेश और निकास समय तथा अनुपलब्ध/अपरिचालित वाहनों द्वारा अपशिष्टों के ढुलाई की प्रविष्टियों द्वारा कपटपूर्ण तरीके से वास्तविक ट्रिपों के संख्या की तुलना में अधिक ट्रिपों का दावा किया गया था, जैसा कि **तालिका 5.25** में दर्शाया गया है और विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 5.16*** पर है।

तालिका 5.25

एजेंसी द्वारा किया गया कपटपूर्ण दावा

विवरण	कपटपूर्ण दावों का तरीका			कुल
	वास्तविक की तुलना में अधिक ट्रिपों की संख्या के मामले	वाहनों के अवास्तविक प्रवेश और निकास समय के मामलों की संख्या	अनुपलब्ध/अपरिचालित वाहनों द्वारा ढुलाई दर्शाये गये मामलों की संख्या	
मामलों की संख्या	249	5	4	...
सम्मिलित राशि (₹ लाख)	17.02	..	..	**17.02**

*(**स्रोतः** गया नगर निगम के अभिलेख)*

तालिका 5.25 इंगित करता है कि गया नगर निगम द्वारा अनुश्रवण की कमी के कारण, एजेंसी ने गलत भुगतान का दावा प्रस्तुत किया था, अथवा अपशिष्टों का वास्तविक प्रसंस्करण किए बिना ही अपशिष्टों के प्रसंस्करण के लिए कपटपूर्ण तरीके से भुगतान का दावा किया था।

गया नगर निगम ने जवाब दिया कि मामले की विस्तृत जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

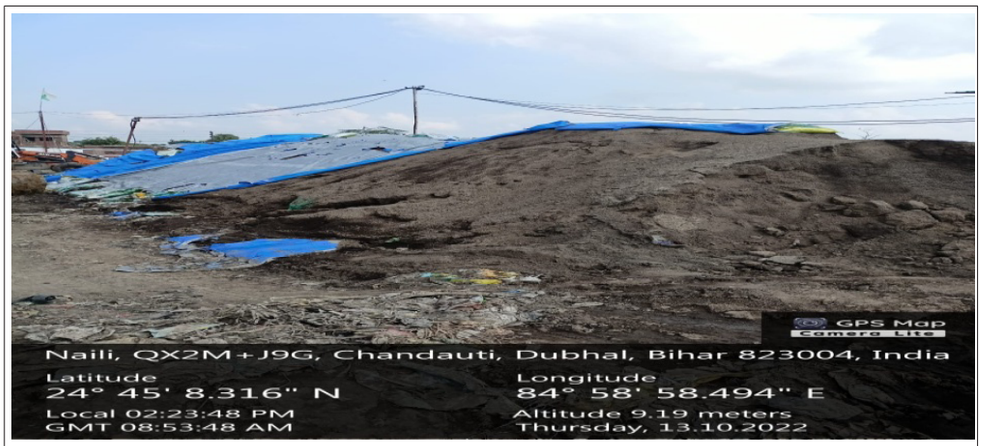
(v) उप–उत्पादों/पुनर्चक्रण योग्य उत्पादों से राजस्व की प्राप्ति न होना

गया नगर निगम और एजेंसी के बीच हुए एकरारनामा (मार्च 2021) के अनुसार, कम्पोस्ट/बायोगैस, कचरा व्युत्पन्न ईंधन, ऊर्जा, पुनर्चक्रण योग्य सामग्री आदि की बिक्री से प्राप्त आय को एजेंसी और गया नगर निगम के बीच 80:20 के अनुपात में साझा किया जाना था।

सभी उप–उत्पादों के विपणन के लिए एजेंसी जिम्मेदार थी। इसके अलावा, पुनः उपयोग योग्य और पुनर्चक्रण उप–उत्पादों को स्थल पर तीन दिनों, जिसकी गणना उप–उत्पादों के उत्पादन की तिथि से की जानी थी, से अधिक समय तक नहीं रखा जाना था।

अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 के दौरान, एजेंसी ने 94,731.98 टन ताजे मिश्रित अपशिष्टों का प्रसंस्करण किया था और इससे 2,513.15 टन (तीन प्रतिशत) कम्पोस्ट का उत्पादन हुआ था। हालांकि, एजेंसी ने अक्टूबर 2022 तक इन उप–उत्पादों को नहीं बेचा था। इसके कारण कम्पोस्ट की बिक्री से कम से कम ₹ 25.13 लाख[155] की वसूली नहीं हुई।

इसके अतिरिक्त, सामग्री वसूली सुविधा केन्द्र में अपशिष्टों के प्रसंस्करण से उत्पन्न हुए कचरा व्युत्पन्न ईंधन, पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक, कांच, कागज आदि प्राप्त हुए थे, लेकिन एजेंसी या गया नगर निगम द्वारा इसका आँकड़ा संधारित नहीं किया गया था, और न ही एजेंसी द्वारा इसे बेचा गया था।



गया नगर निगम में प्रसंस्करण स्थल पर खुले आसमान के नीचे रखा गया कम्पोस्ट

गया नगर निगम ने जवाब दिया कि एजेंसी को कम्पोस्ट बेचने और 20 प्रतिशत राशि वसूलने के लिए स्मारित किया जाएगा।

5.6.1.4 पटना नगर निगम में अपशिष्ट–से–ऊर्जा बनाने का कार्य नहीं किया जाना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 21 में 'अपशिष्ट–से–ऊर्जा' बनाने की परिकल्पना की गई है। यह नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊष्मा या बिजली के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसके अनुरूप, नगर विकास एवं आवास विभाग ने पटना शहर में नगरीय अपशिष्टों के प्रसंस्करण के लिए एक केंद्रीकृत अपशिष्ट–से–ऊर्जा बनाने के संयंत्र की योजना (फरवरी 2019) बनाई थी।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (अक्टूबर 2019) से संबंधित राज्य उच्च सशक्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त की जांच से पता चला कि मेसर्स एजी डॉटर्स वेस्ट प्रोसेसिंग प्राइवेट

[155] *कुल उत्पादित कम्पोस्टः 25,13,150 किलोग्राम x* 20 प्रतिशत (एकरारनामा के अनुसार गया नगर निगम का अंश) = 5,02,630 किलोग्राम, 5,02,630 किलोग्राम *x ₹ पाँच प्रति किलोग्राम (कम्पोस्ट की लागत) = ₹ 25.13 लाख*

लिमिटेड[156] को पटना में अपशिष्ट–से–ऊर्जा बनाने के संयंत्र को स्थापित करना था। यह संयंत्र 1,200 टन प्रति दिन ठोस अपशिष्टों का प्रसंस्करण करता और उसे हरित ऊर्जा में परिवर्तित करता।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के पटना नगर निगम के बजट के अनुसार, इस परियोजना के लिए ₹ 3,540 करोड़ की जरूरत थी जिसे एजेंसी को निवेश करना था।

कंपनी को अपनी लागत से छः स्थानों पर स्थायी ट्रांसफर स्टेशन भी स्थापित करने थे, जहां प्राथमिक संसाधनों के माध्यम से पटना नगर निगम द्वारा एकत्रित किए गए अपृथक्कृत अपशिष्टों को लाया जाना था, और कंपनी के स्वयं के ट्रकों के माध्यम से अपशिष्टों को अपशिष्ट–से–ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र पर स्थानांतरित करना था।

हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया (नवंबर 2022) कि अपशिष्टों के प्रसंस्करण के लिए यह तकनीक अभी तक पटना नगर निगम में लागू नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, ताजा मिश्रित नगरीय अपशिष्टों का परिवहन किया जा रहा था और उसे बिना प्रसंस्करण के डंपिंग स्थल पर डंप किया जा रहा था।

	
रामचक बैरिया में, नगरपालिका वाहन ताजे मिश्रित अपशिष्टों को ढोते हुए	रामचक बैरिया में विशाल मिश्रित अपशिष्टों का ढेर

5.6.1.5 कचरा व्युत्पन्न ईंधन के निपटान में कमी

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार, कचरा व्युत्पन्न ईंधन, ठोस अपशिष्ट के ज्वलनशील भाग, यथा प्लास्टिक, लकड़ी, लुगदी या कार्बनिक अपशिष्ट, क्लोरीनयुक्त पदार्थों से इतर, को सुखाकर, कतरन, निर्जलीकरण और संघनन द्वारा गूटिका या रोंये के रूप मे प्राप्त किया जाना है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी ''अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के लिए चयन मानदंड'' के अनुच्छेद 2.6 के अनुसार, कचरा व्युत्पन्न ईंधन के पेलेटाइजेशन/उत्पादन की प्रक्रिया बताते हुए, निपटान के लिए एकत्र किए गए नगरीय ठोस अपशिष्ट के नमी का परीक्षण किया जाना है और, यदि नमी की मात्रा 35–40 प्रतिशत से अधिक हो; तो उचित कैलोरीफिक/तापमान के साथ ईंधन पैलेट उत्पादित करने के लिए इसे सुखाने की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में, भाप या बिजली उत्पादन के लिए, या औद्योगिक भट्टियों या बॉयलरों में वैकल्पिक ईंधन के रूप में किया जाता है (अपशिष्ट का सह–प्रसंस्करण[157] या सह–भस्मीकरण[158], सीमेंट, चूना और इस्पात उद्योगों में, साथ ही बिजली उत्पादन के लिए)।

---

[156] *लैंगेनबर्ग टेक्नोलॉजी एलएलसी, यूएसए के साथ संयुक्त उद्यम में।*

[157] *ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, ''सह प्रसंस्करण'' का अर्थ है प्राकृतिक खनिज संसाधनों और औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवाश्म ईंधनों को प्रतिस्थापित करने या उन्हें अनुपूरित, दोनों को करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में या ऊर्जा के स्रोत या दोनों के रूप में 1500 किलो कैलोरी से अधिक कैलोरिफिक मूल्य वाले गैर–जैव अवक्रमणीय और गैर–पुनर्चक्रणीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग।*

[158] *नगरीय ठोस अपशिष्ट हस्तक, 2016 के अनुसार, 'सह–भस्मीकरण', ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के लिए अपशिष्ट पदार्थ के उपयोग को संदर्भित करता है।*

दो शहरी स्थानीय निकायों[159] ने नगरीय ठोस अपशिष्ट से कचरा व्युत्पन्न ईंधन प्राप्त किया था।

लेखापरीक्षा ने इस संबंध में निम्नलिखित पायाः

(i) गया नगर निगमः – गया नगर निगम ने 100 टन प्रति दिन अपशिष्टों के प्रसंस्करण के लिए श्रेडर[160] और बेलर[161] सहित कचरा व्युत्पन्न ईंधन प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एक एजेंसी (मैसर्स नैकोफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के साथ एकरारनामा (मार्च 2021) किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि कचरा व्युत्पन्न ईंधन प्रोसेसिंग प्लांट में श्रेडर और बेलर अधिष्ठापित नहीं किया गया था, जबकि कचरा व्युत्पन्न ईंधन प्लांट को चालू करने और प्रसंस्करण के लिए एजेंसी को ₹ 1.34 करोड़ का भुगतान किया गया था।

श्रेडर और बेलर के अभाव में, कचरा व्युत्पन्न ईंधन का कतरन एवं गुटिका, ईंटों या टुकड़ों के रूप में संपीडन नहीं किया जा रहा था। मिश्रित ताजे अपशिष्टों और पुराने अपशिष्टों के प्रसंस्करण के बाद, प्राप्त कचरा व्युत्पन्न ईंधन को उसकी नमी की मात्रा की जांच किए बिना, खुलेरूप में छांटा/पृथक किया जा रहा था। प्रसंस्करण स्थल पर खुले कचरा व्युत्पन्न ईंधन के विशाल ढेर पाए गए।



गया नगर निगम में पुराने अपशिष्टों के प्रसंस्करण के बाद प्राप्त कचरा व्युत्पन्न ईंधन



गया नगर निगम में प्रसंस्करण स्थल पर खुला पड़ा हुआ कचरा व्युत्पन्न ईंधन का ढेर

गया नगर निगम ने जवाब दिया कि कचरा व्युत्पन्न ईंधन को श्रेडिंग की आवश्यकता केवल तभी थी, जब कचरा व्युत्पन्न ईंधन की मोटाई 50 मिली मीटर माइक्रोन से ऊपर हो। हालांकि, कचरा व्युत्पन्न ईंधन की नमी की जांच के लिए एजेंसी को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे और उसके अंतिम निपटान से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे। जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि एकरारनामा के अनुसार, श्रेडर और बेलर को प्रसंस्करण स्थल पर अधिष्ठापित किया जाना था और कचरा व्युत्पन्न ईंधन का निपटान, उसके संपीडित होने के बाद ही किया जा सकता था।

(ii) पटना नगर निगम– पटना नगर निगम ने पुराने अपशिष्टों के निपटान के लिए तीन एजेंसियों[162] के साथ एकरारनामा किया था। इस एकरारनामा के अनुसार, सभी पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रसंस्कृत और निपटान किया जाना था।

---

[159] *गया और पटना*

[160] *'श्रेडर' एक यांत्रिक उपकरण है जिसका उपयोग अपशिष्ट पदार्थ को चीरकर एवं बलपूर्वक छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए किया जाता है। ठोस अपशिष्ट को टुकड़े–टुकड़े करके उसकी मात्रा को कम करने या उसे अधिक आसानी से दहन योग्य बनाने के लिए किया जाता है।*

[161] *एक मशीन जिसका उपयोग मात्रा कम करने के लिए पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को बंडलों में संपीड़ित करने के लिए किया जाता है। बेलर का उपयोग अक्सर समाचार पत्र, प्लास्टिक और घुमावदार कार्डबोर्ड के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को ''बेलिंग'' कहा जाता है।*

[162] *मेसर्स नैकोफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पाथ्या और सीडी ट्रान्सपोर्ट*

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अक्टूबर 2022 तक इन एजेंसियों द्वारा कुल 6,88,314[163] घन मीटर अपशिष्टों को प्रसंस्कृत किया गया था, जिसमें से 1,13,036.66 घन मीटर कचरा व्युत्पन्न ईंधन प्राप्त हुआ जिसे टुकड़े–टुकड़े और संपीडित किए बिना ही निपटान कर दिया गया। इसके अलावा, कचरा व्युत्पन्न ईंधन के उचित निपटान/प्रसंस्करण के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया था।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, पटना नगर निगम के प्रसंस्करण स्थल पर डंप किए गए खुले कचरा व्युत्पन्न ईंधन के विशाल ढेर पाये गए। कचरा व्युत्पन्न ईंधन का निपटान एजेंसी की जिम्मेदारी थी, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया गया था (अक्टूबर 2022)।



पटना नगर निगम के प्रसंस्करण स्थल पर डंप किया हुआ खुला आरडीएफ (नैकोफ)



पटना नगर निगम के प्रसंस्करण स्थल पर डंप किया हुआ खुला आरडीएफ (सीडी ट्रान्सपोर्ट)

5.6.1.6 निक्षालन उपचार की सुविधा विकसित नहीं किया जाना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, किसी भी स्थिति में निक्षालन[164] को खुले वातावरण में नहीं छोड़ा जाना है। इसके अलावा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देश (जनवरी 2021) के अनुसार, पुराने अपशिष्टों[165] के जैव–खनन प्रक्रिया[166] में लगे सभी स्थानीय अधिकारियों को निक्षालन उपचार के लिए पर्याप्त प्रावधान करने की आवश्यकता है।

गया नगर निगम ने पुराने अपशिष्टों और ताजे नगरीय अपशिष्टों के प्रसंस्करण के लिए एक समेकित नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा विकसित किया था (मार्च 2021 से फरवरी 2022)। इस उद्देश्य के लिए, गया नगर निगम ने एक एजेंसी (मैसर्स नैकोफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के साथ एक एकरारनामा (मार्च 2021) किया था। एकरारनामा के अनुसार, एजेंसी को निक्षालन उपचार सुविधा और निक्षालन के लिए उचित नाली का निर्माण करना था। हालांकि, यह देखा गया कि प्रसंस्करण स्थल पर इस सुविधा को विकसित नहीं किया गया था।

163

एजेन्सी का नाम	*कुल प्रसंस्कृत अपशिष्ट (मात्रा घन मीटर में)*	*प्राप्त कचरा व्युत्पन्न ईंधन (मात्रा घन मीटर में)*
नैकोफ	5,02,380	1,00,476
सीडी ट्रान्सपोर्ट	96,215	ऑकड़े उपलब्ध नही
पाथ्या	89,719	12,560,66
कुल	***6,88,314***	***1,13,036,66***

164 *ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार, ''निक्षालन'' का अर्थ वह द्रव है जो ठोस अपशिष्ट के माध्यम से या अन्य माध्यम से रिसता है जिसमें उसमें घुली हुई या निलंबित सामग्री का सत्व है।*

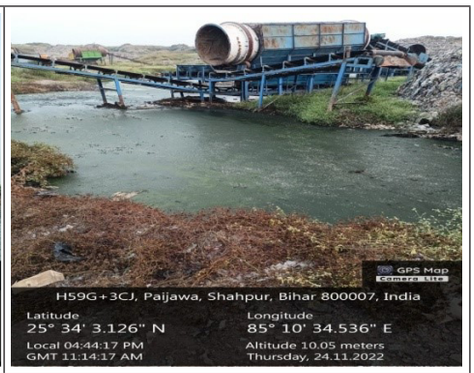
165 *पुराने अपशिष्टों (पुराने नगरीय ठोस अपशिष्ट) के निपटान के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, नगरीय ठोस अपशिष्ट के अनियंत्रित और निरंतर डंपिंग से पुराने अपशिष्ट के पहाड़ बन जाते हैं।*

166 *ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार, ''जैव–खनन प्रक्रिया'' का तात्पर्य पुराने डंप किए गए अपशिष्ट की खुदाई करना और पुराने अपशिष्ट का विंड्रो बनाना है, जिसके बाद बायो–रेमेडिएशन के माध्यम से कचरे का स्थिरीकरण किया जाता है, अर्थात् कंपोस्टिंग बायोकल्चर के उपयोग से सभी अपशिष्ट को हवा में छोड़ना, अर्थात् सभी मूल्यवान संसाधनों को पुनः प्राप्त करने के लिए स्थिर अपशिष्ट की जांच।*

इसके अतिरिक्त, पटना नगर निगम ने भी तीन एजेंसियों[167] के माध्यम से पुराने अपशिष्टों का जैव–उपचार[168] (नवंबर 2021 से फरवरी 2022) भी किया था, लेकिन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, निक्षालन उपचार की सुविधा और इसके लिए उचित नाली सुविधा विकसित करने में विफल रहा।



अतिप्रवाह के कारण गया नगर निगम में पूरे प्रसंस्करण प्लेटफॉर्म पर फैला निक्षालन।



पटना नगर निगम के अपशिष्ट प्रसंस्करण स्थल पर अनुपचारित निक्षालन का जमाव।

प्रसंस्करण स्थल पर निक्षालन का प्रवाह, समीपवर्ती क्षेत्रों में भू–जल दूषण के जोखिम से युक्त था।

पटना नगर निगम ने जवाब दिया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, ताजे अपशिष्टों के प्रसंस्करण और निक्षालन उपचार सुविधा के अधिष्ठापन के लिए एक उचित जल निकास प्रणाली और निक्षालन उपचार सुविधा अनिवार्य है, जो प्रस्ताव के लिए अनुरोध में शामिल नहीं थे। हालांकि, तथ्य यही था कि, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के विपरीत, निक्षालन उपचार नहीं किया जा रहा था।

5.6.2 पुराने अपशिष्टों का निपटान

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 22 में प्रावधान है कि पुराने डंपिंग स्थलों का जैव–उपचार पाँच साल के भीतर कर लिया जाना चाहिए। माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश (जुलाई 2019) के अनुसार, पुराने अपशिष्टों का उपचार 1 नवंबर 2019 से शुरू कर देना था और पुराने अपशिष्ट स्थलों का उपचार शुरू करने में विफल रहने पर, 1 अप्रैल 2020 से अनुपालन किये जाने तक, शहरी स्थानीय निकायों का दायित्व होगा कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मुआवजे[169] का भुगतान करे।

माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को सौंपे गये, शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिवेदनों (दिसंबर 2020) के अनुसार, नमूना जांच किए गए 16 शहरी स्थानीय निकायों में कुल 14.04 लाख टन पुराने अपशिष्ट विभिन्न स्थलों पर डंप किये गये थे। हालांकि, 16 शहरी स्थानीय निकायों[170] में से केवल चार[171] ने पुराने अपशिष्टों का निपटान किया था। इन

---

[167] *60 प्रतिशत पुराने अपशिष्ट को नैकोफ द्वारा प्रसंस्कृत किया जा रहा था (नवंबर 2021), 20 प्रतिशत –20 प्रतिशत पुराने अपशिष्ट को प्रत्येक सीडी ट्रांसपोर्ट (जनवरी 2022) और पथ्या (फरवरी 2022) द्वारा प्रसंस्कृत किया जा रहा था।*

[168] *पुराने अपशिष्ट (पुराने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट) के निपटान के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, 'जैव–उपचार' का अर्थ है सभी मूल्यवान संसाधनों को पुनर्प्राप्त करने के लिए, कंपोस्टिंग बायोकल्चर का उपयोग अर्थात स्थिर अपशिष्ट की स्क्रीनिंग के साथ–साथ सभी अपशिष्टों को हवा में छोड़ना।*

[169] *10 लाख से अधिक की आबादी के लिए प्रति स्थानीय निकाय ₹ 10 लाख प्रति माह की दर से; 5 लाख से 10 लाख के बीच की आबादी के लिए प्रति स्थानीय निकाय ₹ पाँच लाख प्रति माह और अन्य स्थानीय निकाय के लिए ₹ एक लाख प्रति माह। यदि स्थानीय निकाय वित्तीय बोझ उठाने में असमर्थ हैं, तो दायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होगा और वे दोषी स्थानीय निकायों के खिलाफ उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे।*

[170] *पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, छपरा, सहरसा, दानापुर, किशनगंज, सुल्तानगंज, जमुई, दलसिंहसराय, बहादुरगंज, बेलसंड और मुरलीगंज*

[171] *पटना, गया, मुजफ्फरपुर और मुंगेर*

चार शहरी स्थानीय निकायों में, पुराने अपशिष्टों के निपटान में कुछ विसंगतियाँ पायी गईं, जिसकी चर्चा नीचे की गई है।

- ***पटना–*** जनवरी 2022 तक, शहरी स्थानीय निकाय में उत्पन्न पुराने अपशिष्टों की मात्रा 10.08 लाख घन मीटर थी। इसमें से, 6.88 लाख (68 प्रतिशत) घन मीटर का जैव–उपचार/निपटान (जून 2022 तक) प्रतिवेदित किया गया था। हालांकि, दावे का भुगतान न होने और पटना नगर निगम के पास निधि की कमी के कारण, एजेंसी द्वारा काम रोक दिया गया था (जून 2022)।

- ***गया –*** माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को सौंपे गये, शहरी स्थानीय निकाय की रिपोर्ट (दिसंबर 2020) के अनुसार, पुराने अपशिष्टों की मात्रा चार लाख टन अनुमानित की गई थी। अक्टूबर 2022 तक, 4.24 लाख टन पुराने अपशिष्टों का जैव–उपचार/निपटान किया जाना प्रतिवेदित किया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, पुराने अपशिष्ट डंपिंग स्थल पर डंप पाया गया था (अक्टूबर 2022)।

- ***मुजफ्फरपुर–*** अगस्त 2019 तक, पुराने अपशिष्टों की मात्रा 7,878 घन मीटर प्रतिवेदित की गई थी। कार्य की मापी के बिना ही, एजेंसी को ₹ 39.68 लाख का भुगतान कर दिया गया था।

- ***मुंगेर–*** मुंगेर नगर निगम द्वारा किए गए आकलन (दिसंबर 2020) के अनुसार, दिसंबर 2020 तक भरण स्थल पर जमा पुराने अपशिष्टों की मात्रा 2.25 लाख टन थी। इन पुराने अपशिष्टों के निपटान के लिए निविदा मांगी गई (फरवरी 2021) और सबसे कम बोली लगाने वाले, यानी मेसर्स इकोस्टन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (एजेंसी) को पुराने अपशिष्टों के वैज्ञानिक निपटान और निष्क्रिय सामग्री के निपटान हेतु, एक **स्वास्थ्यकर** भरण स्थल को विकसित करने के लिए अनुबंधित किया गया था (मई 2021)।

एजेंसी ने मार्च–जून 2022 के दौरान 2.17 लाख टन (2.25 लाख टन में से) पुराने अपशिष्टों के निपटान और एक **स्वास्थ्यकर** भरण स्थल के विकास का दावा किया। अभिलेख के अनुसार, एजेंसी द्वारा किए गए काम की मात्रा का संयुक्त रूप से कनीय अभियंता, सहायक अभियंता और सिटी मैनेजर द्वारा निरीक्षण किया गया था और एजेंसी द्वारा कार्य पूरा करने के दावे का समर्थन, (01/06/2022) किया गया था। तदनुसार, भुगतान कर दिया गया था।

हालांकि, संयुक्त भौतिक सत्यापन (अगस्त 2022) के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि अलग किये गये प्लास्टिक सामग्री और निष्क्रिय वस्तुएं स्थल पर डंप पड़ी हुई थीं, जमीन की सतह को समतल नहीं किया गया था और **स्वास्थ्यकर** भरण स्थल विकसित नहीं किया गया था। इस प्रकार, कार्य पूर्ण किये बिना ही एजेंसी को पूर्ण भुगतान कर दिया गया था, जैसा कि **तालिका 5.26** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.26
मुंगेर में पुराने अपशिष्टो का अनुचित प्रबंधन

कार्य का विवरण	एकरारनामा के अनुसार किये जाने वाले कार्य			एजेन्सी के द्वारा दावा किये गये कार्य			वास्तविक स्थिति (जैसा कि लेखापरीक्षा के द्वारा देखा गया)
	कार्य की मात्रा	भुगतान का दर	कुल भुगतेय राशि	कार्य की मात्रा	भुगतान का दर	कुल भुगतान	
पुराने अपशिष्टों का वैज्ञानिक निपटान	2.25 लाख टन	₹ 358 प्रति टन	₹ 8.06 करोड़	2.17 लाख टन	₹ 358 प्रति टन	₹ 7.77 करोड़	1. अलग किये हुए प्लास्टिक सामग्री और निष्क्रिय वस्तुएं डंप पाई गईं। इस प्रकार, अपशिष्टों का वैज्ञानिक तरीके से निपटान नहीं किया गया था। 2. पाया गया कि डंपिंग स्थल पर अभी भी अपशिष्टों को डंप किया जा रहा था, इससे यह स्पष्ट था कि जमीन की सतह को समतल नहीं किया गया था। 3. स्वास्थ्यकर भरण स्थल विकसित नहीं किया गया था।
जमीन की सतह का समतलीकरण	--			किया गया			
स्वास्थ्यकर भरण स्थल का विकास	--			किया गया			

*(**स्रोत**: मुंगेर नगर निगम के अभिलेख)*

नगर आयुक्त, मुंगेर ने जवाब दिया कि पुराने अपशिष्टों के वैज्ञानिक निपटान के लिए एजेन्सी को नोटिस निर्गत किया जाएगा और उचित समय में स्थल को साफ कर दिया जाएगा।



पटना में पुराने अपशिष्ट



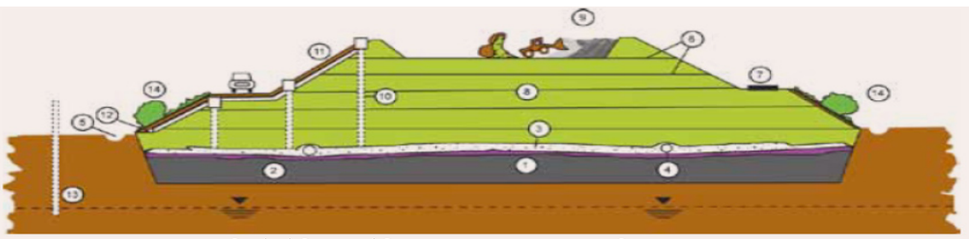
गया में पुराने अपशिष्ट



मुंगेर में डंप किये गये पृथक्कृत ज्वलनशील सामग्री का ढेर

5.6.3 स्वास्थ्यकर भरण स्थल

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 15 (यज) के अनुसार, स्थानीय प्राधिकारों को यह सुनिश्चित करना है कि स्वास्थ्यकर भरण स्थल की स्थापना और संचालन के तुरंत बाद, मिश्रित अपशिष्टों का भूमि भरण और डंपिंग का कार्य बंद कर दिया जाए। आगे, राज्य नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति और रणनीति (फरवरी 2019) के अनुसार, अपशिष्ट प्रबंधन पदानुक्रम में, भरण स्थलों का उपयोग कम से कम और केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना है। निष्क्रिय अपशिष्टों को भरण स्थल पर भरने से पहले, जैविक और पुनर्चक्रणीय सामग्रियों को पूर्णरूप से पुनर्प्राप्त किया जाना चाहिए।



1. जियोलोजिकल बैरियर
2. इमपरमियेबल बेस लाइनर
3. ड्रेनेज लेयर
4. लिचेट संग्रहण तंत्र
5. स्ट्राम–वाटर ड्रेन डिच
6. बार्डरींग डैम
7. सर्कुलेशन मार्ग
8. भूमिभरण स्थल
9. लेयरों में फिलिंग एवं कम्पैक्टिंग
10. गैस निकासी तंत्र
11. सुरक्षा कवच तंत्र
12. गैस संग्राहक
13. भू–जल नियंत्रण
14. रिप्लांटिंग

नगरीय ठोस अपशिष्ट के स्वास्थ्यकर भरण स्थल के आवश्यक घटक

5.6.3.1 स्वास्थ्यकर भरण स्थल की उपलब्धता

(i) स्वास्थ्यकर भरण स्थल[172] के विकास की दिशा में पहले कदम के रूप में, शहरी स्थानीय निकाय को स्वास्थ्यकर भरण स्थल सहित अपशिष्ट प्रसंस्करण, उपचार या निपटान सुविधाएं (यदि कचरे की मात्रा प्रति दिन पाँच मीट्रिक टन से अधिक है) स्थापित करने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में से 12 मामलों[173] में, स्वास्थ्यकर भरण स्थल के विकास के लिए, उन्हें कोई अधिकृत भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

नमूना जांच किए गए 15 शहरी स्थानीय निकायों में, (पटना नगर निगम को छोड़कर), जहां निर्दिष्ट भूमि उपलब्ध थी (या तो हस्तांतरण के माध्यम से या पट्टे के माध्यम से), शहरी स्थानीय निकायों ने स्वास्थ्यकर भरण स्थल के विकास के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त नहीं किया था।

हालांकि, पटना नगर निगम को नवंबर 2013 में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त हुआ था, लेकिन स्वास्थ्यकर भरण स्थल के विकास में (नवंबर 2022 तक) उसने कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की थी।

(ii) गया नगर निगम में, नैली में एक स्वास्थ्यकर भरण स्थल के विकास के लिए गया नगर निगम द्वारा (मैसर्स नैकोफ) एजेंसी के साथ एक एकरारनामा किया गया था (मार्च 2021)।

---

172 *''स्वास्थ्यकर भरण स्थल'' का अर्थ है भूजल, सतही जल एवं हवा में उड़ते धूल कण, हवा में उड़ता कूड़ा–करकट, दुर्गंध, आग का खतरा, पशुओं से खतरा, पक्षियों से खतरा, कीट या चूहों, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, सतत् जैव प्रदूषणकारी तत्व, ढलान में अस्थिरता एवं अपरदन से सुरक्षित, एक सुविधा स्थल पर, अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट एवं निष्क्रिय अपशिष्ट का अंतिम एवं सुरक्षित निपटान।*

173 *दरभंगा, गोपालगंज, हाजीपुर, राजगीर, दलसिंहसराय, बड़हिया, बहादुरगंज, जगदीशपुर, मखदुमपुर, मुरलीगंज, महाराजगंज और बेलसंड।*

एकरारनामा की राशि ₹ 2.64 करोड़ थी। एकरारनामा के शर्तों के अनुसार, 50 प्रतिशत राशि का भुगतान आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एजेंसी द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों (जैसे बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, विमानपत्तन प्राधिकरणों से दूरी मंजूरी) से कोई मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी। हालांकि, एजेंसी द्वारा स्वास्थ्यकर भरण स्थल विकसित करना प्रतिवेदित किया गया था और एजेंसी को ₹2.64 करोड़ का पूर्ण भुगतान कर दिया गया था, लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया था कि उसने आवश्यक मंजूरी प्राप्त नहीं की थी।

(iii) आगे, गया नगर निगम ने 10 साल की अवधि के लिए स्वास्थ्यकर भरण स्थल के संचालन और रखरखाव के लिए उसी एजेंसी (मेसर्स नैकोफ) के साथ एक और एकरारनामा (मार्च 2021) किया। एकरारनामा के अनुसार, एकरारनामा की कुल राशि (₹ 2.84 करोड़) का 95 प्रतिशत (₹ 2.70 करोड़) संचालन शुरू होने के छः महीने के भीतर एजेंसी को भुगतान (अप्रैल 2022) कर दिया गया, जबकि अनुबंध की अवधि 10 वर्षों की थी। इसके अतिरिक्त, भुगतान एजेंसी द्वारा किए गए वास्तविक कार्य से जुड़ा हुआ नहीं था। इस तरह के भुगतान शर्त एजेंसी को अनुचित लाभ पहुंचाने से अभिप्रेत थे।

(iv) गया नगर निगम ने नैली भरण स्थल पर ₹ 80.38 लाख की अनुमानित लागत से चारदीवारी के निर्माण के लिए एक एजेंसी (मेसर्स एसएन एंटरप्राइजेज) को कार्यादेश (नवंबर 2021) निर्गत किया था। कार्य को सितंबर 2021 तक पूर्ण करना था। हालांकि, ₹ 44.70 लाख खर्च करने के बाद भी (मई 2022 तक) मात्र 56 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुआ था।

कार्य आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि शेष कार्य के लिए उपलब्ध भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया था और अतिक्रमित भूमि एजेंसी को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी (अक्टूबर 2022 तक)।

इस प्रकार, नमूना जांच किए गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में स्वास्थ्यकर भरण स्थल उपलब्ध नहीं था।

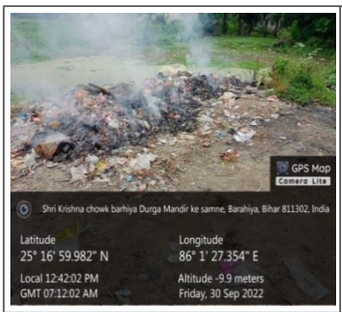
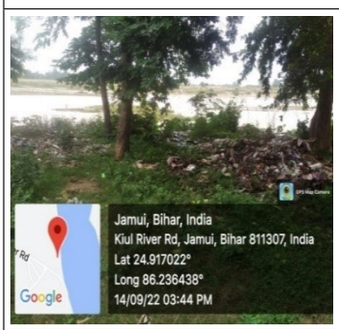
5.6.3.2 अनधिकृत स्थलों पर अपशिष्टों का निपटान

नगरीय ठोस अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान शहरी स्थानीय निकायों के समग्र प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है। अनधिकृत स्थानों पर अपशिष्टों का निपटान और नगरीय अपशिष्टों को जलाना, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों की यह जिम्मेवारी है कि वे अपशिष्ट उत्पादकों को निर्देश दें कि वे सड़कों, खुले सार्वजनिक स्थानों, नालियों या जल स्रोतों पर कोई अपशिष्ट न फेंके, न जलाएं या न दफनाएं। भूमि भरण स्थल को नदियों से 100 मीटर, तालाबों से 200 मीटर और राजमार्गों, बस्तियों, सार्वजनिक पार्कों और जलापूर्ति कुओं आदि से 200 मीटर दूर होना आवश्यक है। इसके अलावा, बाढ़ के मैदानों में भूमि भरण स्थल की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, किसी भी स्थिति में, निक्षालन को खुले वातावरण में नहीं रखना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किए गए किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में स्वास्थ्यकर भरण स्थल उपलब्ध नहीं थे।

तदनुसार, शहरी स्थानीय निकायों ने अपनी सुविधा के अनुसार, भरण स्थल/डंपिंग स्थलों को चुना था, जैसा कि ***परिशिष्ट–5.17*** में विस्तृत विवरण दिया गया है और, जैसा कि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखा गया।

		
बड़हिया में सड़क के किनारे जलता हुआ मिश्रित अपशिष्ट	जहानाबाद में भूमिगत जल पंपिंग स्टेशन के पास मिश्रित अपशिष्टों का डंपिंग	मुरलीगंज में सड़क किनारे, डंप किये हुए मिश्रित नगरीय अपशिष्टों के साथ बचे हुए मेडिकल अपशिष्ट
		
जमुई में किउल नदी (गंगा की सहायक नदी) के तट पर डंप किये हुए मिश्रित अपशिष्ट	डंपिंग स्थल, बैरिया, पटना के पास भवन और कूड़े से निकल रहा निक्षालन	सुल्तानगंज में गंगा नदी के किनारे डंप किये हुए मिश्रित अपशिष्ट

5.6.3.3 अपशिष्ट प्रसंस्करण के अभाव में, अपशिष्ट स्टैकिंग के लिए अर्थ मूवर मशीन किराए पर लेने के कारण ₹ 10.29 करोड़ का परिहार्य व्यय

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार, पुराने डंप को साफ करना तब तक अर्थहीन है, जब तक कि नए खुले डंप स्थलों का निर्माण बंद न हो जाए। जैविक रूप से अपघटित अपशिष्टों के उचित पृथक्करण और एरोबिक कंपोस्टिंग या बायो–मिथेनेशन के माध्यम से प्रसंस्करण के द्वारा इसे सर्वोत्तम तरीके से किया जाता है।

पटना नगर निगम के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपी गई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के वार्षिक प्रतिवेदन (2021–22) के अनुसार, पटना नगर निगम ने (अक्टूबर 2020 से नवंबर 2022 तक) लगभग 1,000 टन प्रति दिन मिश्रित अपशिष्टों को बैरिया भरण स्थल तक पहुंचाया था।

इसके अलावा, चार शहरी स्थानीय निकायों[174] के नगरीय अपशिष्टों को भी बैरिया भरण स्थल पर डंप किया जा रहा था।

इस बीच, पटना नगर निगम ने ताजे अपशिष्टों, जिन्हें बैरिया भरण स्थल, पटना में डंप किया जाना था, को स्टैक करने के लिए एक एजेंसी[175] से नौ अर्थमूवर वाहन किराए पर लिया था (अक्टूबर 2020)। अक्टूबर 2020 से सितंबर 2022 के दौरान, नौ वाहनों का किराया शुल्क, राशि ₹ 10.29 करोड़ एजेंसी को भुगतान किया गया था।

[174] *दानापुर, खगौल, फुलवारीशरीफ और संपतचक नगर परिषद्*

[175] *मेसर्स हर्ष इंजीकॉन प्रा. लिमिटेड, ₹ 1,535 प्रति घंटे की दर से*



पटना के बैरिया डंपिंग स्थल पर अपशिष्टों के ढेर को स्टैक करती अर्थमूवर मशीन।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, पटना नगर निगम ने कहा कि प्रसंस्करण सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण ताजा अपशिष्ट उचित तरीके से प्रसंस्कृत नहीं हो सका, क्योंकि विभाग ने निर्णय लिया था (जून 2022) कि समेकित नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यानी सामग्री वसूली सुविधा, बायो–मिथेनेशन, कंपोस्ट प्लांट, अक्रिय अपशिष्ट के निपटान के लिए स्वास्थ्यकर भरण स्थल आदि का कार्य विभाग द्वारा ही किया जाएगा।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, पुराने अपशिष्टों के साथ–साथ ताजे नगरीय अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित कार्रवाई करना शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। इन नियमों का अनुपालन नहीं करने से न केवल पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, बल्कि ₹ 10.29 करोड़ का परिहार्य व्यय भी हुआ।

5.6.4 निष्कर्ष

अट्ठाईस चयनित शहरी स्थानीय निकायों में से 18 में अपशिष्ट प्रसंस्कृत नहीं किया गया था। सात शहरी स्थानीय निकायों में, अपशिष्ट प्रसंस्करण की मात्रा केवल 14 प्रतिशत तक थी। तीन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा, संबंधित अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपशिष्ट प्रसंस्करण की सही मात्रा ज्ञात नहीं हो सकी। अपशिष्ट प्रसंस्करण की कम मात्रा का कारण प्रसंस्करण केंद्रों की अपर्याप्त क्षमता, आवश्यक मशीनरी की अनुपलब्धता, उपलब्ध क्षमता का कम उपयोग, क्रय की गई मशीनरी का उपयोग नहीं करना आदि था।

इसके अलावा, चयनित शहरी स्थानीय निकायों में कोई स्वास्थ्यकर भरण स्थल नहीं था।

5.5.5 अनुशंसाएं:

- ***न्यूनतम मात्रा में अपशिष्ट का भरण स्थल तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए, शहरी स्थानीय निकाय, अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्रों को तेजी से कार्यशील कर सकते हैं।***
- ***राज्य सरकार पुराने खुले डंपिंग स्थलों के जैव–उपचार, जो निर्धारित अवधि में किया जाना है, नहीं किये जाने के संबंध में एवं मौजूदा डंपिंग स्थलों पर जैव खनन एवं जैव उपचार की संभावना के लिए जिम्मेदारी तय कर सकती है।***
- ***राज्य सरकार भरण स्थलों के प्रबंधन और अपशिष्ट निपटान के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन न करने के मामलों में जिम्मेदारी तय कर सकती है।***

5.7 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत क्रय

शहरी स्थानीय निकाय में प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक उपकरण और वाहनों का क्रय अपरिहार्य है। हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जेम)[176] पोर्टल के माध्यम से उपकरणों के क्रय के लिए अपनाई गई निविदा प्रक्रिया की योजना बनाने में कमी और हेरफेर के मामले पाये गये।

नगर विकास एवं आवास विभाग ने घरेलू डस्टबिन के क्रय के लिए न्यूनतम दर के संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी, लेकिन विभाग द्वारा वाहनों और उपकरणों के क्रय के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया गया था, जिसके कारण शहरी स्थानीय निकायों ने अलग–अलग दरों पर वाहन और उपकरण खरीदे थे।

5.7.1 जेम के जरिए निविदा प्रक्रिया में हेराफेरी के संकेत

नगर विकास एवं आवास विभाग ने क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति में दक्षता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री और सेवाओं के क्रय को अनिवार्य बना दिया था (जुलाई 2018)। क्रेताओं को जेम से संबंधित सभी गतिविधियों में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता थी, जिसमें रिवर्स निलामी[177] का उपयोग करके कीमतों की तर्कसंगतता सुनिश्चित करना भी शामिल था। साथ ही, भाग लेने वाले बोलीदाताओं को अन्य बोलीदाताओं के साथ अपनी बोली के विवरणों का खुलासा नहीं करना था या मूल्य हेरफेर सहित किसी भी प्रतिस्पर्धा–विरोधी व्यवहार में शामिल नहीं होना था।

नमूना जांच किए गए पाँच शहरी स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा में, निविदा प्रक्रिया में हेराफेरी के संकेत देखे गए। निविदा में भाग लेने वाले फर्मों के एक समान प्रतिनिधियों, पते, ईमेल या मोबाइल नंबरों से स्पष्ट था कि निविदाओं में हेर–फेर की गई थी, जैसा कि **तालिका 5.27** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.27
निविदा प्रक्रिया में हेराफेरी के संकेत

क्र. सं	शहरी स्थानीय निकाय (क्रय की गयी सामग्री)	फर्म की संख्या	निविदा प्रक्रिया में हेराफेरी के संकेत का आधार
1	1. सुल्तानगंज (रेफ्युज कम्पेक्टर)	तीन फर्म	सभी फर्मों में समान प्रतिनिधि थे। इसलिए, सबसे कम बोली लगाने वाला कोई भी हो, आपूर्ति आदेश वास्तव में व्यक्तियों के उसी समूह को स्वीकृत होगा।
	2. सुल्तानगंज (1100 लीटर डस्टबिन)	तीन फर्म	सभी फर्मों के पता और मोबाइल नंबर एक थे। इसलिए, सबसे कम बोली लगाने वाला कोई भी हो, आपूर्ति आदेश वास्तव में उसी फर्म को स्वीकृत होगा।
	3. सुल्तानगंज (240 लीटर डस्टबिन)	तीन फर्म	उपरोक्त (2) के समान।

[176] *जेम एक राष्ट्रीय सार्वजनिक क्रय पोर्टल है, जो राज्य सरकार के कार्यालयों और स्थानीय निकायों सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों के लिए आम उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं के क्रय के लिए एक संपूर्ण ऑनलाइन बाजार है।*

[177] *रिवर्स निलामी में, विक्रेता क्रेता से व्यवसाय करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और कीमतें आम तौर पर कम हो जाती हैं, क्योंकि विक्रेता एक–दूसरे से कम बोली लगाते हैं। जेम पोर्टल रिवर्स निलामी टूल प्रदान करता है, जिसका उपयोग क्रेता बेहतर प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त करने के लिए कर सकता है और फिर अनुबंध करने से पहले कीमतों की तर्कसंगतता के बारे में खुद को संतुष्ट कर सकते हैं।*

क्र. सं	शहरी स्थानीय निकाय (क्रय की गयी सामग्री)	फर्म की संख्या	निविदा प्रक्रिया में हेराफेरी के संकेत का आधार
2	4. बड़हिया (240 लीटर डस्टबिन)	तीन फर्म	उपरोक्त (1) के समान।
	5 बड़हिया (रेफ्युज कम्पेक्टर और रोड स्वीपिंग मशीन)	दो फर्म	समान पता और ई–मेल आईडी। इसलिए, सबसे कम बोली लगाने वाला कोई भी हो, आपूर्ति आदेश वास्तव में उसी फर्म को स्वीकृत होगा।
3	6. भागलपुर (ऑटो टिपर)	चार फर्म	सभी चार फर्म एक ही मूल कंपनी के अधिकृत डीलर थे, जो इंगित करता है कि आपूर्ति आदेश अंततः मूल कंपनी को ही जाएगा।
	7. भागलपुर (1100 लीटर डस्टबिन)	दो फर्म	समान पता। इसलिए, सबसे कम बोली लगाने वाला कोई भी हो, आपूर्ति आदेश वास्तव में उसी फर्म को स्वीकृत होगा।
4	8. पूर्णिया (ऑटो टिपर)	दो फर्म	उपरोक्त (2) के समान।
5	9. मुजफ्फरपुर (1100 लीटर डस्टबिन)	दो फर्म	उपरोक्त (2) के समान।

*(**स्रोत**: जेम से संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)*

इन दृष्टांतों ने इंगित किया कि एक ही बोलीदाता द्वारा कई कंपनियों के नाम से बोली लगाई गई थी। इससे ऐसी स्थिति पैदा हुई, जिसमें 'रिवर्स निलामी' के बावजूद, सबसे कम बोली लगाने वाला कोई भी हो, क्रेता द्वारा उचित मूल्य की जांच किए बिना ही, आपूर्ति आदेश उसी फर्म के पास चला गया। इस प्रकार, निविदा प्रक्रिया में स्पष्टतः हेरफेर किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तकनीकी रूप से अन्य योग्य फर्मों को अयोग्य घोषित करके, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इस हेराफेरी को बढ़ावा दिया गया था। योग्य बोलीदाताओं को उनकी बोली के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं करने के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि ये दस्तावेज, वास्तव में, बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न थे। इससे यह भी इंगित हुआ कि जमा किये गये दस्तावेजों की जांच ठीक से नहीं की गई थी। अतः उचित प्रयास की कमी के कारण, नौ में से पाँच मामलों में, अतिरिक्त भुगतान के रूप में, ₹ 1.22 करोड़ की न्यूनतम हानि हुई, जैसा कि **तालिका 5.28** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.28
नगरपालिका निधि की हानि

(₹ लाख में)

क्र सं	शहरी स्थानीय निकाय	सामग्री का नाम	क्रय की गयी मात्रा (सं में)	दर प्रति इकाई	भुगतान की गई राशि	क्रय की तिथि	पिछले छः माह में जेम पर न्यूनतम दर	अधिक भुगतान
1	भागलपुर	ऑटो टिपर	55	10.72	589.60	4/12/2021	9.80	50.60
2	भागलपुर	1100 लीटर डस्टबिन	280	0.40	112.00	14/8/2021	0.33	19.6
3	सुल्तानगंज	1100 लीटर डस्टबिन	100	0.58	58.10	17/3/2022	0.33	25.0
4	सुल्तानगंज	रेफ्युज कम्पेक्टर	01	59.82	59.82	23/3/2022	49.15	10.67
5	बड़हिया	240 लीटर डस्टबिन	200	0.12	24.89	4/5/2022	0.04	16.0
कुल								**121.87**

*(**स्रोत**: जेम से संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)*

नमूना जांच किये गये शेष 23 शहरी स्थानीय निकायों ने लेखापरीक्षा को संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया, अथवा जेम पोर्टल तक पहुंच प्रदान नहीं की। इसी प्रकार के हेरफेर वाली बोली 14 शहरी स्थानीय निकायों में अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई थी[178], जिसकी सूचना पूर्व में ही विभाग को दी जा चुकी थी, जो संकेत करता है कि शहरी स्थानीय निकायों में हेरफेर वाली बोली व्यापक पैमाने पर हो सकती है।

शहरी स्थानीय निकायों ने जवाब दिया कि निविदा समिति के सदस्यों द्वारा निविदाओं की जांच की गई और उन्हें अंतिम रूप दिया गया। जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि बोली दस्तावेजों की जांच करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उचित प्रयास कर सभी आवश्यक उपाय करना शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी थी। बोली दस्तावेजों के जांच में उचित सावधानी अपनाकर हेराफेरी वाले बोली के मामलों पर रोक लगाई जा सकती थी।

5.7.2 ऑटो टिपर के अधिक क्रय पर परिहार्य व्यय– ₹ 13.65 करोड़

नगर विकास एवं आवास विभाग के निदेश (जून 2018) में नागरिकों को बेहतर नागरिक सुविधाएं देने के लिए शहरी स्थानीय निकायों में प्रत्येक 10,000 की आबादी पर एक छोटा टिपर नियत किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में से नौ में, नगर विकास एवं आवास विभाग के उपरोक्त मानदंड और 2022 में शहरी स्थानीय निकाय की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर, 424 टिपरों की आवश्यकता थी। हालांकि, इन शहरी स्थानीय निकायों ने 637 टिपर क्रय किये थे अर्थात् 213 टिपर आवश्यकता से अधिक थे। आवश्यकता से अधिक इस क्रय पर ₹ 13.65 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ, जैसा कि नीचे **तालिका 5.29** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.29
अधिक क्रय किये गये ऑटो टिपर

(₹ लाख में)

क्र.सं	शहरी स्थानीय निकाय	क्रय का वर्ष	जनसंख्या (2022)	अधिकतम आवश्यकता	क्रय की गयी संख्या	अधिक क्रय	प्रति इकाई मूल्य	अधिक व्यय
1.	पटना	2018	22,54,000	226	375	149	5.46	813.54
2.	भागलपुर	2021	5,35,000	54	55	1	10.72	10.72
3.	मुजफ्फरपुर	2021	4,73,000	48	28	0	5.94	0
		2022			25	5	7.16	35.8
		2022			20	20	8.03	160.6
4.	दरभंगा	2020	3,95,000	40	50	10	7.28	72.80
5.	सहरसा	2021	2,09,000	21	10	0	9.8	0
		2022			15	4	9.93	39.72
6.	हाजीपुर	2022	1,96,000	20	39	19	9.8	186.2
7.	राजगीर	2021	55,000	6	8	2	9.99	19.98
8.	बहादुरगंज	2020	49,000	5	6	1	8.83	8.83
9.	झंझारपुर	2020	40,000	4	6	2	8.61	17.22
कुल				**424**	**637**	**213**		**1,365.41**

*(**स्रोत**: शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख और Census2011.co.in)*

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि उपरोक्त नौ शहरी स्थानीय निकायों में से आठ में (भागलपुर को छोड़कर) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत सेवाओं को आउटसोर्स किया गया था। इन शहरी स्थानीय निकायों ने न केवल अधिक ऑटो टिपरों का क्रय किया था, बल्कि उन्हें आउटसोर्सिंग एजेंसियों को किराया हेतु दे दिया था। इस सम्बन्ध में विभाग (अक्टूबर 2023 तक) ने कोई उत्तर नहीं दिया।

[178] *निरीक्षण प्रतिवेदन सं0– 28/2022–23 एवं 29/2022–23। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से बड़हिया, हवेली खड़गपुर, मोकामा, जगदीशपुर, महुआ, जोगबनी, इसलामपुर, औरंगाबाद, बगहा, जहानाबाद, नोखा, भभुआ, डेहरी और शेखपुरा में हेरफेर वाली बोली से संबंधित दृष्टांतो को इंगित किया जा चुका है।*

5.7.3 स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल वाहनों का क्रय नहीं किया जाना– ₹ 3.11 करोड़

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट हस्तक के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को क्रय करने से पूर्व स्थानीय जलवायु परिस्थितियों, क्षेत्र की स्थलाकृतियों और स्थानीय आवश्यकताओं का आकलन करना था। इसके अलावा सड़क सफाई उपकरणों का चयन, सड़क की स्थिति और शहर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सावधानी से करना था।

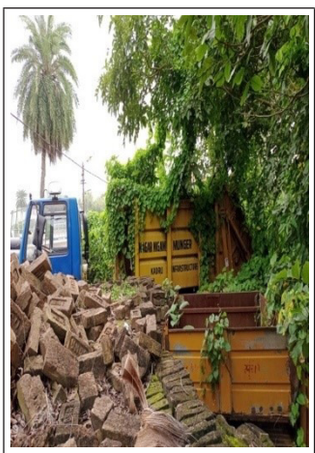
लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा किए गए चार शहरी स्थानीय निकायों ने स्थानीय परिस्थितियों पर विचार किए बिना ₹ 3.11 करोड़ (जैसा कि **तालिका 5.30** में दर्शाया गया है) की लागत से वाहनों (जैसे रिफ्यूज कम्पेक्टर, पोर्टेबल कम्पेक्टर और रोड स्वीपिंग मशीन) का क्रय किया था। नमूना जांच किये गये इन शहरी स्थानीय निकायों में इन वाहनों का उपयोग करने के लिए सड़कें पर्याप्त चौड़ी नहीं थीं। परिणामस्वरूप, क्रय के उपरांत से, ये वाहन आठ से 62 महीनों तक अनुपयोगी खड़े थे और धीरे–धीरे खराब हो रहे थे (अक्टूबर 2022), जैसा कि नीचे दिए गये फोटोग्राफ में दर्शाया गया है।

तालिका 5.30

क्रय किये गये वाहन जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थे

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय	सामग्री का नाम	क्रय का दिनांक	कब से अनुपयोगी	किया गया व्यय (₹लाख में)	अभियुक्ति
1.	मुंगेर	रोड स्वीपिंग मशीन	24/04/2020	जून 2020	62.78	
		रेफ्युज कम्पेक्टर	25/10/2017	क्रय के बाद से ही	29.25	
2.	बड़हिया	रोड स्वीपिंग मशीन	04/08/2021	क्रय के बाद से ही	37.50	
		रेफ्युज कम्पेक्टर	11/09/2021	फरवरी 2022	47.90	क्रय के बाद से फरवरी 2022 में केवल छः दिनों के लिए उपयोग किया गया
3.	जमुई	एक हुक लोडर के साथ तीन पोर्टेबल रिफ्यूज कम्पेक्टर	30/06/2017	क्रय के बाद से ही	119.17	
4.	रामनगर	रोड स्वीपिंग मशीन	12/09/2018	क्रय के बाद से ही	14.70	
कुल					**311.30**	

*(**स्रोत**: संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)*



नगर निगम मुंगेर में दिनांक 25/10/2017 से अकार्यरत पड़ा रेफ्युज कम्पेक्टर





नगर परिषद् जमुई परिसर के बाहर दिनांक 30/06/2017 से अकार्यरत खड़ा एक हुक लोडर के साथ तीन पोर्टेबल कम्पेक्टर

शहरी स्थानीय निकायों ने स्वीकार किया कि ये मशीनें उनके क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं थीं और उन पर किया गया व्यय निरर्थक था।

5.7.4 निम्न गुणवत्ता वाले ई–कार्ट का क्रय– ₹ 96.51 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों को घरों की संख्या का आकलन करने, और उसके अनुसार प्राथमिक अपशिष्ट संग्रहण के लिए ट्राइसाइकिल/कंटेनराइज्ड वाहनों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने का निर्देश (मई 2019) दिया था। हालांकि, इसमें बैटरी चालित हाइड्रोलिक कचरा ई–कार्ट के क्रय और उनकी विशिष्टियों के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, नमूना जांच किए गए चार शहरी स्थानीय निकायों ने संकीर्ण गलियों से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के प्राथमिक संग्रहण और उसके परिवहन के लिए बैटरी चालित हाइड्रोलिक कचरा ई–कार्ट का क्रय किया था, क्योंकि यह स्थानीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त था।

यह पाया गया कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा क्रय किये गए ई–कार्ट दोषपूर्ण थे, क्योंकि उनके हाइड्रोलिक सिस्टम कार्य नहीं कर रहे थे। इसलिए राशि ₹ 96.51 लाख का व्यय करने के बावजूद, ई–कार्ट के क्रय का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, जैसा कि **तालिका 5.31** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.31
निम्न गुणवत्ता वाली ई–कार्ट का क्रय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय	क्रय किए गए ई–कार्ट की संख्या	क्रय की तिथि	किया गया व्यय
1.	जमुई	15	जून 2020	38.50
2.	अमरपुर	14	मई 2022	38.82
3.	रामनगर	06	26/06/2020	19.19
4.	पटना	150	जनवरी 2022	0
कुल				**96.51**

*(**स्रोत**: संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)*

निम्न गुणवत्ता वाले क्रय के लिए जैसा कि नीचे दी गई तस्वीरों में दर्शाया गया है, क्रय की प्रक्रिया के दौरान संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उचित प्रयास की कमी और ई–कार्ट के क्रय और उसकी विशिष्टियों के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देशों की कमी को जिम्मेदार माना जा सकता है।



जमुई में अकार्यरत स्थिति में पड़े ई–कार्ट



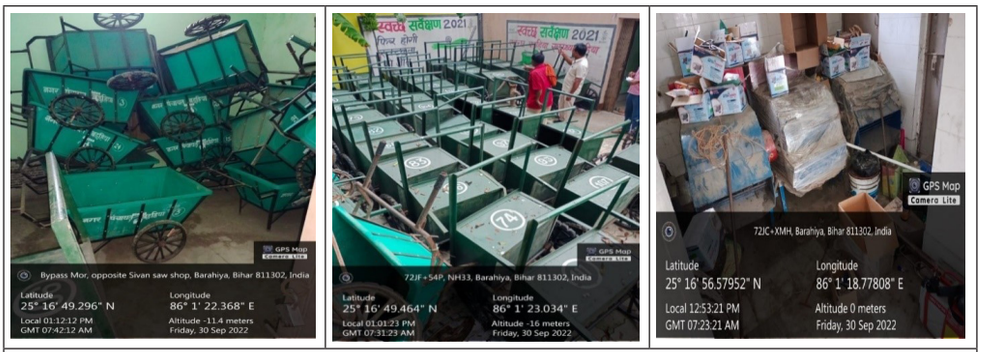
पटना में अपशिष्ट का मैनुअल प्रबंधन

5.7.5 क्रय के बाद से ही अनुपयोगी पड़ी हुई सामग्री

(i) बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम 126 (i) विहित करता है कि आवश्यकता से अधिक क्रय नहीं किया जाना चाहिए, जिससे अनुपयोगी इन्वेंट्री खर्च से बचा जा सके। इसके अलावा, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट हस्तक के अनुसार, उपकरण

या वाहनों के विशिष्टियों की आवश्यकता की गणना शहर में जनित अपशिष्ट के अनुमानों के आधार पर की जानी चाहिए।

नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में से 12 द्वारा अपने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपकरणों की आवश्यकताओं का आकलन नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, ₹ 5.24 करोड़ के उपकरण ***(परिशिष्ट 5.18)***, शहरी स्थानीय निकायों के भंडार में तीन से 60 महीनों तक अनुपयोगी पड़े हुए थे, जैसा कि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखा गया और नीचे दिए गये फोटोग्राफ में दर्शाया गया है।



क्रय के बाद से ही बड़हिया नगर पंचायत के भंडार में अनुपयोगी पड़े हाथ ठेला, ठेला एवं श्रेडिंग मशीन

शहरी स्थानीय निकायों ने जवाब दिया कि उपकरण के अधिकतम उपयोग के लिए कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, वास्तविकता यह था कि शहरी स्थानीय निकायों ने अपनी आवश्यकताओं से अधिक सामग्री खरीदे थे।

(ii) गया नगर निगम (जीएमसी) ने ₹ 39.06[179] लाख व्यय कर एक पशु शवदाह मशीन का क्रय किया (मार्च 2022)। लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2022) के दौरान पाया गया कि मशीन क्रय करने के बाद से ही भरण स्थल पर अनुपयोगी पड़ा हुआ था। मशीन का उपयोग नहीं किया जा रहा था और वह बाहर खुले क्षेत्र में पड़ा हुआ था। इसलिए, बिना किसी उपयोग के, इसका मूल्यह्रास हो रहा था, जैसा कि नीचे दिए गये फोटोग्राफ में दर्शाया गया है।



चिमनियाँ और पशु शवदाह के अन्य उपकरण खुले में अनुपयोगी पड़े हुए पाए गए, और उसके चारों ओर फैला हुआ रिसाव।

पशुओं के शवदाह के लिए खुले में रखा हुआ मोटर

[179] *मशीन की कुल अधिष्ठापन लागत ₹ 69.75 लाख थी। हालांकि, सितंबर 2022 तक केवल ₹ 39.06 लाख का भुगतान किया गया था।*

गया नगर निगम ने जवाब दिया कि बारिश के मौसम के कारण मशीन के अधिष्ठापन में विलंब हुई एवं इसका अधिष्ठापन शीघ्र ही कर लिया जाएगा। जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि मशीन मार्च 2022 में खरीदी गई थी और अक्टूबर 2022 तक बेकार पड़ी हुई थी।

5.7.6 डस्टबिन का क्रय विशिष्टि के अनुरूप नहीं किया जाना

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट हस्तक के अनुसार, महत्वपूर्ण सड़कों, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, पर्यटन स्थलों, बस पड़ाव और रेलवे स्टेशनों, बड़े वाणिज्यिक परिसरों आदि में डस्टबिन उपलब्ध कराया जाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर अपशिष्ट फैले हुए न रहें। इन डस्टबिनों से गीले और सूखे अपशिष्टों कों अलग अलग एकत्र किया जाना है। इसके अलावा, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्गत (जुलाई 2013) ठोस अपशिस्ट प्रबंधन से सम्बंधित उपकरण की तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार, 60 से 150 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक डस्टबिनों को विभिन्न सड़कों के किनारे रखा जाना था।

नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में से चार ने विशिष्टियों के अनुरूप गीले अपशिष्टों के संग्रह के लिए आवश्यक प्लास्टिक डस्टबिन का क्रय नहीं किया था, और इसके जगह पर ₹ 1.89 करोड़ **(तालिका 5.32)** मूल्य के पोल माउंट छिद्रित स्टील डस्टबिन का क्रय तीनों प्रकार के अपशिष्ट, अर्थात् सूखा, गीला और जैव–चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रह के लिए किया था।

तालिका 5.32

विशिष्टियों के अनुरूप क्रय नहीं किये गये डस्टबिन

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय	क्रय का माह	सामग्री का संख्या	प्रति इकाई मूल्य (₹ लाख में)	व्यय की गई राशि (₹ लाख में)
1.	जमुई	जून 2021	400	0.286	114.40
2.	बड़हिया	मई 2022	150	0.288	43.27
3.	मुरलीगंज	मार्च 2022	60	0.340	20.40
4.	मखदुमपुर	अक्टूबर 2020	95	0.110	10.45
कुल					**188.52**

*(**स्रोत**: संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के अभिलेख)*

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, पाया गया कि इन डस्टबिनों को उपयुक्त स्थानों पर अधिष्ठापित नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे दिए गये फोटोग्राफ में दर्शाया गया है।



जमुई में पोल माउंट छिद्रित स्टील डस्टबिन, पैदल मार्ग के बजाये झाड़ियों से घिरे स्थान पर अधिष्ठापित किए गए थे, इसलिए, यह लोगों द्वारा उपयोग के लिए सुविधाजनक नहीं था।



मुरलीगंज में सूखे, गीले और जैव–चिकित्सा कचरे के संग्रह के लिए पोल माउंट छिद्रित स्टील डस्टबिन अधिष्ठापित किए गए थे, इस प्रकार के डस्टबिन गीले अपशिष्ट और जैव–चिकित्सा अपशिष्ट के लिए उपयुक्त नहीं थे।

जमुई नगर परिषद् ने जवाब दिया कि भविष्य में विभाग द्वारा दिए गए विशिष्टियों के अनुरूप उपकरण क्रय किये जाएंगे।

5.7.7 डस्टबिन/कूड़ेदान का अधिक क्रय किया जाना ₹ 4.77 करोड़

5.7.7.1 घरों के लिए अधिक डस्टबिन क्रय किया जाना : ₹ 2.46 करोड़

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्य की नीति और रणनीति के अनुसार, डस्टबिनों का वितरण (निःशुल्क) एक बार किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि गया नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में 75,000 घर (मार्च 2022) थे। इस शहरी स्थानीय निकाय द्वारा (फरवरी 2018) एक लाख जोड़ा डस्टबिन (₹ 4.34 करोड़ की लागत से) का क्रय किया गया था और 87,500 जोड़ा डस्टबिन घरों में वितरित किया गया था। शेष डस्टबिन फरवरी 2018 से भंडार में पड़े हुए थे (अक्टूबर 2022)।

सभी घरों में जोड़ा डस्टबिन वितरित करने के बावजूद, गया नगर निगम ने ₹ 2.46 करोड़ की लागत से (मार्च 2021 से सितंबर 2021) तीन सेट वाले एक लाख डस्टबिन का क्रय किया था तथा 82,943 सेट डस्टबिनों को घरों में वितरित किया था। शेष डस्टबिन क्रय के समय (मार्च 2021 से सितंबर 2021) से ही भंडार में (अक्टूबर 2022) पड़े हुए थे।

गया नगर निगम के उप नगर आयुक्त ने जवाब दिया कि बचे हुए डस्टबिनों का वितरण किया जायेगा। हालांकि, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के राज्य की नीति और रणनीति के विपरीत ₹ 2.46 करोड़ मूल्य के तीन सेट वाले डस्टबिन का क्रय किया गया था, क्योंकि निःशुल्क डस्टबिन का वितरण केवल एक बार करना था।

5.7.7.2 अधिक क्षमता के कूड़ेदानो का क्रय किया जाना

नगर परिषद् दानापुर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में शहर के लिए कूड़ेदान की आवश्यकता का निर्धारण किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दानापुर नगर परिषद् ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में निर्धारित किये गये आवश्यक क्षमता से अधिक कूड़ेदान का क्रय किया था। इसके कारण ₹ 2.31 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ, जैसा की **तालिका 5.33** में वर्णित है।

तालिका 5.33

आवश्यकता से अधिक क्षमता के कूड़ेदान के क्रय के कारण परिहार्य व्यय

शहरी स्थानीय निकाय	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार कूड़ेदान की आवश्यक क्षमता (लीटर में)#	क्रय किये गए कूड़ेदान की वास्तविक क्षमता (लीटर में) #	क्रय की गई अधिक क्षमता (लीटर में)	अधिक क्रय पर व्यय की गई राशि (₹ लाख में)
दानापुर	23,700	7,20,000	6,96,300	230.85

(स्रोत: संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के अभिलेख)

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में क्रय किये जाने वाले प्रत्येक कूड़ेदान की क्षमता 100 लीटर थी, जबकि क्रय किये गये प्रत्येक कूड़ेदान की क्षमता 240 लीटर थी।

5.7.8 घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट तथा जैव–चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामुदायिक डस्टबिनों के क्रय पर परिहार्य व्यय ₹ 55.35 लाख

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का नियम 15 (झ), शहरी स्थानीय निकाय को घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट जमा केंद्र स्थापित करने के लिए निदेशित करता है तथा यह केंद्र बीस वर्ग किलोमीटर या उसके अंदर के क्षेत्र में स्थापित किया जाना है।

इसके अलावा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जैव–चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के साथ यह स्पष्ट करता है कि घरों में उत्पन्न होने वाले जैव–चिकित्सा अपशिष्ट को अलग किया जाना है और अलग–अलग बैग या कंटेनर में नगरपालिका अपशिष्ट संग्राहक को सौंपा जाना है। शहरी स्थानीय निकाय को सामान्य जैव–चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा प्रदाताओं के साथ समझौता करना आवश्यक है, ताकि वे अंतिम निपटान हेतु इस अपशिष्ट को सामग्री वसूली केन्द्रों या घरों से सीधे प्राप्त कर सकें।

नगर परिषद्, किशनगंज ने 330 लिटर क्षमता वाले 185 घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट डस्टबिन और 115 जैव–चिकित्सा अपशिष्ट डस्टबिन का क्रय किया, जिसके लिए ₹ 55.35 लाख का व्यय किया गया था। हालांकि, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि इन डस्टबिनों का उपयोग नगरपालिका अपशिष्ट के संग्रह के लिए किया जा रहा था, न कि घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट और जैव–चिकित्सा अपशिष्ट के लिए।

5.7.9 निर्धारित दरों से अधिक दर पर क्रय के कारण अधिक भुगतान ₹ 61.65 लाख

छपरा नगर निगम ने (सितंबर 2017) बिना निविदा के 10 लीटर क्षमता के 40,000 घरेलू डस्टबिनों के क्रय का फैसला किया, और एजेंसी मेसर्स रिलायबल इंटरप्राइजेज, पटना को ₹ 450/– प्रति पीस डस्टबिन की आपूर्ति के लिए कार्यादेश (सितंबर 2017) निर्गत किया। एजेंसी को कार्यादेश की तारीख से एक महीने के अन्दर सभी डस्टबिन की आपूर्ति करने के लिए कहा गया था, जिसमें विफल होने पर आपूर्ति आदेश रद्द करना था। इसी बीच, नगर विकास एवं आवास विभाग ने (नवंबर 2017) डस्टबिन की अधिकतम दर को संशोधित कर ₹ 225/– कर दिया। इस संशोधन की तारीख तक, एजेंसी ने शहरी स्थानीय निकाय को डस्टबिन की आपूर्ति नहीं की थी। इसलिए, नगर विकास एवं आवास विभाग के दरों के संशोधन (नवंबर 2017) तथा आपूर्ति आदेश में उल्लेखित शर्तों के आलोक में शहरी स्थानीय निकाय को आपूर्ति आदेश रद्द कर देना चाहिए था।

लेकिन शहरी स्थानीय निकाय ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए, एजेंसी ने (जनवरी 2018) 450 रुपये प्रति पीस के दर से 27,400 डस्टबिन (40,000 डस्टबिन की आपूर्ति आदेश के विरूद्ध) का आपूर्ति किया और एजेंसी को इसके लिए ₹ 1.23 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। इस प्रकार ₹ 61.65 लाख का अधिक परिहार्य भुगतान हुआ।

5.7.10 रेफ्यूज कम्पेक्टर की उपलब्धता के बिना 1100 लीटर डस्टबिन का क्रय

नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देशों (जुलाई 2013) के अनुसार, अपशिष्ट संग्रहण डस्टबिन 1100 लीटर क्षमता के और बंद प्रकार के होने चाहिए थे। इन डस्टबिनों को एसे ढक्कन के साथ होना चाहिए था, जो डस्टबिन उठाने वाले मशीन द्वारा उठाने पर स्वचालित रूप से खुल जाये। इसके लिए डस्टबिनों में विशेष लिंक की व्यवस्था करनी थी, जिससे कम्पेक्टर द्वारा डस्टबिन को उठाकर संचालित किया जा सके। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट हस्तक के अनुसार, इसे नीचे दिए गये फोटोग्राफ में दर्शाये गए तरीके से कार्यान्वित किया जाना था।



द्वितीयक संग्रहण डस्टबिन से रेफ्यूज कम्पेक्टर में अपशिष्ट का स्थानांतरण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन[180] शहरी स्थानीय निकायों ने वर्ष 2020 और 2021 के दौरान 1,100 लीटर की क्षमता वाले 523[181] सामुदायिक डस्टबिन खरीदे थे, जिसका लागत ₹ 1.97 करोड़ था। हालांकि, इनमें से किसी भी शहरी स्थानीय निकायों के पास इन सामुदायिक डस्टबिनों को उठाने के लिए रेफ्यूज कम्पेक्टर नहीं था। इन डस्टबिनों से अपशिष्टों को संग्रहित करने के लिए उनके पास कोई अन्य व्यवस्था भी नहीं थी। इस प्रकार, इन डस्टबिनों को सड़कों के किनारे व अन्य स्थानों पर लगाए जाने के बाद से अनुपयोगी पड़े रहने के कारण इनकी स्थिति धीरे–धीरे खराब हो रही थी।

संयुक्त भौतिक सत्यापन में इसकी पुष्टि भी हुई कि इन डस्टबिनों के आसपास और बाहर कूड़ा फेंका जा रहा था। कुछ डस्टबिन ऐसे स्थानों पर रखे गए थे जहां सार्वजनिक पहुंच सुगम नहीं था, जैसा कि नीचे दिए गए फोटोग्राफ में दर्शाया गया है:

रेफ्यूज कम्पेक्टर के अभाव में अनुपयोगी पड़े हुए 1,100 लीटर के डस्टबिन

	
मखदुमपुर में झाड़ियों के बीच रखा हुआ डस्टबिन	जमुई में डस्टबिन के बाहर फेंका गया अपशिष्ट

जमुई नगर परिषद् ने जवाब दिया कि नगरपालिका बोर्ड की अगली बैठक में कम्पेक्टर खरीदने पर विचार किया जायेगा, ताकि इन डस्टबिनों का उपयोग किया जा सके। रामनगर नगर परिषद् एवं मखदुमपुर नगर पंचायत ने जवाब दिया कि नगरपालिका बोर्ड के निर्णय के आलोक में कूड़ेदान का क्रय किया गया था।

जवाब मान्य नहीं थे, क्योंकि 1,100 लीटर के डस्टबिन रेफ्यूज कम्पेक्टर की उपलब्धता के बिना खरीदे गए थे।

5.7.11 निष्कर्ष

नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मशीनों/सामग्रियों के क्रय में बिहार वित्तीय नियमावली के निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। व्यय तदर्थ आधार पर किया गया था और आवश्यकता–आधारित विश्लेषण के आधार पर वास्तविक आवश्यकता के बजाय धन की उपलब्धता से प्रेरित था। लेखापरीक्षा में ₹ 13.65 करोड़ में 213 अधिक ऑटो टिपर का क्रय; वाहनों का क्रय (₹ 3.11 करोड़ में) जो स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं थे, जो आठ से 62 महीनों तक अनुपयोगी पड़े हुए थे; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सामग्रियों का क्रय (₹ 5.63 करोड़ में), जो क्रय के बाद से अनुपयोगी थे; कूड़ेदानों का अधिक क्रय (₹ 2.31 करोड़ में); उठाने वाले रेफ्यूज कम्पेक्टर की उपलब्धता के बिना 1,100 लीटर वाले डस्टबिन (₹ 1.97 करोड़ के लिए) का क्रय आदि का उदाहरण देखा गया। इसके अतिरिक्त, जेम के माध्यम से किये गये निविदा प्रक्रिया में हेराफेरी के संकेत भी मिले।

---

[180] *नगर पंचायत, मखदुमपुर, नगर परिषद्, जमुई तथा नगर परिषद्, रामनगर*

[181] *मखदुमपुर– 50 धातु और 36 एलडीपीई; जमुई– 187; और रामनगर– 250*

5.7.12 अनुशंसाएं

- ***शहरी स्थानीय निकाय बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये बोली दस्तावेजों की जांच करते समय यथोचित प्रयास कर सकते हैं और हेराफेरी वाले बोली को निरूत्साहित करने के लिए कदम उठा सकते हैं।***
- ***ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना को लागू करने के लिए नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हस्तक में बताए गए तरीके से क्रय/व्यय संबंधी निर्णय लिए जा सकते हैं। शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि क्रय किये गये मशीनों/उपकरणों का उद्देश्य के अनुसार उचित उपयोग किया जाए।***

5.8 इंटेलीजेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली

बिहार राज्य के चार शहरों यथा् पटना, भागलपुर, बिहारशरीफ और मुजफ्फरपुर को भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया था। इन चार शहरी स्थानीय निकाय में से तीन शहरी स्थानीय निकायों यथा पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर को इस निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया था। इंटेलिजेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्मार्ट सिटी परियोजना के घटकों में से एक था। स्मार्ट शहरों या अन्य नमूना शहरी स्थानीय निकायों में इंटेलीजेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति **तालिका 5.34** में दर्शायी गई है।

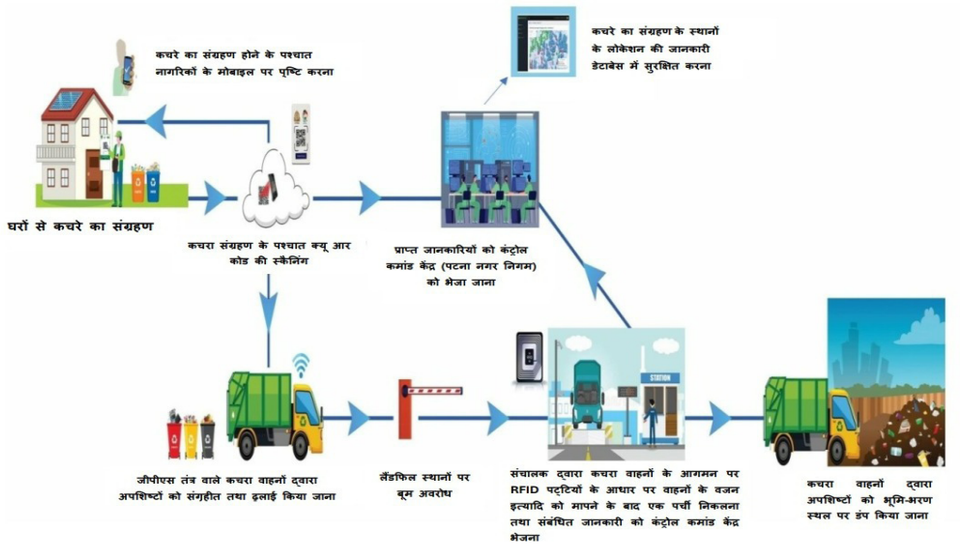
तालिका 5.34
शहरी स्थानीय निकाय में इंटेलीजेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति (जनवरी 2023 तक)

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय	क्या स्मार्ट सिटी परियोजना का हिस्सा है	शहरी स्थानीय निकाय में इंटेलिजेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति
1	पटना	स्मार्ट सिटी	इंटेलिजेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली क्रियान्वित की जा रही है।
2	भागलपुर	स्मार्ट सिटी	इंटेलिजेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अभी लागू नहीं हुआ है।
3	मुजफ्फरपुर	स्मार्ट सिटी	इंटेलिजेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू नहीं किया गया है।
4	गया	स्मार्ट सिटी परियोजना का हिस्सा नहीं	स्मार्ट सिटी परियोजना का हिस्सा नहीं है। हालांकि, इंटेलिजेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली क्रियान्वित की जा रही है।

(स्रोतः नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकाय के अभिलेख)

जैसा कि **तालिका 5.34** से स्पष्ट है, इंटेलिजेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली बिहार के केवल दो शहरी स्थानीय निकायों (पटना और गया) में क्रियान्वित की जा रही है। इंटेलिजेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली से आशय है कि यह शहरी स्थानीय निकायों के नगरीय ठोस अपशिष्ट संचालन की विभिन्न गतिविधियों को सूचना तकनीक हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ट्रैक और मॉनिटर करने में मदद करेगा। इसके कार्यक्षेत्र में नगरपालिका क्षेत्रों में घरों पर क्यूआर कोड की स्थापना; अपशिष्ट संग्रहणकर्ताओं को हस्त मोबाइल उपकरण उपलब्ध कराना; घरों का जियो–टैगिंग; वाहन ट्रैकिंग सिस्टम की स्थापना और कमीशनिंग; नगरपालिका ठोस अपशिष्ट संचालन के दौरान मोबाइल ऐप्स के माध्यम से पर्यवेक्षकों/जोनल अधिकारियों/नगर आयुक्तों को सूचित करने की क्षमताओं वाले मंच/प्रणालियाँ प्रदान करना, शिकायत निवारण प्रणाली आदि प्रदान करना शामिल है, लेकिन इसका कार्य क्षेत्र यहीं तक सीमित नहीं है।

इंटेलिजेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का स्नैपशॉट



*(**स्रोत**: पटना नगर निगम और गया नगर निगम के अभिलेख)*

इंटेलिजेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन में पायी गयी अनियमितताओं की चर्चा आगे की कंडिकाओं में की गई है।

5.8.1 उच्च अधिकारियों से मंजूरी प्राप्त करने से बचने के लिए इंटेलिजेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली कार्य का विभाजन

बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम 206 विहित करता है कि उच्च प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए, किसी भी कार्य को विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। विभाग ने निविदाओं के निपटान के लिए विभिन्न प्राधिकार को मंजूरी देने की शक्तियां प्रदान की थी (जुलाई 2015), जैसा कि **तालिका 5.35** में दिया गया है।

तालिका 5.35

निविदाओं के निपटान हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन

क्र. सं.	स्वीकृतिदाता प्राधिकारी	तकनीकी स्वीकृति की शक्ति	निविदा निपटान की शक्ति
1	सहायक अभियंता	₹ 10 लाख तक	शून्य
2	कार्यपालक अभियंता	₹ 10 लाख से ₹ 50 लाख	₹ 25 लाख तक
3	अधीक्षण अभियंता	₹ 50 लाख से ₹ 02 करोड़	₹ 25 लाख से ₹ 02 करोड़
4	मुख्य अभियंता	₹ 02 करोड़ और उससे ऊपर	₹ 02 करोड़ से ₹ 3.5 करोड़
5	विभागीय निविदा समिति	शून्य	₹ 3.5 करोड़ से ऊपर

*(**स्रोत**: नगर विकास एवं आवास विभाग के अभिलेख)*

गया नगर निगम के लेखापरीक्षा मे पाया गया कि इंटेलिजेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली कार्य की कुल परियोजना लागत ₹ 7.58 करोड़ थी, जिसे चार भागों में विभाजित किया गया था जैसा कि **तालिका 5.36** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.36
इंटेलिजेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली कार्य का विवरण

पैकेज संख्या	मद	एकरारनामा की राशि (₹ करोड़ में)
1	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉनिटरिंग एप्लिकेशन का विकास	1.90
2	डोर–टू–डोर कूड़ा उठाव, कूड़ा अनुश्रवण, क्यूआर कोड सिस्टम	1.88
3	वाहन ट्रैकिंग और प्रबंधन समाधान	1.90
4	कमांड और कंट्रोल इंफ्रा हार्डवेयर और म्यूनिसिपल मॉनिटरिंग	1.90
	कुल	**7.58**

*(**स्रोत**: गया नगर निगम के अभिलेख)*

इसलिए, नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश (जुलाई 2015) के आलोक में, कार्य के लिए निविदा को विभागीय निविदा समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाना था। हालांकि, कार्य को चार भागों में विभाजित किए जाने के कारण कार्य के लिए निविदा को विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने के बजाय अधीक्षण अभियंता[182] द्वारा अंतिम रूप दिया गया था। इस प्रकार, उच्च प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण से बचा गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कार्य के विभाजन के बावजूद, केवल दो बोलीदाताओं ने भाग लिया और कार्य के सभी चार घटकों को एक ही एजेंसी[183] को दे दिया गया। इस प्रकार, निविदा प्रक्रिया में बड़ी फर्मों का वृहत स्तर पर भागीदारी और स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नहीं किया गया था।

गया नगर निगम ने जवाब दिया (अक्टूबर 2022) कि कार्य का विभाजन निधि की उपलब्धता पर आधारित था, क्योंकि कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि सभी एकरारनामा एक ही तारीख और एक ही एजेंसी के साथ निष्पादित किया गया था। इसके अलावा, सभी कार्य एक साथ प्रारंभ किये गये थे और भुगतान भी एक ही तिथि पर किये गये थे।

5.8.2 सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट और एमआईएस प्रतिवेदन की अनुपलब्धता

सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट, सिस्टम की आवश्यकताओं, ऑपरेटिंग वातावरण, सिस्टम और उप–सिस्टम आर्किटेक्चर, फाइलों और डेटाबेस डिजाइन, इनपुट प्रारूपों, आउटपुट लेआउट, मानव–मशीन इंटरफेस, विस्तृत डिजाइन, प्रसंस्करण तर्क और बाहरी इंटरफेस का वर्णन करता है। मेसर्स टेकिंफी द्वारा सितंबर 2020 में पटना नगर निगम के साथ और अक्टूबर 2021 में गया नगर निगम के साथ एक एकरारनामा किया गया था।

सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट को एजेंसी (मेसर्स टेकिंफी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा नगर निगम को एक सूचनात्मक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करना था, ताकि यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सके कि शहरी स्थानीय निकायों ने परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक सभी आँकड़ा प्राप्त कर लिया है।

दो नगर निगमों[184] में इंटेलिजेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन और पाँच साल के संचालन और रखरखाव के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेखों के जांच से ज्ञात हुआ कि सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट नगर निगम के पास उपलब्ध नहीं थे।

सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट के अभाव में, नगर निगम इस महत्वपूर्ण परियोजना के संचालन के लिए पूरी तरह से निजी सॉफ्टवेयर डेवलपर (यानी मेसर्स टेकिंफी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड) पर निर्भर था।

---

[182] *बुडको, गया प्रमंडल*

[183] *मेसर्स टेकिंफी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड*

[184] *पटना और गया*

यह भी पाया गया कि, प्रस्ताव अनुरोध के अनुसार, अनुश्रवण संबंधी उद्देश्यों के लिए नगर निगम की आवश्यकताओं के अनुसार, किसी भी अवधि के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं हेतु ट्रिपों की संख्या के संबंध में तारीख–वार, वाहन–वार एमआईएस प्रतिवेदन तैयार की जानी थी। हालांकि, प्रसंस्करण स्थलों पर वाहनों के ट्रिप के सत्यापन के लिए एमआईएस के माध्यम से ऐसी प्रतिवेदन तैयार नहीं की गई थीं।

गया नगर निगम ने जवाब दिया (अक्टूबर 2022) कि सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट एजेंसी से प्राप्त कर लिया जाएगा। पटना नगर निगम ने स्वीकार किया (फरवरी 2023) कि सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट इसके पास उपलब्ध नहीं था।

5.8.3 नगर निगमों की सभी संपत्तियों पर क्यूआर कोड की स्थापना नहीं करना

नगर निगमों और एजेंसी (मेसर्स टेकिंफी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड) के बीच हस्ताक्षरित एकरारनामों[185] के अनुसार, नगर निगमों की सभी संपत्तियों पर क्यूआर कोड, एकरारनामा की तारीखों से 20 सप्ताह के भीतर स्थापित किए जाने थे, ताकि एजेंसी द्वारा अपशिष्टो के डोर–टू–डोर 'संग्रहण अनुश्रवण प्रणाली' को प्रभावी बनाया जा सके। एजेंसी द्वारा निष्पादित कार्य का एक सार, **तालिका 5.37** में दिया गया है।

तालिका 5.37

क्यूआर कोड स्थापना का विवरण (जनवरी 2023 तक)

क्र. सं.	नगर निगम	स्थापित किए जाने वाले क्यूआर कोड की संख्या	स्थापित क्यूआर कोड की संख्या (प्रतिशत)	स्थापित नहीं किये गये क्यूआर कोड (प्रतिशत)	विलंब (माह में)	22/09/2020 से 31/10/2022 के दौरान प्रत्येक दिन स्कैन किए गए क्यूआर कोड (संपत्तियों पर) की संख्या
1	पटना	3,40,000	1,75,347 (52)	1,64,653 (48)	20	39 से 1,17,009
2	गया	75,000	69,931 (93)	5,069 (07)	11	561 से 46,342
कुल		**4,15,000**	**2,45,278 (59)**	**1,69,722 (41)**	..	..

*(**स्रोत**: नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)*

लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य पूर्ण होने के निर्धारित समयावधि से 11 से 20 माह बीत जाने के बावजूद, कुल संपत्तियों में से 41 प्रतिशत संपत्तियों में क्यूआर कोड नहीं लगाये गये थे। क्यूआर कोड नहीं लगाये जाने के कारण डोर–टू–डोर अपशिष्टों के संग्रहण का पूर्ण अनुश्रवण नहीं हो सका। एकरारनामा में दंड का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण क्यूआर कोड नहीं लगाने के लिए एजेंसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

इसके अलावा, 59 प्रतिशत संपत्तियों में क्यूआर कोड की स्थापना के बाद, सभी संपत्तियों का स्कैन अनुश्रवण हेतु नहीं किया जा रहा था। दिनांक 22/09/2020 से 31/10/2022 के दौरान, अपशिष्ट संग्राहकों द्वारा प्रतिदिन केवल 39 से 1,17,009 संपत्तियों को स्कैन किया गया था। यह इंगित करता है कि अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं द्वारा क्यूआर कोड की स्कैनिंग पूरी तरह से नहीं की जा रही थी और क्यूआर कोड की स्कैनिंग के माध्यम से अपशिष्टों के डोर–टू–डोर संग्रहण का अनुश्रवण केवल आंशिक रूप से किया जा रहा था।

गया नगर निगम ने जवाब दिया (अक्टूबर 2022) कि क्यूआर कोड अब 74,554 संपत्तियों में स्थापित किए जा चुके हैं। पटना नगर निगम ने कहा (फरवरी 2023) कि, नागरिक/वाणिज्यिक परिसरों के कड़े विरोध और इंकार के कारण, कई स्थानों पर, क्यूआर कोड स्थापित नहीं किए जा सके।

---

185 *पटना (सितंबर 2020) और गया (20 अक्टूबर 2021)*

5.8.4 क्यूआर कोड की स्कैनिंग के लिए हस्त मोबाइल उपकरणों का कम वितरण और ₹ 56.62 लाख का अधिक भुगतान

नगर निगमों और एजेंसी के बीच हस्ताक्षरित एकरारनामा[186] के अनुसार, एजेंसी द्वारा 20 सप्ताह के अंदर, क्यूआर कोड की स्कैनिंग के लिए नगर निगम को हस्त मोबाइल उपकरणों की आपूर्ति की जानी थी, ताकि अपशिष्टों का डोर–टू–डोर संग्रहण के लिए एक प्रभावी अनुश्रवण प्रणाली सुनिश्चित की जा सके।

(i) पटना नगर निगम में, एजेंसी द्वारा प्रदान किए जाने वाले 1,200 मोबाइल उपकरणों के स्थान पर, केवल 704 मोबाइल उपकरण प्रदान किए गए थे (नवंबर 2022), लेकिन एजेंसी को 1,200 मोबाइल के लिए कुल भुगतान किया गया था।

(ii) आपूर्ति की गई इन सामग्रियों (हस्त मोबाइल उपकरण और अन्य वस्तुओं) का अधिकतम खुदरा मूल्य, एकरारनामे में निर्दिष्ट दर से कम था। इसलिए, भुगतान अधिकतम खुदरा मूल्य तक ही सीमित होना चाहिए था। हालांकि, नगर निगम ने सत्यापन के बिना एकरारनामा की दरों पर भुगतान किया था। इससे ₹ 56.62 लाख का अधिक भुगतान हुआ, जैसा कि **तालिका 5.38** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.38
अधिक भुगतान

नगर निगम	सामग्री	संख्या	एकरारनामा के अनुसार प्रति इकाई दर (₹)	एकरारनामा दर के अनुसार, एजेंसी को कुल भुगतान (₹ लाख में)	आपूर्ति की गई सामग्री का अधिकतम खुदरा मूल्य (₹)	एजेंसी को भुगतान की जानेवाली राशि (₹ लाख में)	अधिक भुगतान (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8 (8 = 5–7)
पटना	मोबाइल उपकरण	1,200	11,551.30	138.62	9,999	120.00	18.62
गया	मोबाइल उपकरण	200	23,741.77	47.48	10,499	21.00	26.48
	वीडियो वॉल (55 इंच)	8	2,30,508.75	18.44	1,65,000	13.20	5.24
	कंप्यूटर, यूपीएस (कार्यस्थल)	4	2,01,696.50	8.07	68,798	2.75	5.32
	ऑल–इन–वन प्रिंटर	1	1,38,297.00	1.38	42,429	0.42	0.96
कुल							**56.62**

*(**स्रोत**: नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)*

सत्यापन के बिना, एजेंसी को अधिक भुगतान, एजेंसी को अनुचित लाभ पहुचांने का संकेत था।

गया नगर निगम ने जवाब दिया (अक्टूबर 2022) कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी। पटना नगर निगम ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि मोबाइल वितरित किए जाएंगे, लेकिन अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दरों पर क्रय किये गये मोबाइल के संबंध में टिप्पणी का जवाब नहीं दिया।

[186] *पटना (सितंबर 2020) और गया (20 अक्टूबर 2021)*

5.8.5 क्लाउड सर्वर पर परिहार्य व्यय ₹1.25 करोड़

क्लाउड सर्वर (पटना नगर निगम और गया नगर निगम के लिए) पर डाटा को रखने/भंडारण के लिए नगर निगमों और एजेंसी के बीच एक एकरारनामा निष्पादित[187] किया गया था, जैसा कि **तालिका 5.39** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.39
क्लाउड सर्वर की आवश्यकता

शहरी स्थानीय निकाय	सामग्री	कुल एकरारनामा की राशि (₹ लाख में)
पटना	1 साल के लिए क्लाउड सर्वर	9.35
गया	5 वर्षों के लिए क्लाउड सर्वर	115.81
कुल		**125.16**

*(**स्रोत**: नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकाय के अभिलेख)*

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के इलेक्ट्रॉनिक डाटा के भंडारण के लिए, राज्य डाटा केन्द्र निःशुल्क उपलब्ध था। सरकार द्वारा डाटा भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के बावजूद, नगर निगमों द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया गया था। इसके बजाय, नगर निगम ने बिना किसी समुचित कारण के तीसरे पक्ष के क्लाउड सर्वर पर डाटा भंडारण करने का फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.25 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

5.8.6 नेटवर्क कनेक्टिविटी पर परिहार्य व्यय ₹ 23.16 लाख

बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना राज्य मुख्यालय को सभी जिला मुख्यालयों और सभी प्रखंड मुख्यालयों के साथ जोड़ने के लिए की गई थी, जिसका उद्देश्य सरकार से सरकार और सरकार से नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने हेतु एक सुरक्षित सरकारी नेटवर्क बनाना था।

गया नगर निगम और पटना नगर निगम के अभिलेखों के लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2010 से पूरे राज्य में निःशुल्क नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की उपलब्धता के बावजूद, नगर निगमों ने निजी विक्रेताओं के माध्यम से अलग निजी नेटवर्क कनेक्टिविटी खरीदा था और ₹ 23.16 लाख[188] का भुगतान किया था। इससे संकेत मिलता है कि नगर निगम उपलब्ध नेटवर्क संसाधनों का उपयोग नहीं कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप निजी विक्रेताओं को परिहार्य भुगतान किया जा रहा था।

गया नगर निगम ने जवाब दिया (अक्टूबर 2022) कि बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी की निःशुल्क उपलब्धता के सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी।

5.8.7 निष्कर्ष

नगर निगम की सभी संपत्तियों पर क्यूआर कोड अधिष्ठापित नहीं किया गया था। साथ ही, अपशिष्ट संग्रहणकर्ताओं द्वारा अधिष्ठापित क्यूआर कोड का स्कैन, अपशिष्टों का डोर–टू–डोर संग्रहण के अनुश्रवण के लिए नहीं किया जा रहा था।

हस्त मोबाइल उपकरण का क्रय अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दरों पर किया गया था। बिना सत्यापन के एजेंसी को अधिक भुगतान एजेंसी को अनुचित लाभ पहुंचाने का संकेत था।

इसके अलावा, डाटा के भंडारण की निःशुल्क सरकारी सुविधा होने के बावजूद, नगर निगम ने बिना किसी समुचित कारण के, भुगतान के आधार पर, तीसरे पक्ष के क्लाउड सर्वर पर

[187] *पटना (सितंबर 2020) और गया (20 अक्टूबर 2021)*

[188] *गया ₹13,81,781 और पटना ₹ 9,34,560/–*

डाटा भंडारण करने का फैसला किया। इस प्रकार, इंटेलिजेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की दिशा में नगर निगम द्वारा किए गए प्रयास पूरी तरह से प्रभावी नहीं थे।

5.8.8. अनुशंसाएं

- ***शहरी स्थानीय निकाय की सभी संपत्तियों पर क्यूआर कोड का अधिष्ठापन, शहरी स्थानीय निकाय सुनिश्चित कर सकते हैं और अपशिष्टो के डोर–टू–डोर संग्रहण का पूर्ण अनुश्रवण कर सकते हैं।***
- ***शहरी स्थानीय निकाय डाटा के भंडारण और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए उपलब्ध मुफ्त सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और उनके लिए व्यय करने से बच सकते हैं।***

5.9 विशेष अपशिष्ट और अन्य अपशिष्टों का प्रबंधन

नगरीय ठोस अपशिष्ट हस्तक, 2016 के अनुच्छेद 7.1 के अनुसार, विशेष अपशिष्ट में अन्य के साथ–साथ इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई–अपशिष्ट), जैव–चिकित्सा अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट आदि शामिल हैं। इन अपशिष्टों के लिए विशेष प्रबंधन और निपटान प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी प्रकृति और संरचना अन्य नगरपालिका अपशिष्टों से भिन्न होती है।

उपर्युक्त हस्तक के अनुसार, विशेष अपशिष्ट को नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित नहीं होना चाहिए। आगे, हस्तक के अनुसार, ये अपशिष्ट घरेलू और वाणिज्यिक स्तरों पर भी उत्पन्न होते हैं और स्रोत पर पृथक्करण के आभाव के कारण वे अक्सर मिश्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट में मिल जाते हैं।

इसके अलावा, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का भी उचित प्रबंधन करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के अपशिष्ट प्रायः नगरपालिका के डस्टबिन में मिल जाते हैं, जिससे नगरपालिका अपशिष्ट भारी हो जाता है और उपचार हेतु इनकी गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है।

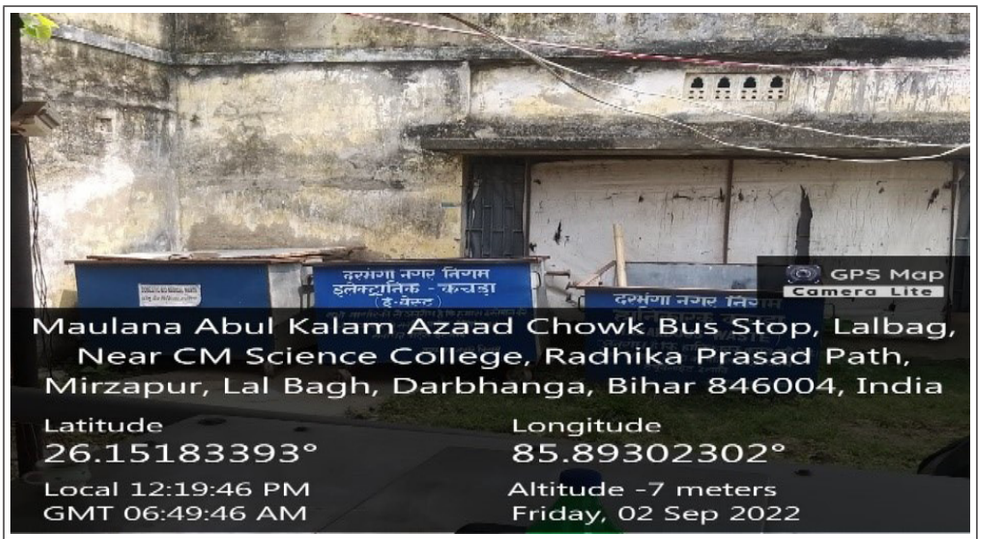
5.9.1 ई–अपशिष्ट प्रबंधन

ई–अपशिष्ट का अर्थ है बिजली या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वाला कोई भी अपशिष्ट, जो पूर्ण या आंशिक रूप से, या उनके निर्माण और मरम्मत प्रक्रियाओं के दौरान छोड़ दिये गये अपशिष्ट से है। 'ई–अपशिष्ट' के उदाहरणों में कंप्यूटर, टाइपराइटर, टेलीफोन, टेलीविजन, पारा लैंप आदि शामिल है।

माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देश के आलोक में, नगर विकास एवं आवास विभाग ने (फरवरी 2021) सभी शहरी स्थानीय निकायों को घरों से जनित ई–अपशिष्ट के उचित निपटान के लिए 'ई–अपशिष्ट निक्षेपण केंद्र' स्थापित करने का निर्देश दिया। नगर विकास एवं आवास विभाग के इस निर्देश के अनुसार, सभी शहरी स्थानीय निकायों को अपने परिक्षेत्रों में बड़े डस्टबिन रखने थे, जिसमे ई–अपशिष्ट के उत्पादकों को, ई–अपशिष्ट को जमा करना था।

शहरी स्थानीय निकायों ने ई–अपशिष्ट के उत्पादन और संग्रहण से संबंधित आँकड़े प्रस्तुत नहीं किए। ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय को नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित ई–अपशिष्ट को अधिकृत ई–अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ताओं तक पहुंचाना चाहिए।

हालांकि, दरभंगा नगर निगम ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देश के अनुपालन में (मार्च 2021) एक ई–अपशिष्ट निक्षेपण केंद्र स्थापित किया था और नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को इस अनुपालन की सूचना दी थी। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस तरह के अपशिष्ट के संग्रहण के लिए केवल एक डस्टबिन रखा गया था, और इसे ई–अपशिष्ट निक्षेपण केंद्र के रूप में नामित किया गया था। इसके अतिरिक्त, संयुक्त भौतिक सत्यापन (अगस्त–सितंबर 2022) के दौरान यह ई–अपशिष्ट वाला डस्टबिन भी खाली पाया गया।



दरभंगा नगर निगम के प्रसंस्करण स्थल पर घरेलू जैव–चिकित्सा अपशिष्ट, ई–अपशिष्ट और परीसंकटमय अपशिष्ट के लिए रखे गए कूड़ेदान, जो खाली थे को दर्शाने वाला छायाचित्र।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गए शहरी स्थानीय निकायों ने ई–अपशिष्ट को एकत्रित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। अपशिष्ट का पृथक्करण भी प्रचलन में नहीं था।

5.9.2 घरेलू जैव–चिकित्सा अपशिष्ट

नगर विकास एवं आवास विभाग ने (अगस्त 2021) शहरी स्थानीय निकायों को घरेलू जैव–चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण और निपटान के लिए निर्दिष्ट जैव–चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एजेंसियों[189] के साथ गठजोड़ करने का निर्देश दिया था। प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को, शहरी स्थानीय निकायों के जिलों के अनुसार, तीन में से एक एजेंसी के साथ जुड़ना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 22 चयनित शहरी स्थानीय निकायों ने घरेलू जैव–चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण और निपटान के लिए जैव–चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एजेंसी के साथ कोई एकरारनामा नहीं किया था, जबकि शेष छः[190] शहरी स्थानीय निकायों ने जैव–चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एजेंसियों के साथ जैव–चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण और निपटान के लिए एकरारनामा (अगस्त 2021– फरवरी 2022) किया था। हालांकि, अपशिष्टों के संग्रहण और निपटान का वास्तविक कार्य प्रारंभ होना शेष था (सितंबर 2022–नवंबर 2022 तक)।

इस प्रकार, नमूना जांच किये गए सभी शहरी स्थानीय निकायों में घरेलू जैव–चिकित्सा अपशिष्ट के महत्वपूर्ण घटक के प्रबंधन के लिए कोई उचित तंत्र उपलब्ध नहीं था।

इन परिस्थितियों में नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ जैव–चिकित्सीय अपशिष्ट के मिश्रण से इंकार नहीं किया जा सकता था। इसकी पुष्टि शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों और संयुक्त भौतिक सत्यापन से भी हुई, लेखापरीक्षा के दौरान आठ शहरी स्थानीय निकायों[191] में सड़क के किनारे चिकित्सीय अपशिष्ट अन्य अपशिष्टों के साथ मिले हुए पाये गये, साथ ही साथ डंपिंग स्थलों आदि पर उपयोग किये हुए सिरिंजों और सुइयों को भी पाया गया।

---

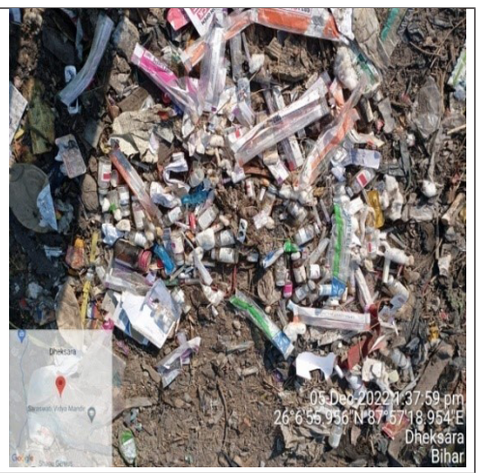
[189] *मेडिकेयर एनवायर्नमेंटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मुजफ्फरपुर या सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, भागलपुर या सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, गया या संगम मेडिसर्व प्राइवेट लिमिटेड, पटना, जैसा कि उनके संबंधित जिलों के अनुसार शहरी नगर निकाय के लिए निर्दिष्ट है।*

[190] *दलसिंहसराय, दानापुर, महाराजगंज, मुरलीगंज, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर*

[191] *दरभंगा, दलसिंहसराय, सहरसा, मुरलीगंज, दानापुर, किशनगंज, गोपालगंज, बेलसंड*



दरभंगा में एक क्लिनिक से अपशिष्ट, पीले डस्टबिन में, सड़क के किनारे डंप किया जा रहा था।



किशनगंज में डंपिंग स्थल पर नगर निगम के ठोस अपशिष्ट के साथ मिला हुआ चिकित्सीय अपशिष्ट।

5.9.3 प्लास्टिक अपशिष्ट

नगरीय ठोस अपशिष्ट हस्तक (अध्याय 7) के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र अंतर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में, पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ताओं के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, सड़क निर्माण के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग को प्रोत्साहित करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, प्रत्येक स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए या तो स्वयं या एजेंसियों के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार है। हस्तक में उल्लेखित है कि प्लास्टिक अपशिष्ट शहरी जल निकास प्रणाली को अवरुद्ध कर देता है, जो कई बार शहरी क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बन जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्टों की सही मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के पास प्लास्टिक अपशिष्टों को तौलने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

चयनित 20 शहरी स्थानीय निकायों[192] ने 2021-22 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजे अपने प्रतिवेदन में बताया था कि 30,185 टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था, जिसमें से 26,095 टन (86 प्रतिशत) का संग्रहण किया गया था, जिसमें से 1,470 टन (छः प्रतिशत) अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया गया था और 24,576 टन (94 प्रतिशत) अपशिष्ट को भूमि भरण स्थलों पर भेजा गया था, जैसा कि **तालिका 5.40** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.40

बिहार के चयनित 20 शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न, संग्रहण और निपटान किये गये प्लास्टिक अपशिष्ट

विवरण	2021–22
वर्ष के दौरान उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन)	30,185
वर्ष के दौरान संग्रहण किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन)	26,095
वर्ष के दौरान पुनर्चक्रण के लिए भेजे गये प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन)	1,470
वर्ष के दौरान भरण स्थलों पर भेजे गए निष्क्रिय या छोड़े गये प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन)	24,576

*(**स्रोत**: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजे गये प्रतिवेदन)*

इस प्रकार, केवल छः प्रतिशत (संग्रहित 26,095 टन में से 1,470 टन) प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनर्चक्रण हेतु भेजने को प्रतिवेदित किया गया था।

[192] *पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा, सहरसा, दानापुर, हाजीपुर, किशनगंज, गोपालगंज, सुल्तानगंज, रामनगर, राजगीर, दलसिंहसराय, झंझारपुर, अमरपुर, महाराजगंज, बेलसंड, जगदीशपुर और मुंगेर।*

हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा चयनित 28 शहरी स्थानीय निकायों में कही भी प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण हेतु भेजने का साक्ष्य नहीं पाया गया।

	
दरभंगा में सड़क के किनारे मिश्रित अपशिष्ट (पांडासराय रेलवे क्रॉसिंग से हाजमा चौक) और उसके आसपास जानवर	दलसिंहसराय में सड़क के किनारे बहता हुआ नाली (महाबीर चौक से बलान नदी पुल रोड)

लेखापरीक्षा द्वारा सड़कों और बाजार क्षेत्रों की सफाई के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान अनेक मामलों में सड़क के किनारे मिश्रित अपशिष्ट के साथ प्लास्टिक अपशिष्ट फैले हुए पाये गये।

5.9.3.1 पटना नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के कतरन के लिए ₹ 5.12 करोड़ का उपयोग नहीं किया जाना

ग्रामीण कार्य विभाग ने प्लास्टिक अपशिष्ट के कतरन के आपूति हेतु, श्रेडिंग इकाई की स्थापना के लिए पटना नगर निगम को ₹ 10.25 करोड़ स्वीकृत (अप्रैल 2018) किया था, जिसमे से ₹ 5.12 करोड़ आवंटित (जून 2018) किया था, जिसका उपयोग ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाये जाने वाले सड़कों में किया जाना था।

कार्य की अनुमानित लागत ₹ 12 करोड़ थी। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा इस कार्य के लिए ₹ 10.25 करोड़ स्वीकृत किया गया (अप्रैल 2018) था। शेष राशि पटना नगर निगम को अपने राजस्व से देना था।

पटना नगर निगम ने शहर में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए एक निविदा आमंत्रित (फरवरी 2019) किया और सबसे कम बोली लगाने वाले को कार्यादेश (जून 2019) दिया। हालांकि, नगर विकास एवं आवास विभाग ने बाद में (मई 2021) निविदा को रद्द करने का फैसला किया, क्योंकि पटना नगर निगम की निविदा समिति मात्र दो करोड़ रुपये तक के कार्य की निविदाओं की स्वीकृति देने के लिए सक्षम थी, जबकि इस कार्य का संविदा मूल्य ₹ 12 करोड़ था। विभागीय निर्देश के आलोक में, पटना नगर निगम ने निविदा रद्द कर दी (जून 2021)। राशि पटना नगर निगम के बैंक खाते में (अगस्त 2022 तक) पड़ी हुई थी।

5.9.4 निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट

(i) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016 के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के उत्पादन पर नज़र रखने, संग्रहित अपशिष्ट को प्रसंस्करण और निपटान हेतु उपयुक्त स्थलों पर ले जाने और साथ ही निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट से बनी सामग्री का उपयोग निर्माण गतिविधियों में, जिसमें गैर–संरचनात्मक कंक्रीट, फ़र्श ब्लॉक, साथ ही सड़क फुटपाथों, कॉलोनियों और ग्रामीण सड़कों की निचली परतों के रूप में करने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रावधान करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित शहरी स्थानीय निकायों में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का वजन करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। अतः, शहरी स्थानीय निकायों ने अपने अधिकार क्षेत्र में किस प्रकार निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट उत्पादन और संग्रहण की मात्रा को ज्ञात किया था, वह स्पष्ट नहीं था।

हालांकि, चयनित आठ शहरी स्थानीय निकायों[193] ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 44,486.20 टन निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के उत्पादन को प्रतिवेदित किया था। उन्होंने इस अवधि (वित्तीय वर्ष 2021–22) के दौरान 36,573 टन (82 प्रतिशत) अपशिष्ट के संग्रहण को भी प्रतिवेदित किया था। शहरी स्थानीय निकायों ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत अपने वार्षिक प्रतिवेदन में इसका उपयोग मरम्मत और सड़क भराई में किया जाना प्रतिवेदित किया था। हालांकि, स्थानों और उपयोग की गई मात्रा का विवरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाया गया।

(ii) दरभंगा नगर निगम का एक निर्माण और विध्वंस स्थल वैदेही नगर, दरभंगा में था। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान वैदेही नगर के निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट स्थल पर कोई निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नहीं पाया गया। इसके बजाय, मिश्रित अपशिष्ट को इस स्थल पर डंप किया हुआ पाया गया।



वैदेही नगर, दरभंगा में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट स्थल पर मिश्रित अपशिष्ट

इस प्रकार, स्थल का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था जिसके लिए इसकी स्थापना हुई थी।

5.9.5 निष्कर्ष

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों ने ई–अपशिष्टों और घरेलू जैव–चिकित्सा अपशिष्टों, जो नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित पाए गए, के संग्रहण और निपटान को सुनिश्चित नहीं किया था। प्लास्टिक अपशिष्टों को पुनर्चक्रण हेतु भेजने के प्रथाओं के अभाव में, ऐसे अपशिष्टों को भरण स्थलों पर डंप किया गया था।

5.9.6 अनुशंसाएं

- ***राज्य सरकार जैव–चिकित्सा अपशिष्ट को स्रोत पर अन्य नगरीय अपशिष्ट से पृथक नहीं करने और संग्रहण और भंडारण स्थलों पर अपशिष्ट के अनुचित प्रबंधन के संबंध में जिम्मेवारी तय कर सकती है।***

[193] *पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, दानापुर, सुल्तानगंज, बेलसंड*

- ***शहरी स्थानीय निकाय ई–अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित कर सकते हैं ताकि वे नगरीय अपशिष्ट के साथ मिश्रित न हों और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को टाला जा सके।***
- ***शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की दिशा में प्रयास कर सकते हैं।***
- ***शहरी स्थानीय निकाय निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के स्रोतों, जहां से उनका संग्रह किया गया था तथा उसकी मात्रा और उसके निपटान के स्थान तथा उसकी मात्रा के संबंध में अभिलेख संधारित कर सकते हैं।***

5.10 अनुश्रवण और मूल्यांकन

एक सतत् और कुशल नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को संस्थागत बनाना आवश्यक है। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उचित कार्यान्वयन हेतु एक व्यापक और मजबूत अनुश्रवण और मूल्यांकन प्रणाली स्थापित किया जाना आवश्यक है। शहरी स्थानीय निकायों और नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रभावी अनुश्रवण और मूल्यांकन के संबंध में किए गए प्रयासों की चर्चा आगे की कंडिकाओं में की गई है।

5.10.1 अपशिष्ट प्रबंधन के अनुश्रवण के लिए संस्थागत तंत्र

5.10.1.1 राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अनुश्रवण में कमी

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हस्तक, 2016 के अनुच्छेद 1.4.5.4 के अनुसार, एक कुशल और उन्नत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की योजना बनाने के लिए, पर्याप्त बुनियादी ढांचे और उपकरणों के अलावा एक कुशल संस्थागत संरचना का होना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 23 (1) के अनुसार, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख (अप्रैल 2016) से छः माह के भीतर स्थानीय निकायों के प्रभार वाले प्रत्येक विभाग को एक राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय का गठन करना था। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 23(2) में किये गये परिकल्पना के अनुसार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य की नीति और रणनीति के कार्यान्वयन के साथ–साथ इन नियमों के शीघ्र और उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देने हेतु, राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय छः महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगा। इस संबंध में समीक्षा प्रतिवेदन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को अग्रसारित की जानी थी।

तदनुसार, बिहार सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में सुधार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय का गठन किया (जनवरी 2018)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अधिसूचना के तारीख से छः माह के भीतर राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय का गठन नहीं किया गया था।

राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय की सात बैठकों[194] में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित पहलूओं पर चर्चा की गई और शहरी स्थानीय निकायों को अनुपालन के लिए निर्देश जारी किये गये। हालांकि, लिए गए निर्णयों से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई प्रभावी नहीं थी, जैसा कि जैविक अपशिष्ट के प्रसंस्करण में कमी, डोर–टू–डोर अपशिष्ट के संग्रहण में कमी, अपशिष्ट का नगण्य पृथक्करण और प्रसंस्करण, स्वास्थ्यकर भूमि भरण स्थल का अभाव आदि, जिसकी चर्चा पूर्ववर्ती कंडिकाओं में की गई है, से ज्ञात होता है।

[194] *(i) 30/01/2018, (ii) 30/07/2018, (iii) 8/03/2019, (iv) 19/03/2020, (v) 19/02/2021, (vi) 11/06/2021* और *(vii) 28/01/2022*

5.10.1.2 जिला एवं शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर अनुश्रवण का अभाव

(i) जिला स्तरीय समीक्षा और अनुश्रवण समिति– ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 12 के अनुसार, जिला स्तर पर, जिला पदाधिकारी को अपशिष्ट पृथक्करण, प्रसंस्करण, उपचार और निपटान के संबंध में प्रति तिमाही कम से कम एक बार शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों की समीक्षा करनी है तथा शहरी स्थानीय निकाय और नगर विकास एवं आवास विभाग के परामर्श से सुधारात्मक उपाय करने हैं। इसके अलावा, मॉडल बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप–नियम, 2019 के अनुच्छेद 14 में एक जिला स्तरीय समीक्षा और अनुश्रवण समिति का प्रावधान है, जिसको प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा और अनुश्रवण करना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 28 चयनित शहरी स्थानीय निकायों में से किसी में भी इस समिति का गठन नहीं किया गया था। हालांकि, पाँच शहरी स्थानीय निकायों[195] ने जवाब दिया कि संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा जिला स्तरीय समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही थीं। परंतु, ये शहरी स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा को इन बैठकों का कार्यवृत्त प्रस्तुत करने में विफल रहे।

(ii) वार्ड स्तरीय समिति– नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हस्तक, 2016 के अनुच्छेद 6.1 के अनुसार, वार्ड स्तरीय समितियों का गठन किया जाना चाहिए, जो पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन, सड़क सफाई, नालियों की सफाई और गंदगी फैलाने पर निषेध सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं को सुनिश्चित और इनका अनुश्रवण करेगा।

हालांकि, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में वार्ड स्तरीय समितियों का गठन नहीं किया गया था जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के अनुश्रवण में कमियों को दर्शाता है।

(iii) विषय समिति– बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 32 के अनुसार, नगर निगम अथवा श्रेणी 'क' के नगर परिषद्, अन्य बातों के साथ–साथ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी पर्यावरण प्रबंधन आदि से निपटने के लिए विषय समितियों का गठन कर सकते है।

प्रत्येक विषय समिति की सिफारिशों को संबंधित सशक्त स्थायी समिति को उसके विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दरभंगा और मुंगेर को छोड़कर किसी भी चयनित[196] नगर निगम और वर्ग 'ए' के नगर परिषदों में विषय समितियों का गठन नहीं किया गया था। हालांकि, दरभंगा या मुंगेर में समितियों द्वारा आयोजित किसी भी बैठक का विवरण अभिलेख में नहीं था। इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकाय विषय–विशिष्ट चर्चाओं और समिति के सुझावों के लाभों से वंचित रह गये, जिससे बेहतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को सुनिश्चित किया जा सकता था।

(iv) सशक्त स्थायी समिति की बैठकें – बिहार नगरपालिका सशक्त स्थायी समिति कार्य संचालन नियमावली, 2010 की धारा 3 और 10 के अनुसार, नगरपालिका की कार्यकारी शक्तियां सशक्त स्थायी समिति में निहित होंगी। समिति को सामान्यतः महीने में दो बार बैठक करनी है। इसको संबंधित नगर निकाय द्वारा चलाये जा रहे विकास गतिविधियों पर आदेश/निर्देश जारी करना है।

---

[195] *दरभंगा, दलसिंहसराय, दानापुर, किशनगंज, बहादुरगंज*

[196] *नगर निगम– पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, छपरा; वर्ग ए नगर परिषद्– सहरसा, दानापुर।*

नमूना जांच किये गये सभी शहरी स्थानीय निकायों में सशक्त स्थायी समितियों का गठन किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि जून 2017 से मार्च 2022 के दौरान, आयोजित की जाने वाली 3,002 बैठकों के स्थान पर, सशक्त स्थायी समितियों द्वारा केवल 884 बैठकें[197] (29 प्रतिशत) आयोजित की गई थीं। अपर्याप्त बैठकें आयोजित करना, समितियों द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण के संकेत थे।

(v) बजट विचलन प्रतिवेदन– बिहार नगरपालिका बजट हस्तक के कंडिका 17.1 के अनुसार, बजट विचलन प्रतिवेदन तिमाही आधार पर, बजट केंद्र स्तर के साथ–साथ समग्र नगरपालिका स्तर पर तैयार की जायेगी। बजट विचलन प्रतिवेदन, प्रतिकूल विचलनों को ठीक करने का आधार बनती हैं और इसलिए, शहरी स्थानीय निकायों के प्रबंधन में मूल्य संवर्धन के लिए आवश्यक थीं। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया की नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने तिमाही बजट विचलन प्रतिवेदन तैयार नहीं किया था। इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित नगरपालिका मामलों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए एक नियंत्रण तंत्र से वंचित रह गये।

5.10.2 प्रदूषण के स्तरों का अनुश्रवण

(i) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम की अनुसूची–I में अन्य बातों के साथ–साथ प्रदूषण निवारण, जल गुणवत्ता अनुश्रवण, और परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि भरण स्थलों से लीचेट प्रवाह को किसी भी नालों, नदियों, झीलों या तालाबों में प्रवेश करने से रोकने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। प्रवाहित होने वाले जल को लीचेट अथवा ठोस अपशिष्ट के साथ मिलने की स्थिति में संपूर्ण मिश्रित जल का उपचार संबंधित प्राधिकार द्वारा किया जाना है। यह सुनिश्चित करने हेतु कि भूजल दूषित न हो, भरण स्थलों की परिधि के 50 मीटर के भीतर भूजल गुणवत्ता का आवधिक अनुश्रवण, वर्ष के विभिन्न मौसमों यथा गर्मी, मानसून और मानसून के बाद की अवधि को शामिल करते हुए, किया जाना है। भरण स्थल और उसके आस–पास नियमित रूप से परिवेशी वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाना है और यह औद्योगिक क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित शहरी स्थानीय निकायों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के आलोक में वायु और जल गुणवत्ता दोनों के संबंध में प्रदूषण के स्तर का आकलन नहीं किया था।

बाजारों/डंपिंग स्थलों आदि के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि कई डंपिंग स्थलों पर दुर्गन्ध और जल स्रोतों, जैसे नदियों (दरभंगा में बागमती नदी, मुरलीगंज में बेंगा नदी आदि), तालाबों आदि के पानी के साथ में अपशिष्ट मिश्रित थे। सतही जल के साथ अपशिष्ट का मिश्रण, भूजल को दूषित करने के जोखिम से भरा था। साथ ही, डंपिंग स्थल पर दुर्गन्ध, सार्वजनिक आक्रोश का कारण बन सकता था।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 16 के अनुसार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण मानकों और अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान स्थलों के लिए अनुसूची I और अनुसूची II के तहत निर्दिष्ट शर्तों के पालन की अनुश्रवण करेगा। इसके अलावा, नगरीय ठोस अपशिष्ट हस्तक के अनुच्छेद 6.5.1 के अनुसार, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उपचार, प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के ऑपरेटर इनके मापदंडों के नियमित अनुश्रवण के

[197] *पटना– 61, गया–40, भागलपुर–24, मुजफ्फरपुर–31, दरभंगा–41, पूर्णिया–34, मुंगेर–86, छपरा–9, सहरसा–अनुपलब्ध, दानापुर –36, हाजीपुर–68, किशनगंज–41, जहानाबाद–24, जमुई–32, गोपालगंज–13, सुल्तानगंज –45, रामनगर–64, राजगीर–30, दलसिंहसराय–20, बड़हिया–13, बहादुरगंज–21, जगदीशपुर–38, मखदुमपुर –30, झंझारपुर–18, मुरलीगंज–15, अमरपुर –12, महाराजगंज–18, बेलसंड–20*

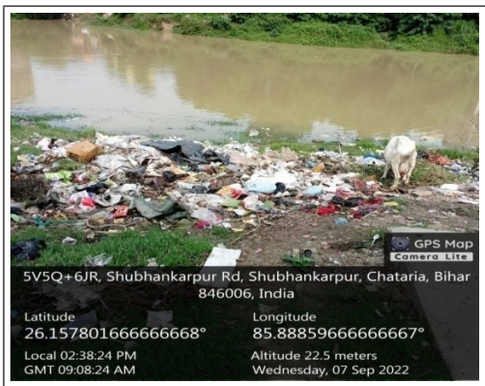
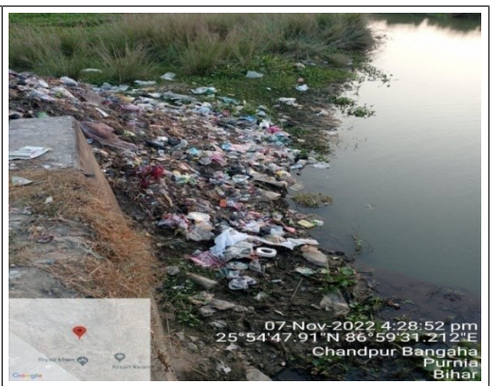
लिए जिम्मेदार हैं। शहरी स्थानीय निकाय द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक आधार पर अनुश्रवण आँकड़ों को शहरी स्थानीय निकायों के वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में प्रतिवेदित किया जाना चाहिए ।

माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश (फरवरी 2020) के अनुसार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का अनुपालन करने में निरंतर विफलता के कारण दिनांक 31/03/2020 से प्रभावी एक अंतरिम मुआवजा पैमाना निर्धारित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थानीय निकाय को प्रति माह प्रति स्थानीय निकाय ₹ 10 लाख, पाँच लाख से 10 लाख के बीच जनसंख्या वाले स्थानीय निकाय को प्रति माह प्रति स्थानीय निकाय ₹ पाँच लाख तथा अन्य स्थानीय निकाय को ₹ एक लाख प्रति माह प्रति स्थानीय निकाय की दर से, दिनांक 01/04/2020 से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन करने तक मुआवजा का भुगतान करने का दायित्व होगा। अंतिम मुआवजे का आकलन और वसूली बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा छः महीने के भीतर किया जाना था।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जवाब दिया (सितंबर 2022) कि किसी भी नगरपालिका प्राधिकार ने उस समय तक स्वास्थ्यकर भरण स्थल सहित अपशिष्ट निपटान सुविधाओं का विकास/स्थापना नहीं किया था। अतः शोधित लीचेट, परिवेशी वायु, भूजल और भस्मीकरण के संबंध में मानकों के अनुश्रवण और अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने 12 नगर निगमों का निरीक्षण किया था और यह पाया था कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रतिवेदित तथा निरीक्षण के दौरान पाये गये तथ्यों और आँकड़ों के बीच भारी अंतर था। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर विकास एवं आवास विभाग को घोर उल्लंघन से अवगत कराया था।

इसके अलावा, उपरोक्त निर्देश के आलोक में, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने (अक्टूबर 2022) 12 नगर निगमों के विरुद्ध ₹ 5.88 करोड़ का जुर्माना लगाया था। अभी तक कोई जुर्माना वसूल नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित नगर परिषदों और नगर पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का अनुपालन नहीं करने के बावजूद नगर परिषदों और नगर पंचायतों के विरुद्ध ऐसा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था।

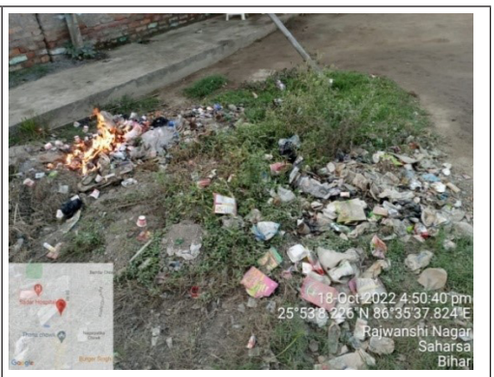
	
दरभंगा के टॉवर चौक के पास बागमती नदी के किनारे अपशिष्ट।	मुरलीगंज में बेंगा नदी के तट पर डंपिंग स्थल और नदी के पानी में मिश्रित अपशिष्ट।

(ii) लेखापरीक्षा ने पाया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 248 के प्रावधानों के विपरीत नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था। अपशिष्ट जलने,

जल स्रोतों के साथ अपशिष्ट के मिश्रण और जल स्रोतों के किनारों पर अपशिष्टों के डंपिंग के उदाहरण कई स्थलों पर देखे गए, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए जोखिम की ओर इशारा करते हैं।



मुरलीगंज में अपशिष्ट जलाने के निशान



सहरसा के सरकारी बस स्टैंड के पास जलता अपशिष्ट



जमुई नगर परिषद् में किऊल नदी के किनारे फेंका गया मिश्रित अपशिष्ट



बड़हिया नगर पंचायत में गंगा नदी से 100 -150 मीटर की दूरी पर जलाया जा रहा अपशिष्ट

5.10.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानवबल/कर्मियों की कमी

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हस्तक, 2016 के अनुच्छेद 1.4.5.4 में कहा गया है कि शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रशाखा या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग होना चाहिए, जिसमें विशेष रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल वाले कर्मी हों, जैसे लोक स्वास्थ्य अधिकारी, स्वच्छता अधिकारी, कनीय अभियंता, स्वच्छता उप–निरीक्षक, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्यावरण अभियंता, आदि। इसके अतिरिक्त, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 37 के अनुसार, सशक्त स्थायी समिति कर्मियों (वैधानिक अधिकारियों के अलावा) को संविदा आधार पर नियुक्त करने का निर्णय ले सकती है।

बिहार सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विभिन्न पदों (यथा स्वच्छता इंस्पेक्टर/मुख्य स्वच्छता इंस्पेक्टर, सफाई जमादार, सहायक लोक स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिकारी/लोक स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिकारी और लिपिक) की स्वीकृति दी (मार्च 2021 तक) थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित शहरी स्थानीय निकायों में इन पदों को नहीं भरा गया था (मार्च 2022)।

स्वीकृत पदों के विरुद्ध 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक कर्मियों की कमी थी, जैसा कि **तालिका 5.41** में दर्शाया गया है और ***परिशिष्ट 5.19*** में विस्तृत विवरण दिया गया है। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में प्रावधान किए जाने के बावजूद शहरी स्थानीय निकायों ने संविदा आधार पर भी आवश्यक कर्मियों की भर्ती नहीं की थी।

तालिका 5.41

चयनित शहरी स्थानीय निकायों में (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए) स्वीकृत बल और कार्यरत बल (मार्च 2022)

स्वीकृत पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	कमी (प्रतिशत)
स्वच्छता इंस्पेक्टर/मुख्य स्वच्छता इंस्पेक्टर	494	16	478 (97)
सफाई जमादार	1,413	104	1,309 (93)
सहायक लोक स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिकारी/उप लोक स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिकारी/लोक स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिकारी	52	0	52 (100)
लिपिक	72	7	65 (90)

*(**स्रोतः** चयनित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दी गई सूचना) *पटना नगर निगम को छोड़कर क्योंकि कार्यरत बलों के आँकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए।*

हालांकि, शहरी स्थानीय निकायों ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से भर्ती किए गए कर्मियों के द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न घटकों यथा पृथक्कृत अपशिष्ट संग्रहण, ढक कर परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान आदि का प्रबंधन करने का प्रयास किया था।

अपशिष्ट प्रबंधन हेतु समर्पित कर्मियों की कमी के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यथा अपर्याप्त डोर–टू–डोर पृथक्कृत अपशिष्ट संग्रहण, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट की पुनः प्राप्ति, अपशिष्ट का वैज्ञानिक निपटान आदि में कमियां थीं।

5.10.4 निष्कर्ष

अक्रियाशील जिला स्तरीय समीक्षा और अनुश्रवण समितियों, वार्ड स्तरीय समितियों और विषय समितियों का गठन नहीं करने और प्रदूषण स्तरों का अनुश्रवण नहीं करने से स्पष्ट था कि अनुश्रवण में कमी थी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 90 से 100 प्रतिशत कर्मियों की कमी थी।

5.10.5 अनुशंसाएं

- *शहरी स्थानीय निकाय अनुश्रवण समितियों को सक्रिय और अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को भी सुदृढ़ कर सकते हैं।*
- *राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरणीय आवश्यकताओं के लिए डिजाइन, निपटान, उपचार और प्रसंस्करण सुविधाओं का अनुश्रवण नहीं करने के संबंध में जिम्मेदारी तय कर सकता है।*
- *विभाग शहरी स्थानीय निकायों में उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मुख्य स्वच्छता निरीक्षक/स्वच्छता निरीक्षक, सफाई जमादार, सहायक लोक स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिकारी/उप लोक स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिकारी/लोक स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिकारियों के पदों को भरने के लिए प्रभावी उपाय कर सकता है।*

राज कुमार

पटना
दिनांक 21 जून 2024

(राज कुमार)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 28 जून 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भः कंडिका–4.1, पृष्ठ–35)

ब्याज और जुर्माने पर परिहार्य व्यय

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	मजदूरी माह	देय तिथि	जमा करने की तिथि	विलम्ब (दिनो की संख्या)	योगदान राशि	ई.पी.एफ.ओ. द्वारा अधिरोपित की गई राशि			शहरी स्थानीय निकाय द्वारा भुगतान की गई राशि
						7 क्यू	14 बी	कुल	
1	जनवरी 2016	15/02/2016	18/11/2020	1,738	4,508	2,577	4,508	7,085	7,085
2	फरवरी 2016	15/03/2016	18/11/2020	1,709	4,508	2,533	4,508	7,041	7,041
3	मार्च 2016	15/04/2016	18/11/2020	1,678	5,860	3,233	5,860	9,093	9,093
4	अप्रैल 2016	15/05/2016	18/11/2020	1,648	10,910	5,911	10,910	16,821	16,821
5	मई 2016	15/06/2016	18/11/2020	1,617	11,630	6,184	11,630	17,814	17,814
6	जून 2016	15/07/2016	18/11/2020	1,587	11,225	5,857	11,225	17,082	17,082
7	जुलाई 2016	15/08/2016	15/04/2020	1,339	3,14,715	1,38,543	2,88,632	4,27,175	4,27,175
8	जुलाई 2016	15/08/2016	18/11/2020	1,556	11,360	5,812	11,360	17,172	17,172
9	अगस्त 2016	15/09/2016	15/04/2020	1,308	3,24,732	1,39,645	2,90,925	4,30,570	4,30,570
10	अगस्त 2016	15/09/2016	18/11/2020	1,525	11,450	5,740	11,450	17,190	17,190
11	सितम्बर 2016	15/10/2016	18/11/2020	1,495	11,405	5,606	11,405	17,011	17,011
12	सितम्बर 2016	15/10/2016	15/04/2020	1,278	3,23,473	1,35,912	2,83,150	4,19,062	4,19,062
13	अक्टूबर 2016	15/11/2016	15/04/2020	1,247	3,21,142	1,31,660	2,74,290	4,05,950	4,05,950
14	अक्टूबर 2016	15/11/2016	18/11/2020	1,464	12,216	5,880	12,216	18,096	18,096
15	नवम्बर 2016	15/12/2016	18/11/2020	1,434	13,884	6,546	13,637	20,183	20,183
16	नवम्बर 2016	15/12/2016	15/04/2020	1,217	3,18,670	1,27,503	2,65,632	3,93,135	3,93,135
17	दिसम्बर 2016	15/01/2017	18/11/2020	1,403	13,884	6,404	13,342	19,746	19,746
18	दिसम्बर 2016	15/01/2017	15/04/2020	1,186	3,14,430	1,22,602	2,55,421	3,78,023	3,78,023

क्रम संख्या	मजदूरी माह	देय तिथि	जमा करने की तिथि	विलम्ब (दिनो की संख्या)	योगदान राशि	ई.पी.एफ.ओ. द्वारा अधिरोपित की गई राशि			शहरी स्थानीय निकाय द्वारा भुगतान की गई राशि
						7 क्यू	14 बी	कुल	
19	जनवरी 2017	15/02/2017	15/04/2020	1,155	3,02,065	1,14,703	2,38,962	3,53,665	3,53,665
20	जनवरी 2017	15/02/2017	23/11/2020	1,377	13,884	6,286	13,095	19,381	19,381
21	फरवरी 2017	15/03/2017	23/11/2020	1,349	12,847	5,698	11,870	17,568	17,568
22	फरवरी 2017	15/03/2017	15/04/2020	1,127	2,74,772	1,01,809	2,12,101	3,13,910	3,13,910
23	मार्च 2017	15/04/2017	23/11/2020	1,318	13,794	5,977	12,453	18,430	18,430
24	मार्च 2017	15/04/2017	15/04/2020	1,096	2,78,148	1,00,224	2,08,801	3,09,025	3,09,025
25	अप्रैल 2017	15/05/2017	28/09/2020	1,232	3,18,288	1,28,920	2,68,583	3,97,503	3,97,503
26	अप्रैल 2017	15/05/2017	23/11/2020	1,288	14,966	6,337	13,203	19,540	19,540
27	मई 2017	15/06/2017	23/11/2020	1,257	15,732	6,501	13,544	20,045	20,045
28	मई 2017	15/06/2017	16/04/2020	1,036	2,96,885	1,01,120	2,10,667	3,11,787	3,11,787
29	जून 2017	15/07/2017	23/11/2020	1,227	15,732	6,346	13,221	19,567	19,567
30	जून 2017	15/07/2017	15/04/2020	1,005	3,01,796	99,717	2,07,743	3,07,460	3,07,460
31	जुलाई 2017	15/08/2017	23/11/2020	1,196	16,048	6,311	13,146	19,457	19,457
32	जुलाई 2017	15/08/2017	16/04/2020	975	3,03,691	97,348	2,02,808	3,00,156	3,00,156
33	अगस्त 2017	15/09/2017	16/04/2020	944	2,97,613	92,366	1,92,429	2,84,795	2,84,795
34	सितम्बर 2017	15/10/2017	23/11/2020	1,135	14,965	5,585	11,634	17,219	17,219
35	सितम्बर 2017	15/10/2017	16/04/2020	914	2,95,693	8,88,54	1,85,112	2,73,966	2,73,966
36	अक्टूबर 2017	15/11/2017	23/11/2020	1,104	20,257	7,353	15,318	22,671	22,671
37	अक्टूबर 2017	15/11/2017	16/04/2020	883	3,87,841	1,12,591	2,34,564	3,47,155	3,47,155
38	नवम्बर 2017	15/12/2017	16/04/2020	853	2,96,288	83,091	1,73,106	2,56,197	2,56,197
39	नवम्बर 2017	15/12/2017	23/11/2020	1,074	15,152	5,350	11,146	16,496	16,496
40	दिसम्बर 2017	15/01/2018	16/04/2020	822	3,85,056	1,04,060	2,16,792	3,20,852	3,20,852

क्रम संख्या	मजदूरी माह	देय तिथि	जमा करने की तिथि	विलम्ब (दिनो की संख्या)	योगदान राशि	ई.पी.एफ.ओ. द्वारा अधिरोपित की गई राशि			शहरी स्थानीय निकाय द्वारा भुगतान की गई राशि
						7 क्यू	14 बी	कुल	
41	दिसम्बर 2017	15 / 01 / 2018	23 / 11 / 2020	1,043	20,547	7,046	14,679	21,725	21,725
42	जनवरी 2018	15 / 02 / 2018	17 / 04 / 2020	792	3,81,403	99,311	2,06,897	3,06,208	3,06,208
43	जनवरी 2018	15 / 02 / 2018	08 / 12 / 2020	1,027	20,258	6,839	14,250	21,089	21,089
44	फरवरी 2018	15 / 03 / 2018	17 / 04 / 2020	764	3,62,032	90,935	1,89,447	2,80,382	2,80,382
45	फरवरी 2018	15 / 03 / 2018	08 / 12 / 2020	999	19,516	6,411	13,354	19,765	19,765
46	मार्च 2018	15 / 04 / 2018	08 / 12 / 2020	968	20,664	6,577	13,701	20,278	20,278
47	मार्च 2018	15 / 04 / 2018	17 / 04 / 2020	733	3,84,818	92,736	1,93,200	2,85,936	2,85,936
48	अप्रैल 2018	15 / 05 / 2018	08 / 12 / 2020	938	19,572	6,036	12,575	18,611	18,611
49	अप्रैल 2018	15 / 05 / 2018	17 / 04 / 2020	703	3,63,270	83,960	1,74,918	2,58,878	2,58,878
50	मई 2018	15 / 06 / 2018	08 / 12 / 2020	907	20,768	6,194	12,902	19,096	19,096
51	मई 2018	15 / 06 / 2018	17 / 04 / 2020	672	3,86,771	85,450	1,78,021	2,63,471	2,63,471
52	जून 2018	15 / 07 / 2018	20 / 04 / 2020	645	3,81,992	81,004	1,68,756	2,49,760	2,49,760
53	जून 2018	15 / 07 / 2018	08 / 12 / 2020	877	20,474	5,904	12,299	18,203	18,203
54	जुलाई 2018	15 / 08 / 2018	08 / 12 / 2020	846	20,473	5,694	11,863	17,557	17,557
55	जुलाई 2018	15 / 08 / 2018	20 / 04 / 2020	614	3,89,020	78,529	1,63,602	2,42,131	2,42,131
56	अगस्त 2018	15 / 09 / 2018	08 / 12 / 2020	815	20,622	5,525	11,511	17,036	17,036
57	अगस्त 2018	15 / 09 / 2018	20 / 04 / 2020	583	3,91,069	74,957	1,56,160	2,31,117	2,31,117
58	सितम्बर 2018	15 / 10 / 2018	08 / 12 / 2020	785	19,073	4,922	10,255	15,177	15,177
59	सितम्बर 2018	15 / 10 / 2018	20 / 04 / 2020	553	3,72,215	67,672	1,40,983	2,08,655	2,08,655
60	अक्टूबर 2018	15 / 11 / 2018	20 / 04 / 2020	522	3,94,513	67,705	1,41,052	2,08,757	2,08,757
61	अक्टूबर 2018	15 / 11 / 2018	08 / 12 / 2020	754	20,562	5,097	10,619	15,716	15,716
62	नवम्बर 2018	15 / 12 / 2018	08 / 12 / 2020	724	17,875	4,255	8,864	13,119	13,119

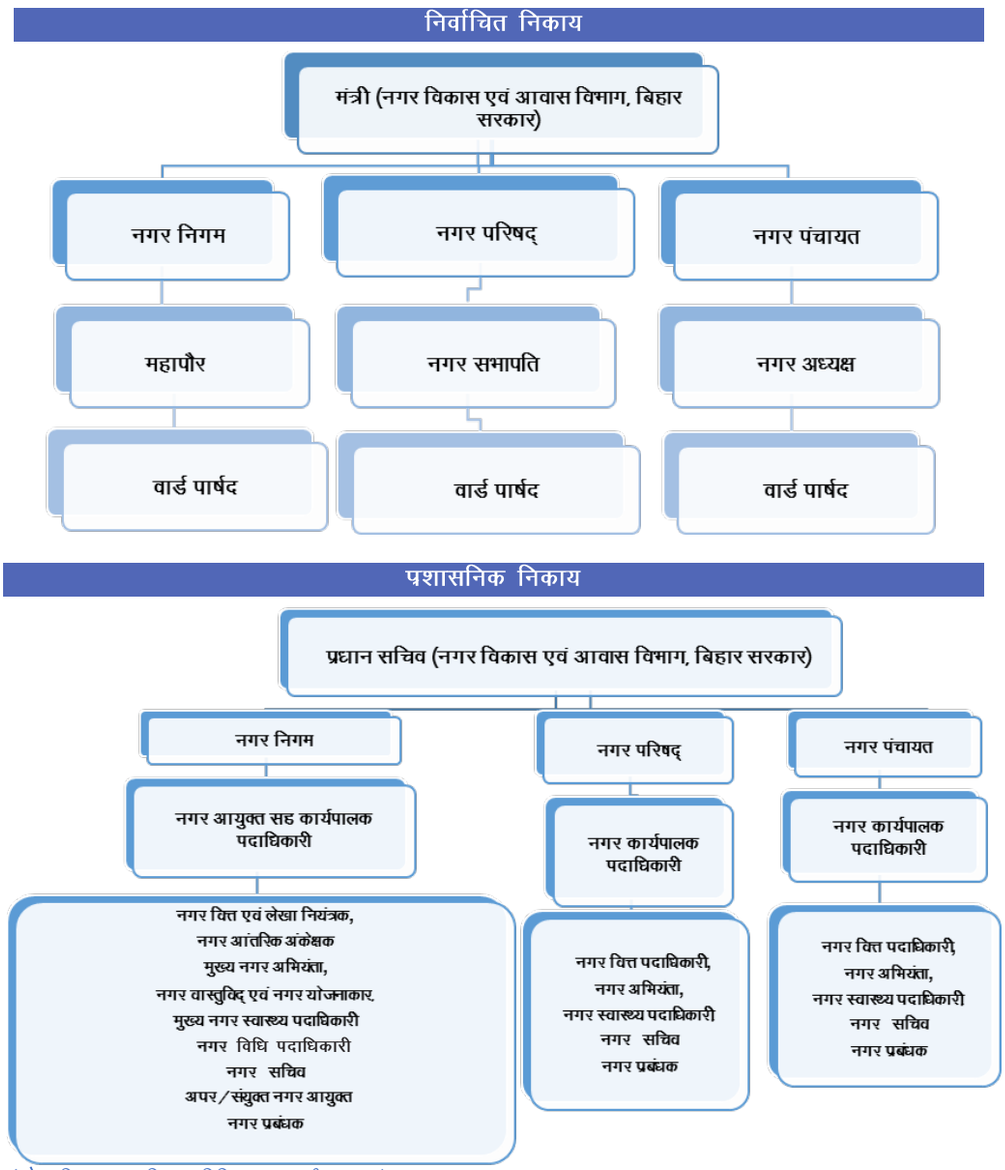
क्रम संख्या	मजदूरी माह	देय तिथि	जमा करने की तिथि	विलम्ब (दिनो की संख्या)	योगदान राशि	ई.पी.एफ.ओ. द्वारा अधिरोपित की गई राशि			शहरी स्थानीय निकाय द्वारा भुगतान की गई राशि
						7 क्यू	14 बी	कुल	
63	नवम्बर 2018	15/12/2018	20/04/2020	492	3,42,835	55,454	1,15,531	1,70,985	1,70,985
64	दिसम्बर 2018	15/01/2019	08/12/2020	693	20,920	4,767	9,929	14,696	14,696
65	दिसम्बर 2018	15/01/2019	20/04/2020	461	4,03,449	61,147	1,27,391	1,88,538	1,88,538
66	जनवरी 2019	15/02/2019	22/04/2020	432	3,93,161	55,840	1,16,332	1,72,172	1,72,172
67	जनवरी 2019	15/02/2019	30/12/2020	684	21,623	4,861	10,130	14,991	14,991
68	फरवरी 2019	15/03/2019	22/04/2020	404	3,66,615	48,694	1,01,448	1,50,142	150,142
69	फरवरी 2019	15/03/2019	30/12/2020	656	19,712	4,251	8,858	13,109	13,109
70	मार्च 2019	15/04/2019	22/04/2020	373	3,84,188	47,113	98,152	1,45,265	1,45,265
71	मार्च 2019	15/04/2019	30/12/2020	625	21,033	4,322	9,004	13,326	13,326
72	अप्रैल 2019	15/05/2019	22/04/2020	343	3,87,546	43,703	91,047	1,34,750	1,34,750
73	अप्रैल 2019	15/05/2019	30/12/2020	595	20,252	3,962	8,253	12,215	12,215
74	मई 2019	15/06/2019	30/04/2020	320	3,97,049	41,771	87,024	1,28,795	1,28,795
75	मई 2019	15/06/2019	30/12/2020	564	22,337	4,142	8,629	12,771	12,771
76	जून 2019	15/07/2019	30/12/2020	534	21,631	3,798	7,911	11,709	11,709
77	जून 2019	15/07/2019	30/04/2020	290	3,86,239	36,825	76,718	1,13,543	1,13,543
78	जुलाई 2019	15/08/2019	18/05/2020	277	3,79,987	34,604	72,093	1,06,697	1,06,697
79	जुलाई 2019	15/08/2019	30/12/2020	503	19,891	3,290	6,852	10,142	10,142
80	अगस्त 2019	15/09/2019	18/05/2020	246	3,67,151	29,694	61,863	91,557	91,557
81	अगस्त 2019	15/09/2019	30/12/2020	472	22,579	3,505	7,300	10,805	10,805
82	सितम्बर 2019	15/10/2019	18/05/2020	216	3,73,410	26,517	55,244	81,761	81,761
83	सितम्बर 2019	15/10/2019	30/12/2020	442	24,078	3,500	7,288	10,788	10,788

क्रम संख्या	मजदूरी माह	देय तिथि	जमा करने की तिथि	विलम्ब (दिनो की संख्या)	योगदान राशि	ई.पी.एफ.ओ. द्वारा अधिरोपित की गई राशि			शहरी स्थानीय निकाय द्वारा भुगतान की गई राशि
						7 क्यू	14 बी	कुल	
84	अक्टूबर 2019	15/11/2019	06/07/2020	234	4,05,258	31,177	64,953	96,130	96,130
85	अक्टूबर 2019	15/11/2019	14/01/2021	426	26,738	3,745	7,802	11,547	11,547
86	नवम्बर 2019	15/12/2019	06/07/2020	204	4,25,192	28,518	59,411	87,929	87,929
87	नवम्बर 2019	15/12/2019	14/01/2021	396	26,942	3,508	7,308	10,816	10,816
88	दिसम्बर 2019	15/01/2020	06/07/2020	173	4,25,703	24,213	30,265	54,478	54,478
89	दिसम्बर 2019	15/01/2020	14/01/2021	365	28,944	3,474	7,236	10,710	10,710
90	जनवरी 2020	15/02/2020	06/07/2020	142	4,23,136	19,754	24,693	44,447	44,447
91	फरवरी 2020	15/03/2020	06/07/2020	113	4,10,502	15,251	12,709	27,960	27,960
92	मार्च 2020	15/04/2020	20/08/2020	127	4,73,554	19,772	24,715	44,487	44,487
93	अप्रैल 2020	15/05/2020	20/08/2020	97	4,65,620	14,849	12,374	27,223	27,223
94	मई 2020	15/06/2020	20/08/2020	66	4,56,643	9,909	8,257	18,166	18,166
95	जून 2020	15/07/2020	20/08/2020	36	4,71,947	5,586	2,328	7,914	7,914
96	जुलाई 2020	15/08/2020	20/08/2020	5	4,97,267	818	341	1,159	1,159
97	अगस्त 2020	15/09/2020	09/11/2020	55	4,67,491	8,453	3,522	11,975	11,975
98	सितम्बर 2020	15/10/2020	09/11/2020	25	4,58,938	3,772	1,572	5,344	5,344
99	अक्टूबर 2020	15/11/2020	28/11/2020	13	4,56,448	1,951	813	2,764	2,764
100	नवम्बर 2020	15/12/2020	29/12/2020	14	4,31,726	1,986	828	2,814	2,814
101	दिसम्बर 2020	15/01/2021	14/01/2021	.1		0	0	0	0
102	जनवरी 2021	15/02/2021	12/03/2021	25	4,63,031	3,806	1,586	5,392	5,392
कुल						**37,59,756**	**76,78,017**	**1,14,37,773**	**1,14,37,773**

(स्रोतः ई०पी०एफ०ओ०, भागलपुर)

परिशिष्ट – 5.1
(संदर्भः कंडिका 5.1.1, पृष्ठ – 41)

शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढाँचा



(स्रोतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 36)

परिशिष्ट – 5.2
(संदर्भः कंडिका 5.2.1, पृष्ठ – 46)
अ. नमूना परीक्षित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिवेदित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये सेवा स्तर मानक (मार्च 2017/ मार्च 2018)

(स्थिति प्रतिशत में)

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय	गृह–स्तर आच्छादन	ठोस अपशिष्ट संग्रहण दक्षता	नगरीय ठोस अपशिष्ट पृथक्करण की मात्रा	नगरीय ठोस अपशिष्ट पुनः प्राप्ति की मात्रा	ठोस अपशिष्ट निपटान की मात्रा	लागत वसूली	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क संग्रहण में दक्षता	उपभोक्ता शिकायत निवारण में दक्षता	अभियुक्तियाँ
1	पटना	50	50	50	50	20	0	80	70	बजट 2017-18
2	गया	50	50	50	70	50	0	80	70	–वही–
3	भागलपुर	100	100	10	10	10	0	0	60	बजट 2018-19
4	मुजफ्फरपुर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	बजट में प्रकाशित नहीं
5	दरभंगा	80	75	20	0	0	0	0	0	बजट 2017-18
6	पूर्णिया	10	10	5	10	10	10	10	0	बजट 2017-18
7	मुंगेर	40	40	0	0	0	0	0	0	बजट 2017-18
8	छपरा	85	80	25	0	0	0	0	0	–वही–
9	सहरसा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	आँकड़े अनुपलब्ध
10	दानापुर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	बजट में प्रकाशित नहीं
11	हाजीपुर	95	95	25	0	0	90	0	0	बजट 2018-19
12	किशनगंज	50	50	50	70	50	0	80	70	बजट 2017-18
13	जहानाबाद	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	बजट में प्रकाशित नहीं
14	जमुई	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	आँकड़े अनुपलब्ध
15	गोपालगंज	15	90	20	20	15	15	10	0	बजट 2018-19
16	सुल्तानगंज	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	आँकड़े अनुपलब्ध
17	रामनगर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	आँकड़े अनुपलब्ध
18	राजगीर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	बजट में प्रकाशित नहीं
19	दलसिंहसराय	100	20	20	0	0	0	0	0	बजट 2018-19
20	बड़हिया	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	आँकड़े अनुपलब्ध
21	बहादुरगंज	75	80	25	0	0	0	0	0	बजट 2018-19
22	जगदीशपुर	85	80	0	0	0	0	0	50	बजट 2018-19
23	मखदुमपुर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	बजट में प्रकाशित नहीं
24	झंझारपुर	85	80	25	0	0	0	0	0	बजट 2018-19
25	मुरलीगंज	70	70	0	0	0	0	60	55	बजट 2018-19
26	अमरपुर	50	50	50	50	50	50	50	50	बजट 2017-18
27	महाराजगंज	50	50	50	70	50	0	80	70	बजट 2018-19
28	बेलसंड	70	50	50	70	0	0	80	70	–वही–
माध्यिका		**70**	**60**	**25**	**5**	**0**	**0**	**5**	**25**	
अंतराल		**0–100**	**0–100**	**0–50**	**0–70**	**0–50**	**0–90**	**0–80**	**0–70**	

(स्रोत : नमूना जांचित शहरी स्थानीय निकायो का बजट आँकड़ा)

ब. नमूना जांच किये गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिवेदित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये सेवा स्तर मानक (मार्च 2022)

(अद्यतन स्थिति प्रतिशत में)

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय	गृह–स्तर आच्छादन	ठोस अपशिश्ट संग्रहण दक्षता	नगरीय ठोस अपशिष्ट पृथक्करण की मात्रा	नगरीय ठोस अपशिष्ट पुनः प्राप्ति की मात्रा	ठोस अपशिष्ट निपटान की मात्रा	लागत वसूली	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क संग्रहण में दक्षता	उपभोक्ता शिकायत निवारण में दक्षता	अभियुक्तियाँ
1	पटना	80	80	50	50	50	5	80	70	
2	गया	50	50	50	70	50	0	80	70	
3	भागलपुर	100	100	60	60	70	70	20	80	
4	मुजफ्फरपुर	100	95	25	0	0	90	0	75	
5	दरभंगा	100	100	100	80	100	100	90	80	
6	पूर्णिया	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	बजट उपलब्ध नहीं कराया गया
7	मुंगेर	60	60	40	40	0	0	0	20	
8	छपरा	100	95	70	70	0	0	0	80	
9	सहरसा	95	95	25	0	0	90	0	0	
10	दानापुर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	बजट में प्रकाशित नहीं
11	हाजीपुर	95	95	25	0	0	90	0	0	
12	किशनगंज	100	100	80	60	0	70	90	80	
13	जहानाबाद	95	95	25	0	0	90	0	0	
14	जमुई	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	बजट में प्रकाशित नहीं
15	गोपालगंज	100	90	80	20	0	0	0	90	
16	सुल्तानगंज	100	100	2	0	0	0	0	30	

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय	गृह–स्तर आच्छादन	ठोस अपशिश्ट संग्रहण दक्षता	नगरीय ठोस अपशिष्ट पृथक्करण की मात्रा	नगरीय ठोस अपशिष्ट पुनः प्राप्ति की मात्रा	ठोस अपशिष्ट निपटान की मात्रा	लागत वसूली	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क संग्रहण में दक्षता	उपभोक्ता शिकायत निवारण में दक्षता	अभियुक्तियाँ
17	रामनगर	80	80	50	50	0	0	0	70	
18	राजगीर	95	95	25	0	0	90	0	0	
19	दलसिंहसराय	100	80	50	5	5	2	80	80	
20	बड़हिया	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	बजट में प्रकाशित नहीं
21	बहादुरगंज	80	80	50	50	0	0	0	70	
22	जगदीशपुर	100	100	100	50	55	0	0	80	
23	मखदुमपुर	100	100	100	0	80	0	80	0	
24	झंझारपुर	85	80	25	0	0	0	0	0	
25	मुरलीगंज	70	70	0	0	0	60	55	0	
26	अमरपुर	50	70	5	20	0	0	0	0	
27	महाराजगंज	80	50	50	40	40	10	10	20	
28	बेलसंड	80	80	50	0	0	70	20	50	
माध्यिका		**95**	**92.5**	**50**	**20**	**0**	**3.5**	**0**	**60**	
अंतराल		**50–100**	**50–100**	**0–100**	**0–80**	**0–100**	**0–100**	**0–90**	**0–90**	

(स्रोत : नमूना जांच किये गए शहरी स्थानीय निकायों का बजट)

स. लेखापरीक्षा द्वारा पाये गये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (मार्च 2022) के लिए सेवा स्तर मानक

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय	1 गृह–स्तर आच्छादन (%)			2. ठोस अपशिष्ट संग्रहण दक्षता (%)			3. नगरीय ठोस अपशिष्ट पृथक्करण की मात्रा (%)			4. नगरीय ठोस अपशिष्ट पुनः प्राप्ति की मात्रा (%)		
		सर्वेक्षित गृहों एवं दुकानों की संख्या जो खुले में अपशिष्ट फेंकते हैं या डोर–टू–डोर संग्रहण के तहत कवर नहीं किए गए हैं	सर्वेक्षित गृहों और दुकानों की कुल संख्या	गृह–स्तर आच्छादन (%)	भा.स्था.नि. द्वारा एकत्रित कुल अपशिष्ट (टन प्रतिदिन)	भा.स्था.नि. में उत्पन्न कुल अपशिष्ट (टन प्रतिदिन)	संग्रहण दक्षता (%)	सर्वेक्षित घरों और दुकानों की संख्या जो स्रोत पर अपशिष्ट को पृथक करते हैं	सर्वेक्षित धरों और दुकानों की कुल संख्या	नगरीय ठोस अपशिष्ट पृथक्करण की मात्रा (%)	पुनर्चक्रण / प्रसंस्कृत अपशिष्ट की मात्रा (टन प्रतिदिन)*	एकत्रित कुल अपशिष्ट (टन प्रतिदिन)	नगरीय ठोस अपशिष्ट पुनः प्राप्ति की मात्रा (%)
1	पटना	12	106	89	1000	1250	80	41	106	39	उपलब्ध नहीं	.	.
2	गया	0	88	100	309	309	100	43	88	49	उपलब्ध नहीं	.	.
3	भागलपुर	5	75	93	267	267	100	1	75	1	0	267	0
4	मुजफ्फरपुर	13	73	82	180	182	99	4	73	5	5.72	180	3
5	दरभंगा	21	76	72	120	201	60	19	76	25	2.09	120	2
6	पूर्णिया	33	75	56	75	122	61	9	75	12	0	75	0
7	मुंगेर	0	66	100	88	89	99	53	66	80	0	88	0
8	छपरा	1	64	98	87.5	89.5	98	2	64	3	0	87.5	0
9	सहरसा	15	65	77	31	75	41	19	65	29	0	31	0
10	दानापुर	16	55	71	95	95	100	21	55	38	उपलब्ध नहीं	.	.
11	हाजीपुर	0	55	100	92	92	100	1	55	2	0	92	0
12	किशनगंज	23	45	49	25	38	66	0	45	0	0	25	0
13	जहानाबाद	12	43	72	37	37	100	11	43	26	0	37	0
14	जमुई	19	45	58	24	29	83	0	45	0	0	24	0
15	गोपालगंज	1	39	97	22	23	96	0	39	0	0	22	0
16	सुल्तानगंज	0	45	100	26	26	100	6	45	13	0.5	26	2
17	रामनगर	11	34	68	18	18	100	0	34	0	0.18	18	1

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय	1 गृह–स्तर आच्छादन (%)			2. ठोस अपशिष्ट संग्रहण दक्षता (%)			3. नगरीय ठोस अपशिष्ट पृथक्करण की मात्रा (%)			4. नगरीय ठोस अपशिष्ट पुनः प्राप्ति की मात्रा (%)		
		सर्वेक्षित गृहों एवं दुकानों की संख्या जो खुले में अपशिष्ट फेंकते हैं या डोर–टू–डोर संग्रहण के तहत कवर नहीं किए गए हैं	सर्वेक्षित गृहों और दुकानों की कुल संख्या	गृह–स्तर आच्छादन (%)	श.स्था.नि. द्वारा एकत्रित कुल अपशिष्ट (टन प्रतिदिन)	श.स्था.नि. में उत्पन्न कुल अपशिष्ट (टन प्रतिदिन)	संग्रहण दक्षता (%)	सर्वेक्षित घरों और दुकानों की संख्या जो स्रोत पर अपशिष्ट को पृथक करते हैं	सर्वेक्षित धरों और दुकानों की कुल संख्या	नगरीय ठोस अपशिष्ट पृथक्करण की मात्रा (%)	पुनर्चक्रण / प्रसंस्कृत अपशिष्ट की मात्रा (टन प्रतिदिन)*	एकत्रित कुल अपशिष्ट (टन प्रतिदिन)	नगरीय ठोस अपशिष्ट पुनः प्राप्ति की मात्रा (%)
18	राजगीर	14	45	69	23	23	100	21	45	47	0	23	0
19	दलसिंहसराय	28	45	38	19	26	73	2	45	4	1.76	19	9
20	बड़हिया	6	30	80	18	18	100	7	30	23	2.5	18	14
21	बहादुरगंज	16	30	47	14	20	70	0	30	0	0	14	0
22	जगदीशपुर	0	29	100	4	17	24	0	29	0	0	4	0
23	मखदुमपुर	0	30	100	11	11	100	16	30	53	0	11	0
24	झंझारपुर	23	40	43	4	10	40	0	40	0	0	4	0
25	मुरलीगंज	21	30	30	5	16	31	0	30	0	0	5	0
26	अमरपुर	26	30	13	5	8	63	0	30	0	0	5	0
27	महाराजगंज	0	20	100	5	8	63	7	20	35	0	5	0
28	बेलसंड	17	30	43	3	7	43	0	30	0	0.35	3	13
कुल		**333**	**1,408**	**76**	**2,607.5**	**3,106.5**	**84**	**283**	**1,408**	**20**	**13.1**	**1,203.5**	**1.09**

**'पटना, गया और दानापुर के आँकड़े शामिल नही*

स. लेखापरीक्षा द्वारा पाये गये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (मार्च 2022) के लिए सेवा स्तर मानक

क्रम सं0	शहरी स्थानीय निकाय	5. ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान की मात्रा (%)			6. लागत वसूली (%)			7. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क संग्रहण में दक्षता (%)			8. उपभोक्ता शिकायत निवारण में दक्षता (%)		
		अपशिष्ट की मात्रा जो नियमानुकुल लैंडफिल/खुली डंप साइट में निपटाई जाती है (टन प्रतिदिन)	कुल अपशिष्ट जो लैंडफिल/खुला डंप साइट में निपटाई जाती है (टन प्रतिदिन)	ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान की मात्रा (%)	वर्ष 2021–22 के दौरान उपभोक्ता शुल्क और अपशिष्ट/कम्पोस्ट की बिक्री से एकत्रित राजस्व (₹करोड़ में)	2021–22 के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए परिचालन व्यय (₹करोड़ में)	लागत वसूली (%)	2021–22 के दौरान वास्तव में एकत्रित राजस्व (उपभोगता शुल्क और अपशिष्ट /कम्पोस्ट की बिक्री से राजस्व) (₹ करोड़ में)	2021–22 के दौरान एकत्र किये जाने योग्य राजस्व (उपभोक्ता शुल्क और अपशिष्ट / कम्पोस्ट की बिक्री से राजस्व) (₹करोड़ में)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्कों के संग्रह में दक्षता (%)	शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर निवारण किये गये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित शिकायतों की कुल संख्या	2021–22 के दौरान प्राप्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित शिकायतों की कुल संख्या	ग्राहक शिकायत के निवारण में दक्षता (%)
1	पटना	0	--	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	21.99	9.88	-	-	-	-
2	गया	0	-----	0	3.04	20.93	15	3.04	1.61	-	-	असंधारित	-
3	भागलपुर	0	267	0	0	14.25	0	0	1.88	0	-	असंधारित	-
4	मुजफ्फरपुर	0	174	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.003	2.82	0	-	असंधारित	-
5	दरभंगा	0	118	0	0.47	3.33	14	0.47	0.72	65	अनुपलब्ध	3	-
6	पूर्णिया	0	75	0	0	4.47	0	0	2.32	0	-	अनुपलब्ध	-
7	मुंगेर	0	88	0	0.05	6.09	1	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	-	असंधारित	-
8	छपरा	0	87.5	0	0	1.64	0	0	0.37	0	-	असंधारित	-
9	सहरसा	0	31	0	0.34	4.92	7	0.34	0.69	49	-	असंधारित	-
10	दानापुर	0	----	0	0	16.52	0	0	0.69	0	-	असंधारित	-
11	हाजीपुर	0	92	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0	0.31	0	अनुपलब्ध	-	-
12	किशनगंज	0	25	0	0.31	2.13	15	0.31	0.43	72	-	असंधारित	-
13	जहानाबाद	0	37	0	0.006	4.05	0	0.006	0.68	1	-	असंधारित	-
14	जमुई	0	24	0	0	3.49	0	0	0.20	0	-	असंधारित	-
15	गोपालगंज	0	22	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0	0.46	0	-	असंधारित	-
16	सुल्तानगंज	0	25.5	0	0	3.79	0	0	0.19	0	-	असंधारित	-
17	रामनगर	0	18	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0	0.14	0	-	असंधारित	-

क्रम सं0	शहरी स्थानीय निकाय	5. ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान की मात्रा (%)			6. लागत वसूली (%)			7. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क संग्रहण में दक्षता (%)			8. उपभोक्ता शिकायत निवारण में दक्षता (%)		
		अपशिष्ट की मात्रा जो नियमानुकुल लैंडफिल/खुली डंप साइट में निपटाई जाती है (टन प्रतिदिन)	कुल अपशिष्ट जो लैंडफिल/खुला डंप साइट में निपटाई जाती है (टन प्रतिदिन)	ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान की मात्रा (%)	वर्ष 2021–22 के दौरान उपभोक्ता शुल्क और अपशिष्ट/कम्पोस्ट की बिक्री से एकत्रित राजस्व (₹करोड़ में)	2021–22 के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए परिचालन व्यय (₹करोड़ में)	लागत वसूली (%)	2021–22 के दौरान वास्तव में एकत्रित राजस्व (उपभोगता शुल्क और अपशिष्ट /कम्पोस्ट की बिक्री से राजस्व) (₹ करोड़ में)	2021–22 के दौरान एकत्र किये जाने योग्य राजस्व (उपभोक्ता शुल्क और अपशिष्ट / कम्पोस्ट की बिक्री से राजस्व) (₹करोड़ में)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्कों के संग्रह में दक्षता (%)	शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर निवारण किये गये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित शिकायतों की कुल संख्या	2021–22 के दौरान प्राप्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित शिकायतों की कुल संख्या	ग्राहक शिकायत के निवारण में दक्षता (%)
18	राजगीर	0	23	0	0.023	2.65	1	0.023	0.21	11	-	असंधारित	-
19	दलसिंह सराय	0	17	0	0.06	0.84	11	0.06	0.41	15	0	10	0
20	बड़हिया	0	15.5	0	0	3.19	0	0	0.09	0	-	असंधारित	-
21	बहादुरगंज	0	14	0	0	1.34	0	0	0.16	0	-	0	-
22	जगदीशपुर	0	4	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0	0.07	0	-	असंधारित	-
23	मखदुमपुर	0	11	0	0	2.38	0	0	0.07	0	-	असंधारित	-
24	झंझारपुर	0	4	0	0	0.95	0	0	0.08	0	-	असंधारित	-
25	मुरलीगंज	0	5	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	-	असंधारित	-
26	अमरपुर	0	5	0	0	1.21	0	0	0.03	0	-	असंधारित	-
27	महाराजगंज	0	5	0	0	0.72	0	0	0.05	0	-	असंधारित	-
28	बेलसंड	0	3	0	0.071	1.45	5	0.007	0.03	23	-	असंधारित	-
कुल		**0**	**1,190.5**	**0**	**4.37**	**100.34**	**4**	**1.219***	**13.1***	**9**			

**पटना और गया के क्षेत्र को बाहर रखा गया है।*

(स्रोतः पारिवारिक/दुकानदार सर्वे, संयुक्त भौतिक सत्यापन और श.स्था.नि. द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत प्रतिवेदन)

द. सेवा स्तर मानक

1. **गृह–स्तर आच्छादनः** शहर में घरों की वास्तविक संख्या और डोर–टू–डोर सिस्टम के तहत आच्छादित घरों से संबंधित जानकारी शहरी स्थानीय निकायों के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, लेखा परीक्षा ने गृह/दुकानदार सर्वेक्षण के आधार पर गृह–स्तर आच्छादन का निर्धारण किया। 1,408 गृहों/दुकानदारों का सर्वेक्षण किया गया।

2. **ठोस अपशिष्ट के संग्रहण में दक्षताः** प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में विभिन्न स्रोतों से अपशिष्टों के उत्पादन के आँकड़ों को लिया गया था।

   (i) अपशिष्टों का वर्गीकरण एवं मात्रा का अध्ययन प्रतिवेदन; यदि उपलब्ध नहीं है, तो

   (ii) नगरीय ठोस अपशिष्ट (एम.एस.डब्ल्यू) मानकों के अनुसार अपशिष्ट उत्पादन और 2022 में शहर की अनुमानित जनसंख्या।

   (iii) यदि अपशिष्ट का संग्रहण उत्पादन से अधिक था (उपर्युक्त दो दस्तावेजों के आधार पर), अपशिष्ट उत्पादन को अपशिष्ट संग्रहण के बराबर कर दिया गया।

   शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट संग्रहण संबंधी आँकड़े संधारित नहीं थे। हालांकि, लेखापरीक्षा गणना के लिए अपशिष्ट संग्रहण आँकडे शहरी स्थानीय निकायों के वार्षिक प्रतिवेदन से प्राप्त किया गया था, जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (2022) को प्रस्तुत किया गया था या शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई अनुमानित जानकारी थी।

3. **नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण की मात्राः** गृहों और दुकानदारों के स्तर पर नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण से संबंधित रिकॉर्ड, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा संधारित नहीं किये गये थे। इसलिए, लेखापरीक्षा ने गृह/दुकानदार सर्वेक्षण के आधार पर पृथक्करण के बारे में पता लगाया।

4. **नगरीय ठोस अपशिष्ट पुनः प्राप्ति की मात्राः** नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण से संबंधित आँकड़े शहरी स्थानीय निकायों में संधारित नहीं किये गए थे। हालांकि, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसकी सूचना दी गई थी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (2022) को प्रस्तुत शहरी स्थानीय निकायों के वार्षिक प्रतिवेदन या शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत अनुमानित जानकारी से अपशिष्ट संग्रहण के आँकड़े लिये गये हैं। अपशिष्ट प्रसंस्करण के आँकड़े निम्नलिखित के आधार पर तैयार किये गये हैं।

   (i) संयुक्त भौतिक सत्यापन, या

   (ii) कार्यशील पिट की क्षमता, या

   (iii) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लेखापरीक्षा को दी गई सूचना।

5. **ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान की मात्राः** अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान की मात्रा संयुक्त भौतिक सत्यापन पर आधारित है। लैंडफिल साइट पर निपटारित अपशिष्ट की मात्रा को कुल अपशिष्ट संग्रहण से प्रसंस्कृत अपशिष्ट की मात्रा घटाकर तैयार किया गया है।

6. **लागत वसूलीः** आउटसोर्सिंग एजेंसियों को एवं स्वच्छता श्रमिकों को किये गये भुगतान, जैसा कि उपलब्ध रिकॉर्ड से पता लगाया जा सका, को परिचालन व्यय माना गया है।

7. **नगरीय ठोस अपशिष्ट शुल्कों के संग्रहण में दक्षताः** किसी विशेष श्रेणी के लिए उपभोक्ता शुल्क की न्यूनतम दरों के आधार पर संग्रहणीय उपभोक्ता शुल्क (राजस्व) की गणना की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपी गई शहरी स्थानीय निकायों के वार्षिक प्रतिवेदन (जून 2022) या शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत की गई जानकारी से परिवारों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों की संख्या ली गई है।

8. **उपभोक्ता शिकायत निवारण में दक्षताः** गृह/दुकानदार सर्वेक्षण के आधार पर, परिवारो/दुकानदारों के बीच शिकायत दर्ज करने संबंधी जागरूकता का आकलन किया गया।

परिशिष्ट–5.3

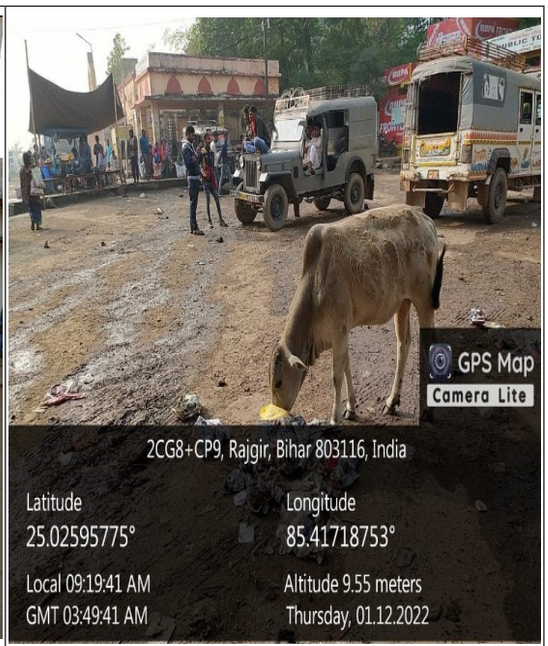
(संदर्भः कंडिका –5.2.1, पृष्ठ– 46)

बिहार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति

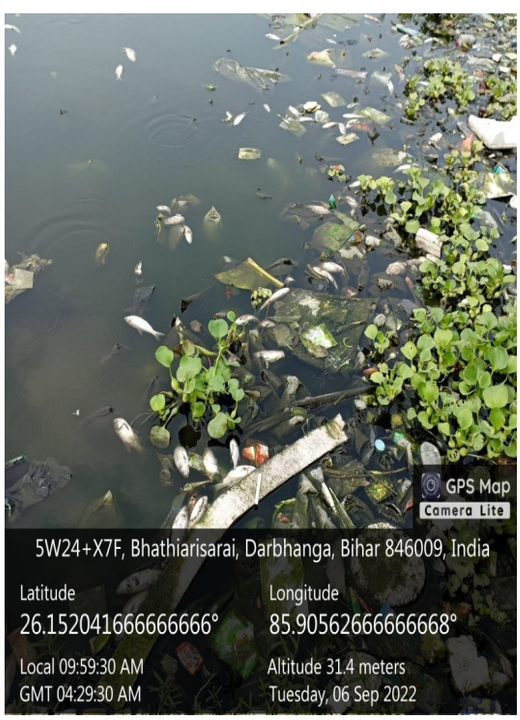
रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि जैसे महत्वपूर्ण स्थानों की तस्वीरें



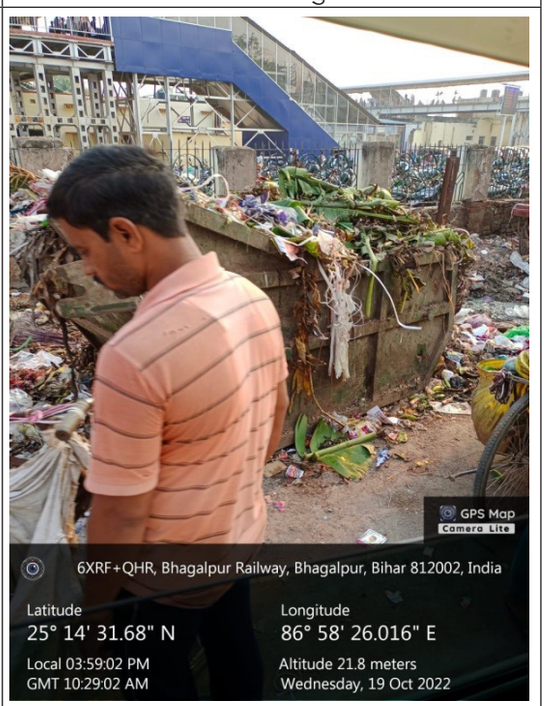
स्वच्छ रेलवे स्टेशन, किशनगंज



राजगीर बस स्टैंड के आसपास अपशिष्ट को खा रहे आवारा पशु



दरभंगा में चंद्रधारी संग्रहालय/पार्क से सटे दिघी तालाब में मरी हुई मछलियां



भागलपुर में रेलवे स्टेशन के बाहर जमा अपशिष्ट

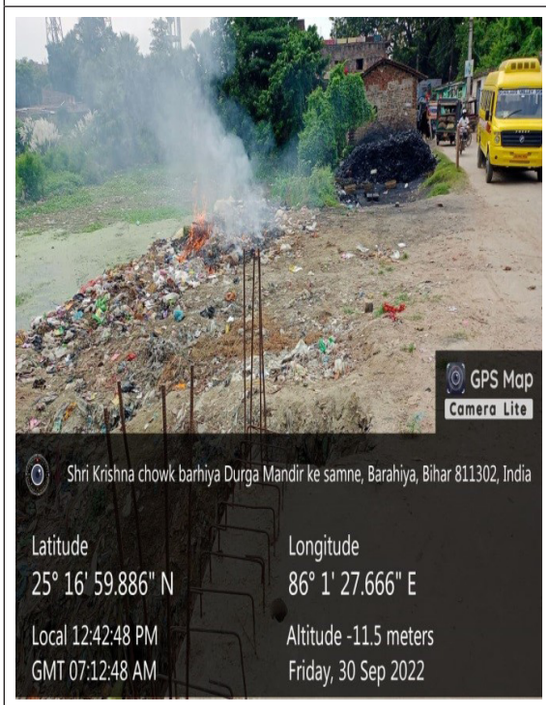
वार्ड और सड़कें



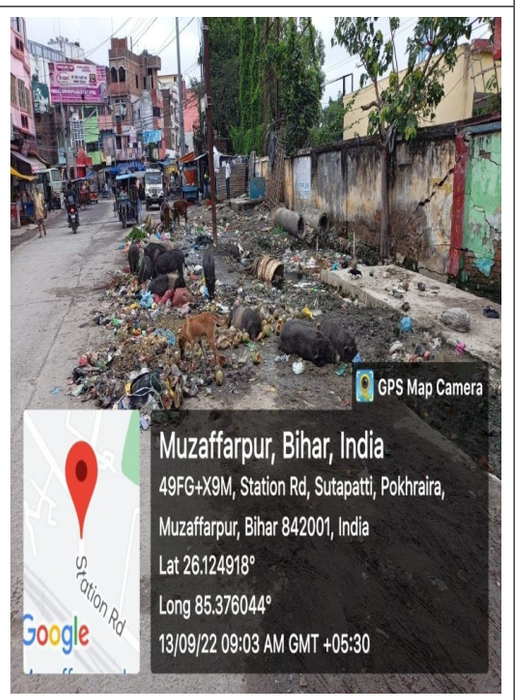
स्टेशन चौक से मीर टोला रोड, सहरसा तक सड़क किनारे अपशिष्ट और खुले में पेशाब करना



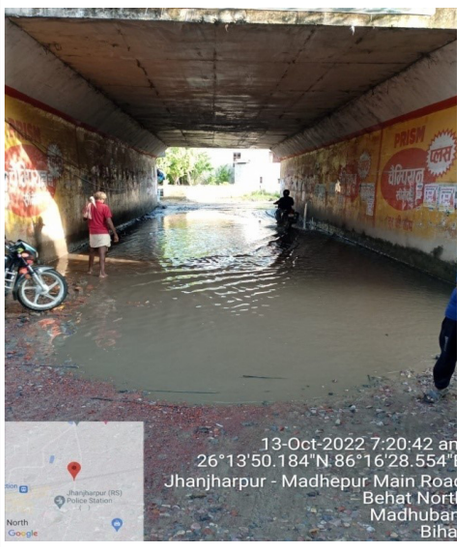
वर्षा के कारण जलजमाव, बेंता चौक से लेहरियासराय रोड, दरभंगा



बड़हिया में सड़क किनारे अपशिष्ट फेंकना और अपशिष्ट जलाना



मुजफ्फरपुर में इमली चट्टी बस स्टैंड के सामने खुले क्षेत्र में फेंके गए मिश्रित अपशिष्ट को खाते आवारा जानवर



कैथी अंडरपास, झंझारपुर के नीचे जलजमाव



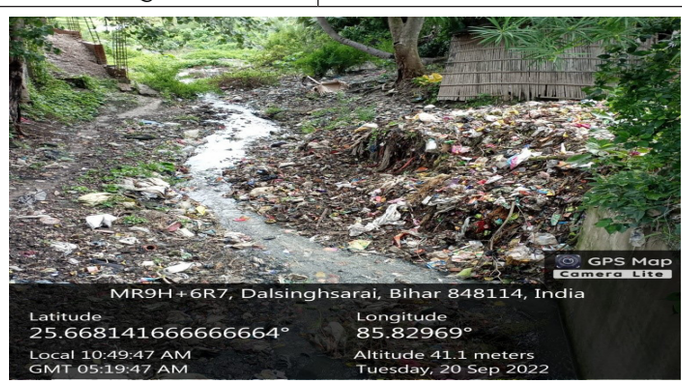
छपरा बाईपास रोड के किनारे जलते हुए अपशिष्ट



रुन्नी सैदपुर बेलसंड रोड पर सड़क के बगल में अस्थायी डंपसाइट पर फेंका हुआ अपशिष्ट



मखदुमपुर–गया रोड, मखदुमपुर के आसपास अपशिष्ट के ढ़ेर



नाली, जहां दलसिंहसराय में नगरपालिका ठेला वालों (वार्ड 1 जो वार्ड 3 बगल में हैं) द्वारा अपशिष्ट डाला जाता है।

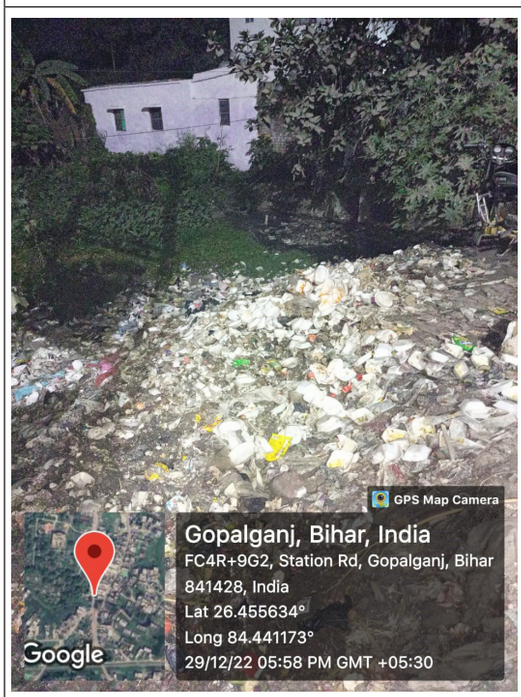
बजारों की तस्वीरें



सुभाषपल्ली चौक, किशनगंज में साफ–सुथरी सड़क



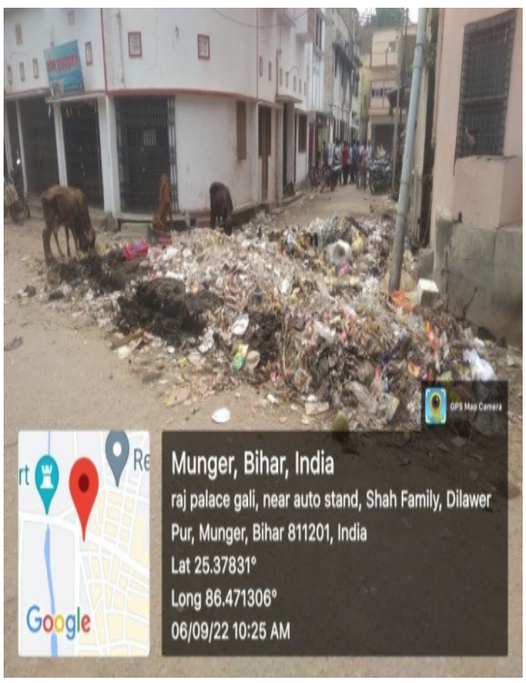
रामविलास गंगा राम महाविद्यालय, महाराजगंज के पास फेंका गया अपशिष्ट



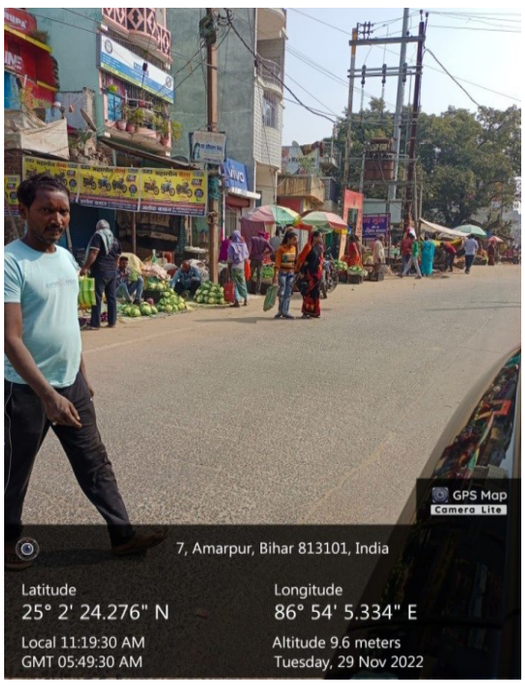
गोपालगंज नगर परिषद् में स्टेशन रोड चौक पर खुले नाले में फेंका गया मिश्रित अपशिष्ट



दलसिंहसराय के गंज रोड स्थित एक अस्पताल के बगल में फेंका गया अपशिष्ट



राजीव चौक, मुंगेर के आसपास फेंका अपशिष्ट



सब्जी मंडी, गोला चौक, अमरपुर में साफ–सुथरी सड़क



राजेंद्र नगर पुल, सब्जी मंडी, पटना के आसपास फैला हुआ अपशिष्ट



रेलवे स्टेशन, झंझारपुर के बाहर सड़क के किनारे फेंका गया अपशिष्ट

अपशिष्ट का संग्रह और परिवहन



दरभंगा के फकीरा चौक के पास टीपर में लादा जा रहा मिश्रित अपशिष्ट



पूर्णिया के खजाँची हाट में बिना सुरक्षा उपकरणों के सफाई कर्मचारी



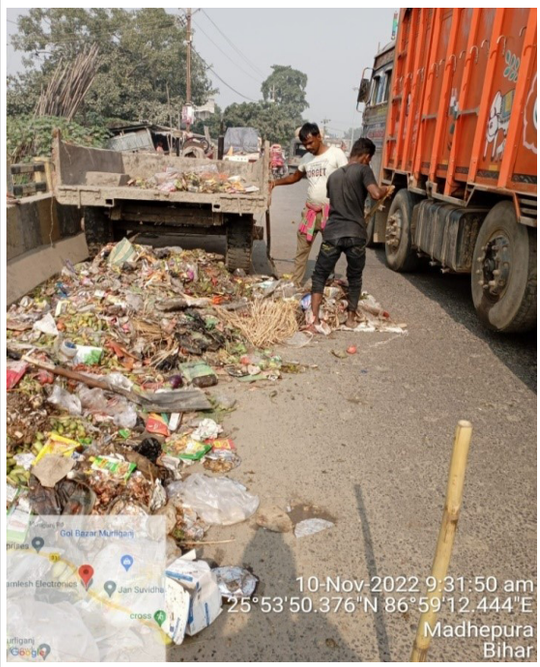
जहानाबाद में पटना–जहानाबाद–गया रोड के किनारे टिपर द्वारा फेंका गया अपशिष्ट



भागलपुर के खंजरपुर में बिना सुरक्षा उपकरणों के श्रमिकों द्वारा सड़क किनारे ट्रैक्टर में अपशिष्ट एकत्र किया जा रहा है



ठेलावालों द्वारा अपशिष्ट एकत्र कर रेलवे स्टेशन (मालगोदाम रोड) दलसिंहसराय के पास फेंक दिया जाता है और यहां से अपशिष्ट ट्रैक्टर में भरकर डंपिंग साइट पर ले जाया जाता है



मुरलीगंज के हाट बाजार में पुल पर अपशिष्ट उतारा जा रहा था, जहां से ट्रैक्टर द्वारा डंपिंग साइट पर ले जाया गया

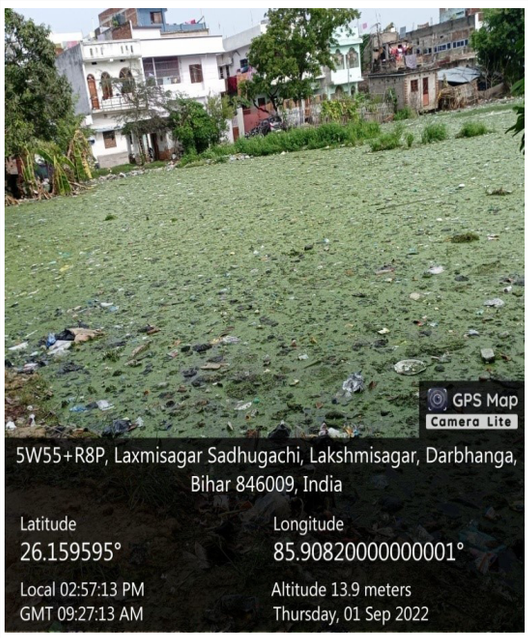
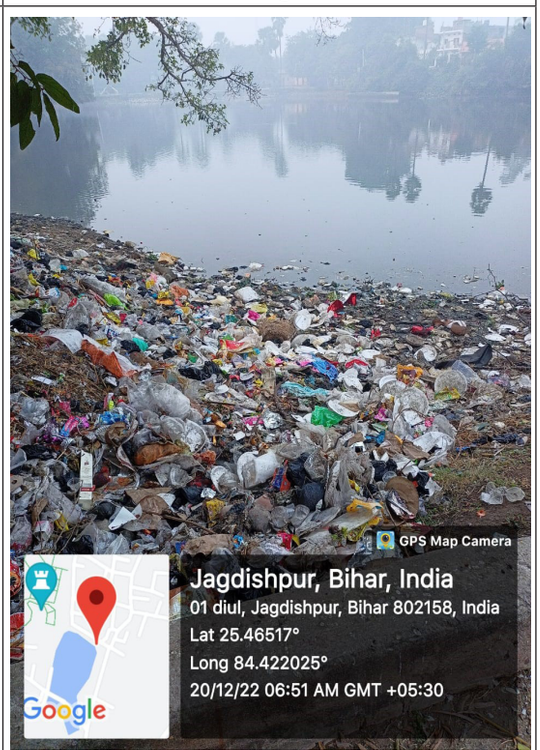


दानापुर में बिना कवर के अपशिष्ट का परिवहन



सुल्तानगंज नगर परिषद के एक ट्रैक्टर द्वारा कवर परिवहन

तालाब, नदी आदि पर अपशिष्ट डालना।

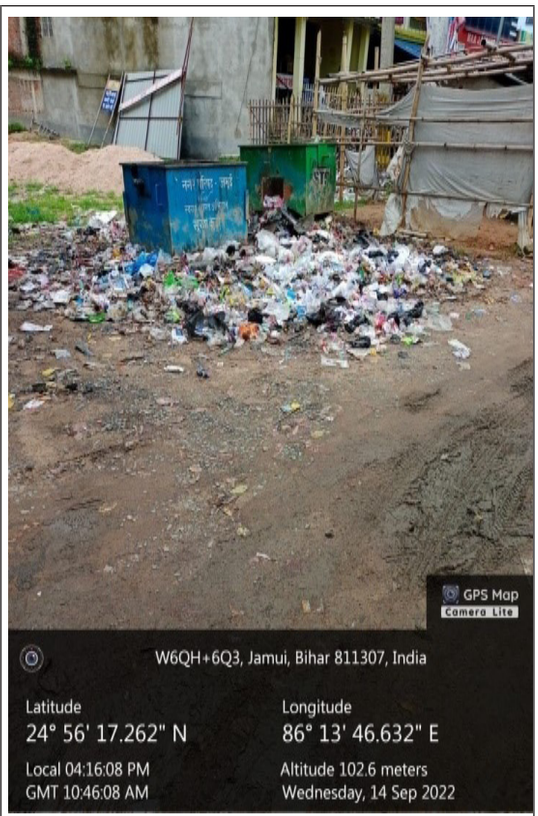
<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>अपशिष्ट से भरे दुल्हिन पोखर, लक्ष्मीसागर, साधुगाछी, दरभंगा</td>
<td>न्यू मार्केट रामनगर के पास राम रेखा नदी के किनारे मिश्रित बिखरा हुआ अपशिष्ट</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>गोलाघाट डंपसाइट, दलसिंहसराय में बलान नदी के किनारे फेंका गया प्लास्टिक अपशिष्ट सहित मिश्रित अपशिष्ट</td>
<td>जगदीशपुर नगर परिषद् में 'खान साहब का पोखरा' में डाला गया मिश्रित अपशिष्ट</td>
</tr>
</table>

सामुदायिक कूड़ेदान की स्थिति

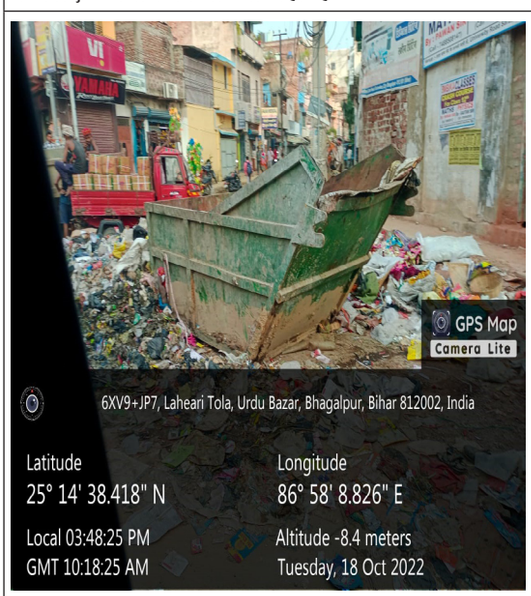




किशनगंज में लाल डस्टबिन (जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए) और काला डस्टबिन (खतरनाक अपशिष्ट के लिए) बाजार में रखा जा रहा है और मिश्रित अपशिष्ट के लिए उपयोग किया जा रहा है



जमुई में जमुई– मुंगेर सड़क के किनारे सामुदायिक कूड़ेदान के अधिष्ठापन के बाद भी सड़क पर कचड़े का बिखराव



भागलपुर नगर निगम के भीखनपुर के पास कूड़े का ढेर और पलटा हुआ डस्टबिन



दानापुर के गोला रोड मार्केट में नियमित रूप से कचड़ा नहीं उठाए जाने के कारण सामुदायिक कूड़ेदान के अंदर और बाहर अपशिष्ट

अपशिष्ट की डंपिंग और प्रसंस्करण की तस्वीरें



मुजफ्फरपुर के रौतिनिया डंपसाइट पर बनाया गया पुराना अपशिष्ट



पुराने डंपिंग साइट, दानापुर में पुराना अपशिष्ट



बैरिया, पटना में कूड़े का विशाल ढ़ेर



डंपिंग साइट के पास की इमारत, बैरिया, पटना, और अपशिष्ट से निकलने वाला पानी (लीचेट)



सुल्तानगंज नगर परिषद् के प्रखंड के अहाते मे स्थित खाद का ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्र



रामनगर नगर परिषद् में जल जमाव क्षेत्र के पासं जीर्ण–शीर्ण स्थिति में खाद का गड्ढा और इसमें डाला गया मिश्रित अपशिष्ट।



मुंगेर नगर निगम में सामग्री रिकवरी केन्द्र के पास जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हॉनी कॉम्ब जिसे खाद निर्माण के लिये बनाया गया था।



डंपिंग साइट, बैरिया, पटना में खाद बनाने और अपशिष्ट को अलग करने की अकार्यशील मशीन।

परिशिष्ट–5.4

(संदर्भः कंडिका–5.3.2, पृष्ठ – 57)

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपभोक्ता शुल्क का अधिरोपण एवं संग्रहण

क्रम सं.	शहरी स्थानीय निकाय	2020.21				2021.22				संग्रहणीय उपभोक्ता शुल्क			2020–21 और 2021–22 में एकत्रित उपभोक्ता शुल्क	बकाया
		परिवारों की संख्या	वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की संख्या	संस्थानों की संख्या	क्षेत्र में बी.पी.एल. परिवारों की संख्य	परिवारों की संख्या	वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की संख्या	संस्थानों की संख्या	क्षेत्र में बी.पी.एल. परिवारों की संख्य	2020–21 में न्यूनतम संग्रहणीय उपभोक्ता शुल्क	2021–22 में न्यूनतम संग्रहणीय उपभोक्ता शुल्क	न्यूनतम कुल संग्रहणीय		
1	पटना	2,31,287	29,700	0	1,24,556	2,72,936	37,800	0	1,24,556	7,40,63,160	9,87,76,800	17,28,39,960	25,30,75,671	-
2	गया	73,840	0	0	30,190	75,000	0	0	30,190	1,57,14,000	1,61,31,600	3,18,45,600	3,20,02,782	-
3	भागलपुर					76,205	200	150	27,050	0	1,88,35,800	1,88,35,800	0	1,88,35,800
4	मुजफ्फरपुर	49,401	0	0	25,527	69,051	10,453	0	25,527	85,94,640	2,82,12,240	3,68,06,880	1,92,920	3,66,13,960
5	दरभंगा	54,505	1,092	0	38,223	54,505	1,092	0	38,223	71,71,920	71,71,920	1,43,43,840	92,09,420	51,34,420
6	पूर्णिया					55,003	8,286	0	18,115	0	2,32,22,880	2,32,22,880	0	2,32,22,880
7	मुंगेर	32,891	1,657	211	24,364					63,24,120	0	63,24,120	9,22,980	54,01,140
8	छपरा	35,216	0	0	25,615	35,919	0	0	25,615	34,56,360	37,09,440	71,65,800	900	71,64,900
9	सहरसा	28,680	2,000	21	21,312	28,680	2,000	21	21,312	68,83,800	68,83,800	1,37,67,600	49,50,000	88,17,600
10	दानापुर	28,932	140	21	17,378	39,636	140	21	17,378	36,55,200	68,66,400	1,05,21,600	0	1,05,21,600
11	हाजीपुर	0	78	0	0	0	3,422	0	0	70,200	30,79,800	31,50,000	0	31,50,000
12	किशनगंज	21,235	2,892	67	16196	21,235	2,892	67	16,196	43,15,500	43,15,500	86,31,000	60,62,020	25,68,980
13	जहानाबाद	20,665	1,650	350	6,648	20,665	2,350	150	6,648	67,40,100	67,70,100	1,35,10,200	1,26,000	1,33,84,200
14	जमुई	0	0	0	0	18,387	52	0	11,890	0	19,95,900	19,95,900	0	19,95,900
15	गोपालगंज	10,658	2,770	79	4,940	10,929	2,810	79	4,940	44,45,400	45,62,700	90,08,100	0	90,08,100
16	सुल्तानगंज	13,885	1,070	10	9,156	12,210	1,070	10	9,156	24,11,700	19,09,200	43,20,900	0	43,20,900
17	रामनगर	10,605	0	0	6,112	9,123	545	14	6,112	13,47,900	14,35,800	27,83,700	0	27,83,700
18	राजगीर	6,850	300	15	3,868	10,150	300	15	3,868	12,09,600	21,99,600	34,09,200	5,98,665	28,10,535
19	दलसिंहसराय	5,068	970	69	3,208	12,120	1,500	40	3,208	11,52,600	41,43,600	52,96,200	13,15,140	39,81,060
20	बड़हिया	0	0	0	0	7,798	200	0	4,654	0	8,74,560	8,74,560	0	8,74,560
21	बहादुरगंज	8,288	2,360	0	7,358	8,288	2,360	0	7,358	16,39,200	16,39,200	32,78,400	0	32,78,400
22	जगदीशपुर	6,326	42	0	3,317	5,716	170	0	3,317	7,47,360	6,77,760	14,25,120	0	14,25,120
23	मखदुमपुर	5,388	0	0	2,624	5,406	0	0	2,624	6,63,360	6,67,680	13,31,040	0	13,31,040
24	झंझारपुर	6,073	880	20	5,112	6,073	880	20	5,112	7,94,640	7,94,640	15,89,280	0	15,89,280
25	मुरलीगंज	7,656	1,102	22	5,049	0	0	0	0	13,26,480	0	.....	अनुपलब्ध	---
26	अमरपुर	4,845	473	107	4,162	5,221	12	10	4,162	6,40,320	2,79,360	9,19,680	0	9,19,680
27	महाराजगंज	4,668	0	0	3,243	4,668	225	14	3,243	3,42,000	5,02,200	8,44,200	0	8,44,200
28	बेलसंड	4,951	290	15	3,673	4,951	16	10	3,673	5,07,720	3,34,320	8,42,040	82,530	7,59,510
								कुल						**17,07,37,465**

(स्रोतः नमूना जांचित भाहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)

क्रम संख्या	विवरण	नगर निगम में न्यूनतम मासिक शुल्क (₹ में)	नगर परिषद् में न्यूनतम मासिक शुल्क (₹ में)	नगर पंचायत में न्यूनतम मासिक शुल्क (रुपये में)
1	आवासीय	30	25	20
2	गैर आवासीय	100	75	50
3	संस्थान	500	250	150
नोटः – नगर परिषद् सहरसा ने आवासीय के लिए मासिक शुल्क 50 रुपये और गैर आवासीय के लिए 100 रुपये निर्धारित किया है।				

नोटः– बिहार सरकार द्वारा एक विशेष श्रेणी (अर्थात् परिवारों, वाणिज्यिक संस्थाओं, संस्थानों आदि) के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम दर के आधार पर न्यूनतम संग्रहणीय राशि की गणना की गई है, जिसे बी.पी.एल. परिवारों के लिए विधिवत् समायोजित करने वाले परिवारों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों/संस्थानों की संख्या से गुणा किया गया है।

किसी विशेष वर्ष के लिए न्यूनतम संग्रहणीय उपभोक्ता शुल्क = {(परिवारों की संख्या–बीपीएल परिवारों की संख्या) x 12 महीने x परिवारों के लिए उपभोक्ता शुल्क की न्यूनतम मासिक दर}+(वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की संख्या x 12 महीने x वाणिज्यिक प्रतिश्ठानों के लिए उपभोक्ता षुल्क की न्यूनतम मासिक दर) + (संस्थानों की संख्या x 12 महीने x संस्थानों के लिए उपभोक्ता शुल्क की न्यूनतम मासिक दर)

परिशिष्ट–5.5

(संदर्भः कंडिका – 5.3.5, पृष्ठ – 61)

अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) जमा करने में विलम्ब

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	शहरी स्थानीय निकाय	अनुदान प्राप्ति की अवधि	शीर्ष–वार प्राप्त अनुदान की राशि (करोड़ में)				कुल	शीर्ष–वार प्रेषित यू.सी. की राशि (करोड़ में)				कुल	यू.सी. जमा करने की अवधि	विलंबित अवधि (माह में)
			पंचम रा.वि.आ.	14वीं वि.आ.	15वीं वि.आ.	नागरिक सुविधा		पंचम रा. वि.आ.	14वीं वि.आ.	15वीं वि.आ.	नागरिक सुविधा			
1.	भागलपुर	अक्टूबर 2018 से अगस्त 2019	41.62	--	--	7	48.62	41.62	--	--	7	48.62	अप्रैल 2021	02 से 11
2.	पूर्णिया	अगस्त 2017 से मई 2020	73.14	33.73	7.26	9.84	123.97	46.70	25.73	2.68	9.83	84.94	अप्रैल 2020 से नवंबर 2022	06 से 30
3.	मुंगेर	अगस्त 2017 से अक्टूबर 2018	35.85	11.56	––	4.31	51.72	28.91	9.29	––	3.98	42.18	मई 2020 से मई 2022	02 स 25
4.	हाजीपुर	जून 2018 से सितंबर 2020	35.39	9.17	7.50	2.42	54.48	35.39	9.17	7.50	2.42	54.48	फरवरी 2021 से नवंबर 2022	02 से 14
5.	जमुई	जुलाई 2018	8.30	––	––	––	8.30	4.10	––	––	––	4.10	मार्च 2020	02
6.	सुल्तानगंज	अगस्त 2017 से मई 2020	12.10	2.30	1.41	1.75	17.56	11.73	2.30	1.41	1.75	17.19	फरवरी 2020 से सितंबर 2202	04 स 32
7.	रामनगर	जूलाई 2018 से नवंबर 2019	6.78	3.94	--	--	10.72	6.78	3.94	--	--	10.72	मई 2020 से सितंबर 2022	04 से 21
8.	महराजगंज	जून 2018 से जनवरी 2019	1.88	0.83	--	--	2.71	1.88	0.83	--	--	2.71	--	01 से 20
9.	बेलसंड	मार्च 2017 से मई 2020	2.84	0.69	1.24	0.28	5.04	2.84	0.69	1.24	0.25	5.02	मई 2021 से जूलाई 2022	08 से 36
कुल			**217.9**	**62.22**	**17.41**	**25.6**	**323.12**	**179.95**	**51.95**	**12.83**	**25.23**	**269.96**		

(स्रोतः नमूना जांचित शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)

परिशिष्ट–5.6

(संदर्भः कंडिका –5.3.5, पृष्ठ – 61)

अगस्त–दिसम्बर 2022 तक अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत नहीं करना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शहरी स्थानीय निकाय	अनुदान प्राप्ति की अवधि	शीर्ष–वार प्राप्त अनुदान की राशि (करोड़ में)				कुल	शीर्ष–वार प्रेषित यू.सी. की राशि (करोड़ में)				कुल	शीर्ष–वार प्रेषित नहीं की गई यू.सी. की राशि (करोड़ में)				कुल	यू.सी. जमा न करने की अवधि (माह में)
			पंचम रा.वि.आ.	14वीं वि.आ.	15वीं वि.आ.	राज्य योजना (नागरिक सुविधा)		पंचम रा.वि.आ.	14वीं वि.आ.	15वीं वि.आ.	राज्य योजना (नागरिक सुविधा)		पंचम रा.वि.आ.	14वीं वि.आ.	15वीं वि.आ.	राज्य योजना (नागरिक सुविधा)		
1.	पटना	फरवरी 2018 से फरवरी 2021	323.91	122.5	--	335.44	781.85	37.29	19.73	--	48.19	105.21	286.62	102.77	--	287.25	676.64	22-57
2.	भागलपुर	जुलाई 2018 से मार्च 2021	31.98	37.24	91.36	1.75	162.33	0	0	0	0	0	31.98	37.24	91.36	1.75	162.33	20-52
3.	मुजफ्फरपुर	सितंबर 2017 से मई 2021	40.35	--	43.37	2.07	85.79	0	--	0	0	0	40.35	--	43.37	2.07	85.79	18-60
4.	पूर्णिया	जुलाई 2018 से मार्च 2021	57.05	27.58	58.38	3.30	146.31	11.34	15.63	2.68	3.29	32.94	45.72	11.95	55.70	0.01	113.38	21-53
5.	मुंगेर	अगस्त 2017 से नवंबर 2020	46.43	25.10	21.01	2.41	94.95	3.23	7.16	0	1.65	12.04	43.20	17.94	21.01	0.77	82.92	22-61
6.	जमुई	अगस्त 2017 से मार्च 2021	22.99	9.22	19.33	2.5	54.04	4.74	0	0	1.08	5.82	18.25	9.22	19.33	1.42	48.22	18-61
7.	सुल्तानगंज	फरवरी 2021	--	--	3.11	0.43	3.54	--	--	0	0	0	--	--	3.11	0.43	3.54	21
8.	अमरपुर	अगस्त 2017 से मई 2020	0.52	0.83	0.75	0.68	2.78	0.51	0.82	0.42	0.48	2.23	0.01	0.01	0.32	0.19	0.53	30-63
9.	हाजीपुर	नवंबर 2019 से मार्च 2021	--	2.04	7.5	--	9.54	--	0.71	1.89		2.6	--	1.33	5.61	--	6.94	21-36
कुल (करोड़ में)			**523.23**	**224.51**	**244.81**	**348.58**	**1,341.13**	**57.11**	**44.05**	**4.99**	**54.69**	**160.84**	**466.13**	**180.46**	**239.81**	**293.89**	**1,180.29**	

(स्रोतः नमूना जांचित शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)

परिशिष्ट–5.7

(संदर्भः कंडिका –5.4.4, पृष्ठ – 66)

2017–22 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों में सूचना, शिक्षण एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों की स्थिति

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय	आई. ई. सी. गतिविधियों पर किया गया व्यय (लाख में)	शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए गए सूचना, शिक्षण एवं संचार गतिविधियों के प्रकार	अभियुक्तियाँ
1	पटना	अनुपलब्ध	स्रोत पृथक्करण, स्वच्छता रैली, स्वच्छता की पाठशाला	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष रूप से नहीं
2	गया	अनुपलब्ध		इकाई द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए
3	भागलपुर	22.62	नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग, जागरूकता	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष रूप से नहीं
4	मुजफ्फरपुर	अनुपलब्ध		इकाई द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए
5	दरभंगा	62.72	नुक्कड नाटक, दिवाल पेंटिंग, माईक से प्रचार,	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष रूप से नहीं
6	पूर्णिया	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	इकाई द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए
7	मुंगेर	अनुपलब्ध	-	इकाई द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए
8	छपरा	अनुपलब्ध	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित सूचना, शिक्षण एवं संचार गतिविधियां	
9	सहरसा	शून्य		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष रूप से नहीं
10	दानापुर	12.29	नुक्कड़ नाटक, दिवाल पेंटिंग, प्लास्टिक प्रतिबंध विज्ञापन, एस.डब्लू. एम. के लिए विज्ञापन आदि	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष रूप से नहीं
11	हाजीपुर	189.8	पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, दिवाल पेंटिंग,	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष रूप से नहीं
12	किशनगंज	30.20	नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग, स्वच्छता सर्वेक्षण, आदि	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष रूप से नहीं
13	जहानाबाद	अनुपलब्ध		इकाई द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए
14	जमुई	6.17	नुक्कड़ नाटक,	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष रूप से नहीं
15	गोपालगंज	3.89		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष रूप से नहीं
16	सुल्तानगंज	अनुपलब्ध		इकाई द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए
17	रामनगर	2.07		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष रूप से नहीं
18	राजगीर	1.94	नुक्कड नाटक, पत्रक	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष रूप से नहीं
19	दलसिंहसराय	7.32	माईक से प्रचार, दिवाल पेंटिंग, सभा, नुक्कड़ नाटक, स्वयं सहायता समूह की भागीदारी	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष रूप से नहीं
20	बड़हिया	शून्य	सूचना, शिक्षण एवं संचार की गतिविधियां नहीं किया जाना	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष रूप से नहीं
21	बहादुरगंज	67.5	दिवाल पेंटिंग, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, स्वयं सहायता समूह की भागीदारी	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष रूप से नहीं
22	जगदीशपुर	अनुपलब्ध		इकाई द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए
23	मखदुमपुर	अनुपलब्ध		इकाई द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए
24	झंझारपुर	0.76	नुक्कड़ नाटक,	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष रूप से नहीं
25	मुरलीगंज	8.53	दिवाल पेंटिंग, नुक्कड़ नाटक	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष रूप से नहीं
26	अमरपुर	5.64	-	इकाई द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए
27	महाराजगंज	1.59	दिवाल पेंटिंग, नुक्कड़ नाटक आदि	
28	बेलसंड	अनुपलब्ध	नुक्कड़ नाटक	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष रूप से नहीं
कुल		**423.04**		

(स्रोतः नमूना जांचित शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)

परिशिष्ट–5.8

(संदर्भः कंडिका –5.5.2,2, पृष्ठ – 72)

2016–22 के दौरान परिवारों को प्रदान किए गए कूड़ेदान की स्थिति

क्रम सं0	शहरी स्थानीय निकाय	परिवारों की संख्या	क्रय किए गए डस्टबिन सेटों की संख्या	परिवारों को उपलब्ध कराए गए डस्टबिन सेट	भण्डार में पड़े हुए डस्टबिन सेट	परिवार जिन्हें डस्टबिन सेट नहीं दिया गया	व्यय (₹लाख में)	क्रय की तिथि/माह	भौतिक सत्यापन/ लेखापरीक्षा की तिथि/माह
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पटना	2,72,936	0	0	0	2,72,936	0	0	0
2	गया	75,000	1,00,000 (जोड़े)	87,500	12,500	0	434.00	फरवरी 2018	अक्टूबर 2022
			1,00,000 (तीन का सेट)	82,943	17,057	0	246.00	मार्च 2021	
3	भागलपुर	79,877	28,900	5,000	23,900	74,877	31.00	31.07.19	18.10.22
4	मुजफ्फरपुर	52,290	81,550	आँकड़े अनुपलब्ध	आँकड़े अनुपलब्ध	आँकड़े अनुपलब्ध	आँकड़े अनुपलब्ध	आँकड़े अनुपलब्ध	आँकड़े अनुपलब्ध
5	दरभंगा	54,505	60,000	51,887	8,113	2,618	84.90	सितम्बर 2019	13.09.22
6	पूर्णिया	55,003	35,000	24,455	10,545	30,548	145.60	2018-19	10.12.22
7	मुंगेर	32,891	32,891	27,125	5,766	5,766	29.11	अगस्त 2019 से दिसम्बर 2019	27.08.22
8	छपरा	35,919	24,700	24,700	0	11,219	254.86	अप्रैल 2017 से जनवरी 2018	22.12.2022
9	सहरसा	28,680	40,000	37,419	2,581	8,739	31.90	25.07.19	नवम्बर 2022
10	दानापुर	आँकड़े अनुपलब्ध	आँकड़े अनुपलब्ध	आँकड़े अनुपलब्ध	आँकड़े अनुपलब्ध	आँकड़े अनुपलब्ध	आँकड़े अनुपलब्ध	आँकड़े अनुपलब्ध	आँकड़े अनुपलब्ध
11	हाजीपुर	22,708	29,000	18,000	11,000	4,708	36.38	14.11.19	दिसम्बर 2022
12	किशनगंज	21,235	15,991	15,991	0	5,244	182.30	मई 2016 एवं अप्रैल 2017	दिसम्बर 2022
13	जहानाबाद	20,665	20,000	आँकड़े अनुपलब्ध	आँकड़े अनुपलब्ध	आँकड़े अनुपलब्ध	31.10	फरवरी 2020	15.09.22
14	जमुई	18,387	7,500	आँकड़े अनुपलब्ध	आँकड़े अनुपलब्ध	आँकड़े अनुपलब्ध	111.00	29.03.17	19.09.22
15	गोपालगंज	10,928	10,658	आँकड़े अनुपलब्ध	आँकड़े अनुपलब्ध	आँकड़े अनुपलब्ध	आँकड़े अनुपलब्ध	आँकड़े अनुपलब्ध	आँकड़े अनुपलब्ध
16	सुल्तानगंज	12,210	12,500	12,053	447	157	21.24	18.08.19	16.11.19
17	रामनगर	10,181	6,262	6,262	0	3,919	8.50	0	0

क्रम सं0	शहरी स्थानीय निकाय	परिवारों की संख्या	क्रय किए गए डस्टबिन सेटों की संख्या	परिवारों को उपलब्ध कराए गए डस्टबिन सेट	भण्डार में पड़े हुए डस्टबिन सेट	परिवार जिन्हें डस्टबिन सेट नहीं दिया गया	व्यय (₹लाख में)	क्रय की तिथि/माह	भौतिक सत्यापन/ लेखापरीक्षा की तिथि/माह
18	राजगीर	10,150	7,500	2,700	4,800	7,450	12.30	अक्टूबर 2021	30.11.22
19	दलसिंहसराय	12,120	6,500	5,249	1,251	6,871	9.87	11.06.21	29.09.22
20	बड़हिया	5,951	16,000	आँकड़े अनुपलब्ध	आँकड़े अनुपलब्ध	आँकड़े अनुपलब्ध	23.93	जुलाई 2019 एवं अगस्त 2021	06.10.22
21	बहादुरगंज	8,288	9,400	7,100	2,300	1,188	53.16	16.01.19	27.12.22
22	जगदीशपुर	6,326	5,716	5,716	0	610	20.25	0	0
23	मखदुमपुर	5,406	3,590	2,995	595	2,411	5.70	अक्टूबर 2020	20.09.22
24	झंझारपुर	6,073	4,200*	3,500*	700*	2573*	19.32	10.02.17	14.10.22
25	मुरलीगंज	7,656	7,500	5,580	1,920	2,076	116.25	23.12.15	15.11.22
26	अमरपुर	5,221	5,000	4,800	200	421	6.93	16.10.17	28.11.22
27	महाराजगंज	4,668	9,000	6,917	2,083	0	24.97	जून 2018 एवं मई 2020	11.01.23
28	बेलसंड	4,951	7,500	500	7,000	4,451	आँकड़े अनुपलब्ध	2015-16	अक्टूबर 2022
कुल							**1,940.57**		

2016–22 के दौरान परिवारों को प्रदान किए गए कूड़ेदान की स्थिति

*(स्रोतः नमूना जांचित शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख) *एकल डस्टबिन क्रय किया गया। # वास्तव में स्टोर में केवल 625 एकल कूड़ेदान उपलब्ध थे। 'एकल कूड़ेदान की क्रय/वितरित किया गया।*

परिशिष्ट–5.9

(संदर्भः कंडिका –5.5.2.7, पृष्ठ – 78)

वर्ष 2017–22 के दौरान विभिन्न सामुदायिक स्थानों पर स्थापित सामुदायिक कूड़ेदानों की स्थिति

(₹ लाख में)

क्रम सं.	शहरी स्थानीय निकाय	बिन की क्षमता (लीटर)														कुल क्षमता (लीटर)
		100		120*/140#		240		330		660		1100		3500		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	पटना	आँ0अनु0	आँ0अनु0	200#	31.92	1,000	33.77	आँ0अनु0	आँ0अनु0	आँ0अनु0	आँ0अनु0	400	89.45	आँ0अनु0	आँ0अनु0	7,08,000
2.	गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	500	45.45	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1,20,000
3.	भागलपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	280	112.00	20	15.00	3,78,000
4.	मुजफ्फरपुर	आँ0अनु0	आँ0अनु0	आँ0अनु0	आँ0अनु0	आँ0अनु0	आँ0अनु0	आँ0अनु0	आँ0अनु0	आँ0अनु0	आँ0अनु0	120	34.80	आँ0अनु0	आँ0अनु0	1,32,000
5.	दरभंगा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	191	42.02	शून्य	शून्य	2,10,100
6.	पूर्णिया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	600	44.94	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	450	216.46	शून्य	शून्य	6,39,000
7.	मुंगेर	शून्य	शून्य	100*	2.49	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	12,000
8.	छपरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	200	78.20	शून्य	शून्य	2,20,000
9.	सहरसा	500	42.48	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	50,000
10.	दानापुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3,000	238.71	शून्य	शून्य	150	64.60	150	74.87	शून्य	शून्य	9,84,000
11.	हाजीपुर	192	41.28	शून्य	शून्य	1500	149.85	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	आँ0अनु0	आँ0अनु0	शून्य	शून्य	3,79,200
12.	किशनगंज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	100	17.96	900	167.31	150	55.46	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4,20,000
13.	जहानाबाद	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	600	75.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1,44,000
14.	जमुई	400	114.40	शून्य	शून्य	280	20.18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	187	61.32	शून्य	शून्य	3,12,900
15.	गोपालगंज	500	109.00	शून्य	शून्य	आँ0अनु0	आँ0अनु0	शून्य	शून्य	आँ0अनु0	आँ0अनु0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	50,000
16.	सुल्तानगंज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	400	73.40	शून्य	शून्य	60	29.91	100	58.10	शून्य	शून्य	2,45,600

क्रम सं.	शहरी स्थानीय निकाय	बिन की क्षमता (लीटर)														कुल क्षमता (लीटर)
		100		120*/140#		240		330		660		1100		3500		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
17.	रामनगर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2100	351.84	शून्य	शून्य	50	24.00	250	105.02	शून्य	शून्य	8,12,000
18.	राजगीर	शून्य	शून्य	50*	1.45	शून्य	शून्य	300	69.00	शून्य	शून्य	100	44.00	शून्य	शून्य	2,15,000
19.	दलसिंहसराय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0
20.	बड़हिया	शून्य	शून्य	150	43.28	200	24.89	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	56	18.31	शून्य	शून्य	1,27,600
21.	बहादुरगंज	शून्य	शून्य	30*	0.96	शून्य	शून्य	500	92.25	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1,68,600
22.	जगदीशपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	50	5.49	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	12,000
23.	मखदुमपुर	24	2.13	शून्य	शून्य	24	2.80	24	3.43	शून्य	शून्य	86	30.70	शून्य	शून्य	1,10,680
24.	झंझारपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0
25.	मुरलीगंज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0
26.	अमरपुर	शून्य	शून्य	44*	1.63	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	6	3.26	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	9,240
27.	महाराजगंज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	300	55.45	30	14.76	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1,18,800
28.	बेलसंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	300	56.70	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	99,000
कुल		**1,616**	**309.29**	**574**	**81.73**	**10,354**	**1,084.28**	**2324**	**444.14**	**446**	**191.99**	**2,570**	**965.25**	**20**	**15**	**66,77,720**
कुल राशि		**3,091.68 (₹ 30.92 करोड़)**														

*(स्रोतः नमूना जांचित शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख) *120 लीटर कम्यूनिटी बिन्स, # 140 लीटर कम्यूनिटी बिन्स*

परिशिष्ट–5.10

(संदर्भः कंडिका –5.5.6.2, पृष्ठ – 82)

बिना पंजीकरण, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन

शहरी स्थानीय निकाय	वाहनों की संख्या	मोटर वाहन अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं होने वाले वाहनों की संख्या	बीमा नहीं कराने वाले वाहनों की संख्या	पी.यू.सी. प्रमाण पत्र नहीं रखने वाले वाहनों की संख्या
भागलपुर	109	54	109	109
छपरा	32	4	32	32
दरभंगा	90	8	90	3
गया	250	174	250	250
मुंगेर	56	36	56	56
मुजफ्फरपुर	169	71	169	169
पटना	832	0	7	0
पूर्णिया	79	44	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही
सहरसा	57	57	57	57
अमरपुर	6	6	6	6
बहादुरगंज	10	9	9	10
बड़हिया	12	12	12	12
बेलसंड	14	14	14	1
जगदीशपुर	6	6	6	0
झंझारपुर	10	4	4	4
महाराजगंज	20	17	20	20
मखदुमपुर	5	5	5	5
मुरलीगंज	7	0	5	5
दलसिंहसराय	20	0	2	0
दानापुर	45	6	40	20
गोपालगंज	20	20	20	20
हाजीपुर	61	20	61	0
जहानाबाद	54	50	44	54
जमुई	19	14	19	19
किशनगंज	10	9	10	9
राजगीर	30	12	30	30
रामनगर	30	30	30	24
सुल्तानगंज	14	14	14	14
कुल	**2067**	**696**	**1121**	**929**

(स्रोतः नमूना जांचित शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)

परिशिष्ट–5.11

(संदर्भः कंडिका –5.5.6.5, पृष्ठ – 84)

जी.पी.एस. के माध्यम से अपशिष्टों के परिवहन में लगे वाहनों की निगरानी नहीं होना

वर्ष	शहरी स्थानीय निकाय	वाहनों की संख्या	वाहनों की संख्या जिनमें जी.पी.एस. लगाया गया था	वाहनों की संख्या जिसमें जी.पी.एस. नहीं लगाया गया था
मार्च 2022 तक	गया	250	173	77
	जहानाबाद	54	0	54
	मखदुमपुर	5	0	5
	पटना	832	832	0
	राजगीर	30	16	14
	छपरा	32	13	19
	महाराजगंज	20	0	20
	बेलसंड	14	0	14
	गोपालगंज	20	0	20
	हाजीपुर	61	59	2
	रामनगर	30	23	07
	मुजफ्फरपुर	169	110	59
	जगदीशपुर	6	0	6
	मुंगेर	56	30	26
	जमुई	19	3	16
	बड़हिया	12	12	0
	भागलपुर	109	61	48
	सुल्तानगंज	14	0	14
	अमरपुर	6	0	6
	पूर्णिया	79	0	79
	सहरसा	57	0	57
	दरभंगा	90	0	90
	दलसिंहसराय	20	0	20
	मुरलीगंज	7	0	7
	झंझारपुर	10	0	10
	किशनगंज	10	0	10
	बहादुरगंज	10	0	10
	दानापुर	45	0	45
	कुल	**2,067**	**1332**	**735**

(स्रोतः नमूना जांचित शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)

परिशिष्ट–5.12

(संदर्भः कंडिका – 5.5.6.6, पृष्ठ–85)

ईंधन लागत के भुगतान पर किया गया अधिक व्यय

(अ) अवधिः 16 दिसम्बर 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक

क्रम संख्या	ऑटो टिपर संख्या	ईंधन की खपत (लीटर में)	तय की गई दूरी (गणनाः 8 कि.मी.प्रति ली.) (कि.मी. में)	कुल व्यय (रुपये में)	औसत मूल्य / लीटर	वास्तविक ईंधन खपत की गणना @ 18 कि.मी. प्रति ली.	वास्तविक व्यय	अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5-8)
1	1/20	690	5,520	57,994	84	307	25,775	32,219
2	2/20	540	4,320	45,315	84	240	20,140	25,175
3	3/20	690	5,520	57,990	84	307	25,773	32,217
4	4/20	505	4,040	42,666	84	224	18,963	23,703
5	5/20	540	4,320	45,242	84	240	20,108	25,134
6	6/20	600	4,800	50,415	84	267	22,407	28,008
7	7/20	600	4,800	50,356	84	267	22,380	27,976
8	8/20	570	4,560	47,910	84	253	21,293	26,617
9	9/20	430	3,440	35,993	84	191	15,997	19,996
10	10/20	510	4,080	42,780	84	227	19,013	23,767
11	11/20	435	3,480	36,508	84	193	16,226	20,282
12	12/20	410	3,280	34,633	84	182	15,392	19,241
13	13/20	570	4,560	47,888	84	253	21,284	26,604
14	14/20	270	2,160	22,665	84	120	10,073	12,592
15	15/20	360	2,880	30,429	85	160	13,524	16,905
16	16/20	480	3,840	39,942	83	213	17,752	22,190
17	17/20	570	4,560	47,991	84	253	21,329	26,662
18	18/20	475	3,800	39,950	84	211	17,756	22,194
19	19/20	480	3,840	40,180	84	213	17,858	22,322
20	20/20	530	4,240	44,538	84	236	19,795	24,743
21	21/20	455	3,640	38,084	84	202	16,926	21,158
22	22/20	450	3,600	38,081	85	200	16,925	21,156
23	23/20	480	3,840	40,329	84	213	17,924	22,405
24	24/20	350	2,800	29,583	85	156	13,148	16,435
25	25/20	440	3,520	36830	84	196	16,369	20,461
26	26/20	385	3,080	32,780	85	171	14,569	18,211
27	27/20	600	4,800	50,575	84	267	22,478	28,097
28	28/20	465	3,720	38,909	84	207	17,293	21,616
29	29/20	385	3,080	31,893	83	171	14,175	17,718
30	30/20	575	4,600	48,392	84	256	21,508	26,884
31	31/20	535	4,280	44,882	84	238	19,948	24,934
32	32/20	560	4,480	46,981	84	249	20,880	26,101
33	33/20	270	2,160	22,659	84	120	10,071	12,588
34	34/20	565	4,520	47,488	84	251	21,106	26,382
35	35/20	505	4,040	42,407	84	224	18,848	23,559
36	36/20	590	4,720	49,904	85	262	22,180	27,724
37	37/20	420	3,360	34,975	83	187	15,544	19,431
38	38/20	630	5,040	52,992	84	280	23,552	29,440
39	39/20	570	4,560	47,921	84	253	21,298	26,623
40	40/20	510	4,080	42,867	84	227	19,052	23,815

क्रम संख्या	ऑटो टिपर संख्या	ईंधन की खपत (लीटर में)	तय की गई दूरी (गणनाः 8 कि.मी.प्रति ली.) (कि.मी. में)	कुल व्यय (रुपये में)	औसत मूल्य / लीटर	वास्तविक ईंधन खपत की गणना @ 18 कि.मी. प्रति ली.	वास्तविक व्यय	अधिक भुगतान
41	41/20	450	3,600	37,900	84	200	16,844	21,056
42	42/20	535	4,280	44,974	84	238	19,988	24,986
43	43/20	510	4,080	42,889	84	227	19,062	23,827
44	44/20	565	4,520	47,521	84	251	21,120	26,401
45	45/20	365	2,920	30,166	83	162	13,407	16,759
46	46/20	660	5,280	55,526	84	293	24,678	30,848
47	47/20	685	5,480	57,541	84	304	25,574	31,967
48	48/20	560	4,480	46,995	84	249	20,887	26,108
49	49/20	550	4,400	45,961	84	244	20,427	25,534
50	50/20	320	2,560	26,875	84	142	11,944	14,931
कुल (अ)		**25,195**	**2,01,560**	**21,16,265**	**84**	**11198**	**9,40,562**	**1,17,5703**

(ब) अवधिः मई 2021 से जुलाई 2022 तक

क्रम संख्या	ऑटो टिपर संख्या	ईंधन की खपत (लीटर में)	तय की गई दूरी (गणनाः 8 कि.मी.प्रति ली.) (कि.मी. में)	कुल व्यय (रुपये में)	औसत मूल्य / लीटर	वास्तविक ईंधन खपत की गणना @ 18 कि.मी. प्रति ली.	वास्तविक व्यय	अधिक भुगतान
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9 = (5-8)**
1	3888	1,840	14,720	1,74,452	95	818	77,534	96,918
2	3889	2,385	19,080	2,25,585	95	1,060	1,00,260	1,25,325
3	3890	2,520	20,160	2,39,191	95	1,120	1,06,307	1,32,884
4	3891	1,720	13,760	1,62,352	94	764	72,156	90,196
5	3892	2,120	16,960	2,01,406	95	942	89,514	1,11,892
6	3893	1,560	12,480	1,48,902	95	693	66,179	82,723
7	3894	1,190	9520	1,12,893	95	529	50,175	62,718
8	3895	1,645	13,160	1,56,427	95	731	69,523	86,904
9	3896	2,280	18,240	2,16,231	95	1,013	96,103	1,20,128
10	3897	1,065	8,520	1,00,603	94	473	44,712	55,891
11	3898	1,980	15,840	1,88,861	95	880	83,938	1,04,923
12	3899	1,950	15,600	1,84,987	95	867	82,216	1,02,771
13	3901	2,030	16,240	1,93,056	95	902	85,803	1,07,253
14	3902	1,405	11,240	1,32,290	94	624	58,796	73,494
15	3903	2,215	17,720	2,10,430	95	984	93,524	1,16,906
16	3904	2,435	19,480	2,31,606	95	1,082	1,02,936	1,28,670
17	3905	2,610	20,880	2,38,278	91	1,160	1,05,901	1,32,377
18	3906	2,390	19,120	2,28,236	95	1,062	1,01,438	1,26,798
19	3907	2,770	22,160	2,63,410	95	1,231	1,17,071	1,46,339
20	3908	2,060	16,480	1,95,321	95	916	86,809	1,08,512

क्रम संख्या	ऑटो टिपर संख्या	ईंधन की खपत (लीटर में)	तय की गई दूरी (गणना: 8 कि.मी.प्रति ली.) (कि.मी. में)	कुल व्यय (रुपये में)	औसत मूल्य / लीटर	वास्तविक ईंधन खपत की गणना @ 18 कि.मी. प्रति ली.	वास्तविक व्यय	अधिक भुगतान
21	3909	1,970	15,760	1,87,784	95	876	83,460	1,04,324
22	3910	2,335	18,680	2,21,121	95	1,038	98,276	1,22,845
23	3911	2,155	17,240	2,05,518	95	958	91,341	1,14,177
24	3912	2,445	19,560	2,31,637	95	1,087	1,02,950	1,28,687
25	3913	1,950	15,600	1,85,343	95	867	82,375	1,02,968
26	3914	180	1,440	16,100	89	80	7,156	8,944
27	3915	2,395	19,160	2,31,560	97	1,064	1,02,916	1,28,644
28	3916	2,925	23,400	2,78,220	95	1,300	1,23,653	1,54,567
29	3917	2,230	17,840	2,11,802	95	991	94,134	1,17,668
30	3918	2,120	16,960	2,00,598	95	942	89,155	1,11,443
31	3919	645	5,160	59,287	92	287	26,350	32,937
32	3920	1,840	14,720	1,74,503	95	818	77,557	96,946
33	3921	120	960	10,737	89	53	4,772	5,965
34	3922	870	6,960	83,531	96	387	37,125	46,406
35	3923	1,980	15,840	1,87,531	95	880	83,347	1,04,184
36	3924	1,980	15,840	1,87,922	95	880	83,521	1,04,401
37	3925	1,765	14,120	1,69,345	96	784	75,264	94,081
38	3926	2,100	16,800	1,98,870	95	933	88,387	1,10,483
39	3927	2,870	22,960	2,72,444	95	1,276	1,21,086	1,51,358
40	3928	2,030	16,240	1,92,364	95	902	85,495	1,06,869
41	3929	1,970	15,760	1,87,170	95	876	83,187	1,03,983
42	3930	1,765	14,120	1,67,980	95	784	74,658	93,322
43	3931	2,110	16,880	2,00,528	95	938	89,124	1,11,404
44	3932	1,842	14,736	1,75,479	95	819	77,991	97,488
45	3933	2,455	19,640	2,33,446	95	1091	1,03,754	1,29,692
46	3934	1,110	8,880	1,05,399	95	493	46,844	58,555
47	3935	2,100	16,800	1,99,536	95	933	88,683	1,10,853
48	3936	2,150	17,200	2,04,004	95	956	90,668	1,13,336
49	3937	2,185	17,480	2,06,808	95	971	91,915	1,14,893
50	3938	2,112	16,896	1,99,771	95	939	88,787	1,10,984
कुल (ब)		**96,874**	**7,74,992**	**91,90,855**	**95**	**43,055**	**40,84,824**	**51,06,031**
कुल योग (अ+ब) = (11,75,703 +51,06,031) = 62,81,734								

परिशिष्ट–5.13

(संदर्भः कंडिका –5.6.1.1, पृष्ठ – 89)

विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण केंद्रों की आवश्यकता

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय	वार्डों की संख्या	नगर विकास एवं आवास विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक प्रसंस्करण केंद्रों की संख्या	नगर विकास एवं आवास विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए आवश्यक कम्पोस्टिंग पिट्स की संख्या	शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विकसित प्रसंस्करण केंद्रों की वास्तविक संख्या	शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित कम्पोस्टिंग पिट्स की वास्तविक संख्या	अकार्यशील कम्पोस्टिंग पिट्स की संख्या	कार्यशील कम्पोस्टिंग पिट्स की संख्या	अपशिष्ट की मात्रा जो उपलब्ध कार्यशील कम्पोस्टिंग पिट्स द्वारा प्रसंस्कृत की जा सकती है (टन प्रति दिन)
1	पटना	75	18	360	8	176	85	91	4
2	गया	-	-	-	-	-	-	-	-
3	भागलपुर	51	12	240	2	20	10	10	0.44
4	मुजफ्फरपुर	49	12	240	5	230	100	130	5.72
5	दरभंगा	48	12	240	2	46	0	46	2.02
6	पूर्णिया	46	11	220	1	20	20	0	-
7	मुंगेर	45	11	220	0	0	-	-	-
8	छपरा	45	11	220	2	40	40	0	-
9	सहरसा	40	10	200	2	102	102	0	-
10	दानापुर	40	6	120	1	20	20	0	-
11	हाजीपुर	39	6	120	1	18	18	0	-
12	किशनगंज	34	5	100	1	20	20	0	-
13	जहानाबाद	33	5	100	1	20	20	0	-
14	जमुई	30	5	100	1	20	20	0	-
15	गेपालगंज	28	4	80	1	18	18	0	-
16	सुल्तानगंज	25	4	80	3	60	20	40	1.76
17	रामनगर	23	4	80	2	40	36	4	0.18

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय	वार्डों की संख्या	नगर विकास एवं आवास विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक प्रसंस्करण केंद्रों की संख्या	नगर विकास एवं आवास विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए आवश्यक कम्पोस्टिंग पिट्स की संख्या	शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विकसित प्रसंस्करण केंद्रों की वास्तविक संख्या	शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित कम्पोस्टिंग पिट्स की वास्तविक संख्या	अकार्यशील कम्पोस्टिंग पिट्स की संख्या	कार्यशील कम्पोस्टिंग पिट्स की संख्या	अपशिष्ट की मात्रा जो उपलब्ध कार्यशील कम्पोस्टिंग पिट्स द्वारा प्रसंस्कृत की जा सकती है (टन प्रति दिन)
18	राजगीर	32	5	100	2	40	40	0	-
19	दलसिंहसराय	28	4	80	2	40	0	40	1.76
20	बड़हिया	24	2	40	0	0	0	0	-
21	बहादुरगंज	18	2	40	1	20	20	0	-
22	जगदीशपुर	18	2	40	1	24	24	0	-
23	मखदुमपुर	19	2	40	1	20	20	0	-
24	झंझारपुर	16	2	40	2	40	40	0	-
25	मुरलीगंज	15	2	40	0	0	0	0	-
26	अमरपुर	14	2	40	1	20	0	20	0.88
27	महाराजगंज	14	2	40	1	20	20	0	-
28	बेलसंड	13	2	40	1	20	12	8	0.35
कुल		**862**	**163**	**3,260**	**45**	**1094**	**705**	**389**	**17.11**

(स्रोतः नमूना जांचित शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)

एक दिन के लिए एक पिट की क्षमता की गणना						
लंबाई (फुट)	चौड़ाई (फुट)	ऊंचाई (फुट)	घन फीट में आयतन	घन मीटर में आयतन	गीले अपशिष्ट को हैंडल करने के लिए एक पिट की क्षमता (कि.ग्रा. में) #	एक पिट/दिन की क्षमता*
1	**2**	**3**	**4=1x2x3**	**5=4x0.028**	**6=5x600**	**7=6/45**
6.5	4.5	4	117	3.276	1,965.6	43.68

एक घन मीटर गीले अपशिष्ट का वजन 600 किलोग्राम लिया गया है जैसा कि शहरी स्थानीय निकायों की अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में माना गया है।

* ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान पर दिशानिर्देश के अनुसार कम्पोस्टिंग के एक चक्र को पूरा करने में 45 दिन लगते हैं।

परिशिष्ट–5.14

(संदर्भः कंडिका –5.6.1.2, पृष्ठ – 91)

कम्पोस्टर्स का सब–ऑप्टिमल उपयोग

क्रम सं.	शहरी स्थानीय निकाय	प्रत्येक मैकेनिकल कम्पोस्टर की क्षमता (कि.ग्रा. में)	कम्पोस्टर की संख्या	क्रय की तिथि/ अवधि	राशि (₹ में)	प्लेटफार्म पर लगे कम्पोस्टर की संख्या	कम्पोस्टर की संख्या जिसमें बिजली कनेक्शन है।	कम्पोस्टरों की संख्या जो कार्यशील थे	अभिलेख के अनुसार उत्पादित कम्पोस्ट की मात्रा (कि.ग्रा.)	बेचे गए कम्पोस्ट की मात्रा	स्टोर किए गए कम्पोस्ट की मात्रा (कि.ग्रा.)	अभियुक्तियाँ
यांत्रिक कमपोस्टर												
1	पटना	2000	3	दिसम्बर–2020	65,50,320	3	3	3	कोई रिकॉर्ड संधारित नहीं	शून्य	कोई रिकॉर्ड संधारित नहीं	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान 02 मशीनें खराब पाई गई।
		500	7	जनवरी-2021	63,20,021	4	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
		250	2	जनवरी-2021	14,23,872	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
		100	1	जनवरी-2021	4,51,387	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
		1000	9	फरवरी-2021	1,69,55,906	7	6	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
2	गया	500	5	सितम्बर-2018	50,38,880	5	5	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान 03 मशीनें खराब पाई गई। शहरी स्थानीय निकाय अप्रैल 2021 के बाद से शेष 02 कम्पोस्टर्स के लिए फीड स्टॉक का आश्वासन नहीं दे रहा था।
		250	3	जनवरी-2020	33,61,950	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
		250	2	फरवरी -2020	22,41,300	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
3	भागलपुर	1000	2	मई– 2017	38,00,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
4	दरभंगा	50	2	जून 2021	आँकड़े अनुपलब्ध	2	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
5	हाजीपुर	350	8	फरवरी -2021	64,80,000	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
6	जहानाबाद	500	1	जून -2022	15,45,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

क्रम सं.	शहरी स्थानीय निकाय	प्रत्येक मैकेनिकल कम्पोस्टर की क्षमता (कि.ग्रा. में)	कम्पोस्टर की संख्या	क्रय की तिथि/ अवधि	राशि (₹ में)	प्लेटफार्म पर लगे कम्पोस्टर की संख्या	कम्पोस्टर की संख्या जिसमें बिजली कनेक्शन है।	कम्पोस्टरों की संख्या जो कार्यशील थे	अभिलेख के अनुसार उत्पादित कम्पोस्ट की मात्रा (कि.ग्रा.)	बेचे गए कम्पोस्ट की मात्रा	स्टोर किए गए कम्पोस्ट की मात्रा (कि.ग्रा.)	अभियुक्तियाँ
7	बड़हिया	350	2	जुलाई -2019	28,50,000	2	2	2	700	शून्य	700	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान कम्पोस्टिंग मशीन के पास 50–50 किलोग्राम के 14 बैग पड़े मिले।
योग			**47**		**5,70,18,636**	**28**	**22**	**5**	**700**	**0**	**700**	
							एरोबिक बॉक्स कम्पोस्टर्स					
7	बड़हिया	450	18	अक्टूबर 2021 (11) और फरवरी 2022 (07)	57,15,400	18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
8	जमुई	450	10	फरवरी और मार्च 2021	24,45,000	10	7	3	50	शून्य	50	खुली जगहो में इकट्ठा किया हुआ
योग			**28**		**81,60,400**	**28**	**7**	**3**	**50**	**0**	**50**	
कुल योग			**75**		**6,51,79,036**	**56**	**29**	**8**	**750**	**0**	**750**	

(स्रोतः नमूना जांचित शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)

परिशिष्ट–5.15

(संदर्भः कंडिका–5.6.1.3, पृष्ठ–93)

गया नगर निगम में केंद्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र से संबंधित कार्य–वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	कार्य विवरण	एकरारनामा राशि	भुगतान	भौतिक स्थिति
1	बिहार में गया नगर निगम के लिए स्वच्छ भारत मिषन के तहत 300 टन प्रति दिन नगरपालिका के मिश्रित ठोस अपशिष्ट और 20 टन प्रति दिन जैविक अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए पृथक्करण एवं जैविक अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना।	2.87	2.87	कार्य के ब्यौरा में विस्तृत रूप से विशिष्टियों का उल्लेख नहीं था और विषेशज्ञ एजेंसी से इसकी संवीक्षा नहीं कराई गई थी। इसलिए, लेखापरीक्षा परियोजना की स्थिति का पता नहीं लगा सकी।
2	बिहार में गया नगर निगम के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 300 टन प्रति दिन नगरपालिका के मिश्रित ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए पृथक्करण और शोधन संयंत्र की स्थापना।	2.24	2.24	संबंधित अभियंता ने मापी पुस्त में प्रमाणित किया कि काम पूरा हो चुका था।
3	बिहार में गया नगर निगम के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 टन प्रति दिन अजैविक नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए श्रेडर, बेलर सहित आर.डी.एफ. प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना।	1.34	1.34	आर.डी.एफ. के प्रसंस्करण के लिए श्रेडर और बेलर की आपूर्ति नहीं की गई थी और न ही कार्य स्थल पर इसकी स्थापना की गई थी।
4	बिहार में गया नगर निगम के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत, ड्रॉइंग के अनुसार विंड्रो कम्पोस्टिंग प्रौद्योगिकी पर आधारित नगरपालिका गीला अपशिष्ट प्रसंस्करण की 300 टन प्रति दिन क्षमता की स्थापना और सूखे अपशिष्ट के लिए सेमी ऑटोमेटिक मेटेरियल रिकवरी फैसिलिटी की स्थापना से संबद्ध सभी सिविल कार्यों का निर्माण।	2.84	2.41	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान विंड्रो के गठन के अभाव के कारण धीमा प्रसंस्करण देखा गया। यह भी देखा गया कि नगरीय अपशिष्ट के विशाल ढ़ेर को प्रसंस्करण स्थल पर ले जाया जा रहा था।
5	संपूर्ण रियायतग्राही अवधि के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा से उत्पन्न अक्रिय अपशिष्ट के निपटान के लिए सेनेटरी लैंडफिल का निर्माण।	2.64	2.64	एजेंसी द्वारा सेनेटरी लैंडफिल साइट के निर्माण हेतु अनुमति (अक्टूबर 2022) नहीं ली गई थी।
6	10 वर्षों की रियायतग्राही अवधि के लिए सैनिटरी लैंडफिल के संचालन एवं रखरखाव, जो पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर नवीकरणीय है।	2.84	2.70	सैनिटरी लैंडफिल का संचालन और रखरखाव 10 वर्षों के लिए था, लेकिन 95 प्रतिशत भुगतान एजेंसी को संचालन प्रारम्भ के छः महीने के भीतर किया गया था (अक्टूबर 2022)।
7	छः माह की रियायतग्राही अवधि के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा का संचालन और रखरखाव जो आवश्यकता के अनुसार नवीकरणीय होगा और एकरारनामा में उल्लिखित किया जाएगा।	3.24	3.24	एारारनामा के अनुसार अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए भुगतान किया गया था। तथापि, उस अवधि में संयंत्र और मशीनरी स्थापित नहीं किये गये थे। इसके अलावा, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रसंस्कृत अपशिष्ट की मात्रा का अनुश्रवण नहीं किया गया था।
8	पुराने अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा, जो प्रति दिन 2000 घन मीटर अपशिष्ट के लिए पर्याप्त हो, की आपूर्ति, निर्माण एवं चालू करना	2.98	2.98	संबद्ध कार्य के निर्माण की जाँच और संयंत्र एवं मशीनरी की स्थापना नहीं की गयी थी। इसलिए, लेखापरीक्षा द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सका।

क्रम संख्या	कार्य विवरण	एकरारनामा राशि	भुगतान	भौतिक स्थिति
9	डंपिंग ग्राउंड में लीगेसी अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए साइट का विकास और उससे संबंधित सिविल कार्य	2.49	2.49	
10	लीगेसी अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लांट में अपशिष्ट की खुदाई, उपचार और प्रसंस्करण सहित लीगेसी अपशिष्ट (पुराना कचड़ा) प्रसंस्करण प्लांट का संचालन और रखरखाव	2.99	2.09	सभी लीगेसी अपशिष्ट का प्रसंस्करण न होने के कारण 20 प्रतिशत भुगतान रोक दिया गया था।
11	लीगेसी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा स्थल से पृथक्करण और पुनः प्राप्ति (रिकवरी) के बाद निर्धारित स्थल पर लीगेसी अपशिष्ट का निपटान	2.99	2.09	
	कुल	**29.46**	**27.09**	

(स्रोतः गया नगर निगम के अभिलेख)

परिशिष्ट–5.16

(संदर्भः कंडिका –5.6.1.3,(iv), पृष्ठ–95)

गया नगर निगम में ताजे मिश्रित अपशिष्ट के प्रसंस्करण के बिलों में दर्शाए गए वाहनों का अधिक फेरा

क्रम संख्या	वाहनों के प्रकार	माह	अधिक फेरों की संख्या	कुल अधिक मात्रा (कि.ग्रा. में)	अधिक भुगतान की राशि (@ ₹ 630 प्रति टन)
1	कॉम्पैक्टर-1	जून से सितम्बर 2022	18	2,10,120	1,32,375.60
2	कॉम्पैक्टर–2	जून से सितम्बर 2022	14	1,68,145	1,05,931.35
3	कॉम्पैक्टर-5	जून से सितम्बर 2022	8	98,115	61,812.45
4	कॉम्पैक्टर-6	जून से सितम्बर 2022	5	60,880	38,354.40
5	कॉम्पैक्टर-7	जून से सितम्बर 2022	12	1,44,925	91,302.75
6	कॉम्पैक्टर-9	जून से सितम्बर 2022	13	1,54,030	97,038.90
7	कॉम्पैक्टर-10	जून से सितम्बर 2022	9	1,21,615	76,617.45
8	डंपर-1	जून से सितम्बर 2022	37	3,67,835	2,31,736.05
9	डंपर-2	जून से सितम्बर 2022	33	3,42,690	2,15,894.70
10	डंपर-3	जून से सितम्बर 2022	22	2,25,935	1,42,339.05
11	डंपर-4	जून से सितम्बर 2022	24	2,42,575	1,52,822.25
12	डंपर-5	जून से सितम्बर 2022	26	2,67,220	1,68,348.60
13	डंपर-6	जून से सितम्बर 2022	28	2,98,080	1,87,790.40
कुल			**249**	**27,02,165**	**17,02,363.95**

(स्रोतः नमूना जांचित शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)

परिशिष्ट–5.17

(संदर्भः कंडिका –5.6.3.2, पृष्ठ – 105)

शहरी स्थानीय निकायों में डंपिंग स्थलों की स्थिति

क्रम सं0	शहरी स्थानीय निकाय	नदी के आस–पास (अनुमानतः 100 मीटर के भीतर)	जल स्रोत के आस–पास या बाढ़ प्रवण क्षेत्र में (अनुमानतः 200 मीटर के भीतर)	जल जमाव प्रवण क्षेत्र में स्थित	निवास स्थान के आस–पास (अनुमानतः 200 मीटर के भीतर)	राजमार्ग के आस–पास (अनुमानतः 200 मीटर के भीतर)	विद्यालय के आस–पास (अनुमानतः 200 मीटर के भीतर)	अपने निवास स्थान के पास अपशिष्ट फेकने का स्थानीय विरोध के उदाहरण देखे गए	डंपिंग साइट पर अपशिष्ट जलाने के निशान देखे गए	डंपिंग साइट पर सूखे पेड़ देखे गए, जो अपशिष्ट डंपिंग के कारण होते हैं	लीचेट को अपशिष्ट से बाहर आते और साइट को कीचड़ युक्त करते हुए देखा गया था
1	पटना	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	न्हीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
2	गया	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	न्हीं	आँकड़े अनुपलब्ध	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
3	भागलपुर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	न्हीं	न्हीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
4	मुजफ्फरपुर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
5	दरभंगा	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं
6	पूर्णिया	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
7	मुंगेर	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	न्हीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
8	छपरा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	न्हीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
9	सहरसा	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	न्हीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10	दानापुर	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	न्हीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
11	हाजीपुर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
12	किशनगंज	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	न्हीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
13	जहानाबाद	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
14	जमुई	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	न्हीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
15	गेपालगंज	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं

क्रम सं0	शहरी स्थानीय निकाय	नदी के आस–पास (अनुमानतः 100 मीटर के भीतर)	जल निकाय के आस–पास या बाढ़ प्रवण क्षेत्र में (अनुमानतः 200 मीटर के भीतर)	जल जमाव प्रवण क्षेत्र में स्थित	निवास स्थान के आस–पास (अनुमानतः 200 मीटर के भीतर)	राजमार्ग के आस–पास (अनुमानतः 200 मीटर के भीतर)	विद्यालय के आस–पास (अनुमानतः 200 मीटर के भीतर)।	अपने निवास स्थान के पास अपशिष्ट फेंकने का स्थानीय विरोध के उदाहरण देखे गए	डंपिंग साइट पर अपशिष्ट जलाने के निशान देखे गए	डंपिंग साइट पर सूखे पेड़ देखे गए, जो अपशिष्ट डंपिंग के कारण होते हैं	लीचेट को अपशिष्ट से बाहर आते और साइट को कीचड़ युक्त करते हुए देखा गया था
16	सुल्तानगंज	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	न्हीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
17	रामनगर	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	न्हीं	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ
18	राजगीर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	न्हीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
19	दलसिंहसराय	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	न्हीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
20	बड़हिया	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	न्हीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
21	बहादुरगंज	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
22	जगदीशपुर	नहीं	आँकड़े अनुपलब्ध	आँकड़े अनुपलब्ध	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
23	मखदुमपुर	नहीं	नहीं	न्हीं	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
24	झंझारपुर	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
25	मुरलीगंज	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
26	अमरपुर	नहीं	हाँ	न्हीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
27	महाराजगंज	नहीं	हाँ	न्हीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
28	बेलसंड	नहीं	नहीं	न्हीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
कुल (हाँ)		**9**	**4**	**11**	**9**	**8**	**3**	**3**	**8**	**3**	**8**

(स्रोतः नमूना जांचित शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)

परिशिष्ट–5.18
(संदर्भः कंडिका –5.7.5, पृष्ठ – 112)
क्रय के बाद से अप्रयुक्त रखे गए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपकरण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय	उपकरण का नाम	क्रय की तिथि	प्रति इकाई लागत	क्रय की मात्रा	भंडार में डंप की गई सामग्रियों की मात्रा	भौतिक सत्यापन की तिथि	भंडार में डंप की गई सामग्रियों की राशि
1.	बड़हिया	श्रेडिंग मशीन	22.12.2021	2.64	03	03	30.09.2022	7.92
		ई रिक्शा	03.06.2022	2.99	30	11		32.89
		व्हील बैरो	25.11.2021	0.20	129	85		16.99
		हैंड कार्ट	27.03.2021	0.19	50	48		9.07
		ट्राईसाईकिल	27.03.2021	0.49	48	26		12.61
		240 लीटर कूड़ेदान	17.05.2022	0.12	200	200		24.89
		120 लीटर एस.एस. पोलमाउंट डस्टबिन	17.05.2022	0.29	150	7		2.02
2.	जमुई	व्हील बैरो	02.05.2022	0.17	100	47	15.09.2022	7.96
3.	मुंगेर	60 लीटर कूड़ेदान	02.01.2021	0.00	500	100	26.08.2022	0.45
		120 लीटर कूड़ेदान	05.02.2021	0.02	100	17		0.42
4.	पूर्णिया	240 लीटर कूड़ेदान	2017-18	0.07	600	91	10.12.2022	6.82
5.	भागलपुर	3500 लीटर कूड़ेदान	अक्टूबर 2021-मई 2022	0.75	20	11	19.10.2022	8.25
6..	मुजफ्फरपुर	रोड स्वीपिंग मशीन	जनवरी 2022	39.90	01	01	08.09.2022	39.90
		सी.एन.जी. टिपर	06.06.2022	8.03	20	20		160.60
7.	जहानाबाद	240 लीटर कूड़ेदान	मई 2022	0.13	600	600	15.09.2022	75.00
8.	मखदुमपुर	60-60 लीटर एस.एस. पोलमाउंट स्टील डस्टबिन	अक्टूबर 2020	0.11	95	80	20.09.2022	8.8
9.	राजगीर	120 लीटर कूड़ेदान	सितम्बर 2021	0.03	50	35	30.11.2022	1.01
10.	बेलसंड	330 लीटर कूड़ेदान	दिसम्बर 2021	0.19	300	131	21.10.2022	24.76
11.	हाजीपुर	240 लीटर कूड़ेदान	अगस्त 2021	0.10	1000	270	06.12.2022	26.97
		व्हील बैरो	मार्च 2021	0.19	230	100		19.19
12.	गोपालगंज	व्हील बैरो	अप्रैल 2022	0.19	200	200	29.12.2022	37.70
कुल								**524.22**

(स्रोतः नमूना जांचित शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)

परिशिष्ट–5.19

(संदर्भः कंडिका –5.10.3, पृष्ठ – 133)

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वीकृत बल और कार्यरत बल की स्थिति

क्रम सं0	शहरी स्थानीय निकाय	स्वीकृत बल				कार्यरत बल			
		स्वच्छता निरीक्षक / मुख्य स्वच्छता निरीक्षक	सफाई जमादार	लोक स्वच्छता और एस.डब्ल्यू.एम. पदाधिकारी /उप लोक स्वच्छता और एस.डब्ल्यू.एम. पदाधिकारी / सहायक लोक स्वच्छता और एस.डब्ल्यू.एम. पदाधिकारी	लिपिक	स्वच्छता निरीक्षक / मुख्य स्वच्छता निरीक्षक	सफाई जमादार	लोक स्वच्छता और एस.डब्ल्यू.एम. पदाधिकारी /उप लोक स्वच्छता और एस.डब्ल्यू.एम. पदाधिकारी / सहायक लोक स्वच्छता और एस.डब्ल्यू.एम. पदाधिकारी	लिपिक
1	गया	55	159	3	3	1	22	0	0
2	भागलपुर	53	153	3	3	0	0	0	0
3	मुजफ्फरपुर	51	147	3	3	1	0	0	0
4	दरभंगा	50	144	3	3	0	10	0	0
5	पूर्णिया	48	138	3	3	2	1	0	0
6	मुंगेर	47	135	3	3	0	14	0	0
7	छपरा	47	135	3	3	9	32	0	2
8	सहरसा	14	40	2	3	0	0	0	0
9	दानापुर	14	40	2	3	0	10	0	0
10	हाजीपुर	14	39	2	3	0	2	0	0
11	किशनगंज	12	34	2	3	0	1	0	0
12	जहानाबाद	12	33	2	3	0	0	0	2
13	जमुई	11	30	2	3	0	0	0	0
14	गेपालगंज	10	28	2	3	0	0	0	0
15	सुल्तानगंज	9	25	2	3	1	3	0	0
16	रामनगर	9	23	2	3	0	0	0	0
17	राजगीर	7	19	2	3	1	0	0	2

क्रम सं0	शहरी स्थानीय निकाय	स्वीकृत बल				कार्यरत बल			
		सेनेटरी इंस्पेक्टर/चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर	सफाई जमादार	लोक स्वच्छता और एस.डब्ल्यू.एम. पदाधिकारी /उप लोक स्वच्छता और एस.डब्ल्यू.एम. पदाधिकारी / सहायक लोक स्वच्छता और एस.डब्ल्यू.एम. पदाधिकारी	लिपिक	सेनेटरी इंस्पेक्टर/चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर	सफाई जमादार	लोक स्वच्छता और एस.डब्ल्यू.एम. पदाधिकारी /उप लोक स्वच्छता और एस.डब्ल्यू.एम. पदाधिकारी / सहायक लोक स्वच्छता और एस.डब्ल्यू.एम. पदाधिकारी	लिपिक
18	दलसिंहसराय	6	14	2	3	0	2	0	0
19	बड़हिया	4	12	1	2	0	0	0	0
20	बहादुरगंज	3	9	1	2	0	1	0	0
21	जगदीशपुर	3	9	1	2	1	1	0	0
22	मखदुमपुर	3	10	1	2	0	1	0	0
23	झंझारपुर	3	8	1	2	0	1	0	1
24	मुरलीगंज	3	8	1	2	0	1	0	0
25	अमरपुर	2	7	1	2	0	0	0	0
26	महाराजगंज	2	7	1	2	0	1	0	0
27	बेलसंड	2	7	1	2	0	1	0	0
कुल*		**494**	**1413**	**52**	**72**	**16**	**104**	**0**	**7**
28	पटना	82	300	18	18	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

** पटना को छोड़कर क्योंकि पटना द्वारा कार्यरत व्यक्तियों की सूचना उपलब्ध नहीं करवाया गया*

(स्रोतः नमूना जांचित शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेख)

संक्षिप्तियों की शब्दावली

संक्षिप्तियों की शब्दावली

पं.रा.वि.आ.	पंचम राज्य वित्त आयोग	आई.एस.डब्ल्यू.एम. सिस्टम	इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम
ष.रा.वि.आ.	षष्ठम राज्य वित्त आयोग	आई.ए. एंड. ए.डी.	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
ते.वि.आ.	तेरहवीं वित्त आयोग	स्था.नि.	स्थानीय निकाय
चौ.वि.आ.	चौदहवीं वित्त आयोग	एल.डी.पी.ई.	लो डेनसिटी पॉली इथिलिन
पं.वि.आ.	पंद्रहवीं वित्त आयोग	एल.एफ.ए.	स्थानीय निधि अधिनियम
ए.ए.पी.	वार्षिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम	एम.ए.एस.	मॉडल लेखांकन प्रणाली
ए.सी.	एब्सट्रैक्ट कंटिंजेंट	एम. एंड ई.	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
ए.ई.	सहायक अभियंता	एम.सी.	नगर निगम
ए.जी.	महालेखाकार	एम.एम.पी.	मिशन मोड प्रोजक्ट
ए.आर.वी.	वार्षिक किराया मूल्य	एम.आई.पी.	कार्यरत बल
ए.टी.आई.आर.	वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन	एम.आई.एस.	प्रबंध सूचना प्रणाली
बी.डी.ओ.	प्रखंड विकास पदाधिकारी	एम.ओ.पी.आर.	पंचायती राज मंत्रालय
बी.एफ.आर.	बिहार वित्तीय नियमावली	एम.ओ.यू.डी.	शहरी विकास मंत्रालय
बी.जी.एस.वाई.	बिहार ग्राम स्वराज योजना	एम.पी.आर.	मासिक प्रगति प्रतिवेदन
बी.जी.	मूल अनुदान	एम.आर.एफ.	सामग्री प्राप्ति सुविधाएं
बी.एच.क्यू.	प्रखंड मुख्यालय	एम.आर.पी.	अधिकतम खुदरा मूल्य
बी.एम.ए.	बिहार नगरपालिका अधिनियम	एम.एस.डब्ल्यू.	नगरीय ठोस अपशिष्ट
बी.एम.ए.एम.	बिहार नगरपालिका लेखांकन हस्तक	एम.एस.डब्ल्यू.एम.	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
बी.एम.ए.आर.	बिहार नगरपालिका लेखांकन नियमावली	एम.वी.	मोटर वाहन
बी.पी.आर.ए.	बिहार पंचायत राज अधिनियम	एन.सी.बी.एफ.	राष्ट्रीय क्षमता वर्धन फ्रेमवर्क
बी.पी.आर.ओ.	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी	एन.जी.ओ.	गैर सरकारी संगठन
बि.पं.स. एवं जि.प. (ब. एवं ले.) नियमावली	बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (बजट एवं लेखा) नियमावली	एन.जी.टी.	राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
बी.आर.जी.एफ.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	एन.एम.एस.	राष्ट्रीय अनुश्रवण प्रणाली
बी.एस.पी.सी.बी.	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
बी.एस.डब्ल्यू.ए.एन.	बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क	पी.ई.एस.	पंचायत इंटरप्राईजेज सूट
बी.टी.सी.	बिहार कोषागार संहिता	नि.अ.	निष्पादन अनुदान
बी.यू.आई.डी.सी.ओ.	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	प.न.नि.	पटना नगर निगम
सी. एंड डी.	संनिर्माण एवं विध्वंस	पी.पी.ई.	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण
सी.ए.	सनदी लेखाकार	पी.आर.डी.	पंचायती राज विभाग
सी.ए.ए.	संविधान संशोधन अधिनियम	पं.रा.सं.	पंचायती राज संस्थान

सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	प्रियासॉफ्ट	पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर
सी.ई.सी.	केन्द्रीय सशक्त समिति	पं.स.	पंचायत समिति
सी.ई.ओ.	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	पी.एस.बी.	पंचायत सरकार भवन
सी.एफ.सी.	केन्द्रीय वित्त आयोग	आर.जी.पी.एस.ए.	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान
सी.पी.सी.बी.	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	आर.ए.वाई.	राजीव आवास योजना
डी.सी.	डिटेल्ड कंटिंजेंट	आर.डी.एफ.	कचड़ा व्यूत्पन्न ईंधन
डी.डी.सी.	उप विकास आयुक्त	आर.एफ.पी.	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
डी.ई.	जिला अभियंता	आर.जी.एस.ए.	राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान
डी.एम.	जिला पदाधिकारी	आर.डब्ल्यू.डी.	ग्रामीण कार्य विभाग
डी.एम.सी.	दरभंगा नगर निगम	एस.ए.एस.	सामाजिक अंकेक्षण समिति
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन	एस.बी.एम.	स्वच्छ भारत अभियान
डी.पी.आर.ओ.	जिला पंचायत राज पदाधिकारी	एस.बी.एम.–यू.	स्वच्छ भारत अभियान–शहरी
डी.पी.आर.सी.	जिला पंचायत संसाधन केन्द्र	एस.डी.डी.	सिस्टम डिजाईन डॉक्यूमेंट
डी.एल.एफ.ए.	निदेशक स्थानीय निधि लेखापरीक्षा	एस.ई.आई.ए.ए.	राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण
डी.पी.सी.	जिला योजना समिति	एस.एफ.सी.	राज्य वित्त आयोग
ई.एल.ए.	स्थानीय लेखापरीक्षक	एस.एच.जी.	स्वयं सहायता समूह
ई.एस.सी.	सशक्त स्थायी समिति	एस.एच.क्यू.	राज्य मुख्यालय
ई.ओ.	कार्यपालक पदाधिकारी	एस.आई.	सिस्टम इंटिग्रेटर
जी.ई.एम.	गवर्मेन्ट ई. मार्केटप्लेस	एस.एल.ए.बी.	राज्य स्तरीय सलाहकार समिति
जी.एम.सी.	गया नगर निगम	एस.एल.बी.	सेवा स्तर मानक
जी.ओ.बी.	बिहार सरकार	एस.ओ.टी.आर.	राज्य स्वयं कर राजस्व
जी.ओ.आई.	भारत सरकार	एस.पी.आर.सी.	राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र
ग्रा.पं.	ग्राम पंचायत	एस.डब्ल्यू.एम.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
जी.पी.डी.पी.	ग्राम पंचायत विकास योजना	टी.जी.एस.	तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग
जी.पी.एम.एस.	ग्राम पंचायत प्रबंधन प्रणाली	टी.पी.डी.	टन प्रति दिन
जी.आर.एस.	शिकायत निवारण प्रणाली	यू.सी.	उपयोगिता प्रमाण पत्र
जी.एस.टी.	वस्तु एवं सेवा कर	यू.डी. एंड एच.डी.	नगर विकास एवं आवास विभाग
आई.एच.एच.एल.	व्यक्तिगत घरेलू शौचालय	श.स्था.नि.	शहरी स्थानीय निकाय
आई.एम.एस. डब्ल्यू.एम.	समन्वित नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	वी.टी.एस.	वाहन ट्रैकिंग सिस्टम
नि.प्र.	निरीक्षण प्रतिवेदन	जि.प.	जिला परिषद्

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

प्रतिवेदन डाउनलोड
करने हेतु
क्यू.आर. कोड
स्कैन करें

https://cag.gov.in/ag/bihar/hi

बिहार सरकार - वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-3